

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मई 2023—ज्येष्ठ 5, शक 1945

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2023

क्र. एफ 11-146-2019-सूअप्र-एक-(9)-312.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 02 से 03 अप्रैल 2023 तक, भोपाल से जम्मू एवं श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) जाने एवं आने हेतु कैलेंडर वर्ष 2023 की एल. टी.सी. एवं दिनांक 03 एवं 06 अप्रैल, 2023 को दो दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 5 अप्रैल 2023 को एक दिवस के ऐच्छिक अवकाश के साथ उक्त अवधि की एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य

“10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण” का (पांचवी बार) लाभ लिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनोज मालवीय, उपसचिव.

गृह विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2023

क्र.-एफ 1(ए)02-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, वि. शा. (सामान्य), पु. मु., भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम पार्टवर्ष दिनांक

3 से 12 मई 2023 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- |                      |   |       |
|----------------------|---|-------|
| 1. श्री आबिद खान,    | — | स्वयं |
| 2. जायरा फातिमा खान, | — | पत्नी |
| 3. असद मोहम्मद खान,  | — | पुत्र |
| 4. अहद मोहम्मद खान,  | — | पुत्र |

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री आबिद खान, भापुसे का चालू कार्य श्री नगेन्द्र सिंह, भापुसे, समन्, विशा. (कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आबिद खान, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा (सामान्य) पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आबिद खान, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आबिद खान, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आबिद खान, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 मई 2023

क्र.-एफ 1(ए)17-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अंकित जायसवाल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला निवाड़ी को दिनांक 16 से 30 मार्च 2023 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंकित जायसवाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला-निवाड़ी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अंकित जायसवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित जायसवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2023

क्र.-एफ 1(ए)31-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री कुमार सौरभ, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि. पु. मु., भोपाल को दिनांक 15 मई से 16 जून 2023 तक, तैंतीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13-14 मई व दिनांक 17-18 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री शियाज ए., भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (अनुसंधान), अ. अ. वि. पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि. पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कुमार सौरभ, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.-एफ 1(ए)59-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस सुधार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 अप्रैल से 6 मई 2023 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-16 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस सुधार), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.-एफ 1(ए)157-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री संजीव शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (चयन/भर्ती) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 12 मई 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 05-07 व 13-14 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री संजीव शर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री विजय कटारिया, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (कल्याण/लेखा), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (चयन /भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजीव शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.-एफ 1(ए)191-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (शिकायत / मा. अ.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 3 से 14 जुलाई 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 01-02 व 15-16 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (शिकायत / मा. अ.), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2023

क्र.-एफ 1(ए)76-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर को दिनांक 10 से 19 अप्रैल 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अमित सांघी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.-एफ 1(ए)176-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रीवा जोन, रीवा को दिनांक 1 से 15 मई 2023 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, रीवा जोन, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2023

क्र.-एफ 1(ए)03-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री गौरव कुमार तिवारी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एटीएस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 22 से 31 मई 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त

अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कुल्लू मनाली (हिमाचल प्रदेश) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री गौरव कुमार तिवारी, — स्वयं
2. श्रीमती आभा तिवारी, — पत्नी
3. कु. अरुण तिवारी, — पुत्री
4. कु. शिवन्या तिवारी — पुत्री
5. श्री अरुण कुमार तिवारी — पिता
6. श्रीमती सरिता तिवारी — माता

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री गौरव कुमार तिवारी, भापुसे, का चालू कार्य श्री प्रणय एस. नागवंशी, रापुसे, पुलिस अधीक्षक, एटीएस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार तिवारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, एटीएस, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री गौरव कुमार तिवारी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री गौरव कुमार तिवारी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौरव कुमार तिवारी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ 1(ए)31-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेन्ज, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 24 मई 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13-14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत लेह (लद्दाख) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्रीमती मोनिका शुक्ला, — स्वयं
2. श्री शशिकांत शुक्ला, — पति
3. देवांशी शुक्ला, — पुत्री

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, का चालू कार्य श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेन्ज, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र.-एफ 1(ए)20-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक / निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 15 मई से 2 जून 2023 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 मई व 03-04 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती हर्षा सिंह, संयुक्त निदेशक, आर. एफ. एस. एल. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक / निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.-एफ 1(ए)172-1997-ब-2-दो.—राज्य शासन, मो. शाहिद अबसार, भापुसे, अति. महानिदेशक, ई. ओ. डब्ल्यू., भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 8 से 12 मई 2023 तक, कुल पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 05-07 व 13-14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण यात्रा गोवाहाटी जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-



1. मो. शाहिद अबसार, — स्वयं
2. श्रीमती शबाना अबसार, — पत्नी
3. कु. नोया अबसार, — पुत्री

भोपाल, दिनांक 16 मई 2023

(2) अवकाश से लौटने पर मो. शाहिद अबसार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. महानिदेशक, ई. ओ. डब्ल्यू., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में मो. शाहिद अबसार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि मो. शाहिद अबसार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

क्र. एफ 1(ए)72-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2023 द्वारा श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल, इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) दिनांक 10 से 25 मार्च 2023 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह नगर जालौन (उ. प्र.) यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी।

(2) श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे को उक्त स्वीकृत अवकाश के साथ दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. एफ-1-53-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, उपेन्द्र जैन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, पुलिस आवास एवं अद्यो. विकास निगम, भोपाल को दिनांक 23 से 26 मई 2023 तक, कुल चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 20-22 व 27-28 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में लंदन की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई (Assignment) नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर उपेन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, पुलिस आवास एवं अद्यो. विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में उपेन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि उपेन्द्र जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनू भलावी, अवर सचिव.

## वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 मई 2023

क्र. 1068-3220-2019-ई-चार.—राज्य शासन, द्वारा नवगठित जिला निवाड़ी में निम्न सेटअप अनुसार 09 नवीन पदों का निर्माण करते हुए, जिला पेंशन कार्यालय की स्थापना किये जाने की स्वीकृति के साथ ही परिशिष्ट-एक अनुसार नवीन जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने हेतु वार्षिक आवर्ती व्यय/अनावर्ती व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

स. क्र.	पदनाम	पदसंख्या
(1)	(2)	(3)
01	जिला पेंशन अधिकारी (म. प्र. वित्त सेवा)	01
02	सहायक पेंशन अधिकारी (म. प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा)	03
03	सहायक ग्रेड-2 (म. प्र. कोषालयीन सेवा)	01
04	सहायक ग्रेड-3	02
05	भृत्य (संविदा)	01
06	सुरक्षाकर्मी (आउटसोर्स से कलेक्टर दर पर)	01
	कुल पद . .	09

(2) यह स्वीकृति दिनांक 14 मार्च 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद् बैठक के आयटम क्रमांक 3 एवं वित्त विभाग बजट 6 के यू. ओ. क्रमांक 241-आर-396-ब-6-चार, दिनांक 1 मई 2023 के अनुक्रम में जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, सचिव.

## परिशिष्ट-1

1. नवीन जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने हेतु वार्षिक आवर्ती व्यय

## (अ) वार्षिक आवर्ती व्यय (वेतन भत्ते)

स. क्र.	पदनाम	पद संख्या	अनुमानित राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जिला पेंशन अधिकारी	01	10,82,184/-
2	सहायक पेंशन अधिकारी	03	17,46,288/-
3	सहायक ग्रेड-2	01	4,06,824/-
4	सहायक ग्रेड-3 (संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर)	01	2,10,600/-
5	भृत्य (संविदा)	01	1,67,400/-
6	सुरक्षाकर्मी (आउटसोर्स से कलेक्टर दर पर)	01	84,000/-
योग . .			36,97,296/-

## (ब) वार्षिक आवर्ती व्यय (अन्य कार्यालयीन व्यय)

स. क्र.	विवरण	अनुमानित राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1	स्टेशनरी	5,000/-
2	दूरभाष	15,000/-
3	डाक व्यय	5,000/-
4	भवन किराया (क्षेत्रफल के आधार पर एवं कलेक्टर रेट के आधार पर)	60,000/-
5	सफाई व्यवस्था	18,000/-
6	मशीन अनुरक्षण	15,000/-
7	बिजली एवं जल प्रभार	28,000/-
8	अन्य आकस्मिक व्यय	30,000/-
योग . .		1,76,000/-

आवर्ती व्यय तालिका 'अ' एवं 'ब' का कुल योग (राशि रु. में) 38,73,296/-

तालिका 'अ' एवं 'ब' अनुसार कुल वार्षिक आवर्ती व्यय राशि रु. 38,73,296/- आकलित है.

## (स) वार्षिक अनावर्ती व्यय

क्र.	सामग्री का विवरण	नाम	संख्या	अनुमानित राशि (रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	फर्नीचर	बड़ी टेबल	01	25,000/-
		छोटी टेबल	05	70,000/-
		एक्जिक्यूटिव कुर्सी	01	10,000/-
		साधारण कुर्सी	05	25,000/-
		अलमारी	04	56,000/-
		आगंतुकों के बैठने हेतु कुर्सियां/बैंच	04	40,000/-
2	कम्प्यूटर सामग्री	कम्प्यूटर	04	4,90,000/-
		प्रिंटर / फोटो कॉपी मशीन	01	85,000/-
योग . .				8,01,000/-

उपरोक्त अनावर्ती व्यय के रूप में राशि रुपये 8,01,000/- का वार्षिक वित्तीय भार आकलित है.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2023

क्र. यूडीएच-3-0098-2023-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अंतर्गत नरसिंहपुर विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-55-2004-बत्तीस, भोपाल, दिनांक 23 जून 2004 को निरस्त करते हुए नरसिंहपुर विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम की धारा	पदनाम	संस्था / पता	समिति में पद
17(क) (1) की उपधारा			
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, नरसिंहपुर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, नरसिंहपुर	सदस्य
(ग)	सदस्य	संसदीय क्षेत्र, होशंगाबाद	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, नरसिंहपुर	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, नरसिंहपुर	सदस्य
(छ)	(1) सरपंच	ग्राम पंचायत, खैरी	सदस्य
	(2) सरपंच	ग्राम पंचायत, देवरीकलां	सदस्य
	(3) सरपंच	ग्राम पंचायत, नकटुवा	सदस्य
	(4) सरपंच	ग्राम पंचायत, खमतारा	सदस्य
	(5) सरपंच	ग्राम पंचायत, रौसरा	सदस्य
	(6) सरपंच	ग्राम पंचायत, करहैयाखेड़ा	सदस्य
(ज)	(1) प्रतिनिधि	क्लेक्टर, जिला नरसिंहपुर	सदस्य
	(2) प्रतिनिधि	वन संरक्षक, जिला नरसिंहपुर	सदस्य
	(3) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जिला नरसिंहपुर	सदस्य
	(4) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला नरसिंहपुर	सदस्य
	(5) प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	(6) प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	(7) प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर (म. प्र.) संयोजक	

क्र. यूडीएच-3-0099-2023-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अंतर्गत बड़वानी विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक-825-844-जियोस-जिसप्र-2002, बड़वानी, दिनांक 10 जून 2002 को निरस्त करते हुए बड़वानी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम की धारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था का नाम / पता	समिति में पद
17(क) (1) की उपधारा			
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, बड़वानी	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, बड़वानी	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(ग)	संसद सदस्य	संसदीय क्षेत्र, बड़वानी	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, बड़वानी	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण/साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, बड़वानी	सदस्य
(छ)	(1) सरपंच	ग्राम पंचायत, भीलखेडा (ग्राम कुकरा)	सदस्य
	(2) सरपंच	ग्राम पंचायत, कल्याणपुरा (ग्राम कल्याणपुरा)	सदस्य
	(3) सरपंच	ग्राम पंचायत, बड़गांव (ग्राम बड़गांव)	सदस्य
	(4) सरपंच	ग्राम पंचायत, आमल्या पानी (ग्राम आमल्या पानी)	सदस्य
	(5) सरपंच	ग्राम पंचायत, बड़वानी खुर्द (ग्राम बड़वानी खुर्द)	सदस्य
(ज)	(1) प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला बड़वानी	सदस्य
	(2) प्रतिनिधि	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् बड़वानी.	सदस्य
	(3) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बड़वानी	सदस्य
	(4) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बड़वानी	सदस्य
	(5) प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	(6) प्रतिनिधि	काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया	सदस्य
	(7) प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश इंदौर (म. प्र.)	सदस्य, सचिव

क्र. यूडीएच-3-0104-अठारह-5-2023.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अंतर्गत पन्ना विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ-3-107-बत्तीस, 97 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1997 को निरस्त करते हुए पन्ना विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा	पदनाम	संस्था / पता	समिति में पद
17(क) (1) की उपधारा			
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिक परिषद्, पन्ना	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, पन्ना	सदस्य
(ग)	सांसद	लोक सभा क्षेत्र, खजुराहो	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, पन्ना	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण/साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, पन्ना	सदस्य
(छ)	(1) सरपंच	ग्राम पंचायत, कृष्ण कल्याणपुर	सदस्य
	(2) सरपंच	ग्राम पंचायत, लक्ष्मीपुर	सदस्य
	(3) सरपंच	ग्राम पंचायत, मनौर	सदस्य
	(4) सरपंच	ग्राम पंचायत, बगौहा	सदस्य
	(5) सरपंच	ग्राम पंचायत, तिलगुवां	सदस्य
	(6) सरपंच	ग्राम पंचायत, सुनहरा	सदस्य
	(7) सरपंच	ग्राम पंचायत, जमुनहाई खुर्द	सदस्य
	(8) सरपंच	ग्राम पंचायत, जनवार	सदस्य
	(9) सरपंच	ग्राम पंचायत, दहलान चौकी	सदस्य
	(10) सरपंच	ग्राम पंचायत, सकरिया	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(ज)	(11) सरपंच	ग्राम पंचायत, मनकी	सदस्य
	(12) सरपंच	ग्राम पंचायत, जरघोवा	सदस्य
	(1) प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला पन्ना	सदस्य
	(2) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना	सदस्य
	(3) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, पन्ना	सदस्य
	(4) प्रतिनिधि	वन मण्डल अधि. उत्तर वन खण्ड पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना.	सदस्य
	(5) प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	(6) प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया	सदस्य
	(7) प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
	(8) प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समिति के संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सागर	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

### संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2023

क्र. 788-1192290-2023-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विभिन्न आदेशों के तहत निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :—

क्र.	राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल हेक्टेयर	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	म. प्र.	बुरहानपुर	नेपानगर	मोती महल	मोतीमहल	28	0.20	आबादी	नहीं
2.	म. प्र.	मंदसौर	नीमच	जीरन	शिवमंदिर (मंदरी)	312	05.501 (30×30 मी.)	शासकीय	-
3.	म. प्र.	मंदसौर	नीमच	जीरन	मंदिर पंचदेवल महादेव के दाहिनी ओर.	312	05.501 (30×30 मी.)	शासकीय	-

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त स्मारकों को मूल स्वरूप में बनाये रखने की शर्त पर ग्राम पंचायत को सौंपा जावे.

क्र. एफ 11-06-2022-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-06-2022-तीस, दिनांक 18 जुलाई 2022 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गई थी, जिसका प्रकाशन राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करता है:—

क्र.	राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व खंड क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल हेक्टेयर	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	म. प्र.	दतिया	इन्दरगढ़	ग्राम पंचायत ऊचाड़	बारादरी	मध्यप्रदेश शासन तहसील इन्दरगढ़	0.04	मध्यप्रदेश शासन	यदाकदा वार्षिक भण्डारा होता है.

क्र. 786-1192307-2023-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विभिन्न आदेशों के तहत निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :—

क्र.	राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व खंड क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल हेक्टेयर	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	म. प्र.	टीकमगढ़	निवाड़ी	ओरछा	हरसिद्धि देवी मंदिर (ओरछा किले के बाहर स्थित स्मारक)	732 जू.	0.037	मध्यप्रदेश शासन	नहीं
2.	म. प्र.	टीकमगढ़	निवाड़ी	ओरछा	हरिराम व्यास की हवेली	455/15	10.131	मध्यप्रदेश शासन	नहीं
3.	म. प्र.	टीकमगढ़	निवाड़ी	ओरछा	गुसाई का मठ	468/2	1.339	मध्यप्रदेश शासन	नहीं

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त स्मारकों को मूल स्वरूप में बनाये रखने की शर्त पर ग्राम पंचायत को सौंपा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना पाण्डेय, अवर सचिव.

कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल  
बी "विंग" भूतल, विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2023

ग्रीष्मकालीन अवकाश बाबत

क्र. सह. अधि.-स्था.-2023-470.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 15 मई से 09 जून 2023 तक, में से 15 दिनों का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तदनुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष, दिनांक 22 से 26 मई 2023 तक (पाँच दिन) एवं दिनांक 1 से 9 जून 2023 तक (नौ दिन) तक, इस प्रकार कुल चौदह दिन तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

मान. अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,  
दीपायन मुखर्जी, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 मई 2023

क्र.-3027-वि.लि.-1 (ए)-2023.—मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34(क) के अनुसार, छिन्दवाड़ा जिले में निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को, इस अधिनियम के अंतर्गत, पंजीयक, लोक न्यास की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं :—

स. क्र.	राजस्व अनुभाग का नाम	राजस्व अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	अनुभाग छिन्दवाड़ा	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छिन्दवाड़ा
2	अनुभाग चौरई	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चौरई
3	अनुभाग अमरवाड़ा	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अमरवाड़ा
4	अनुभाग परासिया	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), परासिया
5	अनुभाग जुन्नारदेव	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जुन्नारदेव
6	अनुभाग पांडुर्णा	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पांडुर्णा
7	अनुभाग सौंसर	पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर

शीतला पटले, कलेक्टर.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 मई 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-482-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	फुरताल खुर्द	3.663	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-483-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	अमकुई	4.293	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-484-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	उमरहट	2.137	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-485-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	खम्हरिया कला	6.708	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहरिया वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-486-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	कोलाड़	2.991	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-487-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	रेरूआ कला	4.814	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-488-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	रेरूआखुर्द	4.953	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-489-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	खैरी	2.454	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-490-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	पतौड़ा	5.594	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-491-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाधेलान	मौहारी कटरा	13.542	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-492-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	उमरी उर्फ शिवराजी	2.966	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-493-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	ओढ़की	2.222	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 11 मई 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-513-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	डाम्हा	4.116	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-514-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची					
भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	छींदा	0.317	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहरिया वितरिका निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23 24-पत्र क्र.-515-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बैरह अकठा टोला	2.484	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय, मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-516-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	पड़हा	6.228	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-517-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	लालपुर	7.821	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-518-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	जुड़मनिया	7.406	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.



भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-519-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	सरवका	7.975	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-520-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	ककरा	20.176	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-521-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	सुआ	9.986	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-525-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	मौहरिया	3.242	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-529-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	अहिरगांव	7.414	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-530-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बैरागल	5.441	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-532-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	कुल्लुहा	5.977	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय, मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-541-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	पाल	9.383	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय, मैहर जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-542-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बाघेलान	बछरा	5.449	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.).	बर्गी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33+000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 10 मई 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-476-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	पिपरी	3.950	उप मुख्य अभियंता निर्माण (II) पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना, जिला सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-481-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विलिंगम सृजित नहीं करेगा:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	नागौद	भाद	0.875	उप मुख्य अभियंता निर्माण (II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना, जिला सतना (म. प्र.).	ललितपुर-सतना, रेवा-सिंगौली, महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 3 मई, 2023

क्र. भू-अर्जन-01 (अ-82) 2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्रो, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी, द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा, इस आशय की, सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

### अनुसूची-II

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	केवलारी मय	120	0.86	कार्यपालन यंत्रो
	(समनापुर वृत्त)	बम्हनी	121	1.98	जल संसाधन
		प. ह. नं.	119	1.11	संभाग डिण्डौरी.
		132	107	0.26	
		रा. नि. म.	27	1.25	
		बम्हनी.	25/1	0.55	
			105	2.00	
			106	1.64	
निजी भूमि का योग . .				10.77	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-02 (अ-82) 2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी, द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण ' किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा, इस आशय की, सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

#### अनुसूची-II

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	एजेंसी का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	डुगरिया रैयत	158	0.80	कार्यपालन यंत्री	खरमेर मध्यम सिंचाई
	(समनापुर वृत्त)	प. ह. नं. 129	400/2	0.35	जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
		रा. नि. म. बम्हनी.	400/4	0.35		

निजी भूमि का योग . . 1.50

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-03 (अ-82) 2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी, द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण ' किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा, इस आशय की, सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

#### अनुसूची-II

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)	एजेंसी का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	अण्डइरैयत	93/2	0.40	कार्यपालन यंत्री	खरमेर मध्यम सिंचाई
	(समनापुर वृत्त).	प. ह. नं. 131	95/1	0.40	जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
		रा. नि. म. बम्हनी.	95/2	0.40		
			92/2	0.28		
			159/2	0.27		

निजी भूमि का योग . . 1.75

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 8 मई 2023

नस्ती क्र. 18-एल. ए.-2023-भू-अर्जन-प्र. क्र.0002-अ-82-2023-24.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	लोहारी	0.120	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 18-2023-एल. ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.0002-अ-82-2023-24.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-Knw/Land, दिनांक 30 जनवरी 2023, प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम लोहारी पटवारी हल्का नं. 103 तह. खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.120 हेक्टर. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :—

स. क्र.	जिला	तहसील	प. ह. नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	103	लोहारी	0.120	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान-परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्र. 1435-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र एफ-22-03-2019-20-ल. सि.-31-1605, भोपाल, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	ग्राम-लकडाई जम्होडी प.ह.नं.-26 ब.न.-515 रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा.	रकबा-19.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा.	लकडाई जम्होडी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट [www.chhindwara.nic.in](http://www.chhindwara.nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हर्गांव परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 मई 2023

रा. प्र. क्र. 15-अ-82-2022-2023.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-परसोली प.ह.नं.-14, ब. नं.-158 रा.नि.मं.- पांजरा.	1. रामभवन पिता तेजलाल जाति मरार निवासी ग्राम भूमिस्वामी	290	0.030	पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये (पूरक प्रकरण).
कुल योग					0.030	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्र. 16-अ-82-2022-2023.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है (7)
जिला	तहसील	नगर/ग्राम				
(1) छिन्दवाड़ा	(2) चौरई	(3) ग्राम-मोरखा प.ह.नं.-24, ब. नं.-237, रा.नि.मं.- चौरई.	(4) 1. रघुवीर पिता कालूराम जाति लोधी निवासी ग्राम भूमिस्वामी	(5) 524/7/1/5	(6) 0.040	पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये (पूरक प्रकरण).
कुल योग					0.040	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 18-अ-82-2022-2023.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है (7)
जिला	तहसील	नगर/ग्राम				
(1) छिन्दवाड़ा	(2) चांद	(3) ग्राम-गोहरगांव प.ह.नं.-31, ब. नं.-68, रा.नि.मं.- चांद.	(4) 1. काशीराम पिता महताब, रम्मा पिता महताब, रेखन पिता महताब, कोशल्या पिता महताब, कौसमा पिता महताब, सुखदानिया पिता महताब जाति लोधी निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	(5) 130/2/1	(6) 0.092	पेंच व्यपवर्तन बांध जल- संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये (पूरक प्रकरण).
कुल योग					0.092	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

रा. प्र. क्र. 19-अ-82-2022-2023.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप “क” में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप “ख” में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय को जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चांद	ग्राम-निशानजानोजी प.ह.नं.-29, ब. नं.-150, रा.नि.मं.- चांद.	1. रामदास पिता नब्बू, जाति किरार निवासी ग्राम भूमि स्वामी 2. रामसिंग पिता नब्बू जाति किरार निवासी ग्राम भूमि स्वामी.	18/2 (s) 23/2 18/1 (s) 23/1	0.071 0.003	पेंच व्यपवर्तन बांध जल-संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये (पूरक प्रकरण).
कुल योग					0.074	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 18 मई 2023

[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

प्र. क्र. 22-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ की ग्राम कराडिया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

## अनुसूची

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि.—ग्राम कराडिया

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जनीय रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मानसिंह, कमल, रामकिशन पिता शंकरलाल, प्रेमबाई कलाबाई पिता शंकरलाल, जाति लोडा.	5/7	0.759	0.759
योग . .			0.759	0.759
कुल योग .				0.759

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 12 अप्रैल 2023

[अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

क्र. 596-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इन्दौर
- (ख) तहसील—जूनी इन्दौर
- (ग) ग्राम—कैलोदहाला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.109 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
281/2/1	0.109
योग . .	0.109

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“इन्दौर-देवास-उज्जैन रेल्वे दोहरीकरण प्रयोजन हेतु”.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग, जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर तथा उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इलैयाराजा टी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 9 मई 2023

क्र. 452-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—उचेहरा  
(ग) नगर/ग्राम—कोल्हुआ  
(घ) क्षेत्रफल—0.4659 हेक्टेयर.

आराजी क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
162/4	0.0140
162/5	0.0030
175/1/1/2	0.0030
176	0.0016
177/1	0.0160
177/2	0.0196
178	0.0100
179	0.1680
193	0.0100
194	0.1280
195/1	0.0180
196	0.0240
310/2	0.0230
311/1	0.0277
योग . .	0.4659

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 453-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—उचेहरा  
(ग) नगर/ग्राम—सेमरी कुर्मिहाई  
(घ) क्षेत्रफल—0.2330 हेक्टेयर.

आराजी क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
94/1	0.0885
94/2	0.0885
94/3	0.0265
94/4	0.0265
95/1	0.0030
योग . .	0.2330

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 454-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—उचेहरा  
(ग) नगर/ग्राम—चकहट  
(घ) क्षेत्रफल—0.0730 हेक्टेयर.

आराजी क्र.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.0200
5/2	0.0530
योग . .	0.0730

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की चकहट माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 5039-भू-अर्जन-2021

धार, दिनांक 28 मार्च 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची पद क्रमांक (01) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

--:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन :-

(क) ग्राम	:-	टाण्डा
(ख) तहसील	:-	कुशी
(ग) जिला	:-	धार
(घ) लगभग क्षेत्रफल	:-	7.728 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
7	0.977	17	0.293	26/2	0.346
8/2	1.875	18	0.088	30/2	0.002
9/1	0.900	22	0.197	24/1	0.107
12	0.112	23	1.203	24/2	0.251
16	0.235	26/1	1.022	24/3	0.120
योग:-					7.728

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- "छोटा उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु।"

3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुशी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

क्र. 5011-भू अर्जन 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची पद क्रमांक (01) में बाणेत भूमि के अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

---:अनुसूची:-

1. भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- बराड़  
(ख) तहसील :- कुशी  
(ग) जिला :- धार  
(घ) अधिग्रहित रकबा :- 18.482 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
37	0.496	74	0.013	248/4	0.289	236/4	0.006	333/1/3	0.100
38	0.454	75	0.137	248/5	0.050	236/12	0.006	333/2/2	0.050
39	0.494	76	0.131	280	0.202	236/13	0.006	334	0.199
41	0.556	77	0.065	281	0.265	236/14	0.006	375	0.530
42/1	0.285	79/1/9	0.708	224	0.337	244/2/1	0.068	376/1/1	0.025
42/2	0.296	27/2	0.140	228/1	0.012	244/2/2	0.068	376/1/2	0.025
44	0.741	27/4	0.137	228/2	0.005	244/2/3	0.068	376/2/1	0.011
50/2	0.122	98/1	0.200	229	0.746	244/3/1	0.068	376/2/2	0.323
51	0.364	98/2	0.200	230	0.416	244/3/2	0.068	376/2/3	0.006
52	0.016	238/1	0.012	231/2	0.010	278/1	0.079	376/3	0.006
56	0.309	241/1	0.315	231/3	0.285	278/2	0.080	377	0.509
57	0.829	241/2	0.315	231/4	0.186	318	0.130	378	0.931
58	0.044	242/1	0.006	231/5	0.340	321	0.598	403	0.774
59	0.136	243/1	0.087	233	0.052	323	0.742	404	0.644
60	0.054	243/2/2	0.163	234	0.204	331	0.367		
70	0.118	247/1	0.049	236/2	0.009	333/1/1	0.100		
73	0.032	248/2	0.400	236/3	0.006	333/1/2	0.051		
योग:-									18.482

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- "छोटा उदयपुर-धार गई बड़ी रेलवे लाईन हेतु।"

3. भूमि के नशा (क्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुशी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, गडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।



क्र. 5043-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची पद क्रमांक (01) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।  
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

## —:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन :-

(क) ग्राम	:-	घोर
(ख) तहसील	:-	कुशी
(ग) जिला	:-	घार
(घ) लगभग क्षेत्रफल	:-	21.355 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
49/2	0.127	277	0.126	310/1	0.031	338	0.166	206/3	0.004
50	3.759	278	0.124	312/1	0.003	339	0.358	212	0.303
51	1.619	279/1	0.123	312/2	0.132	318/1/1	0.418	214/1	0.116
52/2	0.082	279/2	0.040	332/1/1	0.126	318/1/4	0.035	343/1/1	0.069
53/1	0.105	280/1	0.074	332/1/5	0.125	318/1/3	0.035	281/1/1	0.460
53/2	0.209	287	0.513	332/1/6	0.125	318/6	0.394	281/1/2	0.600
54/1	0.083	357	2.040	332/2	0.027	318/2	0.082	281/1/3	0.275
54/2	0.139	356/1	1.202	332/3	0.340	319	0.489	281/2/1	0.571
256/1	0.376	363/1	0.578	332/4/1	0.148	321	0.562	281/2/2	0.318
256/2	0.735	364/1	0.354	334	0.166	322	0.009	281/2/3	0.571
257/1	0.136	367/1	0.077	335	0.209	180/1	0.059	281/2/4	1.013
257/2	0.126	367/2	0.019	336	0.052	206/6	0.198		
योग:-									21.355

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- “छोटा उदयपुर-घार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु।”

3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुशी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

क्र.5045-भू-अर्जन -2023

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद क्रमांक (01) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।  
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

## —:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन :-

(क) ग्राम	:-	कोड़दा
(ख) तहसील	:-	कुशी
(ग) जिला	:-	घार
(घ) लगभग क्षेत्रफल	:-	12.763 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
45	0.249	58	0.800	42/1	0.078	71/2/1	0.168	22/1	0.110
48	0.096	59/1	0.703	42/2	0.243	73/2	0.300	26/3	0.772
44/1	1.321	41/1	0.206	30/1	0.366	73/3	0.052	30/2	0.077
44/2	0.830	41/2	0.551	27/1	0.310	72/1	0.900	30/3/2/1	0.098
44/3	1.140	41/3	0.701	23/10	0.200	20	0.071		
38	0.186	41/4	0.567	69/1	0.691	18/3/1	0.116		
39/2	0.428	60/1	0.020	71/1	0.408	10	0.005		
योग:-									12.763

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- “छोटा उदयपुर-घार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु।”

3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुशी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, बडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

क्र.5357-भू-अर्जन-2023

धार, दिनांक 6 अप्रैल 2023

छाक राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नाच दे गड़ अनुसूची पद क्रमांक (01) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।  
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

## ---:अनुसूची:-

## 1. भूमि का वर्णन :-

(क) ग्राम	:-	बाकी-टाण्डा
(ख) तहसील	:-	कुशी
(ग) जिला	:-	धार
(घ) लगभग क्षेत्रफल	:-	12.556 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
57/1/1	0.040	60/2/1	0.132	12/2	0.182	19	0.297	27	0.365
57/1/2	0.001	60/2/2	0.028	13/3/2	1.135	20/1	2.211	30/1/1	0.016
58/1	0.255	61	0.272	13/4/2	0.541	20/2	0.411	32/1	0.064
59/1/1	0.108	62/1	0.428	14/1	0.628	22	0.215	34/2/1	0.112
59/1/2	0.271	62/2	0.602	14/2	0.145	23/1	0.032	55	0.204
59/1/3	0.300	5/2	1.379	30/2	0.261	23/8	0.019		
59/2/2	0.550	8/2	0.014	31/1	0.084	23/9	0.013		
60/1	0.265	8/2	0.188	17/2	0.784	23/10	0.004		
योग:-									12.556

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- "छोट्ट उदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु।"

3. भूमि के नसा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुशी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, बडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19  
की उपधारा-4 एवं 07

पत्र क्र.-402

सीधी, दिनांक 03 मई 2023

- चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 27.07.2021 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा-19 प्रकाशन के पश्चात अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका है, क्योंकि उपखण्ड अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी सिहावल द्वारा प्रस्तुत एवार्डों का परीक्षण करने पर त्रुटियाँ पाई गई। अतः त्रुटियों की जाँच/निराकरण कराकर त्रुटिरहित एवार्ड पारित किये जाने हेतु 01 वर्ष की समयावधि दी जायेगी। अतः त्रुटियों की जाँच/निराकरण कराकर त्रुटिरहित एवार्ड पारित किये जाने हेतु 01 वर्ष की समयावधि दी जायेगी। 100प्र0 शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायेगा। उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 की उपधारा (4) समयावधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले की तहसील बहरी में महान परियोजना (गुलाब सागर) अंतर्गत बहरी नहर विस्तार योजना के तहत नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली वर्णित भूमियों की समयावधि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है :-

#### 1. भूमि का वर्णन :-

क्र.	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	निजी भूमि का प्रभावित रकबा (हे० में)	धारा-19 के जारी होने का दिनांक	धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा-19 की समयावधि में की गई वृद्धि
1.	2	3	4	5	6	7
1.	मयापुर	बहरी	0.590	27.07.2021	26.07.2022	धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है।
2.	अमरपुर	बहरी	2.187	27.07.2021	26.07.2022	
3.	परसवार	बहरी	2.406	27.07.2021	26.07.2022	
4.	शिवपुर (मरसरहा)	बहरी	3.248	27.07.2021	26.07.2022	
5.	शैरपुर	बहरी	1.369	27.07.2021	26.07.2022	
6.	पुजौही	बहरी	0.868	27.07.2021	26.07.2022	
7.	सरदा	बहरी	4.233	27.07.2021	26.07.2022	
8.	पटेहरा कोठार	बहरी	0.312	27.07.2021	26.07.2022	
9.	रोजहा	बहरी	0.952	27.07.2021	26.07.2022	
10.	पथरौही	बहरी	0.617	27.07.2021	26.07.2022	
11.	पुजौही	बहरी	0.093	27.07.2021	26.07.2022	
12.	गोड़ाही	बहरी	1.820	27.07.2021	26.07.2022	

13.	लौआ	बहरी	1.359	27.07.2021	26.07.2022	
14.	अमडिहा	बहरी	1.166	27.07.2021	26.07.2022	
15.	उमरिया	बहरी	0.657	27.07.2021	26.07.2022	
16.	मयापुर	बहरी	0.259	27.07.2021	26.07.2022	
17.	डढ़िया	बहरी	1.638	27.07.2021	26.07.2022	
18.	डढ़िया	बहरी	1.203	27.07.2021	26.07.2022	
19.	बदौला	बहरी	0.735	27.07.2021	26.07.2022	
20.	बदौला	बहरी	0.928	27.07.2021	26.07.2022	
21.	परवा	बहरी	0.362	27.07.2021	26.07.2022	
22.	झरी	बहरी	2.586	27.07.2021	26.07.2022	
23.	लौआ	बहरी	2.041	27.07.2021	26.07.2022	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- महान परियोजना (गुलाब सागर) अंतर्गत बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के तहत शाखा/उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।
- भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी बहरी/सिहावल से देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-03-अ-82-2021-22

छतरपुर, दिनांक 10 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

**—: अनुसूची :-**

1. भूमि का वर्णन		ख. तहसील - छतरपुर	
क. जिला - छतरपुर		घ. लगभग क्षेत्रफल -	0.955 हे०
ग. ग्राम - दिदौल			
क्र	भूमि स्वामी का नाम	भूमि खसरा क्र.	अर्जित रकवा (हे.)
1	2	3	4
1	श्रीमती श्यामबाई बेवा मंजुवा, रामकुईया पुत्री मंजुवा, बिट्टो पुत्री मंजुवा, सन्तु पुत्री मंजुवा, लच्छन पुत्री मंजुवा सुमित्रा पुत्री मंजुवा, राजाबाई पुत्री मंजुवा रूकमन बेवा बलिया, गनेश पुत्र बलिया, मलोरी पुत्र बलिया, तिजिया पुत्री बलिया, जानकी पुत्री बलिया, रामप्यारी बेवा रामलाल, जगदीश पुत्र रामलाल, किशोरी पुत्री रामलाल, प्रेमबाई पुत्री रामलाल	851/1	0.100
2	श्रीमती हीराबाई बेवा टरिया, काशीराम पुत्र टरिया, पार्वती पुत्री टरिया, गोलू पुत्र हल्के, उमा पुत्री हल्के, भारती पुत्री हल्के, शंकू पुत्र अयोध्या, पुन्ना पुत्र अयोध्या, विनोद पुत्र अयोध्या, चुनु बेवा भगवानदास, श्यामलाल पुत्र भगवानदास, मूलचन्द्र पुत्र भगवानदास, ओमप्रकाश पुत्र भगवानदास, रानी पुत्री भगवानदास	851/2	0.100
3	श्री धरमू पुत्र दलुवा, बालू पुत्र हरिश्चन्द्र, कमलेश पुत्र हरिश्चन्द्र, महेश पुत्र हरिश्चन्द्र हस्सू पुत्र हरिश्चन्द्र, गुडडी पुत्री हरिश्चन्द्र, हरिनारायण पुत्र रामलाल, अमना पुत्र मिखुवा, गोवर्धन पुत्र प्यारेलाल, आशाराम पुत्र अमना, जीतेन्द्र पुत्र अमना, राकेश पुत्र प्यारेलाल, कमली बेवा रामलाल, पार्वती पुत्री गोरेलाल, मुलिया बेवा प्यारेलाल, रामचरन पुत्र प्यारेलाल, बीरन पुत्र प्यारेलाल, काशीराम पुत्र अमना कुशवाहा	854	0.225
		855	0.290
4	श्रीमती सहोदरा पत्नि आशाराम जाति आर्य	856	0.120
5	श्री शिवदयाल तनय मुलुवा, सल्ला तनय परसादी, बाबूलाल मोतीलाल पिता रामभरोसे 1/2, मुलुवा सल्ला पिता परसादी जाति काछी 1/2 भाग	853	0.120
योग:-		05 किता	0.955

(2) धसान नदी के पचेर घाट पर उच्चस्तरीय पुल एवं पङ्कजमार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग**

प्र.क्र.-0001-2022-23-अ-82-भू-अर्जन-4022

श्योपुर, दिनांक 10 मई 2023

**// सूचना-पत्र //**

कार्यपालन यंत्री, हरसी जल संसाधन संभाग डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

बनाम

बादामी पुत्र जीवनलाल जाति कुम्हार अन्य 03 निवासी ग्राम सेहुला तहसील विजयपुर  
जिला श्योपुर

द्वारा- तहसीलदार तहसील विजयपुर।

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है।) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम सेहुला तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित अपर कंकटो बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आशय है।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्यांक 30) की धारा 21 (2) के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान का अधिनियम प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति होतो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांक.....तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/ अधिवक्ता के माध्यम से उप संज्ञात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक.....पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

क्र.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा है, में		
			सिंचित रकवा	असिंचित रकवा	कृषि भूमि
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व वृत्त-गसवानी/ पटवारी हल्का 48 सेहुला/तहसील विजयपुर/जिला श्योपुर				
1	बादामी पुत्र जीवनलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम सेहुला भूमिस्वामी	251/4	0.150	निरंक	कृषि भूमि
2	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायण पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम सेहुला भूमिस्वामी	71/2	0.200	निरंक	कृषिभूमि
3	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायण पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम सेहुला भूमिस्वामी	72/2	0.210	निरंक	कृषिभूमि
4	जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग सम्पूर्ण निवासी ग्राम सेहुला भूमिस्वामी	70/2	0.300	निरंक	कृषिभूमि
	योग		0.860		

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी। अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण/हितबद्ध व्यक्ति को प्रथम से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/5/23 को जारी किया गया।

प्र.क्र.-0002-2022-23-अ-82-भू-अर्जन-4024

कार्यपालन यंत्री, हरसी जल संसाधन संभाग डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

बनाम

कमरलाल पुत्र सुखलाल जाति किरार अन्य 01 निवासी ग्राम फरारा तहसील विजयपुर  
जिला श्योपुर म.प्र.

द्वारा- तहसीलदार तहसील विजयपुर।

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है।) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम फरारा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित अपर ककटो बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आय है।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्यांक 30) की धारा 21 (2) के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान का अधिनियम प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति होतो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांक.....तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/ अधिवक्ता के माध्यम से उप संज्ञात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा नक्शा कार्यालय तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक.....पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

क्र.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा है, में		
			सिंचित रकवा	असिंचित रकवा	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6
	राजस्व वृत्त-गसवानी/ पटवारी हल्का 45 फरारा/तहसील विजयपुर/जिला श्योपुर				
1	कमरलाल पुत्र सुखलाल जाति किरार निवासी ग्राम फरारा भूमिस्वामी	412/2	0.150	निरंक	कृषि भूमि
2	रामचरण पुत्र मोती जाति किरार निवासी ग्राम सहसराम भूमिस्वामी	417	0.030	निरंक	कृषि भूमि
	योग		0.180		

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी। अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण/हितबद्ध व्यक्ति को प्रथम से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/05/23 को जारी किया गया।



प्र.क्र.-0004-2022-23-अ-82-भू-अर्जन-4026

कार्यपालन यंत्री, हरसी जल संसाधन संभाग डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

बनाम

नेतू रामहेत पुत्रगण भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार रामश्री, वत्तो नावा. पुत्रियां भगीता सर.  
सावित्री मां खुद जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार सावित्री देवा भगीता जाति चमार अन्य 05  
निवासी ग्राम नेहरखेड़ा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर

द्वारा- तहसीलदार तहसील विजयपुर।

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है।) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम नेहरखेड़ा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित अपर ककेटो बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आय है।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्यांक 30) की धारा 21 (2) के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका में भू अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान का अधिनियम प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति होतो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांक.....तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/अधिवक्ता के माध्यम से उप सज्ञात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक..... पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

क्र.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा है, में		
			सिंचित रकवा	असिंचित रकवा	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6
	राजस्व वृत्त-गसमानी/ पटवारी हल्का 48 नेहरखेड़ा/तहसील विजयपुर/जिला श्योपुर				
1	नेतू रामहेत पुत्रगण भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार रामश्री, वत्तो नावा. पुत्रियां भगीता सर. सावित्री मां खुद जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार सावित्री देवा भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार	1197	0.170	निरंक	कृषि भूमि
2	खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	1207	0.130	निरंक	कृषि भूमि
3	खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	1208	0.100	निरंक	कृषि भूमि
4	रघुवीर पुत्र कमरलाल भगवती पुत्री कमरलाल शान्ति बेवा कमरलाल समान भाग 1/2 करई पुत्री नारायण भाग 1/2 जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	1200	0.300	निरंक	कृषि भूमि
5	ग्यासिया पुत्र केशरिया जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार	1204	0.100	निरंक	कृषि भूमि
6	वंदन महेश पुत्रगण नक्तू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमिस्वामी कमला पुत्री नक्तू जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	1039	0.610	निरंक	कृषि भूमि
	योग		1.410		

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी। अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण/हितबद्ध व्यक्ति को प्रथम से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 40/05/23 को जारी किया गया।

प्र.क्र. -0003-2022-23-अ-82-भू-अर्जन-4030

कार्यपालन यंत्री, हरसी जल संसाधन संभाग डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

बनाम

जगनू पुत्र फुन्दी जाति सैर अन्य 50 निवासी ग्राम बिनेगा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर

द्वारा- तहसीलदार तहसील विजयपुर।

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है।) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम बिनेगा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित अपर ककटो बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आय है।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्यांक 30) की धारा 21 (2) के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान का अधिनियम प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति होतो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांक.....तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/अधिवक्ता के माध्यम से उप संज्ञात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक.....

पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

क्र.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा हे. में		
			सिंचित रकवा	असिंचित रकवा	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व वृत्त-गसवानी/पटवारी हल्का 48 बिनेगा/तहसील विजयपुर/जिला श्योपुर				
1	जगनू पुत्र फुन्दी जाति सैर पता नि. बिनेगा भूदान भूमिस्वामी	326	0.470	निरंक	कृषिभूमि
2	रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा भू-दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू-दान कृषक	327/1	0.052	निरंक	कृषिभूमि
3	कुन्दन पुत्र सुखू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी कोसा, वैजन्ती पुत्रियां सुखू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी	327/2	0.501	निरंक	कृषिभूमि
4	गोपालपुत्र कमलसिंह जातिरावत पता दाउदपुर भू-दान कृषक	330/2	1.095	निरंक	कृषिभूमि
5	रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा भू दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू-दान कृषक	328	0.398	निरंक	कृषिभूमि
6	मिनी पुत्री रमले जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी	329/1	0.731	निरंक	कृषिभूमि

7	लखनपुत्र छोटे जाति चमार पता बिनेगा 1/2 भाग भूदान भूमिस्वामी मु. साबो बेवा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी कमला, गुडडीनावा. पुत्रीया ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा 1/2 समान भाग भूदान भूमिस्वामी	334	1.108	निरंक	कृषिभूमि
8	हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी	307	0.042	निरंक	कृषिभूमि
9	हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी	306	0.386	निरंक	कृषिभूमि
10	तुलसीराम पुत्र हरभजन जाति ओड पता बिनेगा भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से	300/4	0.585	निरंक	कृषिभूमि
11	छोटेपुत्र शिवलाल जाति चमार पता बिनेगा भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से	300/6	0.147	निरंक	कृषिभूमि
12	रामदयालपुत्र रतनूजातिचमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमिस्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमिस्वामी	291	0.700	निरंक	कृषिभूमि
13	गुलावचन्द पुत्र देवलाल जाति ब्राह्मण पता विजयपुर भूमिस्वामी	335	0.084	निरंक	कृषिभूमि
14	पाना बेवा छत्तू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूदान भूमिस्वामी	336	0.041	निरंक	कृषिभूमि
15	राजेशपुत्र बाबूलाल जाति शिवहरे पता बिनेगा भू-दान कृषक	298	0.481	निरंक	कृषिभूमि
16	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमिस्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमिस्वामी	296	0.449	निरंक	कृषिभूमि
17	चेऊरामपुत्र कुडैरी जाति गुर्जर पता बिनेगा भूमिस्वामी	292	0.094	निरंक	कृषिभूमि
18	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमिस्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमिस्वामी	295	0.167	निरंक	कृषिभूमि
19	रामदयालपुत्र रतनूजातिचमार पता बिनेगा 1/3 भागभूमिस्वामीचतुरो,पंखोपुत्रियां भीखा जातिचमार पता बिनेगा 2/3 भागभूमिस्वामी	294	0.157	निरंक	कृषिभूमि
20	कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी कौसा,वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जाति चमार पता सा. देह समान भाग भूमिस्वामी	274/1	0.094	निरंक	कृषिभूमि
21	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमिस्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमिस्वामी	274/2	0.157	निरंक	कृषिभूमि
22	उम्मेद सिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी	271/1	0.209	निरंक	कृषिभूमि
23	साजो बेवा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी बैजूपुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समानभाग भूमिस्वामी कमला, गुड्डी ना.बा. पुत्रीयां ल्होरिया सर. माँ खुद जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि	271/2	0.397	निरंक	कृषिभूमि
24	उम्मेद सिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा	270	0.156	निरंक	कृषिभूमि

	भूमिस्वामी				
25	उम्मेदसिंह, बट्टी सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी जानकी पुत्री चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी	255	0.094	निरंक	कृषिभूमि
26	उम्मेदसिंह, बट्टी सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी जानकी पुत्री चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी	254	0.063	निरंक	कृषिभूमि
27	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमिस्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमिस्वामी	268	0.084	निरंक	कृषिभूमि
28	रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमिस्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमिस्वामी	267	0.219	निरंक	कृषिभूमि
29	कुन्दन पुत्र सुखू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुखू जाति चमार पता सा. देह समान भाग भूमिस्वामी	265	0.575	निरंक	कृषिभूमि
30	पाचो बेवा केशरिया जाति चमार पता बिनेगा भूमिस्वामी तेजसिंह (वालिंग) पिस्सू दोजा नावालिग पुत्रगण केशरिया सरपरस्त पिता जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी तखो, हन्नी, भन्तो पुत्रियां केशरिया जाति चमार पता बिनेगा समानभाग भूमिस्वामी	266/1	0.157	निरंक	कृषिभूमि
31	उम्मेद सिंह पुत्र चन्दन सिंह-जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी	266/2	0.188	निरंक	कृषिभूमि
32	उम्मेदसिंह, बट्टी सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी जानकी पुत्री चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी	263	0.784	निरंक	कृषिभूमि
33	कुन्दनपुत्र सुखू जाति चमार पता बिनेगा भूमिस्वामी	275	0.333	निरंक	कृषिभूमि
34	रणवीर, निरंजन पुत्रगण देवीसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान 2/3 भाग भूमिस्वामी मंजेश बेवाहर चरण प्रदीप हरेन्द्र नाबा. पुत्रगण हरचरण करिश्मा नाबा. पुत्री हरचरण सर.मों खुद जाति गूजर पता निवासी ग्राम समान 1/3 भाग भूमिस्वामी	236/2	0.084	निरंक	कृषिभूमि
35	सरदार सिंहपुत्र मोहन सिंहजाति गूजर पता बिनेगा 1/2 भाग भूमिस्वामी महाराज सिंह, चिरोजी सुधरसिंह, लालाराम पुत्रगण नवलसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2-समान भाग भूमिस्वामी	232	0.439	निरंक	कृषिभूमि
36	सुल्तान अवतार पुत्रगण होतम सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी	200	0.302	निरंक	कृषिभूमि
37	सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिंह जातिगूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी	178	0.136	निरंक	कृषिभूमि
38	कुअरिराज पुत्र शंकर हि. 3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि. 2/5 जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी	173	0.400	निरंक	कृषिभूमि

39	कुअरिराज पुत्र शंकर हि. 3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि. 2/5 जातिगूजर पता विनेगा भूमिस्वामी	172	0.081	निरंक	कृषिभूमि
40	सुल्तान अवतार पुत्र होतमसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी	177	0.094	निरंक	कृषिभूमि
41	उम्मेद सिंह, बद्री सिंह पुत्रगण चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी जानकी पुत्री चन्दनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी	203	0.219	निरंक	कृषिभूमि
42	बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजी सिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदार सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदार सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 भूमिस्वामी	204	0.324	निरंक	कृषिभूमि
43	बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहन सिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजी सिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदार सिंह जातिगूजर पता बिनेगा भाग 1/18 भूमिस्वामी	208	0.125	निरंक	कृषिभूमि
44	विशम्भर दयाल पुत्र ननकूराम जाति धाकड पता निवासी नेहरखेडा भूमिस्वामी	209	0.449	निरंक	कृषिभूमि
45	उम्मेदसिंह पुत्र चन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी	184	0.020	निरंक	कृषिभूमि
46	बल्लभ पुत्र चक्रपान जाति धाकड पता नि. सेहुला भाग 2033/4065 भूमिस्वामी जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 1355/4065 भूमि स्वामी कल्लू पुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 677/4065 भूमिस्वामी	67/3	0.320	निरंक	कृषिभूमि
47	सतीश कुमार मनोज कुमार पुत्रगण बनवारी समान भाग जाति वैश्य पता बिनेगा शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी	65/2	0.888	निरंक	कृषिभूमि
48	चौहू पुत्र दुरजन जाति सेहर पता बिनेगा भूमिस्वामी	85	0.805	निरंक	कृषिभूमि

49	सुशीला बेवा तेजसिंह मनोज दिलीप पुत्रगण तेजसिंह ममता	64/2	0.500	निरंक	कृषिभूमि
	मन्जू लक्ष्मी पुत्रया तजासह जात जाटव पता बिनगा समान भाग भूमिस्वामी				
50	अजयकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति शिवहरे पता बिनगा भूमिस्वामी	64/4	1.588	निरंक	कृषिभूमि
51	हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनगा भूमिस्वामी	308	0.141	निरंक	कृषिभूमि
	योग		18.113		

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी। अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण/हितबद्ध व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/05/23 को जारी किया गया।

प्र.क्र. 0005-2022-23 -अ-82-भू-अर्जन-4028

कार्यपालन यंत्री, हरसी जल संसाधन संभाग डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

बनाम

बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार अन्य 30 निवासी ग्राम धोबनी तहसील विजयपुर जिला श्योपुर म.प्र.

द्वारा- तहसीलदार तहसील विजयपुर।

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है।) की धारा 21(1) के अन्तर्गत।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम धोबनी तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित अपर ककोटो बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आय है।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्यांक 30) की धारा 21 (2) के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है। तदनुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान का अधिनियम प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति होतो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात् दिनांक.....तक इस न्यायालय में स्वयं/अभिकर्ता/ अधिवक्ता के माध्यम से उप संज्ञात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक.....पश्चात् भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा।

क्र.	राजस्व वृत्त/पटवारी हल्का/ग्राम/तहसील एवं जिले का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का अर्जित रकवा हे. में		
			सिंचित रकवा	असिंचित रकवा	कृषि भिन्न
1	2	3	4	5	6
	राजस्व वृत्त-गसवानी/पटवारी हल्का 48 धोबनी/तहसील विजयपुर/जिला श्योपुर				
1	बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	497/1	0.026	निरंक	कृषिभूमि
2	कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	497/2	0.026	निरंक	कृषिभूमि
3	सोनेराम पुत्र रामरतन जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	497/3	0.021	निरंक	कृषिभूमि
4	सज्जन,ओमी.दोली राजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी, लीला बा.मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपररात गौं खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार	496	0.092	निरंक	कृषिभूमि

5	नथुआ, प्रहलाद, मुरारी, विष्णु पुत्रगण जादौ प्रयागो, रामो पुत्रियां जादौ जाति किरार पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	495/2	0.011	निरंक	कृषिभूमि
6	जादौ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी	495/3	0.011	निरंक	कृषिभूमि
7	जगराम पुत्र मानसिंह जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी राजो बेवा मान सिंह जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमिस्वामी बाबूलाल, द्वारिका प्रसाद( बालिग ,ओमप्रकाश ना.बा. पुत्रगण सवाई सरपरस्त बाबूलाल भाई खुद जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमिस्वामी जादौ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम 1/6 भाग भूमिस्वामी श्री किसन (नाबालिग) पुत्र देवीराम सरपरस्त सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 भाग भूमिस्वामी	478	0.042	निरंक	कृषिभूमि
8	सज्जन, ओमी.दोली राजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी, लीला बा.मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त मौं खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार	517	0.283	निरंक	कृषिभूमि
9	जादौ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी	510	0.136	निरंक	कृषिभूमि
10	गया बाई बेवा चिन्दू जाति मिर्धा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	508/1	0.063	निरंक	कृषिभूमि
11	मु. चन्द्रा बेवा माना जाति मिर्धा पता ग्राम भूमिस्वामी	508/2	0.073	निरंक	कृषिभूमि
12	कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण पता धोबिनी भूमिस्वामी	503	0.200	निरंक	कृषिभूमि
13	बाईसराम पुत्र राम रतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	646/1	0.150	निरंक	कृषिभूमि
14	कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	646/2	0.150	निरंक	कृषिभूमि
15	रामहेत पुत्र खरगजीत जाति किरार पता बूडदै भूमिस्वामी	384	0.105	निरंक	कृषिभूमि
16	सुरेश कुमार कृष्णकान्त पुत्र रामलाल जाति ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	421	0.249	निरंक	कृषिभूमि
17	हरिज्ञान पुत्र सवाई जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी कमला, लीला पुत्रियां सवाई जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी मु. कस्तूरी बेवा सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 समान भाग भूमिस्वामी जगदीश, वीरेन्द्र नाबालिग पुत्रगण रामचरण गायत्री नाबालिग पुत्री रामचरण सर.मौं जाति किरार पता नेहरखेडा भूमिस्वामी मु.कलावती बेवा रामचरण जाति किरार पता नेहरखेडा 1/18 समान भाग भूमिस्वामी मुरारी पुत्र रामजीलाल मु.गया बेवा रामजीलाल जगन्नाथ पुत्र चन्दू 1/3 जाति किरार पता नेहरखेडा 1/9 समान भाग भूमिस्वामी	417	0.137	निरंक	कृषिभूमि
18	प्रहलाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा समानभाग भूमिस्वामी	36/2/3	0.742	निरंक	कृषिभूमि



19	पूरन, लखन, विजय, वीरेन्द्र पुत्रगण जगन्नाथ जाति किरार पता नि.ग्राम भूमिस्वामी अन्जु पुत्री जगन्नाथ जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमिस्वामी गिर्राज, अमरसिंह पुत्रगण जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गीता, जानकी, लीला, त्रिवेनी, पुत्रिया जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी काशी देवा जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमिस्वामी	471	0.251	निरंक	कृषिभूमि
20	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमिस्वामी	473	0.241	निरंक	कृषिभूमि
21	चरणपुत्र कुडरी जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भाग 1/2 भूमिस्वामी गया बेवा कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 प्रभूदयाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 बलराम पाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 केदार पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 मथुरा पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 रामबती पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 नारायणी पुत्री कासीरामजातिगडरिया पता निवासीनेहरखेड़ाभाग 1/14	480	0.094	निरंक	कृषिभूमि
22	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमिस्वामी	485	0.125	निरंक	कृषिभूमि
23	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमिस्वामी	483	0.084	निरंक	कृषिभूमि
24	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमिस्वामी	484	0.073	निरंक	कृषिभूमि
25	कमरलाल, कैलाश पुत्र गणकासीराम जाति मेहतर पता सा.देह भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से मथुरा,रेखा पुत्री गणकासीराम जाति मेहतर पता सा.देह समान भाग भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से	467/1	0.363	निरंक	कृषिभूमि
26	बैजन्तीबेवा खच्चू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भाग महेश पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 राजेन्द्र पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 रामअवतार पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 शिवराम पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 पारवती पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 सकुन्तला पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 भूमिस्वामी	24/1	2.070	निरंक	कृषिभूमि
27	अमरलाल पुत्र ननकू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भूमिस्वामी	24/4/5	0.209	निरंक	कृषिभूमि
28	विनयपाल पुत्र रामजी जाति किरार पता नि. धोबनी	22/4	0.450	निरंक	कृषिभूमि
	भूमिस्वामी				

29	हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमिस्वामी	486	0.052	निरंक	कृषिभूमि
30	दाताराम पुत्र पन्नू जाति किरार निवासी ग्राम धोबनी भू-स्वामी	516	0.109	निरंक	कृषिभूमि
31	प्रहलाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा समान भाग भूमिस्वामी	34/4	1.463	निरंक	कृषिभूमि
:	योग		8.101		

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी अधिनिर्णय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण/हितबद्ध व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक...12/05/23...को जारी किया गया।

शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना दिनांक 01 मई 2023

प्रकरण क्रमांक 05/अ-82 वर्ष 2022-23 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-18 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कड़िका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कड़िका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	—	पन्ना
(ख) तहसील	—	अजयगढ़
(ग) ग्राम	—	विश्रामगंज
(घ) मकान/क्षेत्रफल—		कुल मकान-11 क्षेत्रफल 359.89 वर्गमी०

क्रमांक	मकानक०	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा वर्ग मीटर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	
1	1	348	18.60	निजी भूमि
2	2	26/1	34.92	निजी भूमि
3	3	116	76.25	निजी भूमि
4	4	370/2	54.27	निजी भूमि
5	5	140	09.90	निजी भूमि
6	6	106	21.52	निजी भूमि
7	7	66	48.54	निजी भूमि
8	8	59	21.12	निजी भूमि
9	9	328	22.40	शासकीय भूमि '
10	10	328	31.05	शासकीय भूमि
11	11	213	21.32	शासकीय भूमि
योग	कुल मकान -11		359.89	

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- राज्य मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित छूटे हुये मकानों का अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम विश्रामगंज तह० व अनुभाग अजयगढ़
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरसूद, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

पत्र.क्र.क-वा-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0047-अ-59 -2022-23

हरसूद दिनांक 11 मई 2023

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम-6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 संनं 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 602/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - मोहन्या भाम, प.ह.नं.- 15, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - मोहन्या भाम, प.ह.नं.- 15,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			291	0.038
			290	0.026
			289/3	0.008
			289/1	0.015
			289/2	0.058

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम – मोहन्या भाम, प.ह.नं.- 15,	288	0.005
			287/5	0.020
			297/1	0.012
			298	0.029
			299/2	0.016
			304/1	0.065
			305	0.066
			306	0.044
			307	0.051
			309	0.030
			310/1	0.020
			310/2	0.017
			310/3	0.016
			310/4	0.004
			311	0.003
			23/2	0.004
				0.002
				0.010
			23/3	0.013
			23/4	0.008
			22/2	0.003
			10/8	0.004
			11/8	0.005
			11/7	0.008
			11/6	0.007
			11/5	0.004
			12/1	0.007
			76/1	0.003
			12/3	0.008
			76/2	0.014
			77/3	0.008
			77/2	0.013
			77/1	0.015
			78	0.015
			102	0.039
			99/2	0.017
			99/1	0.004
			89	0.008
			90	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम – मोहन्या भाम, प.ह.नं.– 15,	91	0.011
			23/1	0.008
			22/1	0.002
			21	0.016
			17/1	0.007
			14/1	0.019
			14/2	0.013
			131	0.016
			128/1	0.005
			147/3/2	0.004
			147/4/2	0.001
			147/5/2	0.002
			147/1	0.004
			145/3/1	0.003
			145/3/3	0.005
			362/3	0.005
			362/4	0.003
			362/1	0.002
			139	0.013
			141/2	0.009
			116	0.014
योग निजी भूमि			63	0.946
खण्डवा	खालवा	ग्राम – मोहन्या भाम, प.ह.नं.– 15,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			293	0.004
			300	0.005
			312	0.012
			9	0.003
			61	0.002
			95	0.001
			188	0.002
			16	0.001
			69	0.005
			61	0.001
			56	0.009
			55	0.016
			130	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम – मोहन्या भाम, प.ह.नं.- 15,	132	0.003
				0.007
				0.006
			136	0.003
			137	0.005
				0.005
			148	0.006
			146	0.001
			364	0.001
			125	0.004
			92	0.001
योग शासकीय भूमि			21	0.106
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			84	1.052

पत्र.क्र.क-वा-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0047-अ-59-2022-23

**प्रारूप-घ**  
**[ नियम-6 देखिए ]**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 617/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 4 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - बेड़ाडाना, प.ह.नं.- 29, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - बेड़ाडाना, प.ह.नं.- 29,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			19	0.021
			20/1	0.008
			42	0.019
				0.007
			45	0.004



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम – बेड़ाडाना, प.ह.नं.- 29,	46	0.004
			35	0.004
			65	0.002
			66	0.003
			67	0.005
			68	0.010
			69	0.005
			70	0.005
			71	0.001
			83	0.008
			82	0.006
			81	0.001
			40	0.005
			39	0.005
			33	0.001
योग निजी भूमि			19	0.124
खण्डवा	खालवा	ग्राम – बेड़ाडाना, प.ह.नं.- 29,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			47	0.001
			73	0.001
योग शासकीय भूमि			02	0.002
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			21	0.126

पत्र.क्र.क-वा-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0036-अ-59-2022 23

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 608/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - सिरपुर, प.ह.नं.- 14, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - सिरपुर, प.ह.नं.- 14,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			3/1	0.005
			2/1	0.018
				0.003
			15/1	0.003
			15/2	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम – सिरपुर, प.ह.नं.- 14,	15/3	0.009
			229	0.002
				0.016
			228	0.002
				0.019
			227	0.001
			230	0.001
			225	0.003
			221	0.001
			192	0.006
			189	0.027
			191/1	0.014
			190/3	0.010
			223	0.036
			523/7	0.026
			520/1	0.021
			517	0.024
			518/1	0.021
			504/1	0.014
			504/2	0.006
			488	0.014
			403	0.006
			404	0.008
			407	0.017
			408	0.014
			411/1	0.011
			411/2	0.012
			411/3	0.006
			394	0.004
			392/5	0.016
			392/3	0.006
			392/6	0.005
योग निजी भूमि			34	0.413

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम — सिरपुर, प.ह.नं.— 14,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :—	
			1	0.001
			226	0.001
				0.001
			188	0.002
			527	0.002
			552	0.002
			486	0.001
			485	0.001
			339	0.023
			338	0.011
			341	0.031
			342	0.022
			402	0.004
			400	0.002
			393	0.001
योग शासकीय भूमि			14	0.105
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			48	0.518

पत्र.क्र.क-वा-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0038-अ-59-2022-23

**प्रारूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक-614/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - खालवा सरकार, प.ह.नं.- 20, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - खालवा सरकार, प.ह.नं.- 20,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			379	0.007
			381	0.008
			384	0.012
			383	0.023
			391	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम — खालवा सरकार, प.ह.नं.— 20	412	0.026
			425	0.009
			424	0.024
			444	0.001
			445	0.003
			446	0.002
योग निजी भूमि			11	0.136
खण्डवा	खालवा	ग्राम — खालवा सरकार, प.ह.नं.— 20	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			380	0.001
			442	0.001
			468	0.004
योग शासकीय भूमि			03	0.006
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			14	0.142

A

पत्र.क्र.क-वा-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0012-अ-59-2022-23

**प्ररूप- 'घ'**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन्. 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-605/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्बहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - पिपलटोला, प.ह.नं.- 06, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी वित्त्वंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - पिपलटोला, प.ह.नं.- 06	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			67/1	0.002
			67/2	0.019
			66/2	0.007
			65	0.044
			73/2	0.043

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम — पिपलटोला, प.ह.नं.— 06	73/4	0.012
			75	0.007
				0.020
			103	0.037
			266	0.011
			269	0.009
			272	0.010
			273	0.003
			280/1	0.022
योग निजी भूमि			13	0.246
खण्डवा	खालवा	ग्राम — पिपलटोला, प.ह.नं.— 06	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			62	0.002
			72	0.001
			102	0.007
			101	0.023
			173	0.043
				0.014
			174	0.001
				0.018
			264	0.005
				0.007
			179	0.007
			263	0.004
			268	0.009
			259	0.011
			274	0.001
			277	0.001
			279	0.022
			265	0.002
योग शासकीय भूमि			15	0.178
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			28	0.424



पत्र.क्र.क-वा-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0057-अ-59-2022-23

**प्ररूप- "घ"**  
**[ नियम- 6 देखिए ]**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-611/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- सावलीखेड़ा, प.ह.नं.- 20, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम- सावलीखेड़ा, प.ह.नं.- 20	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			160/2	0.008
			160/1	0.008
				0.003
				0.001
			161/1	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम- सावलीखेड़ा, प.ह.नं.- 20	162/1	0.017
				0.005
			162/2	0.009
				0.006
			157	0.006
			156/1	0.001
			145/1	0.023
			145/2	0.017
			146	0.003
			131/1	0.005
			131/2	0.002
			130	0.011
			129	0.007
			114	0.019
			163/1	0.007
			163/2	0.006
			163/3	0.001
			204	0.006
			203	0.006
			202/1/1	0.007
			202/3	0.009
			199/4	0.006
			187	0.005
			183	0.009
			181	0.007
			178/2	0.001
			414	0.002
			422/1	0.002
			422/2	0.002
			422/3	0.002
			422/4	0.002
			422/5	0.002
			421/2	0.002
			423/1	0.012
			443/2	0.006
			442	0.010
			492/2	0.013
			491	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम- सावलीखेड़ा, प.ह.नं.- 20	478/3	0.005
				0.003
			482	0.006
			481	0.007
			286/2	0.003
			358/4	0.004
			358/3	0.003
			358/2	0.006
			358/1	0.009
			377	0.004
योग निजी भूमि			48	0.334
खण्डवा	खालवा	ग्राम- सावलीखेड़ा, प.ह.नं.- 20	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			159	0.001
			158	0.001
			153	0.001
			126	0.001
			111	0.002
			164	0.001
			169	0.001
			306/1	0.001
			405	0.001
			420	0.026
			423/2	0.001
			476	0.001
			484	0.001
			529	0.001
			368	0.001
			357	0.001
			372	0.016
			371	0.001
			375	0.001
			385	0.005
			382	0.001
योग शासकीय भूमि			21	0.068
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			69	0.402

पत्र.क्र.क-वा-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0048-अ-59-2022-23

**प्ररूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-4733/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन शिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम -नीमखेड़ा रै., प.ह.न.-03, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -नीमखेड़ा रै., प.ह.न.-03,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			84/1	0.037
			125/1	0.011
			73/1	0.021
			71/3	0.014
				0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —नीमखेड़ा रै, प.ह.न.—03,	71/6	0.008
			71/4	0.002
			71/5	0.002
			383	0.022
			373/1	0.011
			373/2	0.006
			372/1	0.018
			356/2	0.008
			356/1	0.021
			361	0.008
			360	0.022
			362	0.013
				0.005
			321/2	0.004
			320	0.007
			323	0.020
			365	0.019
			317/1/1	0.003
			314/2	0.015
			311	0.005
			312/2	0.002
योग निजी भूमि			24	0.307

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —नीमखेड़ा रै., प.ह.न.—03,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			82	0.002
			84/2	0.002
			124	0.001
			122	0.009
			114	0.001
			111	0.016
			75	0.005
			368	0.001
			353	0.001
			322	0.001
			318	0.001
			योग शासकीय भूमि	
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			35	0.347

पत्र.क्र.क-वा-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र.-0021-अ-59-2022-23

**प्रारूप- "घ"**  
**[ नियम- 6 देखिए ]**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक-599/क/वा.-1/भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 03 व 04 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - नामापुर, प.ह.नं.- 28, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - नामापुर, प.ह.नं.- 28,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			126	0.008
			134	0.004
			133	0.007
			132	0.013
			131/1	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम — नामापुर, प.ह.नं.— 28,	131/2	0.003
			140/1	0.016
			142	0.008
			143	0.002
			144	0.007
			145	0.008
				0.002
				0.003
			180	0.008
			182/1	0.004
				0.001
			175	0.010
				0.004
			224	0.004
			225	0.002
			181/2	0.008
			226	0.007
			233	0.001
			234	0.009
			313	0.008
			314	0.007
			350	0.005
			353	0.005
			354/2	0.001
			183/1	0.007
			183/3	0.002
			183/2	0.001
			182/2	0.008
			181/1	0.002
			159/1	0.010
			168	0.009
			167	0.001
			247	0.007
			10	0.007
			11	0.013



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम — नामापुर, प.ह.नं.— 28,	12	0.012
			13	0.013
			27	0.008
			26	0.007
			21	0.021
			22	0.021
			20	0.001
			योग निजी भूमि	
खण्डवा	खालवा	ग्राम — नामापुर, प.ह.नं.— 28,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			129	0.001
			184	0.001
				0.001
			169	0.001
			231	0.001
			312	0.001
			349	0.001
			148	0.001
			166	0.001
			17	0.001
			योग शासकीय भूमि	
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)		52	0.335	

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-2015-रा.प्र.क्र.-0035-अ-59-2022-23

**प्रारूप-“घ”**  
**{ नियम-6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-4748/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -रतनपुर अन्धारिया, प.ह.न.-11, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -रतनपुर अन्धारिया, प.ह.न.-11	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			301/1	0.015
			299/3	0.004
			299/2	0.004
			299/1	0.004
			188	0.011

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —रतनपुर अन्धारिया, प.ह.न.—11	189/1	0.005
				0.005
			192/1	0.013
			192/2	0.011
			191/3	0.007
			194/1	0.001
			196/1	0.011
			286	0.003
			285/1	0.007
			308/1	0.002
			320/3/1	0.003
			320/3/2	0.006
			320/2	0.007
			322/2	0.001
			322/3	0.015
			322/4	0.005
			323/4	0.004
			323/1	0.006
			323/2	0.003
			329/2	0.005
			378/1	0.017
			378/2	0.010
			369/1	0.004
			369/3	0.002
			368/2	0.011
			368/1	0.010
			367/1	0.003
			367/3	0.001
			355	0.011
			357/1	0.005
			357/2	0.001
				0.007
			357/3	0.003
			358/2	0.007
			350/1	0.004
योग निजी भूमि			38	0.254

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम –रतनपुर अन्धारिया, प.ह.न.-11	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			300	0.001
			193	0.001
			198	0.001
			197	0.001
			195	0.001
			293	0.001
			311	0.001
			334	0.001
			366	0.001
			354	0.001
			363	0.001
			351	0.001
योग शासकीय भूमि			12	0.012
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			50	0.266

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-2012-रा.प्र.क्र.-0017 -अ-59-2022-23

**प्रारूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सं 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4736/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 4 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - जामन्या खुर्द, प.ह.नं.- 27, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम - जामन्या खुर्द, प.ह.नं.- 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			114/2	0.008
			115/1	0.003
			114/1	0.005
			116/2/2	0.005
			118/1	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम — जामन्या खुर्द, प.ह.नं.— 27	118/2	0.003
			118/3	0.004
			135	0.011
			134/1	0.007
				0.002
			134/2	0.011
			127/1/1	0.015
			128/1	0.004
			128/3/1	0.009
			128/3/2	0.006
			128/4	0.002
			129/1	0.011
			129/2	0.002
			92	0.002
			95/1	0.007
			95/2	0.006
			95/3	0.005
			97/3	0.012
योग निजी भूमि			22	0.150
खण्डवा	खालवा	ग्राम — जामन्या खुर्द, प.ह.नं.— 27	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			109	0.001
			113	0.005
			117	0.008
			125	0.001
			96	0.001
योग शासकीय भूमि			05	0.016
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			27	0.166

पत्र क्र. क-वा-1-भू-अर्जन-2023-2008-रा.प्र.क्र.-0061-अ-59-2022 23

**प्रारूप- "घ"**  
**{ नियम- 6 देखिए }**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4754/क/वा.-1/भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक- 2 से पम्प हाऊस कमांक- 3 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 व 04 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम -खारकलां, प.ह.न.-24, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

**:: अनुसूची ::**

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम -खारकलां, प.ह.न.-24	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			726	0.008
			725/5	0.001
			347	0.010
			375	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —खारकलां, प.ह.न.—24	377/2/1	0.001
				0.006
				0.004
			378	0.005
				0.006
			380	0.006
				0.003
			388/2	0.020
			395	0.012
			394	0.017
			393	0.001
			403/1	0.005
			403/3	0.007
			403/2	0.004
			403/4	0.003
			405/2	0.006
			405/1	0.010
			290/3	0.009
			408/1	0.006
			377/2/2	0.003
			379	0.003
			382	0.009
			361	0.002
			439/3	0.006
			440	0.011
			448	0.001
			447/4	0.006
			447/1	0.005
योग निजी भूमि			28	0.203



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खालवा	ग्राम —खारकलां, प.ह.न.—24	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			727	0.001
			350	0.001
			349	0.001
			369	0.001
			370	0.006
			367	0.001
			383	0.001
			326	0.001
			404	0.001
			289	0.001
			383	0.001
			योग शासकीय भूमि	
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)			39	0.219

दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी.

## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प्र.क.ए.

राजगढ़, दिनांक 17 मई 2023

ग्रासूप - ख					
नियम 5 कानियम (2) देखिये					
<p>क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बायीं तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम-खीमाखेड़ी, चोण्डापुरा, लिम्बोदा, पाडन्याखेड़ी, कलपोनी, बखेड, चौसत्ता तहसील - खुजनेर जिला राजगढ़ (11) से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है। तहसील पचोर से सारंगपुर एव खिलचीपुर एव राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाईप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।</p> <p>और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।</p> <p>अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।</p> <p>कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी राजस्व राजगढ़ (तहसील -खुजनेर) जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा</p>					
अनुसूची					
ग्राम -खीमाखेड़ी		तहसील -खुजनेर			
अनु क्रमांक	खसरा क्रमांक	भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम	ग्राम का नाम	कुल क्षेत्रफल	उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	10/2	घनश्याम पिता रामचरण जाति अहीर	खीमाखेड़ी	0.742	0.011
2	9/1	सत्यनारयण पिता घीसालाल जाति ब्राम्हण	खीमाखेड़ी	0.818	0.028
3	158	मवरलाल बापूलाल अनारबाई पिता भेरू जाति चमार	खीमाखेड़ी	0.025	0.006
कुल योग	3			1.585	0.045

ग्राम -चोण्डापुरा			तहसील -खुजनेर		
1	242	रामचरण पिता प्रभुलाल जाति बलाई तेजकरण पिता प्रभुलाल जाति बलाई संतोष पिता प्रभुलाल जाति बलाई ममताबाई बेवागोपाल जाति बलाई देवेंद्र पिता गोपाल जाति बलाई निशा पुत्री गोपाल जाति बलाई सुमन पुत्री गोपाल जाति बलाई	चोण्डापुरा	1.783	0.006
2	233/1	ब्रदीलाल पिता पूनमचंद जाति अहीर	चोण्डापुरा	0.265	0.014
3	149/1	धनश्याम पिता रामचरण यादव जाति अहीर	चोण्डापुरा	0.493	0.009
4	149/2/1	हीरालाल पिता भवरलाल जाति अहीर	चोण्डापुरा	0.330	0.021
5	154/1	छितलाल लालजी पिता अमरा जाति चमार	चोण्डापुरा	0.747	0.0009
6	148/2/1	अमरसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत	चोण्डापुरा	0.563	0.017
7	148/2/2	जगदीश पिता अमरसिंह जाति अहीर	चोण्डापुरा	0.253	0.018
कुल योग		7		4.434	0.086
ग्राम -लिम्बोदा			तहसील -खुजनेर		
1	822/1	सिध्दनाथ पिता देवीलाल मु द्रौ पति बाई बेवा देवीलाल	लिम्बोदा	0.529	0.011
2	822/2	मांगीलाल पिता देवीलाल जाति चमार	लिम्बोदा	2.00	0.011
3	821/2/2	सत्यनारायण, संतोष, लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल जाति ब्राम्हण	लिम्बोदा	1.139	0.023
4	819	सिध्दनाथ पिता देवीलाल मु द्रौ पति बाई बेवा देवीलाल	लिम्बोदा	0.443	0.003
कुल योग		4		4.11	0.048

ग्राम -पाडल्याखेडी			तहसील -खुजनेर		
1	965/1	दोलजी पिता रामलाल जाति सौंधिया पारवतीबाई पिता रामलाल जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	1.164	0.025
2	960/1/1	महेन्द्र पिता बापूलाल जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	1.553	0.019
3	960/1/2	बिराम सिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	1.554	0.018
4	960/2	प्रेमसिंह पिता किशनलाल जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	3.107	0.019
5	960/3	बालसिंह पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	3.107	0.019
6	929/1/1	नारायणसिंह पिता धुलजी जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	0.506	0.024
7	929/1/2	शिव नारायण पिता धुलजी जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	0.759	0.025
8	929/2/1	सनतोषबाई पति नारायणसिंह जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	1.044	0.025
9	927/2	शिव नारायण पिता मांगीलाल , शैतान बाई बेवा मांगीलाल जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	0.338	0.015
10	927/3	लखन पिता भगवान सिंह,राजेश पिता भगवानसिंह बलराम पिता भगवानसिंह जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	0.448	0.015
11	927/5/1	जगन्नाथ पिता बदनजी जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	0.146	0.015
12	923/1	रामचंद्र पिता रुघनाथ जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	0.200	0.006
13	924	मांगीलाल पिता माधु जाति सौंधिया	पाडल्याखेडी	0.632	0.020
14	923/6/3	कुमेर सिंह पिता बदनजी जाती सौंधिया	पाडल्याखेडी	0.115	0.010

15	916/2	कनीराम पिता गोपीलाल जाति बलाई	पाडल्याखेडी	0.526	0.009
16	916/3	बंशीलाल पिता गोपीलाल जाति बलाई	पाडल्याखेडी	0.526	0.009
17	916/4	गुलाब बाई बेवा मांगीलाल जाति बलाई	पाडल्याखेडी	0.526	0.009
18	916/6	पुरालाल पिता छितालाल जाति चमार	पाडल्याखेडी	0.527	0.010
19	912/1	रामप्रसाद पिता प्रभुलाल जाति नाई	पाडल्याखेडी	0.435	0.002
20	873	कैन्ह्यालाल पिता भीमा जाति दांगी	पाडल्याखेडी	0.772	0.023
21	867/1/2	राधेश्याम पिता अमरसिंह जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.299	0.013
22	867/2	रामचंद्र पिता पुरालाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	1.068	0.014
23	854/3	लक्ष्मीनारायण पिता कालूसिंह जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.758	0.020
24	855/2	ललताबाई पति गोपालसिंह जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.693	0.022
25	855/4	भगवानसिंह पिता बिहारीलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.694	0.022
26	855/6	कमलसिंह, दरियाव सिंह पिता इंदरसिंह जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.170	0.022
27	850/1	बिरमसीह पिता धुलजी जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.227	0.026
28	849/2/1	मांगीलाल पिता फत्ताजी जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.253	0.018
29	848/3/1	सिद्धलाल पिता प्रभुलाल जाति नाई	पाडल्याखेडी	0.253	0.035
30	617/1	भवरलाल पिता धुलजी बापूलाल पिता धुलजी जाति नाई	पाडल्याखेडी	0.329	0.034
31	838/1	मानसिंह पिता जगनाथ जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	1.895	0.028
32	838/2	नारायणसिंह पिता जगनाथ जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	1.886	0.026
33	835/1	केदार बाई पति रामनारायण जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.632	0.041
34	835/2	हरिसिंह पिता अमरसिंह जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.759	0.033
35	834/2	भगवानसिंह पिता बंदनजी जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.283	0.014

36	834/3	कमेर सिंह पिता बंदनजी जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	0.282	0.015
37	828/1	शिवनारायण पिता मांगीलाल शैतान बेवा मांगीलाल जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	0.790	0.021
38	828/2	रामचंद्र पिता रुघनाथ जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	0.791	0.021
39	828/1	शिवनारायण पिता मांगीलाल शैतान बेवा मांगीलाल जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	0.790	0.006
40	753/2	श्रीलाल पिता भवरलाल जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	0.714	0.030
41	754	धुलजी पिता भेरुसिंह पानबाई विधवा भेरुसिंह	पाडल्याखेडी	1.303	0.027
42	809/1/2	इशाक पिता खुदा बख्स जाति पिंजरी	पाडल्याखेडी	0.382	0.022
43	809/2/3	अजीज खा पिता खुदा बख्स जाति पिंजरी	पाडल्याखेडी	0.382	0.022
44	811	बापूलाल पिता रोड़ा घिसी बाई भूलीबाई उर्फ डाला बाई पिता रोड़ा जाति दांगी	पाडल्याखेडी	0.531	0.007
45	861	मांगीलाल पिता माधु गजरीबाई बेवा माधु जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	0.544	0.008
46	715/6/2	भगवानसिंह पिता बंदनजी जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	0.0100	0.008
47	715/3	कालूसिंह पिता पुरजी जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	0.014	0.008
48	841	ओमप्रकाश सत्यनारायण पिता अमरसिंह दुर्गाबाई शकुंतलाबाई हेमलताबाई होकमबाई पिता अमरसिंह गीताबाई बेवा अमरसिंह जाति नाई	पाडल्याखेडी	0.392	0.010
49	840/1/1	भवरलाल , बापूलाल पिता धुलजी जाति नाई	पाडल्याखेडी	0.234	0.006
50	840/2	गोपाल अशोक जगदीश राहुल पिता रामबाबू जाति नाई	पाडल्याखेडी	0.487	0.006
51	838/2	नारायण सिंह पिता जगन्नाथ जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	1.886	0.0009

52	621	भवरलाल , बापूलाल पिता धुलजी जाति नाई	पाडल्याखेडी	0.696	0.007
53	625/2	लालजी राम पिता छितलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.835	0.017
54	626/1/1	दरियावसिंह पिता भवरलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.557	0.004
55	626/2/2	शिवसिंह पिता भवरलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.292	0.004
56	628/2	हेमराज पिता दरियावसिंह जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.696	0.008
57	600	मांगीलाल पिता माधु जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	1.859	0.004
58	642/2	बालूसिंह पिता मांगीलाल सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.076	0.008
59	645/1/2	रामचरण पिता बापूलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.033	0.003
60	645/3	नरायन सिंह पिता जगन्नाथ जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.082	0.002
61	649/1	कमल सिंह पिता भेरू सिंह जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.063	0.008
62	538/1	देवसिंह पिता रघुनाथ जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.080	0.003
63	538/2	चेनसिंह पिता रघुनाथ जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.046	0.002
64	531/1	बिरमसिंह पिता भेरूसिंह जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.126	0.004
65	531/2	हीरालाल पिता देवजी जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.127	0.003
66	527	हरिसिंह पिता बापूलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.101	0.001
67	528/2/2	जगन्नाथ पिता कनीराम जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.100	0.005
68	528/3/2	लक्ष्मीनारायण पिता बापूलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.139	0.005
69	521/1	कवरलाल पिता रामलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.102	0.002
70	521/2	करणसिंह पिता रामलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.101	0.001
71	521/3	दरियावसिंह पिता रामलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.101	0.001
72	555/1	देवसिंह पिता रघुनाथ जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.193	0.006

73	555/2	चेनसिंह पिता रघुनाथ जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.076	0.006
74	297/1/1	शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.180	0.004
75	297/2	बिहारीलाल पिता रामलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.361	0.004
76	302/2	बनेसिंह दत्तक किशनलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.890	0.002
77	302/3/2	गीताबाई पिता हिंदूसिंह जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.153	0.001
78	301/1	बिरमसीह पिता बापूलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.695	0.013
79	346/1/1	सेवा भूमि रामचरण पिता रामसिंह जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	1.519	0.010
80	126/2/2/1	सज्जनसिंह पिता दोलाजी जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.140	0.005
81	126/2/2/3	प्रतपसिंह पिता दोलाजी लीलाबाई विधवा दोलाजी जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.140	0.005
82	124/1/3	रायसिंह पिता भवरलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.316	0.009
83	122/2	रायसिंह पिता भवरलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.295	0.007
84	122/3	हरिसिंह पिता भवरलाल जाति सोंधिया	पाडल्याखेडी	0.295	0.008
85	79/2/1/1	सुशिल सुनील अनिल पिता ओमप्रकाश रामकांता बेवा ओमप्रकाश जाति ब्राम्हण	पाडल्याखेडी	0.559	0.004
86	79/2/1/3/1	भागवत शरण व्यास पिता लक्ष्मीनारायण व्यास जाति ब्राम्हण	पाडल्याखेडी	0.279	0.005
87	79/2/1/3/2	श्रीमती रामकांता पति ओमप्रकाश व्यास जाति ब्राम्हण	पाडल्याखेडी	0.279	0.005
88	79/2/2/1	मंगल प्रकाश पिता रवि प्रकाश जाति ब्राम्हण	पाडल्याखेडी	1.038	0.004
89	79/2/2/2	रवि प्रकाश पिता पुरुषोत्तम लाल जाति ब्राम्हण	पाडल्याखेडी	0.638	0.005



90	80/1	हरिनारायण पिता लक्ष्मीनारायण जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	0.881	0.010
91	81/2/2	रामलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	1.000	0.020
92	75/2	दिलीपसिंह पिता भेरुसिंह जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	0.190	0.001
93	76	दिलीपसिंह पिता भेरुसिंह जाति सौधिया	पाडल्याखेडी	1.328	0.011
कुल योग	93			8.531	1.140
ग्राम -कलपोनी			तहसील -बुजनेर		
1	751/3/2	जगन्नाथ पिता बदनसिंह जाति सौधिया	कलपोनी	0.152	0.024
2	716/1/2	शांतिबाई पति इंदरसिंह जाति सौधिया	कलपोनी	0.329	0.024
3	750/2	प्रेम नारायण पिता बापूलाल जाति सौधिया	कलपोनी	3.099	0.033
4	708/2/1/1	रामचरण पिता बनेसिंह जाति सौधिया	कलपोनी	0.053	0.010
5	708/2/1/2	महेन्द्रसिंह पिता बनेसिंह जाति सौधिया	कलपोनी	0.053	0.010
6	708/2/3	होमक बाई पति प्रेम नारायण जाति सौधिया	कलपोनी	0.574	0.010
7	699	ऊकार सिंह पिता करणसिंह जाति सौधिया	कलपोनी	0.190	0.011
8	697/2	ऊकार सिंह पिता करणसिंह शिवसिंह पिता जगन्नाथ प्रेम नारायण पिता बापूलाल हम रलाल पिता बापूलाल जाति सौधिया	कलपोनी	0.114	0.014
9	695/1/2	अनारजी पिता रोडजी जाति सौधिया	कलपोनी	0.155	0.007
10	695/2	प्यारजी पिता रोडजी जाति सौधिया	कलपोनी	0.259	0.007
11	695/3/2	नरभेसिंह पिता रोडजी जाति सौधिया	कलपोनी	0.193	0.007
12	695/4	प्रेमसिंह पिता रोडजी जाति सौधिया	कलपोनी	0.360	0.007

13	454/1/2/2	कृष्ण बाई पति तावरसिंह जाति सोंधिया	कलपोनी	0.251	0.011
14	454/1/3	प्रेमनारायण पिता देवीलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.501	0.011
15	454/2/2	नाथूलाल पिता घीसालाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.253	0.011
16	443/1/1	मांगीलाल पिता माधु जाति सोंधिया	कलपोनी	0.280	0.007
17	441/1/1	मांगीलाल पिता माधु जाति सोंधिया	कलपोनी	0.175	0.021
18	462	उकारसिंह पिता करणसिंह जाति सोंधिया	कलपोनी	0.240	0.009
19	443/1/1	मांगीलाल पिता माधु जाति सोंधिया	कलपोनी	0.280	0.002
20	443/2	धुलजी पिता बापूलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.089	0.003
21	428	नारायणसिंह दरयाव सिंह पिता बापूलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.848	0.019
22	321	कवरलाल पिता घीसालाल जाति सोंधिया	कलपोनी	1.808	0.013
23	323/1/1	दिनेश सिंह फूलसिंह पिता मदनसिंह देव बाई बेवा मदनसिंह जाति सोंधिया	कलपोनी	1.226	0.029
24	325/1	देवकलाबाई पति रामकृष्ण जाति सोंधिया	कलपोनी	1.630	0.046
25	328/2/1	रामप्रसाद पिता प्रभुलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.328	0.003
26	329	भवरलाल पिता रुघनाथ जाति सोंधिया	कलपोनी	1.025	0.034
27	333/1	मानसिंह पिता भवरलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.937	0.018
28	335/1	संगीताबाई पिता श्रीलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.612	0.012
29	335/2	बिराम सिंह पिता उकारलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	1.223	0.012
30	335/3/2	रामचरण पिता विजयसिंह जाति सोंधिया	कलपोनी	0.047	0.011

31	257/1	रामचरण पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया	कलपोनी	1.096	0.012
32	257/2	कमलबाई पति गोवर्धनलाल जाति दांगी	कलपोनी	0.548	0.013
33	257/1	रामचरण पिता हिन्दुसिंह जाति सौधिया	कलपोनी	1.096	0.011
34	255/1/1	दरियाव सिंह पिता विजय सिंह जाति सौधिया	कलपोनी	0.242	0.005
35	255/2/1	मानसिंह नारायणसिंह आ भवरलाल जाति जाति सौधिया	कलपोनी	0.443	0.006
36	255/2/2	सर्जनसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौधिया	कलपोनी	1.012	0.006
37	253	भवरलाल पिता रुघनाथ जाति सौधिया	कलपोनी	0.493	0.005
38	245	कवरलाल पिता घीसालाल जाति सौधिया	कलपोनी	0.961	0.015
39	246/1	दरियाव सिंह पिता विजय सिंह जाति सौधिया	कलपोनी	0.417	0.006
40	246/2/2	मुल्तानसिंह पिता विजय सिंह जाति सौधिया	कलपोनी	0.127	0.006
41	232/2	आ नोख सिंह पिता हीरालाल जाति सौधिया	कलपोनी	0.662	0.007
42	232/3/1	सुरजबाई पति दरियावसिंह जाति सौधिया	कलपोनी	0.114	0.007
43	232/3/2	फूलसिंह पिता हिरालाल जाति सौधिया	कलपोनी	0.383	0.007
44	233/1/2	आ नोख सिंह पिता हीरालाल जाति सौधिया	कलपोनी	0.253	0.005
45	233/1/3	फूलसिंह पिता हिरालाल जाति सौधिया	कलपोनी	0.253	0.005
46	233/2	घीसालाल पिता हरिसिंह जाति सौधिया	कलपोनी	2.187	0.011
47	234	दिलीप सिंह पिता मानसिंह जाति सौधिया	कलपोनी	0.392	0.004
48	226/1	धूलजी पिता बापूलाल जाति सौधिया	कलपोनी	0.215	0.016

49	11/1/1	नाथूसिंह पिता धुलजी जाति सोंधिया	कलपोनी	0.423	0.007
50	11/1/2	बिरमसीह पिता धुलजी जाति सोंधिया	कलपोनी	0.433	0.007
51	11/1/3	कानजी पिता धुलजी जाति सोंधिया	कलपोनी	0.433	0.007
52	11/2/1	गंगराम पिता भोना जाति सोंधिया	कलपोनी	0.651	0.007
53	11/2/2	शिवसिंह पिता भोना जाति सोंधिया	कलपोनी	0.651	0.007
54	6/1	सम्पतबाई पति कवरलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.089	0.004
55	6/2	कानजी पिता धुलजी जाति सोंधिया	कलपोनी	0.379	0.005
56	6/4/2	बीरमसिंह पिता धुलजी जाति सोंधिया	कलपोनी	0.568	0.005
57	8	मानसिंह पिता उकारलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.696	0.0003
58	7/1/1	सीमाबाई पति बद्रीलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.433	0.007
59	7/1/2	सुल्तानसिंह पिता विजय सिंह जाति सोंधिया	कलपोनी	0.126	0.007
60	5/1/1	मोतीलाल पिता धुलजी जाति सोंधिया	कलपोनी	0.362	0.004
61	5/1/3	रतनबाई पति श्रीलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.363	0.002
62	5/2	प्रेमनारायण पिता बापूलाल जाति सोंधिया	कलपोनी	0.253	0.002
63	4	रुद्रप्रताप पिता हेमराज जाति सोंधिया	कलपोनी	0.683	0.011
64	2/1	यादवेंद्र पिता शिवनारायण जाति सोंधिया	कलपोनी	0.429	0.009

65	2/2	रघुवीरसिंह पिता प्रेमनारायण जाति सोंधिया	कलपोनी	0.912	0.009
66	257/1	रामचरण पिता हिन्दुसिंह जाति सोंधिया	कलपोनी	1.096	0.014
67	257/2	कमलबाई पति गोवर्धनलाल जाति दांगी	कलपोनी	0.548	0.036
कुल योग	67			5.987	0.737
राम -बखेड			तहसील -खुजनेर		
1	421/1	रामचरण पिता प्रभुलाल जाति दांगी	बखेड	0.616	0.002
2	407/2	शिवनारायण रामबाबू पिता प्रभुलाल जाति दांगी	बखेड	0.320	0.003
3	415/3	मांगीलाल पिता प्रभुलाल जाति दांगी	बखेड	0.076	0.006
4	436/1	शिवनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी	बखेड	0.430	0.006
5	417/2	रामचरण पिता हीरालाल जाति दांगी	बखेड	0.101	0.006
6	422/3/1	रामनारायण पिता देवसिंह जशोदाबाई पति देवसिंह जाति दांगी	बखेड	0.136	0.001
7	418/2	रामचरण पिता नरसंगलाल जाति दांगी	बखेड	0.215	0.004
8	464/1/2	बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जाति दांगी	बखेड	0.253	0.004
9	464/2	रोडमल पिता रामनारायण जाति दांगी	बखेड	0.417	0.004
10	465/1	मानसिंग पिता किशनलाल जाति दांगी	बखेड	0.709	0.003

11	465/2	रामचरण पिता किशनलाल जाति दांगी	बखेड	0.708	0.002
12	458/1	हरिसिंह दत्तक पुत्र देवचंद जाति भील	बखेड	0.784	0.021
13	456	रामचंद्र पिता नाथू जाति दांगी	बखेड	0.873	0.021
14	443/2	राजूबाई पिता हाजरी पति दिनेश जाति बलाई	बखेड	0.310	0.004
15	822/2	बिहारीलाल पिता छितलाल जाति सौधिया	बखेड	2.706	0.012
<b>कुल योग</b>	<b>15</b>			<b>2.943</b>	<b>0.099</b>
<b>ग्राम -चौसना</b>			<b>तहसील -खुजनेर</b>		
1	839/1/1	देव नारायण पिता मांगीलाल जाति दांगी	चौसला	1.264	0.007
2	839/2	बद्रीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी	चौसला	0.253	0.007
3	840	मांगीलाल पिता भवरलाल जाति दांगी	चौसला	0.114	0.001
4	841	भगवानसिंह पिता पुरीलाल जाति दांगी	चौसला	0.531	0.006
<b>कुल योग</b>	<b>4</b>			<b>0.367</b>	<b>0.021</b>

जूही गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.-एफ-6-75-2019-सात-शा.3

भोपाल, दिनांक 23 मई 2023

नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वर्तन से संबंधित वर्तमान में प्रभावी 'राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार क्रमांक 1 - मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020' में समय-समय पर किये गये संशोधनों के प्रावधानों को समाहित करते हुए इन निर्देशों का अद्यतन संस्करण जारी किया जाता है अर्थात्-

## अनुक्रमणिका

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020  
तृतीय संस्करण, वर्ष 2023

कण्डिका	शीर्षक	
	अध्याय - एक सामान्य	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना	
2.	इन निर्देशों में संशोधन की प्रक्रिया	
3.	परिभाषाएं	
4.	नजूल भूमि के अभिलेखों का निर्माण तथा संधारण	
5.	लोक प्रयोजन के लिये भूमि का पृथक् रखा जाना	
6.	लैण्ड बैंक	
7.	संहिता का लागू होना	
8.	नजूल भूमि के निर्वर्तन के लिए जिला, संभाग तथा राज्य स्तर पर समितियाँ	
9.	अपर आयुक्त तथा अपर कलेक्टर को शक्तियों का प्रत्यायोजन	
10.	नजूल भूमि का निर्वर्तन के तरीके	

	<p style="text-align: center;"><b>अध्याय – दो</b>  <b>राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण</b></p>	
11.	सक्षम प्राधिकारी	
12.	भूमि का चिन्हांकन तथा आवेदन	
13.	जांच प्रतिवेदन	
14.	भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति	
15.	सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन	
16.	विभाग को भूमि का हस्तांतरण	
17.	हस्तांतरण की गई भूमि पर कर निर्धारण	
18.	राज्य शासन के किसी विभाग से अनुपयोगी भूमि का वापस लिया जाना	
	<p style="text-align: center;"><b>अध्याय – तीन</b>  <b>स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि का निर्वर्तन</b></p> <p style="text-align: center;"><b>भाग – क</b>  <b>स्थायी पट्टे पर निर्वर्तन – सामान्य</b></p>	
19.	प्रयोजन, सक्षम प्राधिकारी, प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक तथा आवंटन की प्रक्रिया	
	<p style="text-align: center;"><b>भाग – ख</b>  <b>स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन की सामान्य प्रक्रिया</b></p>	
20.	इस भाग के उपबंधों का लागू होना	
21.	भूमि आवंटन के लिए आवेदन	
22.	जांच प्रतिवेदन	
23.	स्थायी पट्टे की स्वीकृति	
24.	प्रब्याजि तथा भू-भाटक	
25.	पट्टे का निष्पादन	



	<b>भाग – ग</b> <b>पूर्ण संस्था को पूर्ण प्रयोजन के लिए स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन</b>	
26.	सक्षम प्राधिकारी	
27.	भूमि आवंटन के लिये अर्हताएँ	
28.	भूमि आवंटन के लिये आवेदन	
29.	परीक्षण तथा जांच प्रतिवेदन	
30.	जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय	
31.	प्रब्याजि तथा भू-भाटक	
32.	पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य शर्तें जोड़ी जाना	
33.	इस भाग के प्रावधान लागू न होना	
	<b>भाग— घ</b> <b>मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल को कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन</b>	
34.	सक्षम प्राधिकारी	
35.	भूमि आवंटन के लिये अर्हताएँ	
36.	भूमि आवंटन के लिये आवेदन	
37.	आवेदन पत्र का परीक्षण तथा जांच प्रतिवेदन	
38.	जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय	
39.	प्रब्याजि तथा भू-भाटक	
40.	पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य शर्तें जोड़ी जाना	
41.	इस भाग के प्रावधान लागू न होना	
	<b>भाग – ङ</b> <b>मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को भूमि आवंटन</b>	

42.	मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को भूमि का आवंटन	
	<b>भाग — च</b> <b>चहुँमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में भूमि आवंटन</b>	
43.	निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नजूल भूमि का आवंटन	
44.	सक्षम प्राधिकारी	
45.	निवेशक द्वारा विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना	
46.	विभाग के द्वारा निवेशक के आवेदन का परीक्षण करना	
47.	विभाग द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के लिए समय—सीमा	
48.	कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण	
49.	सार्वजनिक उद्घोषणा	
50.	जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय	
51.	प्रब्याजि तथा भू-भाटक	
52.	पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य शर्तें जोड़ी जाना	
53.	स्थायी पट्टे की शर्तों का पालन कराने के संबंध में संबंधित विभाग का उत्तरदायित्व	
54.	आवंटित भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन की स्थिति में देय राशि	
55.	निजी पूंजी निवेशकों को आवंटित शासकीय पट्टे की भूमियों के अभिहस्तांकन (conveyance) की अनुमति	
56.	अभिहस्तांकन की शर्तें	
57.	अभिहस्तांकन की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना	
58.	कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित करना	
59.	राज्य शासन के द्वारा अभिहस्तांकन की अनुमति के आवेदन पर निर्णय लिया जाना	
60.	ऋणदाता संस्था के पक्ष में अभिहस्तांकित भूमि का हस्तांतरण	

	<b>भाग—छ</b> <b>स्थायी पट्टे का निष्पादन, अग्रिम आधिपत्य तथा समर्पण</b>	
61.	प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक जमा करना	
62.	पट्टे का निष्पादन तथा भू-अभिलेखों में प्रविष्टियों का अद्यतनीकरण	
63.	भूमि का आधिपत्य देना	
64.	पट्टे का आरंभ और भू-भाटक की देयता	
65.	स्थायी पट्टे की अवधि	
66.	स्थायी पट्टा समर्पण या पुनर्प्रवेश के मामले में प्रब्याजि वापसी	
67.	सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व	
68.	गृह निर्माण सहकारी समितियों के उपपट्टेदारों के मामलों में कार्यवाही	
	<b>भाग — ज</b> <b>भूमि के अग्रिम आधिपत्य देने पर प्रतिबंध तथा अग्रिम आधिपत्य के पुराने मामलों में भूमि का आवंटन, प्रब्याजि व वार्षिक भू-भाटक का अधिरोपण तथा पट्टा निष्पादन</b>	
69.	भूमि के अग्रिम आधिपत्य देने पर प्रतिबंध	
70.	इस भाग के प्रावधानों का लागू होना	
71.	प्रब्याजि का निर्धारण	
72.	वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण	
73.	वार्षिक भू-भाटक की गणना की प्रक्रिया	
74.	आवंटिति संस्था द्वारा प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक की उप पट्टेदार से वसूली	
75.	पट्टे का निष्पादन	
76.	इस भाग का पूर्व में निवर्तित मामलों में लागू न होना	
	<b>भाग — झ</b> <b>स्थायी पट्टे का नवीनीकरण</b>	
77.	स्थायी पट्टे के नवीनीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी	

78.	स्थायी पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन	
79.	नजूल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना	
80.	स्थायी पट्टे की शर्त का उल्लंघन या अपालन न होने की दशा में पट्टे का नवीनीकरण	
81.	स्थायी पट्टे के नवीनीकरण पर वार्षिक भू-भाटक का पुनर्निर्धारण	
82.	स्थायी पट्टे की शर्त का उल्लंघन या अपालन होने की दशा में पट्टे का नवीनीकरण	
83.	भूखण्ड के भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए आवेदन	
84.	भूखण्ड में अनुमत क्षेत्रफल से अधिक निर्माण के मामलों में कार्यवाही	
85.	पट्टे की अन्य शर्तों के उल्लंघन के मामलों में कार्यवाही	
86.	नवीनीकरण के पूर्व नामांतरण की कार्यवाही करना	
87.	शमन राशि का जमा किया जाना	
88.	पट्टावधि के दौरान भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाना	
89.	पट्टावधि के अवसान पर नवीकृत पट्टा विलेख का निष्पादन तथा पंजीयन	
<b>भाग — अ अस्थायी पट्टे</b>		
90.	वर्तमान अस्थायी पट्टों का निराकरण	
<b>अध्याय — चार स्थानीय निकाय को तथा विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि दी जाना भाग— क नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि का आवंटन</b>		
91.	सक्षम प्राधिकारी	
92.	प्रयोजन	
93.	भूमि का चिन्हांकन तथा आवेदन	
94.	जांच प्रतिवेदन	
95.	नगरीय निकाय को नजूल भूमि भूमिस्वामी अधिकार में आवंटित करने की स्वीकृति	

96.	प्रब्याजि तथा भू-राजस्व	
97.	आवंटन आदेश एवं भू-अभिलेखों की प्रविष्टियों का	अद्यतनीकरण
	<b>भाग - ख</b> <b>स्थानीय निकाय को ध्वजदंड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन</b>	
98.	सक्षम प्राधिकारी	
99.	भूमि का आकार	
100.	आवंटन की प्रक्रिया	
101.	जांच प्रतिवेदन	
102.	जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय और भू-राजस्व की देयता	
103.	भूमि का कब्जा सौंपना	
	<b>भाग - ग</b> <b>विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि का आवंटन</b>	
104.	सक्षम प्राधिकारी	
105.	प्रयोजन, प्रब्याजि तथा भू-राजस्व	
106.	भूमि आवंटन के लिए आवेदन	
107.	जांच प्रतिवेदन	
108.	विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को नजूल भूमि भूमिस्वामी हक में आवंटित करने की स्वीकृति	
109.	आवंटन आदेश एवं भू-अभिलेखों में प्रविष्टियों का	अद्यतनीकरण
	<b>अध्याय - पांच</b> <b>नजूल भूमि का नीलामी द्वारा भूमिस्वामी हक में निर्वर्तन</b>	
110.	नीलामी द्वारा नजूल भूमि के निर्वर्तन के लिए भूमि का चयन	
111.	नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिए भूमि का चयन करने एवं नीलाम करने	

	के लिए सक्षम प्राधिकारी	
112.	नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिए भूमि के चयन के लिए प्रतिवेदन तैयार करना	
113.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी द्वारा निर्वर्तन हेतु भूमि के चयन की स्वीकृति	
114.	चयनित भूमि के क्षेत्रफल का सत्यापन एवं सीमांकन	
115.	नीलामी की प्रक्रिया	
116.	निविदा में भाग लेने हेतु पात्रता	
117.	निविदाओं का परीक्षण एवं निराकरण	
118.	भू-राजस्व	
119.	विक्रय विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जे का प्रदाय	
120.	वित्तीय प्रावधान	
	<b>अध्याय – छः लाइसेंस</b>	
121.	प्रयोजन जिनके लिए नजूल भूमि लाइसेंस पर दी जा सकती है	
122.	सक्षम प्राधिकारी	
123.	पुल, पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली निर्माण के लिये लाइसेंस की अहर्ताएँ और शर्तें	
124.	गौशाला के लिए लाइसेंस	
125.	लाइसेंस के लिये आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क	
126.	लाइसेंस फीस	
127.	लाइसेंस का प्ररूप	
	<b>अध्याय – सात भूमिस्वामी हक में कृषि प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन</b>	
128.	सक्षम प्राधिकारी	
129.	आवंटन के लिए पात्रता	
130.	वंटन के लिए भूमि	
131.	पात्रता में प्राथमिकता क्रम	
132.	कृषि प्रयोजन के लिए आवंटन की सीमा	

133.	आवंटन की प्रक्रिया	
134.	आवंटित कृषि भूमि पर भू-राजस्व का निर्धारण	
135.	भूमिस्वामी अधिकार पत्र	
136.	भू-अभिलेख में प्रविष्टि	
	<b>अध्याय – आठ</b> <b>स्थायी पट्टे का भूमिस्वामी हक में संपरिवर्तन</b>	
137.	स्थायी पट्टाधिकार का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन	
138.	संपरिवर्तन की प्रक्रिया	
139.	संपरिवर्तन प्रभार	
140.	हस्तांतरण विलेख	
141.	भू-राजस्व	
	<b>अध्याय – नौ</b> <b>प्रकीर्ण</b>	
142.	सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करने की रीति	
143.	नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र	
144.	शासकीय निर्माण कार्य के लिए निजी भूमि का विनिमय	शासकीय भूमि से
145.	अभ्यावेदन	
146.	स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण	
147.	नजूल भूमि के निर्वर्तन के मामलों में प्राप्त राशि जमा किया जाना	शासकीय खजाने में
148.	निरसन तथा व्यावृत्ति	
	<b>परिशिष्ट</b>	
परिशिष्ट 'क'	नजूल भूमि के निर्वर्तन के मामलों में प्राप्त राशि जमा करने की मदें	शासकीय खजाने में

	प्ररूप	
प्ररूप एक	नजूल भूमि के हस्तांतरण/आवंटन के लिए आवेदन का प्ररूप	
प्ररूप दो	नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जांच प्रतिवेदन का प्ररूप	
प्ररूप तीन	नजूल भूमि का स्थायी पट्टा	
प्ररूप चार	मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत अस्थायी पट्टाधिकार में परिवर्तन हेतु आवेदन	
प्ररूप पांच	नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र को नजूल भूमि का भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन	विकास प्राधिकरण आदेश का प्ररूप
प्ररूप छह	मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख	अंतर्गत निष्पादित
प्ररूप सात	नजूल अधिकारी द्वारा नीलामी के लिये भूमि के चयन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन का प्ररूप	
प्ररूप आठ	नजूल भूमि के नीलामी द्वारा निर्वर्तन की सार्वजनिक उद्घोषणा का प्ररूप	
प्ररूप नौ	नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नजूल भूमि की ई-नीलामी की कार्यवाही का प्रतिवेदन	
प्ररूप दस	भूमि प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नजूल भूमि की ई-नीलामी का प्रतिवेदन	
प्ररूप ग्यारह	नजूल भूमि का नीलामी द्वारा निर्वर्तन – विक्रय विलेख	
प्ररूप बारह	नजूल भूमि पर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) हेतु आवेदन	
प्ररूप तेरह	नजूल भूमि पर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)	
प्ररूप चौदह	मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अध्याय सात 'भूमिस्वामी हक में कृषि प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन' के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार पत्र	
प्ररूप पंद्रह	मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत स्थायी पट्टाधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन हेतु आवेदन	
प्ररूप सौलह	मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत निष्पादित हस्तांतरण-विलेख	
प्ररूप सत्रह	नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र	
प्ररूप अठारह	नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र	



**मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक एफ 6-75/2019/सात/शा.3

भोपाल दिनांक ....., 2023

**राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार कमांक 1  
मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020  
तृतीय संस्करण, वर्ष 2023**

**अध्याय – एक  
सामान्य**

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना—** (1) इन निर्देशों का नाम मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा।

<sup>1</sup>(3) ये निर्देश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे, परन्तु राज्य सरकार की किसी योजना अंतर्गत सक्षम स्तर से, ऐसी योजना में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, भूमि के निर्वर्तन के मामले में ये निर्देश लागू नहीं होंगे।

**2. इन निर्देशों में संशोधन की प्रक्रिया—** (1) इन निर्देशों में किए जाने वाले प्रत्येक संशोधन, परिवर्धन या विलोपन को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा उसे पहचान के लिए एक सरल कमांक तथा दिनांक दिया जाएगा।

(2) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में यथासम्भव जनवरी माह में पिछले वर्ष तक जारी किए गए समस्त संशोधनों के प्रावधानों को समाहित करते हुए इन निर्देशों का अद्यतन संस्करण जारी किया जाएगा।

**3. परिभाषाएं—** (1) इन निर्देशों में, जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो,—

1. म.प्र. राजपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2021 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना कमांक 6-75/2019/सात-3 दि. 3 अगस्त, 2021 संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित
---

- (क) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
- (ख) 'विकास योजना' या 'मास्टर प्लान' से अभिप्रेत है, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (छ) में परिभाषित विकास योजना;
- (ग) 'नजूल भूमि' के अंतर्गत है, संहिता की धारा 2 (1) (य-3) में यथापरिभाषित समस्त दखलरहित भूमि तथा राज्य शासन के द्वारा गैर-कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई भूमि :

परन्तु नगरेतर क्षेत्र में संहिता की धारा 237 के अंतर्गत निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक् रखी गई भूमि तथा धारा 233-क के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई भूमि नजूल भूमि नहीं है;

- (घ) 'नजूल अधिकारी' से अभिप्रेत है, ऐसा उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जिसे किसी स्थानीय क्षेत्र में इन निर्देशों द्वारा नजूल अधिकारी को प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने तथा इन निर्देशों द्वारा नजूल अधिकारी पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कलेक्टर, राज्य शासन द्वारा अधिरोपित किए गए किन्हीं साधारण या विशेष निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करे;
- (ङ) 'लैण्ड बैंक' से अभिप्रेत है, कंडिका 6 के उपबंधों के अधीन आयुक्त, भू-अभिलेख की वेबसाइट [mpbhulekh.gov.in](http://mpbhulekh.gov.in) पर प्रदर्शित लैण्ड बैंक;
- (च) 'बाजार मूल्य' से अभिप्रेत है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन बनाए गए "मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000" के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य;

परन्तु यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्तानुसार बाजार मूल्य उपलब्ध न हो तो प्रश्नाधीन भूमि के निकट की समान आकार व प्रयोजन की भूमि के उस वर्ष की बिक्री-छांट के आधार पर परिगणित मूल्य;

- (छ) 'पूर्त प्रयोजन' (Charitable Purpose) से अभिप्रेत है शारीरिक और/अथवा मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिये संस्था/अनाथ आश्रम स्थापित करना, लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास

स्थापित करना, वृद्धाश्रम स्थापित करना, स्कूल शिक्षा/कौशल विकास गतिविधियों के लिये संस्था स्थापित करना, खेलकूद संबंधी सुविधाएं विकसित करना और ऐसा ही कोई अन्य प्रयोजन जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा अधिसूचित करे, या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (15) में परिभाषित पूर्त प्रयोजन;

(ज) 'पूर्ण संस्था' (Charitable Institution) से अभिप्रेत है पूर्त प्रयोजन से संबंधित गतिविधियां संचालित करने वाली संस्था जो आवेदन की दिनांक से तीन वर्ष पूर्व से सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीकृत है (जैसे— मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 आदि);

(झ) 'आदिम जनजाति' से तात्पर्य किसी ऐसी जाति से है, जिसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में आदिम जनजाति घोषित किया गया हो;

(ञ) 'अनुसूचित जाति' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों में से किसी अनुसूचित जाति का हो;

(ट) 'पिछड़ा वर्ग' से तात्पर्य ऐसी जाति से है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16 (4) में विहित निर्देशों की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया हो;

(ठ) 'भूमिहीन व्यक्ति' से तात्पर्य ऐसे वास्तविक कृषक या कृषि श्रमिक से है जो राज्य के किसी नगरेतर क्षेत्र में कम से कम 12 वर्ष से निवासरत हो तथा जिसके पास अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के पास संयुक्त रूप से या पृथकतः 01 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं हो; और

(ड) 'कुटुम्ब' में वह स्वयं, उसकी पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, माता या पिता सम्मिलित माने जाएंगे।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन निर्देशों में प्रयोग में लाई गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वहीं अर्थ होंगे जो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उनके लिये दिये गये हैं।

**4. नजूल भूमि के अभिलेखों का निर्माण तथा संधारण—** नजूल भूमि के अभिलेखों के निर्माण तथा संधारण का कार्य आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार संपादित किया जाएगा।

**5. लोक प्रयोजन के लिये भूमि का पृथक् रखा जाना—** (1) कलेक्टर, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 233-क तथा राज्य शासन द्वारा इस निमित्त जारी निर्देशों के अनुसार, किसी नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि पृथक् रख सकेगा, उस लोक प्रयोजन को परिवर्तित कर सकेगा जिसके लिए वह भूमि पृथक् रखी गई है अथवा पृथक् रखने की कार्यवाही समाप्त कर सकेगा :

परन्तु कोई भूमि ऐसे प्रयोजन के लिए पृथक् नहीं रखी जाएगी, जो कि अनुमोदित विकास योजना से असंगत है।

(2) धारा 233-क के अंतर्गत किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई भूमि का निर्वर्तन केवल उसी लोक प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा।

**6. लैण्ड बैंक—** (1) समस्त नजूल भूमि के विस्तृत विवरण, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा उनके कार्यालय की वेबसाइट [mpbhulekh.gov.in](http://mpbhulekh.gov.in) पर प्रदर्शित किये जाएंगे। इन विवरणों में भूमि की नोडियत तथा विकास योजना (मास्टर प्लान) में उल्लेखित भूमि उपयोग यदि कोई निर्धारित है, और यदि एक से अधिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग किया जा सकता है, तो सभी अनुज्ञेय उपयोगों का उल्लेख भी किया जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध उक्त जानकारी को इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए 'लैण्ड बैंक' कहा जाएगा।

**स्पष्टीकरण—** यद्यपि वेबसाइट पर प्रदर्शित लैण्ड बैंक में उल्लेखित भूमियों के लिए भूमि उपयोग का उल्लेख होगा तथापि लैण्ड बैंक में दर्शित भूमियों के लिये भूमि उपयोग तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में निर्धारित भूमि उपयोग ही मान्य होगा।

(2) नजूल भूमि का निर्वर्तन किए जाने अथवा निर्वर्तित भूमि पर शासन द्वारा पुनर्प्रवेश की कार्यवाही से वापिस प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों के अनुरूप लैण्ड बैंक की प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी।

**7. संहिता का लागू होना—** यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 नजूल भूमि पर भी लागू होती है। इसलिए नजूल भूमि के संबंध में प्रसंग अनुसार संहिता तथा उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

**8. नजूल भूमि के निर्वर्तन के लिए जिला, संभाग तथा राज्य स्तर पर समितियाँ—**

(1) नजूल भूमि के निर्वर्तन के संबंध में निर्णय लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार समितियाँ होंगी—

- (क) जिला नजूल निर्वर्तन समिति;  
 (ख) संभाग नजूल निर्वर्तन समिति;  
 (ग) राज्य नजूल निर्वर्तन समिति; और  
 (घ) 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति'।

(2) इन समितियों का गठन उपकंडिका (3), (4), (5), तथा (6) के अनुसार हं तथा उनके द्वारा ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाएगा जो इन निर्देशों उन पर अधिरोपित किए गए हैं तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा जो निर्देशों में उन्हें प्रदत्त की गई हैं।

(3) जिला नजूल निर्वर्तन समिति निम्न से मिलकर बनेगी—

- |  |               |
|--|---------------|
| (क) कलेक्टर  | अध्यक्ष       |
| (ख) उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश                  | सदस्य         |
| (ग) जिला पंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन                             | सदस्य         |
| (घ) संबंधित आयुक्त नगरनिगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी               | सदस्य         |
| (नगरीय क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि के मामलों में)                |               |
| (ङ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत                         | सदस्य         |
| (ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भूमि के मामलों में)                   |               |
| (च) उपखण्ड अधिकारी (जिस उपखण्ड में भूमि स्थित है)                | सदस्य         |
| (छ) अध्यक्ष की अनुमति से आमंत्रित                                | सदस्य         |
| (ज) कलेक्टर कार्यालय में नजूल शाखा का प्रभारी संयुक्त/उप कलेक्टर | सदस्य<br>सचिव |

(4) संभाग नजूल निर्वर्तन समिति निम्न से मिलकर बनेगी—

- |   |         |
|---|---------|
| (क) आयुक्त                                      | अध्यक्ष |
| (ख) अपर आयुक्त                                  | सदस्य   |
| (ग) नगर तथा ग्राम निवेश का संभाग स्तरीय अधिकारी | सदस्य   |

(घ) संभाग मुख्यालय के जिले में पदस्थ जिला पंजीयक	सदस्य
(च) अध्यक्ष की अनुमति से आमंत्रित	सदस्य
(छ) उपायुक्त राजस्व	सदस्य
	सचिव

**स्पष्टीकरण—** किसी संभाग में एक से अधिक अपर आयुक्त होने की दशा में ऐसा अपर आयुक्त जिसे आयुक्त द्वारा नाम निर्देशित किया जाए, संभाग नजूल निर्वर्तन समिति का सदस्य होगा।

(5) राज्य नजूल निर्वर्तन समिति निम्न से मिलकर बनेगी—

(क) मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	अध्यक्ष
(ख) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	सदस्य
(ग) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	सदस्य
(घ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग	सदस्य
(ङ) मामले से संबंधित मध्यप्रदेश शासन के विभाग का सचिव	सदस्य
(च) आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य
(छ) आयुक्त, भू-अभिलेख	सदस्य
(ज) प्रमुख राजस्व आयुक्त	सदस्य
(झ) अपर/उप सचिव, राजस्व विभाग (संबंधित शाखा)	सदस्य सचिव

(6) 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति' —

(क) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ख) सचिव, वित्त	सदस्य
(ग) सचिव, नगरीय विकास एवं आवास	सदस्य
(घ) अन्य आमंत्रित	सदस्य

(ड) सचिव, राजस्व

सदस्य  
सचिव**स्पष्टीकरण—**

1. सचिव, राजस्व विभाग से अभिप्रेत है, राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव
2. वित्त विभाग, नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग तथा अन्य विभाग के सचिव से अभिप्रेत है, उस विभाग द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अथवा सचिव।

(7) जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय अनुसार यथास्थिति आवंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का आदेश कलेक्टर जारी करेगा। इसी प्रकार संभाग नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय अनुसार यथास्थिति आवंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का आदेश संभागायुक्त जारी करेगा और राज्य नजूल निर्वर्तन समिति अथवा 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति' के निर्णय अनुसार यथास्थिति आवंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का शासनादेश राजस्व विभाग जारी करेगा।

**9. अपर आयुक्त तथा अपर कलेक्टर को शक्तियों का प्रत्यायोजन—** आयुक्त या कलेक्टर नजूल भूमि के संबंध में इन निर्देशों के द्वारा उसे प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा इन निर्देशों के द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए यथास्थिति अपर आयुक्त या अपर कलेक्टर को लिखित आदेश के द्वारा निर्देशित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे:

परन्तु निम्नलिखित वर्गों के मामलों में आयुक्त या कलेक्टर के द्वारा कृत्यों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग सदैव स्वयं ही किया जाएगा—

- (क) यथास्थिति संभाग नजूल निर्वर्तन समिति अथवा जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक की अध्यक्षता करना;
- (ख) नजूल भूमि नीलामी के द्वारा भूमिस्वामी हक में दिये जाने की स्वीकृति/अस्वीकृति का आदेश जारी करना;
- (ग) नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दिये जाने की स्वीकृति/अस्वीकृति का आदेश जारी करना;
- (घ) राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण करने या उससे अनुपयोगी भूमि वापिस लेने का आदेश जारी करना;
- (ङ) नगरीय निकाय को नजूल भूमि भूमिस्वामी हक में दिये जाने की स्वीकृति/अस्वीकृति का आदेश जारी करना;

- (च) भारत शासन या उसके उपक्रम को नजूल भूमि का स्थायी पट्टे पर आवंटन करने की स्वीकृति/अस्वीकृति का आदेश जारी करना;
- (छ) नजूल भूमि के संबंध में वरिष्ठ स्तर को प्रस्ताव, प्रतिवेदन या अभिमत प्रेषित करना; और
- (ज) **कंडिका 90 की उपकंडिका (4)** के अंतर्गत अस्थायी पट्टे को स्थायी पट्टे में परिवर्तित करना।

**10. नजूल भूमि के निर्वर्तन के तरीके—** (1) इन निर्देशों के प्रभावशील होने के बाद नजूल भूमि का निर्वर्तन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकेगा—

- (क) राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरण द्वारा;
- (ख) स्थायी पट्टे पर दी जाना;
- (ग) स्थानीय निकाय को भूमिस्वामी अधिकार में दी जाना;
- (घ) नीलामी द्वारा भूमिस्वामी अधिकार में दी जाना;
- (ङ) लाइसेंस पर दी जाना; और
- (च) कृषि प्रयोजन हेतु भूमिस्वामी अधिकार में दी जाना।

(2) इन निर्देशों में किसी बात के होते हुये भी, पंचमढ़ी में राज्य शासन की अनुमति के बिना नजूल भूमि का निर्वर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि के हस्तांतरण किये जाने, स्थायी पट्टे पर दिये जाने या भूमिस्वामी हक में निर्वर्तित किये जाने की कार्यवाही **कंडिका 8 की उपकंडिका (6)** में गठित समिति द्वारा की जाएगी।



## अध्याय – दो

### राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण

**11. सक्षम प्राधिकारी—** राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि हस्तांतरित करने के लिए या किसी विभाग को हस्तांतरित भूमि राजस्व विभाग को वापस करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति', संभाग मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति होगा।

**12. भूमि का चिन्हांकन तथा आवेदन—** संबंधित विभाग के द्वारा लैण्ड बैंक में से भूमि का चयन किया जाएगा। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा कलेक्टर को प्ररूप एक में आवेदन किया जाएगा। किसी विभाग का विभागाध्यक्ष न होने की स्थिति में विभाग के सचिव द्वारा आवेदन किया जाएगा।

**13. जांच प्रतिवेदन—** (1) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर आवेदन पत्र अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा। स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे और यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित हस्तांतरण में कोई आपत्ति नहीं है।

(3) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा—

(क) तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नहीं? ;

- (ख) भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन;
- (ग) आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता; और
- (घ) क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

(4) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रारूप दो में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा।

**14. भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति—** (1) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर आवेदक विभाग को सूचित किया जाएगा और जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा अपने अभिमत के साथ मामला उसे प्रेषित किया जाएगा।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक विभाग तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा:

परन्तु भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित भूमियों के मामले में "भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" सक्षम प्राधिकारी है अतः भोपाल संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपने अभिमत के साथ मामला उक्त समिति को प्रेषित किया जाएगा।

**15. सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन—** सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई विभाग ऐसे निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के भीतर राज्य शासन के राजस्व विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा जो सुसंगत दस्तावेज प्राप्त कर तथा संबंधित विभागों से परामर्श कर अभ्यावेदन का निराकरण करेगा।

**16. विभाग को भूमि का हस्तांतरण—** सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर कलेक्टर के द्वारा विभाग को भूमि का हस्तांतरण कर कब्जा सौंपा जाएगा।

**17. हस्तांतरण की गई भूमि पर कर निर्धारण—** राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा।

**18. राज्य शासन के किसी विभाग से अनुपयोगी भूमि का वापस लिया जाना— (1)** सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर जिले में स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों, कार्यस्थलों, योजनाओं या परियोजनाओं आदि के लिए उन्हें पूर्व में आवंटित की गई, उपयोग में लाई गई तथा शेष भूमियों की जानकारी संकलित करेगा एवं वर्तमान समय के संदर्भ में विभागों को भूमि की आवश्यकता की समीक्षा करेगा।

(2) विभाग के कार्यालयों, कार्यस्थलों, योजनाओं या परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का आकलन मानक मापदंडों पर किया जाएगा। मानक मापदंड न होने की स्थिति में युक्तियुक्त मापदंडों का प्रयोग किया जाएगा। पूर्व से निर्मित या प्रस्तावित संरचना के लिए भूमि की आवश्यकता के आकलन में क्षितिजीय प्रसार (horizontal spread) के स्थान पर ऊर्ध्वाधर रचना (vertical rise) की संभावना पर भी विचार किया जाएगा।

(3) समीक्षा उपरांत सक्षम प्राधिकारी राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित भूमि अंशतः या पूर्णतः राजस्व विभाग को वापिस करने का निर्णय कर सकेगा।

(4) यदि संबंधित विभाग सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित है तो वह राज्य शासन के राजस्व विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा जो सुसंगत दस्तावेज प्राप्त कर व संबंधित विभागों से परामर्श कर अभ्यावेदन का निराकरण करेगा।

## अध्याय – तीन स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि का निर्वर्तन

### भाग – क स्थायी पट्टे पर निर्वर्तन – सामान्य

**19. प्रयोजन, सक्षम प्राधिकारी, प्रब्याजि (Premium), वार्षिक भू-भाटक (Annual Lease-rent) तथा आवंटन की प्रक्रिया—** (1) इन निर्देशों के प्रभावशील होने के बाद नजूल भूमि का स्थायी पट्टे पर निर्वर्तन नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। इन मामलों में स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी, प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक तथा आवंटन की प्रक्रिया तालिका के क्रमशः कालम (3), (4), (5) तथा (6) अनुसार होंगे—

#### तालिका

**स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि दिए जाने के प्रयोजन, सक्षम प्राधिकारी, प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक तथा आवंटन प्रक्रिया**

सरल क्रमांक	प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाना है	स्वीकृति हेतु *सक्षम प्राधिकारी (मोपाल विकास योजना क्षेत्र को छोड़कर)	प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)	वार्षिक भू-भाटक	आवंटन की प्रक्रिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रेलवे मंत्रालय अथवा नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यथास्थिति—  (क) रेल मार्ग निर्माण हेतु केवल रेल लाइन निर्माण के लिए आवश्यक भूमि  (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण अथवा पूर्व निर्मित सड़क के चौड़ीकरण के लिए	1. संभाग मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति  2. अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति	शून्य  शून्य	1/—  (एक रुपया)  1/—  (एक रुपया)	सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)

सरल क्रमांक	प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाना है	स्वीकृति हेतु *सक्षम प्राधिकारी (मोपाल विकास योजना क्षेत्र को छोड़कर)	प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)	वार्षिक भू-भाटक	आवंटन की प्रक्रिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	आवश्यक भूमि				
2	केन्द्र सरकार के किसी विभाग या उपक्रम को पूर्ण प्रब्याजि व भू-भाटक पर	राज्य नजूल निर्वर्तन समिति	100 प्रतिशत	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना	सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)
3	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण				
	(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रयोजित ई.डब्ल्यू.एस. या कमजोर वर्ग के लिये आवासीय योजना अंतर्गत  (ख) ई.डब्ल्यू.एस. या कमजोर वर्ग के आवासीय प्रयोजन के	1. संभागीय मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति  2. अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में	शून्य        50 प्रतिशत	1/- (एक रुपया)       मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता	सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)

सरल क्रमांक	प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाना है	स्वीकृति हेतु *सक्षम प्राधिकारी (भोपाल विकास योजना क्षेत्र को छोड़कर)	प्रव्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)	वार्षिक भू-भाटक	आवंटन की प्रक्रिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	लिए  (ग) व्यावसायिक प्रयोजन के लिए (घ) उपरोक्त खण्ड (क), (ख) तथा खण्ड (ग) को छोड़कर अन्य मामले में	जिला नजूल निर्वर्तन समिति  राज्य नजूल निर्वर्तन समिति  राज्य नजूल निर्वर्तन समिति	  100 प्रतिशत  60 प्रतिशत	(भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना  —तथैव—  —तथैव—	-
4	राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं नियंत्रित कृषि उपज मंडी समिति को मंडी प्रांगण के लिए  (मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 के नियम 3 के अनुसार वर्गीकृत मंडी समितियों के लिये)	1. संभाग मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति  2. अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति	प्रथम वर्ग मंडी समिति के लिये 50 प्रतिशत  द्वितीय वर्ग मंडी समिति के लिये 40 प्रतिशत  तृतीय वर्ग मंडी समिति के लिये 30 प्रतिशत	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना	सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)

सरल क्रमांक	प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाना है	स्वीकृति हेतु *सक्षम प्राधिकारी (भोपाल विकास योजना क्षेत्र को छोड़कर)	प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)	वार्षिक भू-भाटक	आवंटन की प्रक्रिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			चतुर्थ वर्ग मंडी समिति के लिये 20 प्रतिशत		
5	स्टेट वेयर हाउसिंग एवं सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन तथा फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के गोदामों के लिए	राज्य नजूल निर्वर्तन समिति	75 प्रतिशत	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना	सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)
6	नवोदय के मामले में अधिकतम 10 हेक्टेयर या केन्द्र सरकार द्वारा नियत मानदण्ड अनुसार में से जो कम हो और केन्द्रीय विद्यालयों के मामलों में अधिकतम 2 हेक्टेयर या केन्द्र सरकार द्वारा नियत मानदण्ड अनुसार में से जो कम हो	1. संभाग मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति 2. अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति	शून्य	1/- (एक रुपया)	सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)

सरल क्रमांक	प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाना है	स्वीकृति हेतु *सक्षम प्राधिकारी (भोपाल विकास योजना क्षेत्र को छोड़कर)	प्रस्ताजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)	वार्षिक भू-माटक	आवंटन की प्रक्रिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	सहकारी बैंकों को (क) नगरीय क्षेत्र में  (ख) नगरेतर क्षेत्र में	राज्य नजूल निर्वर्तन समिति  1. संभागीय मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति  2. अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति	50 प्रतिशत  50 प्रतिशत	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना	सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)
8	पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय भवन के लिए	1. संभाग मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति  2. अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति	शून्य	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना	सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)
9	राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं नियंत्रित दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध	राज्य नजूल निर्वर्तन समिति	50 प्रतिशत	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता	सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख)



सरल क्रमांक	प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पदटे पर दी जाना है	स्वीकृति हेतु *सक्षम प्राधिकारी (भोपाल विकास योजना क्षेत्र को छोड़कर)	प्रव्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)	वार्षिक भू-भाटक	आवंटन की प्रक्रिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	संग्रह या शीत केन्द्र के लिए			(भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना	अनुसार)
10	युद्ध में मृत सैनिकों के परिवारों को आवासीय प्रयोजन के लिए (क) कमीशनड अधिकारी के मामले में 220 वर्गमीटर तक (ख) अन्य मामले में 140 वर्गमीटर तक	राज्य नजूल निर्वर्तन समिति	शून्य	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना	सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)
11	पूर्त संस्था को	भाग-ग अनुसार	भाग-ग अनुसार	भाग-ग अनुसार	भाग-ग अनुसार
12	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल को कार्यालय भवन निर्माण भूमि के लिए	भाग-घ अनुसार	भाग-घ अनुसार	भाग-घ अनुसार	भाग-घ अनुसार
13	मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन या पारेषण	भाग-ड	भाग-ड	भाग-ड	भाग-ड

सरल क्रमांक	प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाना है	स्वीकृति हेतु *सक्षम प्राधिकारी (भोपाल विकास योजना क्षेत्र को छोड़कर)	प्रव्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)	वार्षिक भू-भाटक	आवंटन की प्रक्रिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	तथा वितरण कम्पनियों को भूमि का आवंटन	अनुसार	अनुसार	अनुसार	अनुसार
14	चहुँमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में भूमि का आवंटन	भाग-च अनुसार	भाग-च अनुसार	भाग-च अनुसार	भाग-च अनुसार

\* इन निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी, भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमियों के निर्वर्तन के लिये उक्त तालिका में विहित उपबंधों के अध्याधीन सक्षम प्राधिकारी "भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" होगी।

(2) जिन मामलों में वार्षिक भू-भाटक मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना रखा गया है उनमें पट्टे की अवधि के दौरान जब-जब भी राज्य शासन के द्वारा निर्धारण दरों में परिवर्तन अधिसूचित किया जाएगा, तब-तब पट्टे का वार्षिक भू-भाटक भी ऐसी पुनरीक्षित निर्धारण दरों के दो गुना स्वयमेव निर्धारित हुआ समझा जाएगा।

(3) इन निर्देशों के पूर्व जारी पट्टों के मामले में भू-भाटक संबंधित पट्टे की शेष अवधि तक पूर्वानुसार देय होगा तथा पट्टे के नवीनीकरण के समय कंडिका 81 के उपबंध अनुसार भू-भाटक पुनर्निर्धारित होगा।

## भाग – ख स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन की सामान्य प्रक्रिया

**20. इस भाग के उपबंधों का लागू होना—** स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन की सामान्य प्रक्रिया इस भाग के उपबंधों के अनुसार होगी, परन्तु भाग—ग, घ, ङ तथा च के अंतर्गत आने वाले मामलों में उस भाग में विहित की गई प्रक्रिया के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

**21. भूमि आवंटन के लिए आवेदन—** (1) स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन के लिए प्ररूप एक में आवेदन पत्र कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

**22. जांच प्रतिवेदन—** (1) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर आवेदन पत्र अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

(3) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, आवेदक के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा।

(4) नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा। स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे, यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है।

(5) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा—

- (क) तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नहीं? ;
- (ख) भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन;
- (ग) आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता; और
- (घ) क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

(6) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा।

**23. स्थायी पट्टे की स्वीकृति—** (1) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर आवेदक को सूचित किया जाएगा। जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति या राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या "भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा अपने अभिमत के साथ मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा। जिस मामले में राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या "भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला यथास्थिति राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या "भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" को प्रेषित किया जाएगा।

(3) जिस मामले में राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति' स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें ऐसी समिति द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामलों में निर्णय लिया जाकर आवेदक, जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा।

**24. प्रब्याजि तथा भू-भाटक—** (1) इस भाग के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले स्थायी पट्टों पर प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक **कंडिका 19 की उपकंडिका (1)** में दी गई तालिका के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा।

(2) पट्टे की अवधि के दौरान वार्षिक भू-भाटक के संबंध में **कंडिका 19 की उपकंडिका (2)** के प्रावधान लागू होंगे।

**25. पट्टे का निष्पादन—** सक्षम प्राधिकारी से पट्टे की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् पट्टे के निष्पादन की कार्यवाही इस अध्याय के **भाग- छ** के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

## भाग - ग

## पूर्ण संस्था को पूर्ण प्रयोजन के लिये स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन

**26. सक्षम प्राधिकारी—** पूर्ण (charitable) संस्था को पूर्ण प्रयोजन के लिये स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि का आवंटन करने के मामले में सक्षम प्राधिकारी राज्य नजूल निर्वर्तन समिति होगी:

परंतु भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के आवंटन के मामले में सक्षम प्राधिकारी “भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति” होगी:

परंतु यह और कि ऐसे मामले में, जिनमें एक ही भूखण्ड के लिये एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं, निर्वर्तन का निर्णय राज्य के मंत्री-परिषद द्वारा लिया जाएगा।

**27. भूमि आवंटन के लिये अर्हताएँ—** (1) केवल ऐसी पूर्ण संस्था को पूर्ण प्रयोजन के लिये स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटित की जाएगी जो—

(क) आवेदन की दिनांक से तीन वर्ष पूर्व से सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीकृत है (जैसे— मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 आदि);

(ख) संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता हो;

परन्तु यदि कोई संस्था जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर अपनी गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में भेदभाव नहीं करती हो तो केवल इस कारण से कि संस्था के नाम में किसी जाति, समुदाय या धर्म का उल्लेख है, उसे अनर्ह नहीं समझा जायेगा।

(ग) संस्था की आय तथा आस्तियां उन्हीं उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त किये जाते हों जो कि उसके उद्देश्यों तथा उपविधियों में वर्णित हों;

(घ) ऐसी संस्था कंडिका (3) के खण्ड (ज) में परिभाषित पूर्ण संस्था हो;

(ङ) आवेदन की दिनांक से ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों में संस्था के द्वारा अपने उद्देश्यों पर औसतन रुपए पांच लाख वार्षिक व्यय किया गया हो तथा आयकर विवरणियां दाखिल की गई हों;

- (च) संस्था के पास न्यूनतम रुपए दस लाख या आवेदित भूखण्ड के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि के बराबर, इनमें से जो कम हो, की कॉरपस निधि (Corpus fund) हो;
- (छ) संस्था की आय का कोई अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके सदस्यों, संचालकों, संस्थापकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों को वितरित नहीं किया जाता हो या किये जाने योग्य नहीं हो; और
- (ज) संस्था की उपविधियों के अनुसार संस्था के परिसमापन पर उसकी निबल आस्तियां (Net assets) उसकी देनदारियों की पूर्ति के उपरांत उसके सदस्यों, संचालकों, संस्थापकों व दानदाताओं को वापस नहीं होती हों।

(2) किसी भी ऐसी संस्था को एक नगरीय क्षेत्र या ग्राम में एक से अधिक स्थानों पर भूमि आवंटित नहीं की जाएगी।

**28. भूमि आवंटन के लिये आवेदन—** (1) आवेदक संस्था द्वारा लैण्ड बैंक में से भूमि का चयन कर कलेक्टर को प्ररूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

**29. परीक्षण तथा जांच प्रतिवेदन—** (1) कलेक्टर आवेदन पत्र का संक्षिप्त परीक्षण कर लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के आधार पर उसे अमान्य कर सकेगा।

(2) उपकंडिका (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र अमान्य न किये जाने की दशा में उसे संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित किया जाएगा।

(3) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

(4) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, आवेदक संस्था के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा।

(5) सार्वजनिक उद्घोषणा में यह भी लिखा जाएगा कि यदि कोई अन्य पूर्ण संस्था आवेदित भूमि का आवंटन चाहती है तो वह उद्घोषणा में उल्लेखित अंतिम तिथि तक प्ररूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगी। ऐसी अन्य संस्था द्वारा प्रक्रिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(6) नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग का अभिमत प्राप्त किया जाएगा। स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे, यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है।

(7) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा—

- (क) तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नहीं? ;
- (ख) भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन;
- (ग) आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता; और
- (घ) क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

(8) यदि किसी भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए अर्हता रखने वाली एक से अधिक संस्थाएँ आवेदन करती हैं तो उनमें से चयन करने हेतु निम्न मानदण्डों का उपयोग किया जा सकेगा—



- (क) संस्थाओं के द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों का क्षेत्रीय संदर्भ में तुलनात्मक महत्व;
- (ख) संस्थाओं द्वारा परिचालित गतिविधियों का वर्तमान आकार-वित्तीय एवं भौतिक आयामों पर; और
- (ग) संस्थाओं की दीर्घकालीन संवहनीयता की संभावनाएं।

(9) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा।

**30. जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय—** (1) यदि जिला नजूल निर्वर्तन समिति आवेदक संस्था (या संस्थाओं) को स्थायी पट्टा स्वीकृत करना उपयुक्त समझती हैं तो उसके द्वारा अपनी अनुशंसा अंकित कर मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा। अन्यथा स्थिति में जिला नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा आवेदन पत्र अमान्य कर आवेदक संस्था (या संस्थाओं) को सूचित किया जाएगा।

(2) यदि संभाग नजूल निर्वर्तन समिति आवेदक संस्था (या संस्थाओं) को स्थायी पट्टा स्वीकृत करना उपयुक्त समझती है तो उसके द्वारा अपनी अनुशंसा अंकित कर मामला यथास्थिति राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति' को प्रेषित किया जाएगा। अन्यथा स्थिति में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा आवेदन पत्र अमान्य कर आवेदक संस्था (या संस्थाओं) तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा।

(3) (एक) एकल आवेदन के मामले में यथास्थिति राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति' द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक संस्था, जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा।

(दो) एक भूखण्ड के लिये एक से अधिक आवेदन के मामले में राज्य के मंत्री-परिषद् द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक संस्थाओं, जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा।

**31. प्रब्याजि तथा भू-भाटक-** (1) पूर्त संस्था को स्वीकृत किए जाने वाले स्थायी पट्टों पर बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना वार्षिक भू-भाटक अधिरोपित किया जाएगा।

(2) पट्टे की अवधि के दौरान वार्षिक भू-भाटक के संबंध में **कंडिका 19 की उपकंडिका (2)** के प्रावधान लागू होंगे।

**32. पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य शर्तें जोड़ी जाना-** (1) सक्षम प्राधिकारी से पट्टे की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात पट्टे के निष्पादन की कार्यवाही इस अध्याय के **भाग- छ** के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) पूर्त संस्था को रियायती दर पर स्वीकृत स्थायी पट्टे में सामान्य शर्तों के साथ-साथ निम्न शर्तें जोड़ी जाएंगी-

- (क) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा विभाजन नहीं किया जाएगा;
- (ख) संस्था द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो;
- (ग) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत नजूल अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार या अन्य व्यक्ति को संस्था के लेखा अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा;
- (घ) आवंटित भूमि पर संचालित संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा;
- (ङ) यदि विकास योजना में व्यावसायिक उपयोग अनुमत है तो आवंटित भूमि पर संस्था द्वारा आवंटित भूमि में निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यावसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा तथा ऐसे क्षेत्र के लिये व्यावसायिक उपयोग हेतु वार्षिक भू-भाटक देय होगा; और
- (च) अन्य बिन्दु जो प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार कलेक्टर ठीक समझे।

**33. इस भाग के प्रावधान लागू न होना-** पूर्त संस्थाओं के ऐसे मामलों में इस भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जिनमें पूर्व में भूमि आवंटन के आदेश सक्षम स्तर से जारी किये जा चुके हैं।

**भाग— घ****मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल को कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन**

**34. सक्षम प्राधिकारी—** मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल को स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि का आवंटन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य के मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुक्रम में राज्य सरकार होगी :

परंतु भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के आवंटन के मामले में 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति' की अनुसंशा पर निर्वर्तन का निर्णय राज्य के मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाएगा।

**35. भूमि आवंटन के लिये अर्हताएँ—** (1) केवल ऐसे राजनैतिक दल को कार्यालय भवन निर्माण के लिए नजूल भूखण्ड आवंटन के लिये अर्हता होगी जो तत्समय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो।

(2) उपकंडिका (1) के अधीन अर्हता रखने वाले राजनैतिक दल को अपने प्रादेशिक कार्यालय के लिए प्रदेश में केवल एक भूखण्ड आवंटन की तथा एक जिले में जिला कार्यालय के लिये केवल एक भूखण्ड आवंटन की पात्रता होगी।

(3) यदि किसी राजनैतिक दल को प्रादेशिक कार्यालय या जिला कार्यालय के लिये पूर्व से शासकीय भूखण्ड आवंटित है तो ऐसे दल को यथास्थिति प्रादेशिक कार्यालय या उसी जिले में जिला कार्यालय के लिए पुनः शासकीय भूखण्ड के आवंटन की पात्रता नहीं होगी।

(4) भूखण्ड का आवंटन किसी व्यक्ति या किसी पदाधिकारी के नाम से नहीं किया जाएगा, बल्कि आवंटन राजनैतिक दल के नाम से किया जाएगा।

**36. भूमि आवंटन के लिये आवेदन—** (1) राजनैतिक दल के द्वारा इस निमित्त अधिकृत किए गए पदाधिकारी द्वारा लैंड बैंक में से भूमि का चयन कर कलेक्टर को प्ररूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में **परिशिष्ट 'क'** में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

**37. आवेदन पत्र का परीक्षण तथा जांच प्रतिवेदन —** (1) कलेक्टर आवेदन पत्र का संक्षिप्त परीक्षण कर लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के आधार पर उसे अमान्य कर सकेगा।

(2) **उपकंडिका (1)** के अंतर्गत आवेदन पत्र अमान्य न किये जाने की दशा में उसे संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित किया जाएगा।

(3) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में **कंडिका 142** में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

(4) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, आवेदक राजनैतिक दल के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा।

(5) सार्वजनिक उद्घोषणा में यह भी लिखा जाएगा कि यदि कोई अन्य अर्हता प्राप्त राजनैतिक दल आवेदित भूमि का आवंटन चाहता है तो वह उद्घोषणा में उल्लेखित अंतिम तिथि तक **प्ररूप एक** में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसे आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में **परिशिष्ट 'क'** में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(6) नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा। स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन

में देंगे, यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है।

(7) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा—

- (क) तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नहीं? ;
- (ख) भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन;
- (ग) आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता; और
- (घ) क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

(8) यदि किसी भू-खण्ड प्राप्त करने के लिए अर्हता रखने वाले एक से अधिक राजनैतिक दल आवेदन करते हैं तो राज्य की विधानसभा में जिस राजनैतिक दल के विधायकों की संख्या अधिक होगी उसे वरीयता दी जाएगी। यदि विधायकों की संख्या बराबर हो तो जिस राजनैतिक दल के राज्य से निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिक हो उसे वरीयता दी जाएगी। यदि ऐसे लोकसभा सदस्यों की संख्या भी बराबर हो तो जिस राजनैतिक दल के संसद सदस्यों की संख्या अधिक हो उसे वरीयता दी जाएगी।

(9) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा।

**38. जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय—** (1) नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया जांच प्रतिवेदन जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति के अभिमतों के साथ राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

(2) यथास्थिति राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये गठित नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक राजनैतिक दल (या दलों), जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा।

**39. प्रब्याजि तथा भू-भाटक-** (1) राजनैतिक दल को स्वीकृत किए जाने वाले स्थायी पट्टों पर प्रब्याजि निम्नानुसार देय होगी-

**भूखण्ड का क्षेत्रफल**

**प्रब्याजि**

**(बाजार मूल्य का प्रतिशत)**

(क) 1000 वर्गमीटर तक

50 प्रतिशत

(ख) 1000 वर्गमीटर से अधिक

100 प्रतिशत

(2) ऐसे स्थायी पट्टे पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना वार्षिक भू-भाटक अधिरोपित किया जाएगा।

(3) पट्टे की अवधि के दौरान वार्षिक भू-भाटक के संबंध में **कंडिका 19 की उपकंडिका (2)** के प्रावधान लागू होंगे।

**40. पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य शर्तें जोड़ी जाना-** (1) सक्षम प्राधिकारी से पट्टे की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात पट्टे के निष्पादन की कार्यवाही इस अध्याय के **भाग- छ** के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) राजनैतिक दल को रियायती दर पर स्वीकृत स्थायी पट्टे में सामान्य शर्तों के साथ-साथ निम्न शर्तें जोड़ी जाएंगी-

(क) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा विभाजन नहीं किया जाएगा;

(ख) राजनैतिक दल द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो;

(ग) यदि किसी कारणवश राजनैतिक दल अस्तित्व में नहीं रहता है तो आवंटित भूखंड एवं उस पर निर्मित संरचना (भवन) राज्य शासन में वेष्टित हो जाएंगे तथा उसके द्वारा भूखंड के लिए राज्य शासन को प्रब्याजि अथवा भू-भाटक के मददे जमा की गई राशि वापिस नहीं लौटाई जाएगी और न ही भूखंड पर निर्मित संरचना के लिए कोई प्रतिफल देय होगा; और

(घ) यदि विकास योजना में व्यावसायिक उपयोग अनुमत है तो आवंटित भूमि पर राजनैतिक दल के द्वारा निर्मित क्षेत्र के अधिकतम 10 प्रतिशत क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां अनुज्ञेय होंगी तथा ऐसे क्षेत्र के लिये व्यावसायिक उपयोग हेतु वार्षिक भू-भाटक देय होगा।

**41. इस भाग के प्रावधान लागू न होना—** राजनैतिक दल को भूखण्ड आवंटन के ऐसे मामलों में इस भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जिनमें पूर्व में भूमि आवंटन के आदेश सक्षम स्तर से जारी किए जा चुके हैं।

### भाग — ड

#### मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को भूमि आवंटन

**42. मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को भूमि का आवंटन—** मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को भूमि राजस्व विभाग द्वारा सीधे आवंटित नहीं की जाएगी। राजस्व विभाग के द्वारा विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण संबंधी परियोजनाओं के लिए अध्याय— दो में विहित प्रक्रिया के अनुसार ऊर्जा विभाग को भूमि हस्तांतरित की जाएगी। इस प्रकार हस्तांतरित भूमि ऊर्जा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित मध्यप्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी, मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विभाग की विभागीय नीति के अनुसार स्थायी पट्टे पर दी जाएगी।

## भाग — च

## चहुँमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में भूमि आवंटन

**43. निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नजूल भूमि का आवंटन—**(1) प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए औद्योगिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित कर प्रदेश में अधोसंरचना विकास के साथ-साथ रोजगार के वृहद् अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निवेशकों को शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाना वांछनीय है।

(2) राज्य शासन के निम्न विभागों द्वारा जारी की गई विभागीय नीतियों/निर्देशों के अंतर्गत निवेशकों को भूमि का निर्वर्तन इन विभागों द्वारा किया जाता है—

(क) औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग;

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग;

(घ) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग;

(ङ) पर्यटन विभाग;

(च) पशुपालन विभाग; और

(छ) अन्य विभाग (जो भविष्य में मंत्रि-परिषद के अनुमोदन से उनकी विभागीय नीति जारी किये जाने पर शामिल होगा);

राजस्व विभाग के द्वारा उपरोक्त विभागों को, उनकी मांग प्राप्त होने पर, इन निर्देशों के **अध्याय— दो** में विहित प्रक्रिया के अनुसार भूमि हस्तांतरित की जाएगी। संबंधित विभाग के द्वारा अपनी विभागीय नीति के अनुसार निवेशकों को भूमि का निर्वर्तन किया जाएगा। निर्वर्तित भूमि पर प्रब्याजि तथा भू-भाटक का अधिरोपण, वसूली, पट्टे का निष्पादन, प्रशासन तथा नवीनीकरण आदि समस्त कार्यवाहियां संबंधित विभाग के द्वारा अपनी विभागीय नीति के अनुसार की जाएंगी। संबंधित विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसे राजस्व विभाग से हस्तांतरित भूमि तथा निवेशकों को निर्वर्तित की गई भूमि के नक्शे, ले-आउट, सूचियां तथा अन्य आवश्यक अभिलेख समुचित रूप से संधारित करे व राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें उपलब्ध कराए।

(3) **उपकंडिका (2)** में उल्लेखित विभागों द्वारा अपनी विभागीय नीतियों/निर्देशों के अधीन भूमि आवंटन के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में राजस्व विभाग के द्वारा ऐसे निवेशकों को, जो राज्य शासन के किसी विभाग की नीति के अंतर्गत दी जाने



वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हुए शासकीय भूमि प्राप्त करने के इच्छुक हों, आगामी कंडिकाओं अनुसार नजूल भूमि का स्थायी पट्टे पर आवंटन किया जाएगा।

**44. सक्षम प्राधिकारी—** निवेशकों को स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे—

#### तालिका

निवेशकों को स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी

क्र.	भूमि का क्षेत्रफल एवं बाजार मूल्य	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)
1.	नगरीय क्षेत्र में 4000 वर्गमीटर तक या नगरेतर क्षेत्र में पाँच हेक्टेयर तक क्षेत्रफल की भूमि जिसका बाजार मूल्य रुपये एक करोड़ तक है	ज़िला नजूल निर्वर्तन समिति
2.	नगरीय क्षेत्र में 4000 वर्गमीटर से अधिक परन्तु एक हेक्टेयर तक या नगरेतर क्षेत्र में पाँच हेक्टेयर से अधिक परन्तु दस हेक्टेयर तक क्षेत्रफल की भूमि जिसका बाजार मूल्य रुपये पाँच करोड़ तक है	संभाग नजूल निर्वर्तन समिति
3	संभाग नजूल निर्वर्तन समिति की अधिकारिता के बाहर के मामले	राज्य नजूल निर्वर्तन समिति

**45. निवेशक द्वारा विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना—** (1) निवेशक परियोजना का विस्तृत विवरण (Detailed Project Report-डी.पी.आर.) पूंजी निवेश के प्रस्ताव के साथ विभागीय नीति में घोषित सुविधाओं का उल्लेख करते हुए लैंड बैंक में से भूमि का चयन कर संबंधित विभाग को भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रारूप एक में करेगा।

(2) आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

**46. विभाग के द्वारा निवेशक के आवेदन का परीक्षण करना—** आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित विभाग निवेशक के आवेदन और परियोजना विवरण का विधिवत् परीक्षण करेगा। संबंधित विभाग यदि प्रस्तावित परियोजना को विभागीय नीति के अंतर्गत उपयुक्त पाता है तो परियोजना के लिए आवेदित भूमि के संदर्भ में अपनी विभागीय नीति के प्रावधानों के अनुसार अथवा विकास योजना (मास्टर प्लान) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अंतर्गत अनुमत भूमि उपयोग (land use) तथा तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित ऊर्ध्वाकार (vertical) निर्माण को ध्यान में रखते हुए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन करेगा।

**47. विभाग द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के लिए समय-सीमा—** संबंधित विभाग के द्वारा किसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण आगामी माह के प्रथम सप्ताह के भीतर किया जाएगा तथा पात्र तथा उपयुक्त पाए गए आवेदन को भूमि आवंटन के लिए उपयुक्तता तथा विभागीय नीति के अंतर्गत भूमि आवंटन के मामले में दी जाने वाली सुविधाओं (जिसमें प्रब्याजि एवं भू-भाटक की देयता में रियायत आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा) का प्रमाणीकरण करते हुए और आवंटन की स्वीकृति की दशा में जारी किये जाने वाले स्थायी पट्टे में विभागीय नीति के अनुसार अधिरोपित की जाने वाली विशिष्ट शर्तों के उल्लेख के साथ माह के द्वितीय सप्ताह के सोमवार को और यदि सोमवार अवकाश दिवस है तो आगामी कार्य दिवस को संबंधित कलेक्टर को अग्रेषित किया जाएगा।

**48. कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण—** (1) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर आवेदन पत्र अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को परीक्षण कर प्रस्तुत करने के लिए प्रेषित करेगा।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण किया जाएगा जिनमें प्रमुखतः निम्न बिन्दु शामिल होंगे—

- (क) आवेदित भूमि संबंधी भू-अभिलेख जिसमें नोईयत का उल्लेख भी होगा एवं मानचित्र;
- (ख) आवेदित भूमि की उपलब्धता;
- (ग) विभागीय नीति के प्रावधानों के अनुसार अथवा विकास योजना (मास्टर प्लान) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अंतर्गत अनुमत भूमि उपयोग (land use) तथा तल क्षेत्र अनुपात (एफ ए आर) के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित ऊर्ध्वाकार (vertical) निर्माण को ध्यान में रखते हुए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता;
- (घ) यदि भूमि विकास योजना क्षेत्र में स्थित है तो विकास योजना में नियत भूमि उपयोग; तथा यदि भूमि विकास योजना क्षेत्र के बाहर स्थित है तो आवेदित भूमि उपयोग के लिए ग्राम तथा नगर निवेश विभाग के प्रतिवेदन अनुसार भूमि उपयोग की उपयुक्तता;
- (ङ) लैण्ड बैंक में अंकित प्रविष्टि के अनुसार आवेदित भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु, जिस हेतु आवंटन चाहा गया है, आवंटन योग्य है अथवा नहीं;
- (च) मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार आवेदित भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य;
- (छ) संबंधित विभाग द्वारा अग्रेषित आवेदन के अनुसार उस विभाग की विभागीय नीति के अनुसार देय प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक;
- (ज) स्थानीय निकाय—नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या ग्राम पंचायत से परामर्श;
- (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत/परामर्श लिया जाएगा, यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है;
- (ञ) भूमि की मौके पर उपलब्धता संबंधी विस्तृत जाँच जिसमें अतिक्रमण आदि का भी उल्लेख होगा; और
- (ट) अन्य कोई अनुषांगिक विषय।

(3) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन **प्ररूप दो** में तैयार किया जाकर सामान्यतः दो माह के भीतर कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त कलेक्टर यदि पाता है कि निवेशक को आवेदित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता तो वह तदनुसार विभाग को सूचित करेगा।

(5) यदि कलेक्टर यह पाता है कि निवेशक को भूमि आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है तो वह नजूल अधिकारी को इस आशय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए निर्देशित करेगा।

**49. सार्वजनिक उद्घोषणा—** (1) नजूल अधिकारी द्वारा **कंडिका 142** में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर न्यूनतम पंद्रह दिवस की अवधि देते हुए आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

(2) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, आवेदक के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा।

(3) नजूल अधिकारी द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा में प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर जांच कर अपना अभिमत अंकित किया जाएगा।

(4) एक ही भूमि या उसके अंशभाग के आवंटन हेतु यदि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनके संबंध में आपत्तियों और सुझावों के निराकरण के पश्चात् आवंटन हेतु पात्र आवेदन पत्रों से किसी एक के चयन के लिए नजूल अधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर तुलनात्मक परीक्षण किया जाएगा—

(क) परियोजना द्वारा सृजित होने वाला सीधा रोजगार;

(ख) परियोजना में किए जा रहे निवेश का आकार;

(ग) आवेदक द्वारा प्रदेश में पूर्व से स्थापित और गतिशील परियोजनाएँ; और

(घ) परियोजना की स्थापना से जिले को प्राप्त होने वाले अन्य लाभ (उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में गुणात्मक या परिमाणात्मक वृद्धि)।

(5) नजूल अधिकारी अपने जांच प्रतिवेदन तथा प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के संबंध में अपने अभिमत के साथ मामला जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित करेगा।

**50. जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय—** (1) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर आवेदक (या आवेदकों) तथा संबंधित विभाग (या विभागों) को सूचित किया जाएगा। जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति अथवा राज्य नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा अपने अभिमत के साथ मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक (या आवेदकों), संबंधित विभाग (या विभागों) तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा। जिस मामले में राज्य नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला राज्य नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा।

(3) जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर निराकरण किया जाएगा।

(4) जिस मामले में राज्य नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामलों में निर्णय लिया जाकर आवेदक (या आवेदकों), संबंधित विभाग (या विभागों), जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा।

**51. प्रब्याजि तथा भू-भाटक—** (1) ऐसे मामलों में बाजार मूल्य के बराबर प्रब्याजि तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना भू-भाटक देय होगा:

परन्तु यदि किसी विभाग की नीति के अनुसार निवेशक को प्रब्याजि या भू-भाटक पर कोई रियायत प्राप्त करने की पात्रता है तो आवंटित भूमि के संबंध में ऐसी दरों पर प्रब्याजि तथा भू-भाटक देय होगा।

(2) पट्टे की अवधि के दौरान वार्षिक भू-भाटक के संबंध में कंडिका 19 की उपकंडिका (2) के प्रावधान लागू होंगे।

**52. पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य शर्तें जोड़ी जाना—** (1) सक्षम प्राधिकारी से पट्टे की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् पट्टे के निष्पादन की कार्यवाही इस अध्याय के भाग— छ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) ऐसे स्थायी पट्टों में सामान्य शर्तों के साथ-साथ संबंधित विभागीय नीति में उल्लेखित शर्तें तथा निम्न शर्तें जोड़ी जाएंगी—

- (क) परियोजना, जिसके लिए भूमि आवंटित की गई है, की स्थापना का कार्य आवंटन उपरांत भूमि का आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रारंभ किया जाएगा तथा तीन वर्ष के भीतर पूर्ण कर परियोजना प्रारंभ की जाएगी;
- (ख) आवंटिती द्वारा आवंटित भूमि या उसके किसी भाग को विक्रय, दान, उप पट्टा या अन्यथा अंतरित नहीं किया जाएगा; और
- (ग) आवंटिती अथवा उसकी सहमति से किसी अन्य द्वारा आवंटित भूमि या उसका कोई भाग राज्य शासन की पूर्वानुमति के बिना बंधक नहीं रखी जाएगी।

उपरोक्त शर्तों का अपालन या उल्लंघन पाए जाने पर आवंटन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

**53. स्थायी पट्टे की शर्तों का पालन कराने के संबंध में संबंधित विभाग का उत्तरदायित्व—** कलेक्टर स्वीकृति आदेश की एक प्रति के साथ निष्पादित पट्टे की प्रति संबंधित विभाग को प्रेषित करेगा। पट्टे की शर्तों तथा विभागीय नीति का आवंटिती से पालन कराना सुनिश्चित करने का दायित्व उस सीमा तक, जो संबंधित विभाग द्वारा नीति का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित की गयी हो, संबंधित विभाग का होगा।

**54. आवंटित भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन की स्थिति में देय राशि—** (1) किसी निवेशक को यदि किसी एक प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की जाती है और भविष्य में राज्य शासन की पूर्वानुमति से उसे किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग में लाया जाता है तो निवेशक द्वारा शमन राशि का राज्य शासन को भुगतान करना

होगा जो यथास्थिति रियायत देते हुए आवंटित भूमि के मामले में कंडिका 82 की उपकंडिका (2) की तालिका के सरल क्रमांक 8 और अन्य मामलों में कंडिका 82 की उपकंडिका (2) की तालिका के सरल क्रमांक 6 अनुसार होगी।

(2) नए प्रयोजन के लिए तत्समय देय वार्षिक भू-भाटक का पुनर्निर्धारण किया जाएगा जो पट्टे की शेष अवधि के लिए देय होगा।

**55. निजी पूंजी निवेशकों को आवंटित शासकीय पट्टे की भूमियों के अभिहस्तांकन (conveyance) की अनुमति—** (1) ऐसी शासकीय भूमि, जो निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवंटित की गई है, को अभिहस्तांकित कर वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से परियोजना के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अंतर्गत घोषित लोक वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकारों का अभिहस्तांकन की अनुमति आगामी उपबंधों के अधीन उपलब्ध होगी।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिहस्तांकन (conveyance) बंधक (mortgage) नहीं है, न ही आवंटिती को पट्टाधिकार के अभिहस्तांकन की पूर्ण शक्ति (full power) या समग्र प्राधिकार (absolute authority) है। आवंटिती की अभिहस्तांकन की शक्ति सीमित है।

**56. अभिहस्तांकन की शर्तें—** अभिहस्तांकन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जा सकेगी:—

- (क) भूमि पर राज्य शासन को देय प्रभार प्रथम दायित्व होगा, किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य का नहीं;
- (ख) भूमि के अभिहस्तांकन के उपरान्त भी भूमि का उपयोग यथापूर्व प्रयोजन के लिये ही किया जा सकेगा, प्रयोजन परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा;
- (ग) पट्टाधारी से किसी राशि की वसूली के लिये किसी न्यायालय या प्राधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत वाद या दावे में राज्य शासन आवश्यक पक्षकार होगा। अभिहस्तांकिती ऐसा वाद या दावा राज्य शासन को पक्षकार बनाए बिना प्रस्तुत नहीं कर सकेगा;
- (घ) अभिहस्तांकिती अपनी देय राशि प्रथमतः अभिहस्तांकित भूमि पर स्थित समस्त चल सम्पत्ति से वसूल कर सकेगा, उसके बाद भूमि पर स्थापित संरचना से वसूल कर सकेगा;

- (ड) पट्टेदार और बैंक या वित्तीय संस्था के बीच ऋण की शर्तों के तहत वसूली की कार्यवाही करने के पूर्व बैंक या वित्तीय संस्था को कम से कम 3 माह पूर्व राज्य शासन को नोटिस देना होगा;
- (च) बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा वसूली के अनुक्रम में अभिहस्तांकित भूमि के लीज का हस्तांतरण पट्टे की शेष अवधि के लिए होगा और इसके पश्चात् हस्तांतरिती को पट्टे का नवीनीकरण कराना होगा;
- (छ) कम्पनी के मामलों में हस्तांतरण से तात्पर्य वही माना जायेगा जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों में निहित है;
- (ज) भूमि का मूल्यांकन हस्तांतरण के समय प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार संगणित बाजार मूल्य और आवंटन दिनांक को आवंटिती द्वारा प्रब्याजि के रूप में भुगतान की गयी राशि के अन्तर की 10 प्रतिशत राशि के बराबर हस्तांतरण शुल्क सरकारी खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा करना होगा। अभिहस्तांकन के प्रत्येक पश्चात्वर्ती मामले में भी पश्चात्वर्ती तथा पूर्ववर्ती हस्तांकनों के समय के संगणित बाजार मूल्यों के अंतर की 10 प्रतिशत राशि के बराबर हस्तांतरण शुल्क अधिरोपित किया जाएगा;
- (झ) अभिहस्तांकिती प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में सभी पर्यावरणीय दायित्वों के निर्वहन के लिये उत्तरदायी होगा;
- (ञ) यदि अभिहस्तांकन के उपरान्त कभी भी यह प्रकट होता है कि अभिहस्तांकन की नीति अथवा उसकी वर्जना संबंधी शैथिल्य किसी तथ्य के छुपाने (suppression) या किसी दुर्व्यपदेशन (misrepresentation) या छल से प्राप्त किया गया है तो अभिहस्तांकन शून्य समझा जाएगा;
- (ट) केवल उसी ऋणदाता के पक्ष में अभिहस्तांकन अनुमत होगा जो या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत एक शेड्यूल्ड बैंक है अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक लोक वित्तीय संस्थान है :

परन्तु यदि ऋणदाता एक कॉन्सॉर्शियम (consortium) है और उसके सभी सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत शेड्यूल्ड बैंक अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थान नहीं हैं, तो यथास्थिति ऐसे कॉन्सॉर्शियम द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी (lead) बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत शेड्यूल्ड बैंक होना अथवा वित्तीय संस्था के मामले में



उसका कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थान होना आवश्यक होगा;

- (ठ) यदि ऋण एक कॉन्सॉर्शियम (consortium) द्वारा दिया गया है, तो इस विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऋणदाताओं के पक्ष में यथास्थिति उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी (lead) बैंक अथवा वित्तीय संस्था को आवेदक कम्पनी के साथ अभिहस्तांकन या अन्तरण अनुबंध हस्ताक्षरित करने की अनुमति होगी;
- (ड) अभिहस्तांकन के मामले में लैण्डर्स स्टेप-इन राइट (lender's step-in right) का सिद्धान्त लागू होगा; और
- (ढ) यदि परियोजना हेतु स्वीकृत पुनर्वास पैकेज की या अन्य किसी या किन्हीं निर्धारित शर्तों का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

**57. अभिहस्तांकन की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना—** (1) अभिहस्तांकन की अनुमति के लिए अभिहस्तांतरणकर्ता कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा। अभिहस्तांतरणकर्ता अपने आवेदन के साथ,—

- (क) इस आशय का शपथ-पत्र देगा कि वह अभिहस्तांकन विषयक किसी निर्योग्यता अथवा अक्षमता से ग्रस्त नहीं है;
- (ख) इस आशय का अदेयता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि राज्य शासन को देय किसी भी प्रकार का कर, उपकर, प्रभार या भू-राजस्व बकाया नहीं है; और
- (ग) ऐसी संस्थाओं की सूची जिनके पक्ष में अभिहस्तांकन प्रस्तावित है, प्रस्तुत करते हुए अभिहस्तांकन के लिए आवश्यकता के कारणों का विवरण, आवश्यक दस्तावेज तथा ऐसे अन्य विवरण जिनसे यह सिद्ध हो सके कि अभिहस्तांकन के बिना परियोजना का कार्यान्वयन संभव नहीं है, प्रस्तुत करेगा।

(2) कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का होगा, प्राप्त आवेदन की जांच के लिए समस्त प्रासंगिक तथ्यों एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा एवं इस हेतु भूमि पर प्रवेश कर सकेगा।

**58. कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित करना— (1)**  
कलेक्टर मामले में परीक्षण निम्न बिन्दु सम्मिलित करते हुए अपना प्रतिवेदन तैयार करेगा:—

- (क) प्रकरण का तिथिवार तथ्यात्मक विवरण;
- (ख) आवेदक या अभिहस्तांतरणकर्ता की परियोजना की वर्तमान स्थिति;
- (ग) आवेदक आवंटिती को प्रश्नाधीन भूमि पूर्ण प्रब्याजि पर आवंटित की गई है अथवा रियायती दर पर; रियायती दर पर आवंटित भूमि के मामले में कलेक्टर, आवेदक आवंटिती द्वारा भूमि आवंटन के समय भुगतान की गयी प्रब्याजि की राशि का उल्लेख करते हुए, अभिहस्तांकन की अनुमति की अनुशंसा करते समय यह स्पष्ट उल्लेख करेगा कि भूमि का आवंटन रियायती दर पर किया गया है;
- (घ) ऋणदाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत एक शेड्यूल्ड बैंक है अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक लोक वित्तीय संस्थान है:  
परन्तु यदि ऋणदाता एक कॉन्सॉर्शियम (consortium) है और उसके सभी सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत शेड्यूल्ड बैंक अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थान नहीं हैं, तो यथास्थिति ऐसे कॉन्सॉर्शियम द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी (lead) बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत शेड्यूल्ड बैंक है अथवा वित्तीय संस्था कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थान है;
- (ङ) यदि ऋण एक कॉन्सॉर्शियम (consortium) द्वारा दिया गया है, तो इस विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऋणदाताओं के पक्ष में यथास्थिति उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी (lead) बैंक अथवा वित्तीय संस्था के साथ अभिहस्तांकन या अन्तरण अनुबंध हस्ताक्षरित करने के लिए आवेदक या अभिहस्तांतरणकर्ता सहमत है;
- (च) आवेदक या अभिहस्तांतरणकर्ता का इस आशय का स्वीकारोक्ति पत्र (undertaking) कि उसे अभिहस्तांकन की अनुमति जिन शर्तों पर दी जाएगी, वह पालन करने को तत्पर है;
- (छ) आवेदक या अभिहस्तांतरणकर्ता द्वारा आवंटन की किसी शर्त का उल्लंघन या अपालन नहीं किया गया है;
- (ज) परियोजना के लिए यदि कोई पुनर्वास पैकेज स्वीकृत है तो आवेदक या अभिहस्तांतरणकर्ता द्वारा ऐसे पैकेज का पालन किया गया है; और

(झ) अन्य बिन्दु जिसे कलेक्टर उचित समझे।

(2) कलेक्टर उक्तानुसार जांच उपरान्त अभिहस्तांकन की अनुमति के लिए केवल उन्हीं मामलों में अनुशंसा करेगा, जिनमें उसकी संतुष्टि हो जाए कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में संहिता की धारा 182 की उपधारा (2) के अंतर्गत पुनः प्रवेश के अधिकार का प्रयोग करने के आधार उपलब्ध नहीं हैं।

(3) कलेक्टर उक्तानुसार प्रतिवेदन तैयार कर अपनी अनुशंसा या अभिमत के साथ आयुक्त को प्रस्तुत करेगा जो कलेक्टर के प्रतिवेदन पर अपना स्पष्ट अभिमत अंकित कर उसे राज्य शासन, राजस्व विभाग को प्रेषित करेगा।

**59. राज्य शासन के द्वारा अभिहस्तांकन की अनुमति के आवेदन पर निर्णय लिया जाना—** राज्य शासन आयुक्त के माध्यम से कलेक्टर के प्रतिवेदन के साथ प्राप्त अभिहस्तांकन की अनुमति के आवेदन पर विचार करेगा और प्रकरण के गुण-दोष पर विचार उपरान्त ऊपर कंडिका 56 में वर्णित शर्तों पर अभिहस्तांकन की अनुमति दे सकेगा।

**60. ऋणदाता संस्था के पक्ष में अभिहस्तांकित भूमि का हस्तांतरण—** अभिहस्तांकन की अनुमति जारी होने पर यदि ऋणदाता संस्था द्वारा अभिहस्तांकित भूमि के हस्तांतरण की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऋणदाता संस्था कंडिका-56 की शर्तों की पूर्ति करते हुए राज्य शासन को आवेदन करेगी जिस पर विचार कर राज्य शासन लीज के हस्तांतरण के लिए अनुमति जारी करेगा।

**भाग-छ****स्थायी पट्टे का निष्पादन, अग्रिम आधिपत्य तथा समर्पण**

**61. प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक जमा करना—** (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी पट्टे के आवंटन की स्वीकृति जारी करने की दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर आवंटिती द्वारा ऐसे आदेश के पालन में देय प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक की राशि जमा करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार नियत समयावधि के भीतर राशि जमा नहीं करने की दशा में आवंटन की स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

(2) यदि आवंटिती द्वारा स्थायी पट्टे के आवंटन की स्वीकृति की दिनांक से दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व देय राशि जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो कलेक्टर युक्तियुक्त आधारों पर अधिकतम एक माह की अतिरिक्त समयावधि स्वीकृत कर सकेगा। ऐसी दशा में राशि के भुगतान की तिथि को लागू बाजार मूल्य के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर संगणित प्रब्याजि एवं उस तिथि को प्रश्नाधीन भूमि पर लागू दर पर वार्षिक भू-भाटक और ऐसी कुल देय राशि पर अतिरिक्त स्वीकृत समयावधि के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा। ऐसी देय राशि का भुगतान अतिरिक्त समयावधि के भीतर जमा न किए जाने पर पट्टे के आवंटन की स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

**62. पट्टे का निष्पादन तथा भू-अभिलेखों में प्रविष्टियों का अद्यतनीकरण—** (1) स्थायी पट्टे की स्वीकृति या अस्थायी पट्टे का स्थायी पट्टे में परिवर्तन की स्वीकृति तथा यथास्थिति प्रब्याजि या परिवर्तन शुल्क और वार्षिक भू-भाटक के भुगतान के पश्चात् कलेक्टर प्ररूप-तीन में पट्टा-विलेख तीन प्रतियों में तैयार करवायेगा।

(2) स्थायी पट्टे की सामान्य शर्तों के साथ-साथ इन निर्देशों के द्वारा विहित की गई अतिरिक्त शर्तों और पट्टा आवंटन की स्वीकृति आदेश में उल्लेखित विशेष शर्तों का पट्टा-विलेख में यथास्थान अंकित किया जायेगा।

(3) पट्टा विलेख में कंडिका 19 की उपकंडिका (2) में उल्लेखित शर्त का उल्लेख, ऐसे मामले में जहां लागू हो, जोड़ा जाएगा।

(4) पट्टा-विलेख कलेक्टर को हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व नजूल अधिकारी के द्वारा पट्टा-विलेख की निम्न बिन्दुओं के विषय में सावधानीपूर्वक जाँच-पड़ताल की जाएगी कि—

- (क) प्ररूप में केवल अनपेक्षित अंश ही काटा/हटाया गया है;
- (ख) अपेक्षित अंश रखा गया है;
- (ग) खाली स्थान ठीक से भरे गये हैं;
- (घ) जिस दिनांक से पट्टेदार भू-भाटक का भुगतान करने के लिए बाध्य है, वह ठीक से लिखी गई है;
- (ङ) विशिष्ट मामले में आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित परिवर्तन कर दिये गये हैं, विशेषतः यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन निर्देशों में विहित की गई अतिरिक्त शर्तों और पट्टा आवंटन की स्वीकृति आदेश में उल्लेखित विशेष शर्तों का पट्टा-विलेख में यथास्थान अंकित किया गया है;
- (च) पट्टे में ऐसे अतिरिक्त खण्ड जोड़ लिये गये हैं, जो कि स्वीकृति आदेश के अनुसार आवश्यक हों और यदि आवंटित भूखंड किसी सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक या प्लॉट संख्यांक का अंशभाग है तो ऐसे अंशभाग को नक्शे में स्पष्ट दर्शाया गया है;
- (छ) संबंधित भू-खण्डों के भू-खण्ड संख्यांक और क्षेत्रफल आदि ठीक से लिखे गये हैं; और
- (ज) पट्टे पर यथाविधि प्रश्नाधीन भूमि के प्रमाणित रेखा-चित्र की प्रति अनुलग्न की गई है।

(5) कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से समुचित अधिकारी के रूप में पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(6) मुद्रांक शुल्क का भुगतान पट्टेदार द्वारा किया जाएगा। निष्पादन के बाद पट्टे की मूल प्रति पट्टेदार को दी जायेगी और दूसरी प्रति संदर्भ के लिए राजस्व मामले में रखी जायेगी।

(7) पट्टे के पंजीयन के उपरांत भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी तथा उसके पश्चात् ही मामला अभिलेख कक्ष में जमा किया जाएगा।

(8) कभी-कभी पट्टा-विलेख निष्पादित करने के पूर्व ही भू-खण्ड का कब्जा दे दिया जाता है। कभी-कभी लिखे गए पट्टा-विलेख का पंजीयन नहीं किया जाता

है या वह किसी अन्य प्रकार से अनुपयोगी हो जाता है और नया पट्टा-विलेख लिखना आवश्यक हो जाता है। ऐसे मामलों में वह दिनांक ठीक-ठीक लिखना आवश्यक है जब से कि पट्टेदार भू-भाटक का भुगतान करने को बाध्य हो। पट्टे के प्ररूप में ऐसे समुचित परिवर्तन किए जाने चाहिए, जो कि प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल हों।

(9) ऐसे मामलों में, जिनमें बिना प्रब्याजि लिए या एक रुपये प्रब्याजि लिये तथा एक रुपये वार्षिक भू-भाटक लेकर स्थायी पट्टे मंजूर किए गए हैं और आधिपत्य भी सौंपा जा चुका है किन्तु पट्टा निष्पादित नहीं है, उनमें प्ररूप- तीन में पट्टा निष्पादित किया जाएगा।

**63. भूमि का आधिपत्य देना-** पट्टे पर दिये गये भूखंड का आधिपत्य पट्टेदार को पट्टे के यथाविधि निष्पादित होने के बाद ही दिया जाएगा।

**64. पट्टे का आरंभ और भू-भाटक की देयता-** (1) पट्टा, पट्टेदार द्वारा उसके निष्पादित किए जाने की दिनांक से अथवा पट्टे में उल्लेखित की गई दिनांक से या अग्रिम आधिपत्य के मामले में अग्रिम आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से प्रारम्भ होगा। पट्टा प्रारंभ होने की दिनांक के राजस्व वर्ष की अंतिम दिनांक को पट्टावधि का प्रथम वर्ष समाप्त माना जाएगा।

(2) वार्षिक भू-भाटक, पट्टा निष्पादन के राजस्व वर्ष की पहली दिनांक अर्थात् 01 अप्रैल से देय होगा तथा शेष पट्टावधि के उत्तरवर्ती वर्षों के लिये भी 01 अप्रैल से देय होगा।

(3) सभी निष्पादित स्थायी पट्टों में पट्टे के आरंभ और भू-भाटक की देयता के लिये उपकंडिका (1) एवं (2) के प्रावधान लागू होंगे।

**65. स्थायी पट्टे की अवधि-** (1) स्थायी पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिये दिया जाएगा जो पट्टावधि के अवसान के एक वर्ष पूर्व आवेदन करने पर इस अध्याय के भाग-झ के उपबंधों के अधीन नवकरणीय होगा।

(2) पट्टावधि के तीस वर्ष की गणना पट्टे के प्रारंभ वर्ष को प्रथम वर्ष मानते हुए की जाएगी।

(3) उपकंडिका (1) में किसी बात के होते हुए भी कतिपय विशिष्ट मामलों में वित्त विभाग की सहमति से राजस्व विभाग द्वारा 99 वर्ष की अवधि के लिए स्थायी पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा।

**66. स्थायी पट्टा समर्पण या पुनर्प्रवेश के मामले में प्रब्याजि वापसी—** (1) इस कंडिका के प्रावधान केवल ऐसे स्थायी पट्टों के मामलों पर लागू होंगे जो इन निर्देशों के अधीन **कंडिका 19 की उपकंडिका (1)** में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अथवा **कंडिका 142** में निरसित किये गये निर्देशों के अनुसार राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा आवंटित हुये हैं। ये प्रावधान राज्य शासन के अन्य विभागों या उपक्रमों (जैसे औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना मंडल, विकास प्राधिकरण, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम आदि) के माध्यम से आवंटित पट्टों के मामलों में लागू नहीं होंगे।

(2) कृषि भिन्न प्रयोजन यथा—आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक या अन्य प्रयोजन के लिये स्थायी पट्टे पर आवंटित भूमि का आवंटिती अथवा पट्टेदार द्वारा उपयोग नहीं किये जाने पर, राज्य शासन के पक्ष में समर्पण कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत किए गए अपर कलेक्टर के द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा जिसे इस कंडिका में आगे 'प्राधिकृत अधिकारी' कहा जाएगा।

(3) आवंटिती अथवा पट्टेदार पट्टाधीन भूमि राज्य शासन के पक्ष में समर्पित करने तथा उसके द्वारा जमा कराई गई प्रब्याजि की राशि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा। आवंटिती अथवा पट्टेदार अपने आवेदन के साथ इस आशय का घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि पट्टाधीन भूमि पूर्णतः विल्लंगम मुक्त (free from all encumbrances) है तथा किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विवादित नहीं है।

(4) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार से स्थल प्रतिवेदन प्राप्त करेगा। तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रमुखतः पट्टाधीन भूमि की वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया जाएगा, यथा— स्थल पर पट्टाधीन भूमि रिक्त है; कोई अतिक्रमण आदि नहीं है; आवंटिती अथवा पट्टेदार या किसी अन्य द्वारा भूमि पर कोई स्थाई या अस्थायी निर्माण आदि नहीं किये गये हैं; यदि कोई निर्माण

किया गया था तो उसे हटा लिया गया है और स्थल पर पट्टाधीन भूमि को उसी स्थिति में वापस लाया जा चुका है जिस स्थिति में आवंटिती अथवा पट्टेदार को आवंटन के समय कब्जा सौंपा गया था। तहसीलदार अपने प्रतिवेदन में सम्यक् जांच उपरांत यह भी पुष्टि करेगा कि पट्टाधीन भूमि पूर्णतः विल्लंगम मुक्त (free from all encumbrances) है।

(5) तहसीलदार अपना प्रतिवेदन नजूल अधिकारी के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि प्राधिकृत अधिकारी पट्टा समर्पण का आवेदन मान्य करने योग्य पाता है तो वह आवंटन स्वीकृति अथवा पट्टे में उल्लेखित वार्षिक भू-भाटक का बकाया तथा अन्य देय प्रभार की गणना कर पट्टेदार के वसूली योग्य राशि निर्धारित करेगा।

(7) प्राधिकृत अधिकारी पट्टाधीन भूमि के लिए आवंटिती अथवा पट्टेदार द्वारा जमा की गई प्रब्याजि की राशि में से प्रारंभिक कटौती के रूप में जमा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर तथा आवंटन स्वीकृति की दिनांक से पट्टाधीन भूखण्ड समर्पण के आवेदन की दिनांक के बीच की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए दो प्रतिशत के मान से संगणित राशि समर्पण शुल्क के रूप में कटौती कर शेष राशि आवंटिती अथवा पट्टेदार को वापस लौटाये जाने का निर्णय लेगा। उदाहरण के लिये 15 वर्ष पश्चात् समर्पण किये जाने पर  $10+30=40$  प्रतिशत राशि काटी जाएगी। प्रब्याजि से वापस की जाने वाली संगणित राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(8) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पट्टाधीन भूमि समर्पण के आवेदन को स्वीकृत किए जाने तथा आवंटिती अथवा पट्टेदार को राशि लौटाए जाने का निर्णय लिए जाने पर आवंटिती अथवा पट्टेदार प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को पट्टाधीन भू-खंड का रिक्त कब्जा सौंपेगा।

(9) यदि पट्टा निष्पादित किया जा चुका है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राशि लौटाए जाने का निर्णय लिए जाने पर पट्टेदार 30 दिवस के भीतर, पट्टा निरस्तीकरण विलेख तैयार कराकर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसे प्राधिकृत अधिकारी पंजीकृत करायेगा।



(10) पट्टा निरस्तीकरण विलेख पंजीकृत किये जाने के उपरांत प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा **उपकंडिका (6)** में संगणित वापसी योग्य राशि में से **उपकंडिका (5)** में निर्धारित की गई वसूली योग्य राशि घटाकर शेष राशि आवंटिती अथवा पट्टेदार को वापस लौटाई जाएगी।

(11) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटिती अथवा पट्टेदार को राशि लौटाये जाने का निर्णय लिए जाने पर 'पट्टा निरस्तीकरण विलेख' के आधार पर भू-अभिलेख में अद्यतन प्रविष्टि प्रमाणित करने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाएगा जो भू-अभिलेख अद्यतन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

(12) रियायती दर पर आवंटित पट्टों पर भी यह प्रावधान समान रूप से लागू होगा। ऐसे मामले में रियायती आधार पर जमा प्रब्याजि में से आनुपातिक कटौती कर राशि लौटाई जा सकेगी।

(13) प्रब्याजि में से लौटाई जाने वाली राशि को दोनों ही मामलों में, चाहे आवंटिती अथवा पट्टेदार द्वारा समर्पण के लिये आवेदन दिया गया हो अथवा कलेक्टर द्वारा पुनर्प्रवेश (री-एंट्री) की कार्यवाही की गयी हो, एक समान रूप से संगणना अनुसार राशि वापस लौटाई जाएगी।

(14) यदि भूमि पर कोई निर्माण आदि है और आवंटिती अथवा पट्टेदार द्वारा समर्पण चाहा गया है किन्तु ऐसा निर्माण नहीं हटाया गया है तो समर्पण का आवेदन स्वीकार किये जाने के उपरांत पट्टाधीन भूमि का कब्जा राज्य शासन हित में लिए जाने पर भूमि के साथ ऐसा निर्माण भी शासन में वेष्टित समझा जाएगा और निर्माण के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(15) यदि भूमि का अधिपत्य उद्योग या परियोजना हेतु आवंटिती अथवा पट्टेदार को दिया गया है तो **उपकंडिका (6)** के अनुसार राशि की कटौती की जावेगी, परन्तु यदि वनीकरण अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित हुई है और अधिपत्य आवंटिती अथवा पट्टेदार को नहीं दिया गया है तो कटौती नहीं की जावेगी।

(16) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समर्पित की जा रही भूमि अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए जाने पर, आवंटित भूमि के अंश भाग को भी समर्पित किया जा सकेगा।

(17) अंश भाग समर्पित किये जाने की दशा में उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसरण में समानुपातिक गणना कर राशि वापिस की जाएगी।

**67. सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व—** (1) राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्थायी पट्टे पर आवंटित भूखंडों के मामले में सरकारी पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व पट्टे में उल्लेखित निबंधन या शर्तों के अधधीन होंगे।

(2) नजूल भूमि का स्थायी पट्टे पर आवंटन मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 182 के उपबंधों के अनुसार सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (1895 का संख्यांक 15) के अर्थ के अंतर्गत अनुदान समझा जाता है, अतः ऐसे सरकारी पट्टेदार को उसकी भूमि से संहिता के उक्त प्रावधान के अनुसार कलेक्टर द्वारा कतिपय आधारों पर बेदखल किया जा सकता है। कलेक्टर उक्त धारा 182 के अंतर्गत पट्टे के किसी निबंधन या शर्त के उल्लंघन या अपालन के संबंध में, यदि शमन नहीं किया गया है, सरकारी पट्टेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत बेदखली का आदेश पारित कर सकेगा।

(3) कलेक्टर द्वारा उक्त उपकंडिका के अनुसरण में पारित किया गया आदेश संहिता की धारा 182 के अंतर्गत पारित आदेश होगा और ऐसे आदेश के संबंध में आगे समस्त कार्यवाहियां संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत की जा सकेंगी।

**68. गृह निर्माण सहकारी समितियों के उप पट्टेदारों के मामलों में कार्यवाही—** (1) राज्य शासन द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों को उनके सदस्यों के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थायी पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराई गई है। ऐसी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को राज्य शासन से प्राप्त स्थायी पट्टे की भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु उपपट्टे पर दी गई है। ऐसी समितियां जो क्रियाशील नहीं हैं, उनके उपपट्टेदारों के पट्टों के नवीनीकरण की समस्या है।

(2) ऐसी समितियों के संबंध में जो क्रियाशील नहीं हैं, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए परिसमापन किए जाने पर परिसमापन आदेश कलेक्टर को संसूचित किया जाएगा जिसमें परिसमापित समिति को स्थायी पट्टे पर आवंटित भूमि के ब्यौरे एवं ऐसी भूमि में से समिति के सदस्यों को प्रदत्त उपपट्टों के ब्यौरे होंगे।

(3) ऐसे उपपट्टेदारों या उनके वैध उत्तराधिकारियों, वसीयत प्राप्तकर्ताओं या अंतरितियों को सरकारी पट्टेदार समझा जाएगा तथा उन पर उपपट्टे में उल्लेखित निबंधन एवं शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

**स्पष्टीकरण—** भूखण्ड पर एक से अधिक प्रकोष्ठधारी होने की दशा में उक्त उपबंध मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2001) के अध्याधीन होंगे।

(4) उक्त **उपकंडिका (3)** अनुसार समझे गए सरकारी पट्टेदारों के संबंध में उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी जैसे कि उन्हें सीधे राज्य शासन से स्थायी पट्टे पर भूखंड आवंटित किये गये हैं।

(5) कार्यशील सहकारी समितियां, जिनके कतिपय उप पट्टेदारों द्वारा शर्त उल्लंघन किया गया है, के मामले में मूल पट्टेदार (सहकारी समिति) अपने मूल पट्टे के नवीनीकरण के आवेदन के साथ ऐसी शर्त उल्लंघन के संबंध में प्रतिवेदन कंडिका 77 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी, जिस पर सक्षम प्राधिकारी ऐसे उप पट्टेदार को इन निर्देशों की कंडिका 82 के उपबंध अनुसार शर्त उल्लंघन का शमन कराने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा और ऐसा उप पट्टेदार यदि शमन राशि जमा कराता है तो मूल पट्टा ऐसी समिति के पक्ष में नवीकृत किया जा सकेगा, अन्यथा ऐसे उप पट्टेदार (जो शर्त उल्लंघन हेतु शमन नहीं कराते) के उप पट्टे सहकारी समिति द्वारा निरस्त किये जाने पर उप पट्टों के भूखंडों को कम करते हुए मूल पट्टे के शेष भाग का पट्टा नवीकृत किया जायेगा तथा ऐसे उप पट्टेदारों के उप पट्टे के प्रश्नाधीन भूखंडों के मामले में कंडिका 85 के उपबंध अनुसार कार्यवाही की जायेगी जिसमें पुनर्प्रवेश की कार्यवाही भी सम्मिलित है।

**भाग — ज****भूमि के अग्रिम आधिपत्य देने पर प्रतिबंध तथा अग्रिम आधिपत्य के पुराने मामलों में भूमि का आवंटन, प्रब्याजि व वार्षिक भू-भाटक का अधिरोपण तथा पट्टा निष्पादन**

**69. भूमि के अग्रिम आधिपत्य देने पर प्रतिबंध—** (1) इन निर्देशों के प्रभावशील होने के बाद स्थायी पट्टे पर आवंटन के किसी भी मामले में नजूल भूमि का अग्रिम आधिपत्य राज्य शासन के अनुमोदन के बिना नहीं दिया जायेगा।

(2) राज्य शासन के अनुमोदन से अग्रिम आधिपत्य सौंपने के पश्चात् भूमि का स्थायी पट्टा स्वीकृत किए जाने के मामले में अग्रिम आधिपत्य दिये जाने की दिनांक को लागू प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक की दरें देय होंगी। इस प्रकार कुल देय संगणित राशि में अग्रिम आधिपत्य के समय जमा की गई राशि को समायोजित करते हुए अग्रिम आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से भुगतान दिनांक तक की अवधि के लिए प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा।

**70. इस भाग के प्रावधानों का लागू होना—** इन निर्देशों के प्रभावशील होने के पूर्व जिन मामलों में कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए शासकीय भूमि या नजूल भूमि की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि का अग्रिम आधिपत्य दिया गया है और ऐसे प्रकरणों में औपचारिक आवंटन आदेश बाद में जारी किए गए हैं अथवा औपचारिक आवंटन आदेश जारी होना शेष हैं, उनमें आगामी कंडिकाओं के अनुसार स्थायी पट्टे के आवंटन तथा निष्पादन की कार्यवाही की जाएगी।

**71. प्रब्याजि का निर्धारण—** (1) भूमि आवंटन के ऐसे मामलों में जिनमें राज्य शासन, आयुक्त या कलेक्टर द्वारा तत्समय प्रभावशील राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार क्रमांक-1 या अन्य किन्हीं तत्समय विद्यमान निर्देशों के अनुसार औपचारिक आवंटन की स्वीकृति के पूर्व भारत सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग, उपक्रम या राज्य सरकार के किसी उपक्रम (निगम, मंडल या विकास प्राधिकरण आदि), सहकारी संस्थाएं, गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं, स्थानीय निकाय, सुधार न्यास, पूर्त संस्थाएं अथवा औद्योगिक या व्यावसायिक प्रयोजन या शैक्षणिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को भूमि का अग्रिम आधिपत्य सौंपा गया है और ऐसे मामलों में अंततः राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन का निर्णय लिया जाता है तो जिस वर्ष भूमि

का अग्रिम आधिपत्य सौंपा गया था उस वर्ष के संगणित बाजार मूल्य को आधार मानकर **कंडिका 19** में दी गई तालिका में सुसंगत प्रयोजन के लिए दर्शाए गए प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि का निर्धारण किया जाएगा।

(2) यदि आवंटिती द्वारा अग्रिम आधिपत्य के समय प्रब्याजि के पेटे कोई राशि जमा कराई गई है तो ऐसी राशि का उक्तानुसार निर्धारित प्रब्याजि में समायोजन किया जायेगा।

(3) यदि **उपकंडिका (2)** के अनुसार राशि के समायोजन के उपरांत कोई राशि आवंटिती के पक्ष में देय होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसी राशि का समायोजन आगामी वर्षों के वार्षिक भू-भाटक के पेटे किया जाएगा।

(4) यदि **उपकंडिका (2)** के अनुसार राशि के समायोजन के उपरांत कोई राशि राज्य शासन के पक्ष में देय होती है तो ऐसी बकाया राशि और उस पर भुगतान दिनांक तक की अवधि के लिए प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक की शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज राशि वसूल की जाएगी।

**72. वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण-** (1) ऐसे मामलों में अग्रिम आधिपत्य दिये जाने की दिनांक को प्रभावशील वार्षिक भू-भाटक की दरें लागू होंगी तथा उस पर भुगतान दिनांक तक की अवधि के लिए प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

(2) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (पूर्व नाम मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल), स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरणों के ऐसे विशिष्ट मामलों में जिनमें अग्रिम आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से 30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है और किन्हीं कारणों से आवंटन आदेश जारी नहीं हो पाया है, उनमें औपचारिक आवंटन जारी किया जाएगा:

परन्तु ऐसे आवंटन आदेश में अग्रिम आधिपत्य की दिनांक से दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिए **उपकंडिका (1)** के अनुसार परिगणित वार्षिक भू-भाटक प्रभावशील रखा जाएगा तथा इसके बाद की अवधि के लिए **कंडिका 19** में दी गई तालिका में दर्शाई गई दर के अनुसार लागू दर पर वार्षिक भू-भाटक नियत किया जाएगा।

**73. वार्षिक भू-भाटक की गणना की प्रक्रिया—** (1) ऐसे मामलों में जिनमें इन निर्देशों के प्रभावशील होने के पूर्व अग्रिम आधिपत्य दिया गया है, उनमें वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण आवासीय/शैक्षणिक प्रयोजन के मामलों में प्रब्याजि के 5 प्रतिशत और आवासीय/शैक्षणिक से भिन्न प्रयोजन के मामले में प्रब्याजि के 7.5 प्रतिशत के मान से किया जाएगा।

(2) ऐसे मामलों में जिनमें इन निर्देशों के प्रभावशील होने के पश्चात् अग्रिम आधिपत्य दिया जाता है, उनमें वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना के मान से किया जाएगा।

**74. आवंटिती संस्था द्वारा प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक की उप पट्टेदार से वसूली—** ऐसे मामलों में जिनमें भूमि का अग्रिम आधिपत्य किसी निकाय या संस्था को इस आशय के साथ सौंपा गया है कि भूमि का स्थल पर विकास उपरान्त विकसित भूखंडों को उप-पट्टे पर दिया जाएगा, उनमें **कंडिका 71, 72 तथा 73** के अनुसार निर्धारित प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक आवंटिती संस्था द्वारा उप पट्टेदार से समानुपातिक निर्धारण के आधार पर वसूल किया जा सकेगा, उससे अधिक नहीं।

**75. पट्टे का निष्पादन—** (1) ऐसे मामलों में जिनमें तत्समय प्रभावशील नियमों या परिपत्रों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार से किसी उपक्रम, संस्था, उद्योग या व्यक्ति के पक्ष में भूमि का आवंटन जारी किया गया है और आवंटिती द्वारा आवंटन आदेश की शर्त अनुसार मांग पत्र के आधार पर प्रब्याजि की राशि और उस पर देय वार्षिक भू-भाटक की वर्तमान तक की बकाया राशि जमा कराई गयी है तो ऐसे आवंटिती के पक्ष में स्थायी पट्टा निष्पादित किया जाएगा:

परन्तु यदि ऐसे मामले में प्रब्याजि या वार्षिक भू-भाटक की कोई राशि बकाया है तो ऐसी बकाया राशि और उस पर प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज राशि जमा कराए जाने पर पट्टा निष्पादित किया जाएगा।

(2) ऐसे मामलों में जहां इन निर्देशों के प्रभावशील होने के पश्चात् औपचारिक आवंटन आदेश जारी किए जाएँ उनमें **कंडिका 71, 72 तथा 73** के अनुसार देय प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण कर उसकी बकाया राशि तथा उस पर प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक 15

प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज राशि जमा कराए जाने पर पट्टा निष्पादित किया जाएगा।

(3) पट्टे के निष्पादन, पंजीयन तथा भू-अभिलेखों में प्रविष्टियों की अद्यतनीकरण के संबंध में इस अध्याय के **भाग-छ** में दिए गए उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

**76. इस भाग का पूर्व में निर्वर्तित मामलों में लागू न होना—** ऐसे मामलो में जिनमें पट्टा निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, इस भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे, तात्पर्य यह कि पूर्व में निर्वर्तित हो चुके मामलों को प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक की संगणना के लिये पुनः नहीं खोला जाएगा।

**स्पष्टीकरण—**‘निर्वर्तित मामला’ से तात्पर्य है, ऐसा मामला जिसमें सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के उपरान्त पट्टा निष्पादन किया जा चुका है।

## भाग— झ स्थायी पट्टे का नवीनीकरण

**77. स्थायी पट्टे के नवीनीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी—** स्थायी पट्टे के नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन के शमन (compounding) के लिए कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी होंगे।

**78. स्थायी पट्टे का नवीनीकरण** (1) पट्टेदार स्थायी पट्टे की अवधि के अवसान वर्ष की दिनांक 01 अप्रैल से अवसान दिनांक तक की अवधि के दौरान कभी भी पट्टे के नवीनीकरण के लिये सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) ऐसे मामलों में जहां **उपकंडिका (1)** के अनुसार नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया जाता है, उनमें सक्षम प्राधिकारी —

- (क) पट्टावधि के अवसान होने के बाद विलंब से प्रस्तुत किये गये नवीनीकरण के आवेदन पर पट्टा नवीनीकरण योग्य पाये जाने पर विलंब के लिये शमन राशि अधिरोपित करेगा; तथा
- (ख) विलंब के लिये अधिरोपित शमन राशि नियत किये जाने पर प्रकरण के पट्टे की शर्तों के उल्लंघन या अपालन का परीक्षण करते हुए नवीनीकरण के लिये अग्रसर होगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऐसे स्थायी पट्टों, जिनकी अवधि का अवसान हो चुका है, के नवीनीकरण के लिए इस भाग के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण करते हुए स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही कर सकेगा।

(4) स्थाई पट्टों के नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन तथा अपालन के मामले में ऐसे प्रकरणों पर जिनमें पूर्व के परिपत्रों (जो निरसित हैं या इन निर्देशों की कंडिका 148 द्वारा निरसित किये जा रहे हैं) के आधार पर शमन राशि अधिरोपित की गयी है एवं पट्टेदार द्वारा शमन राशि का भुगतान नहीं किया गया है और इस कारण ऐसे प्रकरणों में लीज नवीनीकरण लंबित है, ऐसे मामलों को अंतिम रूप से निराकृत नहीं मानते हुए पुनर्विचार में लेकर इन निर्देशों के अनुसार निराकृत किया जाएगा और तदनुसार निर्धारित शमन राशि जमा किये जाने पर पट्टे के नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी:



परन्तु जिन मामलों में निरसित परिपत्रों के आधार पर शमन राशि का आदेश पारित किये जाने के आधार पर निराकृत प्रकरणों में शमन राशि का भुगतान शासन पक्ष में किया जा चुका है, ऐसे मामलों को अंतिम रूप से निराकृत मानते हुए पुनः विचारण में नहीं लिया जायेगा।

**79. नजूल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना—** सक्षम प्राधिकारी मामले में नजूल अधिकारी से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्राप्त करेगा:—

- (क) पट्टेदार द्वारा वार्षिक भू-भाटक जमा किया गया है या नहीं, क्या उस पर कोई बकाया शेष है, यदि शेष है तो कब से, और अद्यतन बकाया राशि का विवरण;
- (ख) पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों का पालन किया गया है या नहीं, यदि किन्हीं शर्तों का उल्लंघन या अपालन पाया जाता है तो उल्लंघन या अपालन का विवरण;
- (ग) भूखण्ड का उपयोग तत्समय प्रवृत्त विकास योजना (मास्टर प्लान) में नियत प्रयोजन के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं;
- (घ) यदि भूमि उपयोग में परिवर्तन कर शर्त उल्लंघन किया गया है तो ऐसी दशा में भूखण्ड के पूर्ण या अंश भाग, जिसका भूमि उपयोग परिवर्तित किया गया है, का क्षेत्रफल तथा नजरी नक्शा;
- (ङ) पट्टेदार द्वारा पट्टे की अवधि के दौरान किसी शर्त के उल्लंघन या अपालन किए जाने पर ऐसे उल्लंघन या अपालन के मामले में किसी सक्षम प्राधिकार से शमन स्वीकृत किया गया है या नहीं और यदि हाँ तो ऐसे आदेश का विवरण; और
- (च) ऐसा अन्य कोई बिन्दु जिसे सक्षम प्राधिकारी उचित समझे।

**80. स्थायी पट्टे की शर्त का उल्लंघन या अपालन न होने की दशा में पट्टे का नवीनीकरण—** नजूल अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरांत यदि सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि स्थायी पट्टे की शर्त का कोई उल्लंघन या अपालन नहीं हुआ है या उल्लंघन या अपालन का शमन स्वीकृत हो चुका है और पट्टेदार पर कोई बकाया शेष नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सामान्यतः पट्टे का नवीनीकरण आगामी तीस वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगा:

परन्तु मूल पट्टे में यदि तीस वर्ष से भिन्न पट्टावधि रही है तो ऐसी दशा में पट्टे का नवीनीकरण उतनी अवधि, जितनी कि मूल पट्टे की पट्टावधि रही है, के लिये किया जायेगा।

**81. स्थायी पट्टे के नवीनीकरण पर वार्षिक भू-भाटक का पुनर्निर्धारण—** (1) यदि स्थायी पट्टे की अवधि का अवसान इन निर्देशों के प्रभावशील होने के दिनांक को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसे पट्टे का नवीनीकरण करते समय सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत नवीनीकरण करने की दिनांक को लागू दर से दो गुना वार्षिक भू-भाटक पुनर्निर्धारित करेगा।

(2) यदि स्थायी पट्टे की अवधि का अवसान इन निर्देशों के प्रभावशील होने की दिनांक के पूर्व हुआ है तो सक्षम प्राधिकारी—

(क) पट्टा अवसान की दिनांक से इन निर्देशों के प्रभावशील होने की दिनांक की अवधि के लिए—

(एक) यदि ऐसी अवधि तीस वर्ष का या उससे कम है तो ऐसी अवधि के लिए पट्टे में उल्लेखित वार्षिक भू-भाटक दर का छः गुना वार्षिक भू-भाटक पुनर्निर्धारित करेगा; और

(दो) यदि ऐसी अवधि तीस वर्ष से अधिक है तो प्रत्येक तीस वर्ष के पूर्ण या आंशिक कालखंड के लिए उसके ठीक पूर्ववर्ती कालखंड के लिए निर्धारित वार्षिक भू-भाटक का छः गुना वार्षिक भू-भाटक पुनर्निर्धारित करेगा; और

(ख) इन नियमों के प्रभावशील होने के दिनांक से **उपकंडिका (1)** के अनुसार वार्षिक भू-भाटक पुनर्निर्धारित करेगा।

(3) नवीनीकृत पट्टे में नियत वार्षिक भूभाटक के संबंध में **कंडिका 19 की उपकंडिका (2)** के प्रावधान लागू होंगे।

(4) उपकंडिका (1), (2) तथा (3) के प्रावधान ऐसे स्थायी पट्टों, जो नाममात्र वार्षिक भू-भाटक पर दिए गए हैं, पर लागू नहीं होंगे और ऐसे पट्टों की नवीनीकरण अवधि के दौरान पूर्वानुसार नाममात्र वार्षिक भू-भाटक अधिरोपित किया जाएगा।

**82. स्थायी पट्टे की शर्त का उल्लंघन या अपालन होने की दशा में पट्टे का नवीनीकरण—** (1) स्थायी पट्टों की शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन या अपालन

प्रतिवेदित होने या पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी पट्टेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण का निराकरण करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार शमन राशि लेकर पुनर्प्रवेश (re-entry) के अधिकार का त्यजन करते हुए शर्त उल्लंघन के मामले का निराकरण कर सकेगा—

### तालिका

स्थायी पट्टे के शर्त उल्लंघन या अपालन के मामले में देय शमन राशि

स. क्र.	शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप	शमन राशि
(1)	(2)	(3)
1	पट्टा अवधि अवसान के बाद नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के मामले में विलंब माफी के लिये (पट्टा अवधि अवसान से आवेदन के दिनांक तक के वर्षों हेतु)	प्रत्येक चूक वर्ष के लिए आवेदन के दिनांक को लागू बाजार मूल्य के 0.01 प्रतिशत के मान से।
2	पट्टा अवधि के अवसान होने की तिथि को कुल देय भू-भाटक की राशि जमा नहीं किए जाने की दशा में	देय बकाया राशि, देय बकाया राशि पर बकाया की दिनांक से प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज एवं बकाया राशि के 10 प्रतिशत के मान से शास्ति।
3	निर्धारित अवधि में भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करना—	
3.1	पट्टे में निर्माण हेतु उल्लेखित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न किए जाने पर, पुनर्प्रवेश के अधिकार का त्यजन करते हुए एक बार तीन वर्ष की	शमन राशि के निर्धारण हेतु आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य के 0.05 प्रतिशत के मान से।

स. क्र.	शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप	शमन राशि
(1)	(2)	(3)
	अतिरिक्त अवधि निर्माण करने हेतु प्रदान करने के लिए	
3.2	स.क्र. 3.1 के अनुसार प्रदत्त अतिरिक्त अवधि की समाप्ति एवं पट्टा अवसान के मध्य की अवधि में निर्माण करने पर, पुनर्प्रवेश के अधिकार का त्यजन करने के लिए	शमन राशि के निर्धारण हेतु आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य के 0.1 प्रतिशत के मान से।
3.3	पट्टे अवधि अवसान होने के उपरांत निर्माण कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में पट्टे का नवीनीकरण करने पर पुनर्प्रवेश के अधिकार का त्यजन कर एक बार पुनः तीन वर्ष की अवधि निर्माण हेतु प्रदान करने के लिए	शमन राशि के निर्धारण हेतु आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के मान से। टीप— पट्टे का नवीनीकरण किये जाने पर वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण स्थायी पट्टे के नवीनीकरण के सामान्य प्रावधान के अनुसार होगा (देखें कंडिका 81)
4	अंतरण की प्रतिबंधित अवधि के भीतर तथा/अथवा बिना समुचित अनुमति प्राप्त किये दान अथवा विक्रय द्वारा या अन्यथा (उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण को छोड़कर) भूखण्ड अंतरित किये जाने की दशा में	अंतरण दिनांक के बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत के मान से राशि और उस पर प्रथम वर्ष के लिये 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से और उसके पश्चात् की अवधि के लिये भुगतान दिनांक तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज टीप— अंतरणीय पट्टे के मामले में ही शमन स्वीकृत किया जाएगा, अहस्तांतरणीय पट्टे के मामले में नहीं। अन्य मामलों में पुनर्प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।

स. क्र.	शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप	शमन राशि
(1)	(2)	(3)
5	भूखण्ड के विभाजन के साथ हस्तांतरण—	
5.1	उत्तराधिकार के आधार पर भूखण्ड का विभाजन किये जाने पर	<p>एक मुश्त रूपये 2,000 /—</p> <p><b>टीप—</b> ऐसे प्रकरणों में तभी शमन किया जाएगा जब तत्समय प्रभावशील विकास योजना के अंतर्गत भूखण्ड का विभाजन अनुज्ञेय हो।</p>
5.2	उत्तराधिकार से भिन्न आधार पर भूखण्ड का विभाजन किये जाने पर	<p>आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत के मान से।</p> <p><b>टीप—</b> ऐसे मामलों में तभी शमन किया जाएगा जब तत्समय प्रभावशील विकास योजना के अंतर्गत भूखण्ड का विभाजन अनुज्ञेय हो।</p>
6	<p>आवासीय प्रयोजन के भूखण्ड का आवासीय से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि उपयोग किए जाने की दशा में, यदि ऐसे भिन्न प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग तत्समय प्रवृत्त विकास योजना (मास्टर प्लान) तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय हो</p> <p>कृपया इस तालिका के सरल क्रमांक 8 और नीचे इस कंडिका की उपकंडिका (4) तथा कंडिका 83 भी देखें,</p>	<p>(क) जहां पट्टेदार द्वारा ऐसे उपयोग के लिए आवेदन किया जाए—</p> <p>(एक) ऐसे भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल के, आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत राशि के बराबर प्रब्याजि प्रयोजन परिवर्तन शुल्क के रूप में ली जाएगी;</p> <p>(दो) ऐसे भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल पर मध्यप्रदेश</p>

स. क्र.	शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप	शमन राशि
(1)	(2)	(3)
		<p>भू-राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर परिगणित वार्षिक भू-भाटक नियत किया जाएगा; और</p> <p>(तीन) मूल प्रयोजन में उपयोग में लाए जाने वाले शेष क्षेत्रफल के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर संगणित वार्षिक भू-भाटक नियत किया जाएगा:</p> <p>परन्तु इन निर्देशों के प्रभावशील होने से पूर्व जारी पट्टों के मामलों में मूल प्रयोजन में उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल के लिये पूर्वानुसार भू-भाटक देय होगा और परिवर्तित क्षेत्रफल के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर संगणित वार्षिक भू-भाटक नियत किया</p>

स. क्र.	शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप	शमन राशि
(1)	(2)	(3)
		<p>जाएगा।</p> <p>(ख) जहां पटटेदार द्वारा बिना अनुमति प्रयोजन परिवर्तन कर लिया जाता है—</p> <p>(एक) ऐसे भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल के, आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत राशि के बराबर प्रब्याजि प्रयोजन परिवर्तन शुल्क के रूप में ली जाएगी;</p> <p>(दो) ऐसे भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर परिगणित वार्षिक भू-भाटक नियत किया जाएगा; और</p> <p>(तीन) मूल प्रयोजन में उपयोग में लाए जाने वाले शेष क्षेत्रफल के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर संगणित वार्षिक भू-भाटक नियत किया</p>

स. क्र.	शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप	शमन राशि
(1)	(2)	(3)
		<p>जाएगा:</p> <p>परन्तु इन निर्देशों के प्रभावशील होने से पूर्व जारी पट्टों के मामलों में मूल प्रयोजन में उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल के लिये पूर्वानुसार भू-भाटक देय होगा और परिवर्तित क्षेत्रफल के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर संगणित वार्षिक भू-भाटक नियत किया जाएगा।</p> <p>(ग) सभी मामलों में पट्टे में <b>कंडिका 19 की उपकंडिका (2)</b> में विहित शर्तें भी जोड़ी जाएंगी</p>
7	प्रयोजन परिवर्तन की शर्त उल्लंघन का नोटिस दिये जाने पर भूखण्ड का परिवर्तित प्रयोजन में उपयोग बंद कर उसे मूल प्रयोजन में उपयोग में लाए जाने की दशा में	एक मुश्त रुपये 20,000 /—
8	प्रब्याजि या भू-भाटक में रियायत देते हुए जारी किए गये आवासीय पट्टे में उल्लेखित भूमि उपयोग में परिवर्तन कर शर्त उल्लंघन किए जाने की दशा में, यदि ऐसा परिवर्तित	(एक) इस तालिका के सरल क्रमांक 6 के उपबंधानुसार प्रयोजन परिवर्तन शुल्क राशि तथा मूल पट्टा स्वीकृति के समय प्रब्याजि में दी गई रियायत के प्रतिशत को वर्तमान



स. क्र.	शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप	शमन राशि
(1)	(2)	(3)
	भूमि उपयोग तत्समय प्रवृत्त विकास योजना (मास्टर प्लान) तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय हो	<p>बाजार मूल्य से गुणा करने पर परिगणित राशि प्रब्याजि के रूप में ली जाएगी; और</p> <p>(दो) इस तालिका के सरल क्रमांक 6 के उपबंध अनुसार भू-भाटक भी नियत किया जायेगा।</p> <p><b>उदाहरण—</b> (1) आवंटिती 'क' को बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत प्रब्याजि के आधार पर आवंटित भूखंड के मामले में इस तालिका के सरल क्रमांक 6 के उपबंधानुसार प्रयोजन परिवर्तन शुल्क और (प्रब्याजि में दी गई रियायत का प्रतिशत <math>100 - 25 = 75\%</math> होगा) वर्तमान बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रब्याजि के रूप में और मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर संगणित वार्षिक भू-भाटक नियत किया जाएगा</p> <p>(2) आवंटिती 'क' को बिना प्रब्याजि के आधार पर आवंटित भूखंड के मामले में इस तालिका के सरल क्रमांक 6 के उपबंधानुसार प्रयोजन परिवर्तन</p>

स. क्र.	शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप	शमन राशि
(1)	(2)	(3)
		<p>शुल्क और (प्रब्याजि में दी गई रियायत का प्रतिशत <math>100 - 0 = 100\%</math> होगा) वर्तमान बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रब्याजि के रूप में और मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर संगणित वार्षिक भू-भाटक नियत किया जाएगा</p> <p>(तीन) सभी मामलों में पट्टे में कंडिका 19 की उपकंडिका (2) में विहित शर्तें भी जोड़ी जाएंगी</p>

(3) उपरोक्तानुसार शमन राशि की गणना करते समय आंशिक वर्ष के मामले में छह माह या अधिक की अवधि की गणना एक वर्ष के रूप में की जाएगी।

(4) तालिका के सरल क्रमांक 6 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि:-

(एक) (क) आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भूखण्ड में पट्टेदार द्वारा आवासीय उपयोग के साथ-साथ संरचना के 25 प्रतिशत से कम भाग का उपयोग स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा द्यूशन कार्य अथवा सिलाई-कढ़ाई, पापड़-बड़ी जैसे कुटीर उद्योग हेतु किया जाता है तो उसे व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तन नहीं माना जावेगा:

परंतु संरचना या उसके किसी भाग का उपयोग कोचिंग क्लासेस जैसे कार्य हेतु अथवा बुटीक, ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय के लिये उपयोग किया जाता है तो इसे व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तन माना जायेगा; और

(ख) आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित भूखण्ड पर निर्मित संरचना को यदि आवासीय प्रयोजन के लिये किराए पर दिया जाता हो, इसे व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तन नहीं माना जाएगा:

परंतु संरचना के सम्पूर्ण अथवा अंश भाग का उपयोग गेस्ट हाउस अथवा होस्टल के रूप में किया जाता है तो इसे व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तन माना जाएगा।

(दो) राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को आवंटित भूमि के मामले में तालिका के सरल क्रमांक 6 एवं 8 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(5) तालिका के सरल क्रमांक 8 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि रियायती पट्टे से तात्पर्य है पूर्ण बाजार मूल्य से कम राशि प्रब्याजि के रूप में जमा किये जाने के आधार पर आवंटित भूमि के पट्टे।

**83. आवासीय भूखंड के भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए आवेदन—** (1) यदि आवासीय भूखंड के पट्टेदार पट्टावधि के दौरान अथवा नवीनीकरण की कार्यवाही के दौरान पूर्ण भूखण्ड अथवा उसके अंश भाग का उपयोग परिवर्तित करना चाहता है और ऐसा परिवर्तन विकास योजना में अनुमत है तो वह सक्षम प्राधिकारी को इस हेतु अनुमोदित ले-आउट प्लॉन एवं विकास योजना में उक्त भूमि के उपयोग की सक्षम स्वीकृति के प्रमाण के साथ आवेदन करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी इस बात की संतुष्टि करेगा कि परिवर्तित भूमि उपयोग तत्समय प्रचलित विकास योजना (मास्टर प्लान) तथा अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार अनुमत है और ऐसी संतुष्टि के उपरान्त उपरोक्त तालिका के सरल क्रमांक 6 में वर्णित प्रयोजन परिवर्तन के कारण प्रयोजन परिवर्तन शुल्क एवं वार्षिक भू-भाटक तथा सरल क्रमांक 6 से भिन्न आवासीय पट्टों के मामलों में सरल क्रमांक 8 में वर्णित प्रयोजन परिवर्तन शुल्क, प्रब्याजि अंतर की राशि एवं वार्षिक भू-भाटक निर्धारित करेगा। आवेदक द्वारा इस प्रकार संगणित राशि जमा किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी भूमि के उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दे सकेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्वीकृति जारी होने पर पट्टे की शर्तों को उस सीमा तक संशोधित माना जायेगा।

**84. भूखण्ड में अनुमत क्षेत्रफल से अधिक निर्माण के मामलों में कार्यवाही—** यदि भूखण्ड में पट्टे की शर्त में निर्माण के लिये अनुमत क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण किया गया है और ऐसे निर्माण के लिए स्थानीय निकाय द्वारा लिखित अनुमति दी गई है अथवा शमन कर दिया गया है तो पट्टे की ऐसी सुसंगत शर्तों को उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

**85. पट्टे की अन्य शर्तों के उल्लंघन के मामलों में कार्यवाही— कंडिका-82** में दी गई तालिका में उल्लेखित मामलों के सिवाय पट्टे में अंकित किसी अन्य शर्त के उल्लंघन की दशा में अथवा शमन राशि का भुगतान न करने की स्थिति में अथवा पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी पट्टा नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुण-दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण छह माह में किया जाएगा। निराकरण में पुनर्प्रवेश की कार्यवाही भी सम्मिलित रहेगी।

**86. नवीनीकरण के पूर्व नामांतरण की कार्यवाही करना—** (1) पट्टे के नवीनीकरण के ऐसे मामले में जिसमें मूल पट्टेदार की मृत्यु हो चुकी है और पट्टे के नामांतरण की कार्यवाही नहीं कराई गई है, उसमें नवीनीकरण के पूर्व सर्वप्रथम पट्टेदार के उत्तराधिकारियों द्वारा यथास्थिति उत्तराधिकार या वसीयत के आधार पर पट्टे के नामांतरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा।

(2) ऐसे मामले में जिसमें पट्टेदार द्वारा भूखण्ड का विक्रय या दान से या अन्यथा अंतरण किया गया है, किन्तु पट्टे के नामांतरण की कार्यवाही नहीं कराई गई है, अंतरिती द्वारा पट्टे के नामांतरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा। यह कार्यवाही अहस्तांतरणीय स्थायी पट्टों के संबंध में नहीं की जा सकेगी।

(3) देय बकाया राशि एवं शमन राशि के भुगतान के उपरान्त ही नामांतरण की कार्यवाही की जाएगी। पट्टे के नामांतरण होने के उपरान्त ही नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही अहस्तांतरणीय स्थायी पट्टों के संबंध में नहीं की जा सकेगी।

(4) ऐसे मामले में जिसमें पट्टावधि अवसान होने के बाद पट्टे का नवीनीकरण कराए बिना ही भूखण्ड का अंतरण किया गया है, अंतरिती द्वारा पट्टे का नवीनीकरण चाहे जाने पर नवीनीकरण के अन्य प्रावधानों के अध्वधीन रहते हुए सर्वप्रथम मूल पट्टेदार के नाम कल्पित नवीनीकरण स्वीकार करते हुए, तदक्रम में

अंतरण के आधार पर अंतरिती के नाम से नवीनीकरण किया जाएगा। यह कार्यवाही अहस्तांतरणीय स्थायी पट्टों के संबंध में नहीं की जा सकेगी।

**87. शमन राशि का जमा किया जाना—** शर्त उल्लंघन के मामले में शमन राशि जमा किए जाने की सूचना देने के एक माह के अंदर आवेदक को शमन राशि जमा करना होगा।

**88. पट्टावधि के दौरान भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाना—** पट्टावधि के दौरान स्थायी पट्टे की शर्त उल्लंघन या अपालन के शमन किये जाने पर या अनुज्ञेय अंतरण के मामले में यथास्थिति भू-अभिलेख में प्रविष्टियां अद्यतन की जायेंगी। इस प्रकार प्रविष्टि अद्यतनीकरण के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत पंजीयन की अनिवार्यता नहीं होगी।

**89. पट्टावधि के अवसान पर नवीकृत पट्टा विलेख का निष्पादन तथा पंजीयन—**

(1) पट्टावधि के अवसान पर

(क) यदि पट्टावधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किए गये हैं, तो नवीनीकरण किये जाने पर नवीकृत पट्टा विलेख का पंजीयन कराया जायेगा; और

(ख) जिन मामलों में पट्टावधि के दौरान भू-अभिलेख की प्रविष्टियों में विधिसंगत परिवर्तन अंकित किये गये हैं, उनके अद्यतन भू-अभिलेख के अनुसरण में नवीकृत पट्टा विलेख का पंजीयन कराया जायेगा।

(2) यदि पट्टेदार नवीकृत पट्टा निष्पादित न कराए तो यह माना जाएगा कि उसने नवीकरण की अपनी मांग वापस ले ली है या उसे त्याग दिया है। अतः उसे ऐसी सूचना दी जाने पर भी कि यदि निर्दिष्ट अवधि में उसने पट्टा-विलेख निष्पादित न कराया तो यह माना जाएगा कि वह भूमि को पट्टे पर चालू नहीं रखना चाहता; यदि पट्टेदार नवीकृत पट्टा निष्पादित नहीं कराता तो ऐसी स्थिति में पट्टेदार को अतिक्रमणकर्ता मानकर बेदखल करने की कार्यवाही की जाएगी।

(3) नवीकृत पट्टे की अवधि मूल अवधि समाप्त होने की आगामी दिनांक से प्रारम्भ मानी जाएगी और भू-भाटक का पहला भुगतान उस दिनांक के तुरंत बाद की पहली अप्रैल को देय होगा।

(4) इसकी संभावना नहीं है कि कोई पट्टेदार नया पट्टा पंजीकृत कराने से मना करेगा तथापि यदि कोई ऐसा करने से इंकार करें, तो भी उसके द्वारा पहले से निष्पादित पट्टा वैध माना जाएगा, क्योंकि पंजीयन अधिनियम, 1908 (क्रमांक सोलह, सन् 1908) की धारा 90 (1) (घ) के उपबंधों की दृष्टि से उसका पंजीयन अनिवार्य नहीं है।

## भाग — अ

### अस्थायी पट्टे

**90. वर्तमान अस्थायी पट्टों का निराकरण—** (1) इन निर्देशों के प्रभावशील होने के बाद नजूल भूमि का निर्वर्तन अस्थायी पट्टे द्वारा नहीं किया जायेगा।

(2) पूर्व में जो अस्थायी पट्टे जारी किए जा चुके हैं, उन्हें आगे नवीकृत भी नहीं किया जायेगा; किन्तु ऐसे अस्थायी पट्टे जो विधिसंगत आदेश द्वारा प्रदत्त किए गये हैं, उनकी पट्टावधि अवसान तक प्रभावशील रहेंगे।

(3) ऐसे अस्थायी पट्टे जिनकी पट्टावधि का अवसान हो चुका है, किन्तु नवीकृत नहीं कराए गये हैं और पट्टेदार अथवा उसका विधिक उत्तराधिकारी भूमि पर काबिज है या ऐसे अस्थायी पट्टे जिनकी पट्टावधि शेष है, को यदि अस्थायी पट्टेदार या उसका विधिक उत्तराधिकारी जो काबिज है स्थायी पट्टे में परिवर्तित कराना चाहता है, तो वह स्थायी पट्टे में परिवर्तन के लिये **प्ररूप चार** में कलेक्टर को आवेदन दे सकेगा:

परंतु उक्त उपबंध मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1985) के अंतर्गत प्रदत्त पट्टाधृति अधिकार के मामले में लागू नहीं होंगे।

(4) कलेक्टर ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर यदि पट्टे का प्रयोजन विकास योजना (यदि कोई लागू है) के अनुरूप है (वर्तमान उपयोग पूर्व में दिये गये अस्थायी पट्टे के प्रयोजन से भिन्न होने के स्थिति में भी), तो स्थानीय निकाय का परामर्श प्राप्त कर, यदि कलेक्टर यह पाता है कि ऐसे प्रश्नाधीन भूखण्ड को स्थायी पट्टे में परिवर्तित किये जाने पर कोई लोक प्रयोजन प्रतिकूल प्रभावित नहीं होगा या लोक स्वास्थ्य के लिये हानिकर नहीं होगा तो —

(एक) ऐसे अस्थायी पट्टे के अवसान की दिनांक से वर्तमान तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना की दर पर वार्षिक भू-भाटक की संगणित राशि और ऐसे अस्थायी पट्टे की प्रश्नाधीन भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर की राशि, परिवर्तन शुल्क के रूप में लेकर स्थायी पट्टे में परिवर्तित कर सकेगा और मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं

पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना वार्षिक भू-भाटक नियत करेगा; और

- (दो) ऐसे अस्थायी पट्टे जिनकी पट्टावधि शेष है पट्टे की प्रश्नाधीन भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि, परिवर्तन शुल्क के रूप में लेकर स्थायी पट्टे में परिवर्तित कर सकेगा और मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना वार्षिक भू-भाटक नियत करेगा।

(5) कलेक्टर द्वारा उपकंडिका (4) में परिवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने पर परिवर्तन शुल्क एवं वार्षिक भू भाटक की राशि परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मदों में जमा की जाएगी।

(6) ऐसे स्थायी पट्टों पर **कंडिका 19 की उपकंडिका (2)** के उपबंध भी लागू होंगे।

(7) स्थायी पट्टे में परिवर्तन की स्वीकृति के पश्चात् स्थायी पट्टे के निष्पादन की कार्यवाही इस अध्याय के **भाग छ** के अनुसार की जाएगी।

(8) ऐसे अस्थायी पट्टे, जिनकी पट्टावधि का अवसान हो चुका है और जिनके संबंध में उपकंडिका (4) के अंतर्गत स्थायी पट्टे में परिवर्तित नहीं किया गया है, के भूखण्ड पर काबिज व्यक्ति को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में मानते हुए, संहिता की धारा **248** के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

**अध्याय – चार****नगरीय निकाय को तथा विकास प्राधिकरण/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि दी जाना****भाग— क****नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि का आवंटन**

**91. सक्षम प्राधिकारी—** नगरीय निकाय को नजूल भूमि भूमिस्वामी हक में आवंटन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी संभागीय मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति होगा:

परंतु भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के आवंटन के मामले में सक्षम प्राधिकारी 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति' होगी।

**92. प्रयोजन—** नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में भूमि का आवंटन निम्न तालिका में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा—

**तालिका**

नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि का आवंटन :  
प्रयोजन तथा प्रब्याजि

सरल क्रमांक	प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में दी जाना है	प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
1	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए— जैसे सड़क, उद्यान, खेल का मैदान, फिल्टर प्लांट, कचरा खन्ती (ट्रेचिंग ग्राउंड), अस्पताल, स्कूल, कार्यालय, 1-बस स्टैंड आदि	शून्य
2	शत प्रतिशत राज्य पोषित योजना हेतु	शून्य
3	ऐसी भूमि जिन पर बिना खास निर्माण किए आय होती है— जैसे हाट बाजार, मनोरंजन स्थल के लिये	शून्य



सरल क्रमांक	प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में दी जाना है	प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
4	केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आवासीय योजनाओं के लिये	शून्य
5	ऐसी भूमियां जिन पर योजना बनाकर निर्माण करने से नियमित आय होती है— जैसे मार्केट, कॉम्प्लेक्स, <sup>1</sup> (विलोपित) आदि के लिये	50 प्रतिशत
6	ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए	50 प्रतिशत
7	नगरीय निकाय द्वारा अपने कर्मचारियों की आवासीय योजना के लिए	50 प्रतिशत

**93. भूमि का चिन्हांकन तथा आवेदन—** (1) नगरीय निकाय द्वारा लैण्ड बैंक में से भूमि का वयन किया जाएगा। भूमि आवंटन के लिए यथास्थिति नगर निगम आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा कलेक्टर को प्ररूप एक में आवेदन किया जाएगा।

(2) शून्य प्रब्याजि पर भूमि आवंटन की श्रेणी से भिन्न मामले में आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

**94. जांच प्रतिवेदन—** (1) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन पत्र को अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

1. म.प्र. राजपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2021 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्रमांक 6-76/2019/सात-3 दि. 3 अगस्त, 2021 संशोधन द्वारा (मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अध्याय-चार, भाग-क की कंडिका-92 की तालिका के सरल क्रमांक-5 के कालम-2 में अंकित ऐसी भूमियों, जिन पर योजना बनाकर निर्माण करने से नियमित आय होती है—जैसे मार्केट, कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड आदि में से केवल शब्दों "बस स्टैंड" को विलोपित किया जाकर उसे तालिका के सरल क्रमांक-1 के कालम-2 में अंकित शब्दों "सार्वजनिक प्रयोजन के लिए—जैसे सड़क, उद्यान, खेल का मैदान, फिल्टर प्लांट, कचरा खन्ती (ट्रेडिंग गार्लर) अस्पताल स्कूल कार्यालय" के पश्चात प्रतिस्थापित किया गया)

(3) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, आवेदक नगरीय निकाय के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा।

(4) नजूल अधिकारी द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा। नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे, यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है।

(5) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा—

- (क) तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नहीं?;
- (ख) भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन;
- (ग) आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता; और
- (घ) क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

(6) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन **प्ररूप दो** में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा।

**95. नगरीय निकाय को नजूल भूमि भूमिस्वामी अधिकार में आवंटित करने की स्वीकृति—** (1) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर नगरीय निकाय को सूचित किया जाएगा। जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर नगरीय निकाय तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा किन्तु भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

(3) जिस मामले में भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये गठित नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाएगा जो राजस्व विभाग द्वारा नगरीय निकाय तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा।

**96. प्रब्याजि तथा भू-राजस्व-** आवंटित की गई भूमि पर **कंडिका 92** की तालिका के कॉलम (3) में विहित दर से प्रब्याजि तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार वार्षिक भू-राजस्व देय होगा।

**97. आवंटन आदेश एवं भू-अभिलेखों की प्रविष्टियों का अद्यतनीकरण-** (1) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर नगरीय निकाय के द्वारा प्रब्याजि की राशि जमा कर दिए जाने के उपरान्त कलेक्टर द्वारा नगरीय निकाय के पक्ष में भूमि के भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन का आदेश **प्ररूप पांच** में जारी किया जाएगा।

(2) कलेक्टर, आवंटन आदेश के पश्चात् तथा देय शोध्द, यदि कोई हो, के जमा कराये जाने के पश्चात्, **प्ररूप छह** में 'भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख' निष्पादित करेगा।

(3) भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख निष्पादित होने के पश्चात् नगरीय निकाय को भूमि का आधिपत्य सौंपा जाएगा तथा भू-अभिलेखों की प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी।

### भाग — ख

#### स्थानीय निकाय को ध्वजदंड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन

**98. सक्षम प्राधिकारी** — स्थानीय निकाय को ध्वजदंड या प्रतिमा स्थापित करने के लिए भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि का आवंटन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी संभागीय मुख्यालय पर स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति होगा:

परंतु भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के आवंटन के मामले में सक्षम प्राधिकारी 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति' होगी।

**99. भूमि का आकार** — ऐसे प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त आकार की भूमि जो सामान्यतः 10x10 मीटर (एक सौ वर्गमीटर) से अधिक नहीं होगी, दी जा सकेगी।

**100. आवंटन की प्रक्रिया** — (1) यदि कोई संस्था ध्वजदंड अथवा अखिल भारतीय या राज्य स्तर के ख्याति प्राप्त व्यक्ति की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव करे तो वह लैंड बैंक में से भूमि का चयन कर अपना आवेदन **प्ररूप एक** में कलेक्टर को प्रस्तुत करेगी।

(2) आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में **परिशिष्ट 'क'** में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(3) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन पत्र को अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा।

**101. जांच प्रतिवेदन**— (1) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में **कंडिका 142** में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा। स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे और यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है।

(3) स्थानीय निकाय प्रस्तावित ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना के लिए सहमत है तो उसे यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति अनिवार्यतः देनी होगी कि ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना के उपरान्त भविष्य में उसे संरक्षित, गरिमामय एवं दर्शनीय स्थिति में रखा जाएगा जिसका दायित्व स्थानीय निकाय का होगा।

(4) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा —

- (क) प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन;
- (ख) ध्वजदंड या प्रतिमा की गरिमा एवं दर्शनीयता की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता;
- (ग) सड़क—सुरक्षा तथा यातायात की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता; और
- (घ) प्रस्तावित स्थल पर भविष्य में समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होने (जैसे जयंती, पुण्यतिथि आदि अवसरों पर) अथवा बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना की दृष्टि से स्थल की उपयुक्तता।

(5) सड़क, चौराहा या तिराहा के बीच में ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह सड़क—सुरक्षा तथा यातायात की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। साथ ही भविष्य में सड़क, चौराहा आदि के विस्तार की स्थिति निर्मित होने पर प्रतिमा के अन्यत्र विस्थापन पर विवाद की संभावना रहती है।

(6) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जा कर जिला नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा।

## 102. जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय और भू-राजस्व की देयता—

(1) यदि जिला नजूल निर्वर्तन समिति मामले में सक्षम प्राधिकारी है तथा भूमि का आवंटन करना उपयुक्त समझती है तो वह राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग

तथा संस्कृति विभाग को अपना प्रतिवेदन प्रेषित कर उनकी सहमति प्राप्त करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग तथा संस्कृति विभाग की सहमति प्राप्त होने पर जिला नजूल निर्वर्तन समिति ध्वजदंड या प्रतिमा स्थापना के लिए स्थानीय निकाय को भूमि का आवंटन बिना प्रब्याजि के भूमिस्वामी हक में स्वीकृत कर सकेगी।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति नजूल अधिकारी का जांच प्रतिवेदन अपने अभिमत के साथ संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित करेगी। यदि संभाग नजूल निर्वर्तन समिति भूमि का आवंटन करना उपयुक्त समझती है तो वह अपना प्रतिवेदन राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग तथा संस्कृति विभाग को प्रेषित कर उनकी सहमति प्राप्त करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग तथा संस्कृति विभाग की सहमति प्राप्त होने पर संभाग नजूल निर्वर्तन समिति स्थानीय निकाय को भूमि का आवंटन बिना प्रब्याजि के भूमिस्वामी हक में कर सकेगी:

परन्तु भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति अपने अभिमत के साथ मामला राज्य शासन को प्रेषित करेगी। ऐसे मामले में भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये गठित नजूल निर्वर्तन समिति भूमि का आवंटन बिना प्रब्याजि के भूमिस्वामी हक में कर सकेगी।

(3) आवंटन आदेश **प्ररूप पांच** में जारी किया जाएगा।

(4) उपकंडिका (1) अथवा (2) के अंतर्गत आवंटित की गई भूमि पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार वार्षिक भू-राजस्व देय होगा।

(5) कलेक्टर, आवंटन आदेश के पश्चात् **प्ररूप छह** में 'भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख' निष्पादित करेगा।

(6) भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

**103. भूमि का कब्जा सौंपना** — सक्षम प्राधिकारी से भूमि आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने तथा भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख निष्पादित होने पर कलेक्टर स्थानीय निकाय को भूमि का कब्जा सौंपेगा। तदुपरांत भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाएगी।

**भाग — ग****विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि का आवंटन**

**104. सक्षम प्राधिकारी—** (1) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 के अंतर्गत नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा अंतिम नगर विकास स्कीम प्रकाशित किये जाने पर ऐसी स्कीम से आच्छादित क्षेत्र के भीतर स्थित नजूल भूमि यथास्थिति विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमिस्वामी अधिकार में निर्वर्तित की जा सकेगी।

(2) कंडिका 104 में वर्णित नगर विकास स्कीम से आच्छादित क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि, यदि स्कीम के अधीन आने वाली भूमि के कुल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, के भूमिस्वामी हक में आवंटन के लिये सक्षम प्राधिकारी संभागीय मुख्यालय में स्थित मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति होगी:

परंतु भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के आवंटन के मामले में सक्षम प्राधिकारी 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति' होगी।

**105. प्रयोजन, प्रब्याजि तथा भू-राजस्व—** (1) विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमि का आवंटन कंडिका 104 में वर्णित उनकी घोषित स्कीम में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये भूमि के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर की प्रब्याजि राशि लेकर भूमिस्वामी हक में दी जा सकेगी।

(2) आवंटित की गई भूमि पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार वार्षिक भू-राजस्व देय होगा।

(3) विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटन के आदेश की दिनांक से तीन वर्ष के भीतर प्रब्याजि की राशि जमा कराई जा सकेगी। आवंटन की दिनांक से दो वर्ष तक कोई ब्याज देय नहीं होगा किन्तु दो वर्ष की अवधि के अवसान उपरांत देय राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय होगा।

(4) विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा नियत भू-राजस्व आवंटन की दिनांक से देय होगा। भू-राजस्व की अदायगी में चूक के मामले में बकाया पर प्रथम वर्ष के लिये 12 प्रतिशत और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक की शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

**106. भूमि आवंटन के लिये आवेदन-** (1) यथास्थिति विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 के अंतर्गत नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा अंतिम नगर विकास स्कीम प्रकाशित किये जाने पर ऐसी स्कीम से आच्छादित क्षेत्र के भीतर स्थित नजूल भूमि में से भूमि का चयन कर भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिये कलेक्टर को **प्ररूप एक** में आवेदन किया जाएगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क रुपये दस हजार सरकारी खजाने में **परिशिष्ट 'क'** में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

**107. जांच प्रतिवेदन-** (1) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन पत्र को अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में **कंडिका 142** में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

(3) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, आवेदक नगरीय निकाय के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा।

(4) नजूल अधिकारी द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा। नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे, यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है।



(5) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन **प्ररूप दो** में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा।

**108. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को नजूल भूमि भूमिस्वामी हक में आवंटित करने की स्वीकृति—** (1) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर नगरीय निकाय को सूचित किया जाएगा। जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर नगरीय निकाय तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा किन्तु भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

(3) जिस मामले में भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये गठित नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाएगा जो राजस्व विभाग द्वारा नगरीय निकाय तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा।

**109. आवंटन आदेश एवं भू अभिलेखों में प्रविष्टियों का अद्यतीकरण—** (1) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर यथास्थिति विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूमि के भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन का आदेश **प्ररूप पांच** में जारी किया जाएगा।

(2) कलेक्टर, आवंटन आदेश के पश्चात् तथा देय शोध, यदि कोई हो, के जमा कराये जाने के पश्चात्, **प्ररूप छह** में 'भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख' निष्पादित करेगा।

(3) भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क यथास्थिति विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख निष्पादित होने के पश्चात् यथास्थिति विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमि का आधिपत्य सौंपा जाएगा तथा भू अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी।

## अध्याय — पांच

### नजूल भूमि का नीलामी द्वारा भूमिस्वामी हक में निर्वर्तन

**110. नीलामी द्वारा नजूल भूमि के निर्वर्तन के लिए भूमि का चयन—** (1) सामान्यतः निम्न प्रकृति की भूमियां नीलामी द्वारा भूमिस्वामी हक में निर्वर्तन के लिए चयनित की जाएंगी—

- (क) ऐसी नजूल भूमियां जो व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित हैं या निजी भूमियों से घिरी हुई हैं या अन्य कोई भूमियां जिनका निर्वर्तन व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है; और
- (ख) नगरीय क्षेत्र में स्थित बड़े आकार की रिक्त नजूल भूमियां जो विकास योजना के अनुरूप प्रयोजन हेतु नीलामी द्वारा निर्वर्तित किए जाने योग्य हैं।

(2) ऐसी भूमियां जिनकी आवश्यकता किसी महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है, नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिए चयनित नहीं की जाएंगी।

**111. नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिए भूमि का चयन करने एवं नीलाम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी—** (1) नीलामी निर्वर्तन के लिये भूमि के चयन एवं नीलाम करने के लिये सक्षम प्राधिकारी निम्न तालिका अनुसार होंगे :—

#### तालिका

नीलामी हेतु भूखण्ड के चयन एवं स्वीकृति की प्राधिकारिता

क्र.	भूमि का क्षेत्रफल एवं बाजार मूल्य	सक्षम प्राधिकारी	
		चयन हेतु	नीलामी की कार्यवाही हेतु
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1.1 नगरीय क्षेत्र में 10,000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के मामले में 1.2 नगरेतर क्षेत्र में 50,000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के मामले में	संभाग नजूल निर्वर्तन समिति	जिला नजूल निर्वर्तन समिति
2.	2.1 नगरीय क्षेत्र में 10,000 वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्ड के मामले में 2.2 नगरेतर क्षेत्र में 50,000 वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्ड के मामले में	राज्य नजूल निर्वर्तन समिति की अनुशंसा पर भूमि प्रबंधन प्राधिकारी	भूमि प्रबंधन प्राधिकारी

(2) उक्त तालिका में उल्लेखित भूमि प्रबंधन प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा।

### **112. नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिए भूमि के चयन के लिए प्रतिवेदन तैयार करना—**

(1) नजूल अधिकारी कलेक्टर के निर्देश पर लैण्ड बैंक में उपलब्ध किसी नजूल भूमि को नीलामी द्वारा निर्वर्तित किये जाने हेतु चयनित करने के लिए प्रतिवेदन तैयार करेगा।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के नीलामी द्वारा निर्वर्तन के संबंध में **कंडिका 142** में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

(3) नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा। स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे, यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित निर्वर्तन में कोई आपत्ति नहीं है।

(4) नजूल अधिकारी अपना प्रतिवेदन **प्ररूप सात** में जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सचिव को प्रेषित करेगा जिसमें एक से अधिक भूखण्ड होने की दशा में अथवा किसी बड़े भूखण्ड का अंशभाग होने की दशा में ऐसे निर्वर्तन किये जाने वाले प्रत्येक भूखण्ड तक आवागमन के लिये युक्तियुक्त माप के पहुंचमार्ग को भी प्रतिवेदन के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाया जाएगा। किसी बड़े भूखण्ड के अंशभाग के निर्वर्तन के मामले में शेष भाग के लिये भी भविष्य में पहुंचमार्ग उपलब्ध रहे यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।

### **113. सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी द्वारा निर्वर्तन हेतु भूमि के चयन की स्वीकृति—**

(1) नजूल अधिकारी के प्रतिवेदन का परीक्षण कर जिला नजूल निर्वर्तन समिति अपने अभिमत के साथ मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित करेगी।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है वहां उसके द्वारा नीलामी द्वारा निर्वर्तन हेतु भूमि के चयन की स्वीकृति देने के संबंध में अंतिम निर्णय लेकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा। जिस मामले में

राज्य नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें संभाग नजूल निर्वर्तन समिति अपने अभिमत के साथ मामला राज्य नजूल निर्वर्तन समिति को निर्णय हेतु मामला प्रेषित किया जाएगा।

(3) जिस मामले में चयन हेतु राज्य नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है वहां उसके द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में नीलामी द्वारा निर्वर्तन हेतु भूमि के चयन की स्वीकृति देने के संबंध में निर्णय लेकर भूमि प्रबंधन प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी द्वारा निर्वर्तित किये जाने हेतु चयनित भूमि का आधार मूल्य (अपसेट प्राईज) नियत किया जायेगा जो चयनित भूमि के लिये अनुमत प्रयोजनों के लिये निर्धारित दरों में से उच्चतम दर के आधार पर संगणित बाजार मूल्य से कम नहीं होगा।

**114. चयनित भूमि के क्षेत्रफल का सत्यापन एवं सीमांकन—** सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित भूखण्डों की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व स्थल पर क्षेत्रफल सत्यापन कराएगा और सीमांकन उपरांत प्रत्येक भूखण्ड पर सीमाचिन्ह स्थापित कर पृथक-पृथक दर्शाया जाएगा।

**115. नीलामी की प्रक्रिया—** (1) नीलामी द्वारा निर्वर्तन हेतु भूमि के चयन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त होने तथा **कंडिका 114** के अनुसार सीमांकन तथा क्षेत्रफल का सत्यापन किये जाने के उपरांत ऐसी भूमि को नीलाम किया जायेगा।

(2) नीलामी की कार्यवाही **कंडिका 111** में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी के निर्देशन में की जाएगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी नीलामी की सार्वजनिक उद्घोषणा **प्ररूप आठ** में **कंडिका 142** में विहित रीति से जारी करेगा, जिसमें नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति या संस्था को पंजीयन हेतु न्यूनतम 21 दिवस का समय दिया जायेगा।

(4) सार्वजनिक उद्घोषणा उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, किया जाएगा। व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए नीलामी के विज्ञापन का प्रकाशन दोहराया भी जा सकता है।

(5) नीलामी ई-ऑक्शन की प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी, जिसमें समस्त कार्यवाही चिन्हित पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जाएगी।

(6) चिन्हित पोर्टल पर ई-ऑक्शन किये जा रहे भूखण्ड का ब्यौरा, उसकी पहचान, उसका सांकेतिक स्थल मानचित्र, निविदा दस्तावेज का अवलोकन करने एवं डाउन लोड करने के निर्देश, **कंडिका 113 की उपकंडिका (4)** के अनुसार संगणित भूमि का न्यूनतम आधार मूल्य (अपसेट प्राईज), और उसके आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार वार्षिक निर्धारण (भू-राजस्व) तथा निविदा में भाग लेने के लिये अन्य आवश्यक जानकारी यथा- निविदा ऑफर जमा करने एवं निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान और प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) जो भूखण्ड के न्यूनतम आधार मूल्य (अपसेट प्राईज) के दो प्रतिशत के मान से होगी, आदि महत्वपूर्ण ब्यौरे भी प्रदर्शित किए जाएंगे। निविदा दस्तावेज राजस्व विभाग तथा जिले के कलेक्टर की वेबसाइटों से भी डाउन लोड किए जा सकेंगे।

(7) भूखंड की नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति या संस्था को उक्त पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रथमतः निर्धारित प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) वेबसाइट के माध्यम से, अपने वांछित विवरण तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर अपना पंजीयन कराना होगा।

(8) पंजीयन उपरांत इच्छुक व्यक्ति या संस्था लॉग-इन आई. डी. एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए ई-नीलामी के लिए नियत समयावधि (टाइम विंडो) के भीतर अपना ऑफर दर्ज कर नीलामी की ऑन लाइन प्रक्रिया में भाग ले सकेगा।

**116. निविदा में भाग लेने हेतु पात्रता-** राज्य में भूमि धारण करने के लिए पात्र सभी व्यक्ति तथा संस्थाएँ नीलामी में भाग ले सकेंगे जब तक कि उन्हें किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नीलामी में भाग लेने से निरह न किया गया हो।

**117. निविदाओं का परीक्षण एवं निराकरण-** (1) चिन्हित पोर्टल पर निविदाकर्ताओं के द्वारा दिए गए ऑफरों के तुलनात्मक पत्रक के आधार पर उच्चतम निविदा ऑफरकर्ता की निर्धारित प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) रोक कर अन्य निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गयी निर्धारित प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में अंतरित कर वापिस की जाएगी।

(2) **कंडिका 111** की तालिका के सरल क्रमांक 1 के मामलों में, नजूल अधिकारी नीलामी की कार्यवाही का प्रतिवेदन **प्ररूप नौ** में तैयार कर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित करेगा। जिला नजूल निर्वर्तन समिति नीलामी की कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लेकर जिला कलेक्टर को आगामी कार्यवाही हेतु संसूचित करेगी।

(3) **कंडिका 111** की तालिका के सरल क्रमांक 2 के मामलों में, भूमि प्रबंधन प्राधिकारी नीलामी की कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लेकर **प्ररूप दस** में निर्णय की संसूचना राज्य शासन (राजस्व विभाग) को प्रेषित करेगा। राज्य शासन प्राप्त संसूचना के आधार पर जिला कलेक्टर को उप कण्डिका 4 के अनुसरण में कार्रवाई हेतु संसूचित करेगा।

(4) कलेक्टर यथास्थिति उप कंडिका (2) या (3) के निर्णय के अनुसरण में सफल निविदाकार को संसूचित करते हुए यह अपेक्षा करेगा कि उसके द्वारा ऑफर राशि में धरोहर राशि के समायोजन उपरांत शेष राशि नियत कालावधि जो तीस दिवस से अधिक की नहीं होगी, के भीतर **परिशिष्ट 'क'** में उल्लेखित मद में जमा करे। कलेक्टर सफल निविदाकार के आवेदन पर अपेक्षित शेष राशि जमा करने के लिए नियत समयावधि में 60 दिवस से अनधिक वृद्धि स्वीकृत कर सकेगा:

परन्तु ऐसी वृद्धि तभी स्वीकृत की जा सकेगी जब सफल निविदाकार अपने आवेदन पत्र के साथ अतिरिक्त अवधि के लिए देय राशि पर बारह प्रतिशत वार्षिक के दर से साधारण ब्याज जमा करने पर सहमति दे।

(5) नियत समयावधि और यदि अतिरिक्त अवधि स्वीकृत की गई है तो ऐसी अतिरिक्त अवधि के अवसान तक निविदाकार द्वारा अपेक्षित शेष राशि जमा नहीं करायी जाती है तो निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी और निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) राजसात हो जाएगी।

(6) उपरोक्त उपकंडिका (5) के अधीन निविदा निरस्त होने पर प्रश्नाधीन भूखण्ड की पुनः नीलामी की जा सकेगी।

(7) नीलामी की प्रक्रिया, प्राप्त निविदाओं के परीक्षण एवं निराकरण तथा अन्य अनुषांगिक बिन्दुओं पर कार्यवाही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन होगी।

**118. भू-राजस्व—** नीलामी से भूमिस्वामी हक में निर्वर्तित की गई भूमि पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार वार्षिक भू-राजस्व देय होगा।

**119. विक्रय विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जे का प्रदाय—** सफल निविदाकार की ओर से समस्त राशियां जमा किए जाने पर कलेक्टर द्वारा विक्रय विलेख प्रारूप ग्यारह में निष्पादित किया जाएगा जिसे निविदाकार स्वयं के व्यय पर पंजीकृत करवाएगा। पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाने पर भूखण्ड का कब्जा क्रेता को सौंपा जाएगा। तदुपरांत भू-अभिलेखों की प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी।

**120. वित्तीय प्रावधान—** भू-खण्डों की नीलामी किए जाने पर होने वाले व्यय के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान प्रमुख राजस्व आयुक्त के बजट में राजस्व विभाग द्वारा किए जाएंगे। प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार इस मद में जिलों को बजट आवंटन दिया जाएगा।

## अध्याय — छह लाइसेंस

**121. प्रयोजन जिनके लिए नजूल भूमि लाइसेंस पर दी जा सकती है—** इन निर्देशों के प्रभावशील होने के बाद नजूल भूमि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए लाइसेंस पर दी जा सकेगी—

- (क) खुली नजूल भूमि, जो अतिक्रमित नहीं की गई है, भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण किए बिना नियत अवधि के लिए उपयोग में लाने के लिए;
- (ख) नदी या नाले पर आवागमन के लिये पुल, पुलिया निर्माण या कन्वेयर बेल्ट अथवा रोप ट्रॉली द्वारा सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिये न्यूनतम आवश्यक निर्माण के साथ उपयोग में लाए जाने के लिए; और
- (ग) गौशाला के लिए।

**122. सक्षम प्राधिकारी—** (1) लाइसेंस देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे—

- (क) खुली नजूल भूमि यथा तम्बू या शामियाना लगाने या निर्माण सामग्री इकट्ठी कर रखने के लिए अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए— कलेक्टर;
- (ख) नदी या नाले के ऊपर से पुल, पुलिया निर्माण के लिए या सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने हेतु कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के निर्माण के लिए अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए— जिला नजूल निर्वर्तन समिति;
- (ग) गौशाला के लिये दस एकड़ तक भूमि, अधिकतम 10 वर्ष के लिये— जिला नजूल निर्वर्तन समिति; और
- (घ) गौशाला के लिये दस एकड़ से अधिक भूमि, पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित लाइसेंस अवधि के लिये— पशुपालन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।



(2) लाइसेंस नवीकृत नहीं किया जाएगा। यदि आवेदक लाइसेंस की समयावधि में वृद्धि चाहता है तो उसके आवेदन पर नया लाइसेंस तत्समय प्रचलित नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा।

**123. पुल, पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली निर्माण के लिये लाइसेंस की अहताएँ और शर्तें—** (1) ऐसे धारक को, जिसकी भूमियां किसी नदी या नाले के दोनों किनारों पर स्थित हों, अपने दोनों भू-भागों में आवागमन को सुगम बनाने के लिये नदी या नाले पर, जल प्रवाह को अवरुद्ध किए बिना, समुचित ऊँचाई की पुल, पुलिया निर्माण के लिए या कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के माध्यम से सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए लाइसेंस दिया जा सकेगा।

(2) लाइसेंस में ऐसे पुल, पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली की अनुमत ऊँचाई, अन्य सामान्य शर्तें तथा ऐसी विशिष्ट शर्तें जिन्हें कलेक्टर आवश्यक समझे, का उल्लेख किया जाएगा।

(3) लाइसेंसधारी द्वारा पुल, पुलिया कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के निर्माण का संरचना रूपांकन (Structural Design) पंजीकृत संरचना यंत्री (Registered Structural Engineer) से तैयार कराकर, लोक निर्माण विभाग अथवा स्थानीय निकाय के कार्यपालन यंत्री से अनुमोदन कराया जाएगा।

(4) पुल, पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली जैसी संरचना के रख रखाव का दायित्व लाइसेंस अवधि के दौरान लाइसेंसधारी पर होगा और अवधि अवसान के पश्चात्, यदि नया लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो ऐसी संरचना लाइसेंस अवधि के पश्चात् तीन माह की अवधि के भीतर लाइसेंसधारी द्वारा हटाई जाएगी। यदि नियत अवधि में ऐसी संरचना नहीं हटाई जाती है तो कलेक्टर लाइसेंसधारी के व्यय पर उसे हटवा सकेगा:

परंतु यदि ऐसी संरचना लोक हित में उपयोगी है तो कलेक्टर उसे राजसात करते हुए स्थानीय निकाय अथवा लोक निर्माण विभाग या अन्य एजेंसी को प्रबंधन एवं संधारण के लिये सौंप सकेगा।

**124. गौशाला के लिए लाइसेंस** — (1) गौशाला के लिये भूमि का निर्वर्तन लाइसेंस पर निम्न तरीकों से किया जा सकेगा:—

(क) जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा— गौशाला समितियों को दस एकड़ तक भूमि; और

(ख) पशुपालन विभाग द्वारा— पशुपालन विभाग को हस्तांतरित भूमि तथा पशुपालन विभाग के पास पूर्व से उपलब्ध भूमि पर:

परंतु जिला नजूल निर्वर्तन समिति अथवा पशुपालन विभाग द्वारा ऐसी भूमि जो किसी नगरीय क्षेत्र अथवा विकास योजना क्षेत्र की बाहरी सीमा से 5 किलोमीटर के उपांत क्षेत्र में स्थित है या किसी नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 (कमांक 47 सन् 1956) विनिर्दिष्ट किये गये या उसके अधीन घोषित किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग के या मध्यप्रदेश हाईवेज एक्ट, 1936 (कमांक 34 सन् 1936) की धारा 2 के अधीन अधिसूचित लोक मार्ग के दोनों ओर एक किलोमीटर की दूरी के भीतर या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित मार्ग के दोनों ओर पाँच सौ मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो, बंटाई नहीं की जाएगी।

(2) लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—

(क)— उप कंडिका (1) के खण्ड (क) के मामले में—

(एक) जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा तत्समय प्रवृत्त अधिनियमिति के अंतर्गत पंजीकृत गौशाला समिति की मांग पर एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर एक ग्राम पंचायत में एक गौशाला समिति के लिये प्रति 100 गौवंश के लिये अधिकतम 2.5 एकड़ तक भूमि लाइसेंस पर दी जा सकेगी, किन्तु किसी गौशाला समिति को दस एकड़ से अधिक भूमि लाइसेंस पर नहीं दी जाएगी।

(दो) समिति को गौशाला हेतु दिये जाने वाले लाइसेंस में सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी जोड़ी जाएंगी:—

(क) गौशाला में पंचायत क्षेत्र के ऐसे गौवंश (गाय, बछड़ा) रखे जाएंगे जिनका कोई स्वामी न हों, अशक्त, बीमार या वृद्ध हों; ऐसे कम से कम पचास गौवंशी पशु उपलब्ध हों;

(ख) गौवंश के जीवित पशु व मृत पशु रो होने वाली आय गौशाला के खाते में जमा होगी और उसका व्यय गौशाला के उन्नयन पर किया जाएगा।

(ग) भूमि का उपयोग केवल गौशाला एवं तत्संबंधी गतिविधियों के लिए ही किया जा सकेगा;

- (घ) लाइसेंस प्राप्त भूमि को विक्रय, दान, पट्टा, उप-पट्टा, बंधक या किराये पर अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा;
- (ङ) भूमि के उपयोग का लाइसेंस अस्थाई तौर पर केवल गौशाला के उपयोग मात्र के लिए ही होगा; मूलतः यह भूमि शासकीय सम्पत्ति रहेगी तथा भू-अभिलेख में भूमिस्वामी के कॉलम में "मध्यप्रदेश शासन" लिखा रहेगा;
- (च) गौशाला की स्थापना के पश्चात् संचालक समिति को गौशाला का पंजीयन मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में कराना अनिवार्य होगा;
- (छ) गौशाला के संचालन के लिये मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा नियमों के अनुसरण में समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना होगा; और
- (ज) अन्य ऐसी शर्तें जो सक्षम प्राधिकारी उचित समझे।
- (तीन) किसी शर्त उल्लंघन की स्थिति में उसी गौशाला समिति को भविष्य में प्रदेश में गौशाला के लिये भूमि उपयोग हेतु लाइसेंस देने के लिये विचार में नहीं लिया जाएगा।
- (चार) गौशाला से संबंधित संरचना के रख रखाव का दायित्व लाइसेंस अवधि के दौरान लाइसेंसधारी पर होगा और अवधि अवसान के पश्चात्, यदि नया लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो ऐसी संरचना लाइसेंस अवधि के अवसान पर तीन माह की अवधि के भीतर लाइसेंसधारी द्वारा हटाई जाएगी। यदि नियत अवधि में ऐसी संरचना नहीं हटाई जाती है तो कलेक्टर ऐसी संरचना राजसात करेगा अथवा लाइसेंसधारी के व्यय पर उसे हटवा सकेगा।

(ख)– उप कंडिका (1) के खण्ड (ख) के मामले में–

- (एक) गौपालन की परियोजना के लिये प्रति 100 गौवंश के लिये अधिकतम 2.5 एकड़ तक भूमि लाइसेंस पर दी जा सकेगी।
- (दो) 1000 गौवंश या इससे अधिक निराश्रित गौवंश की गौशालाओं के लिये गोबर, गौमूत्र व दूध से विभिन्न उत्पादों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं हेतु अधिकतम पाँच एकड़ अतिरिक्त भूमि के मान से लाइसेंस पर दी जा सकेगी।
- (तीन) पशुपालन विभाग द्वारा भूमि लाइसेंस पर दिये जाने के लिये आवश्यकतानुसार शर्तें निर्धारित की जा सकेंगी जिसमें लाइसेंस की

अवधि, लाइसेंस शुल्क तथा लाइसेंसधारी के दायित्व आवश्यक रूप से उल्लेखित होंगे।

(3) पशुपालन विभाग से मांग प्राप्त होने की स्थिति में दस एकड़ से अधिक भूमि गौशाला स्थापित किये जाने हेतु इन निर्देशों के अध्याय दो में विहित प्रक्रिया के अनुसार पशुपालन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।

**125. लाइसेंस के लिये आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क—** (1) आवेदक कलेक्टर को प्ररूप बारह में लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा, जिसमें यथास्थिति अपनी विस्तृत परियोजना नक्शा सहित संलग्न करेगा।

(2) आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क, जो लौटाया नहीं जाएगा, के रूप में छः माह से कम अवधि के लिए लाइसेंस के मामले में पांच सौ रुपये तथा अन्य मामलों में एक हजार रुपये की राशि शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखनीय मद में जमा कर उसकी पावती की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा:

परंतु गौशाला के लिये आवेदन के मामले में प्रक्रिया शुल्क देय नहीं होगा।

**126. लाइसेंस फीस—** (1) जहां कलेक्टर द्वारा खुली नजूल भूमि यथा तम्बू या शामियाना लगाकर या निर्माण सामग्री इकट्ठी कर रखने के लिये लाइसेंस दिया जाता है वहां लाइसेंस फीस प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये भूखण्ड के बाजार मूल्य के आधा प्रतिशत की राशि के बराबर देय होगी।

(2) नदी या नाले के ऊपर से पुल, पुलिया निर्माण के लिए या सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने हेतु कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के निर्माण के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर देय होगी।

**स्पष्टीकरण—** पुल, पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली निर्माण के मामले में उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल की संगणना में ऐसे पुल, पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के नीचे आने वाली युक्तियुक्त चौड़ाई की भूमि शामिल होगी।

(3) गौशाला के लिये भूमि वार्षिक एक रुपया सांकेतिक शुल्क (लाइसेंस फीस) पर दी जाएगी।

**127. लाइसेंस का प्ररूप—** लाइसेंस प्ररूप तैरह में निष्पादित किए जाएंगे।

## अध्याय — सात

### भूमिस्वामी हक में कृषि प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन

**128. सक्षम प्राधिकारी — कंडिका 133** के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, नगरेतर क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति को भूमिस्वामी हक में कृषि प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित करने के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी होगी।

**129. आवंटन के लिये पात्रता—** भूमि केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित की जा सकेगी जो भूमिहीन व्यक्ति हो परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को पात्रता नहीं होगी जिसने सरकार से आवंटित भूमि किसी अन्य को अंतरित कर दी हो।

**130. बंटन के लिये भूमि—** ग्राम की आबादी एवं निस्तार अधिकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त, उसी ग्राम के अथवा समीपवर्ती (सीमा से जुड़ा हुआ) ग्राम के कोटवार को यदि नियमानुसार भूमि देना शेष हो तो उसके लिये निर्धारित भूमि सुरक्षित की जाकर उस ग्राम में उपलब्ध काबिलकाश्त भूमि ही भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि प्रयोजन के लिये बंटित की जा सकेगी:

परंतु ऐसी भूमि जो किसी नगरीय क्षेत्र अथवा विकास योजना क्षेत्र की बाहरी सीमा से 5 किलोमीटर के उपांत क्षेत्र में स्थित है या किसी नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 (क्रमांक 47 सन् 1956) विनिर्दिष्ट किये गये या उसके अधीन घोषित किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग के या मध्यप्रदेश हाईवेज एक्ट, 1936 (क्रमांक 34 सन् 1936) की धारा 2 के अधीन अधिसूचित लोक मार्ग के दोनों ओर एक किलोमीटर की दूरी के भीतर या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित मार्ग के दोनों ओर पाँच सौ मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो, बंटित नहीं की जाएगी।

**131. पात्रता में प्राथमिकता क्रम—** बंटन की पात्रता के लिये प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा:—

- (क) आदिम जनजाति;
- (ख) अनुसूचित जाति;
- (ग) पिछड़ा वर्ग; और
- (घ) अन्य वर्ग।

**132. कृषि प्रयोजन के आवंटन की सीमा—** भूमिहीन व्यक्ति को असिंचित अधिकतम दो हेक्टेयर या सिंचित अधिकतम एक हेक्टेयर कृषि प्रयोजन हेतु भूमि, यदि उसके पास पूर्व से भूमिस्वामी धारणाधिकार में कृषि भूमि उपलब्ध है तो उतना क्षेत्रफल कम

कर जो कि उसके पास पूर्व से है, भूमिस्वामी अधिकार में निःशुल्क आवंटित की जा सकेगी:

परन्तु यदि उस ग्राम में या निकटतम ग्राम में उपलब्ध भूमि पर्याप्त न हो, तो पात्रता रखने वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों को भूमि बंटन करने का प्रयास इस प्रकार किया जायेगा कि बंटिती के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि न हो।

**133. आवंटन की प्रक्रिया—** (1) इस अध्याय के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, कृषि प्रयोजन के लिये बंटन, राज्य शासन द्वारा कार्यकारी निर्देश जारी किये जाने पर ही किया जा सकेगा।

(2) उपकंडिका (1) के अधीन जारी किये गये कार्यकारी निर्देशों के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला नजूल निर्वर्तन समिति प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरांत निर्णय लेगी। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कृषि भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया जाता है तो अपने निर्णय में आवंटिती के नाम (उनके पूर्ण पता सहित), उन्हें आवंटित की जाने वाली कृषि भूमि के विवरण—सर्वेक्षण संख्यांक, (यदि किसी बड़े आकार के सर्वेक्षण संख्यांक में के अंश भाग आवंटित किए जाते हैं तो नक्शा संलग्न करते हुए ऐसे अंश भाग को पृथक-पृथक दर्शाया जाए) और उनके क्षेत्रफल के विवरण दिए जाएंगे।

**134. आवंटित कृषि भूमि पर भू-राजस्व का निर्धारण —** यदि जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा कृषि भूमि के आवंटन का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी दशा में आवंटित भूमि का आवंटिती के पक्ष में भूमिस्वामी अधिकार पत्र जारी किए जाने के पूर्व कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 60 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारण नियत किया जाएगा।

**135. भूमिस्वामी अधिकार पत्र —** जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन हेतु कलेक्टर के निर्देश के अनुसरण में संबंधित तहसीलदार आवंटिती के पक्ष में भूमिस्वामी अधिकार पत्र प्ररूप चौदह में जारी करेगा।

**136. भू-अभिलेख में प्रविष्टि —** तहसीलदार कंडिका 135 में जारी किए गए भूमिस्वामी अधिकार पत्र की संबंधित भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां दर्ज कराएगा और संबंधित आवंटिती को भू-अधिकार पुस्तिका प्रदत्त करेगा और स्थल पर आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि का आधिपत्य भी सौंपेगा।

## अध्याय – आठ

### स्थायी पट्टे का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन

**137. स्थायी पट्टाधिकार का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन—** (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिये प्रदान किये गये स्थायी पट्टाधिकार, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल या विकास प्राधिकरण या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित या मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम या तत्सम्यम प्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी सोसायटी को प्रदत्त पट्टाधिकार को छोड़कर, को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तित कराया जा सकेगा:

परंतु किसी व्यक्ति/संस्था के पक्ष में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल या विकास प्राधिकरण या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित या मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम या तत्सम्यम प्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी सोसायटी द्वारा, उसे राज्य शासन से प्राप्त स्थायी पट्टे की भूमि में से 30 वर्ष या अधिक अवधि के लिये आवासीय प्रयोजन हेतु निष्पादित उपपट्टे के आधार पर पट्टाधिकार दिया गया है, ऐसे व्यक्ति/संस्था, यथास्थिति ऐसे मण्डल या प्राधिकरण या संघ या निगम या सोसायटी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत, संपरिवर्तन के लिये पात्र होंगे। ऐसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए उक्त संस्थाओं द्वारा कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि उक्त उपबंध,—

(क) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1985) के अंतर्गत प्रदत्त पट्टाधृति अधिकार के मामले में; तथा

(ख) निजी पूँजी निवेशक को यदि किसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम और ऐसे निवेशक के मध्य निष्पादित किसी अनुबंध के अनुक्रम में भूमि का आवंटन किया गया है, ऐसी भूमि के मामले में;

लागू नहीं होंगे।

(2) स्थायी पट्टाधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन के लिये सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर होगा।

(3) कोई व्यक्ति जो संपरिवर्तन के लिये पात्र सरकारी पट्टेदार के रूप में भूमि धारण करता है सक्षम प्राधिकारी को **प्ररूप पन्द्रह** में आवेदन कर सकेगा। संपरिवर्तन के लिये प्रस्तुत आवेदन पर कोई प्रक्रिया शुल्क देय नहीं होगा।

**138. संपरिवर्तन की प्रक्रिया—** (1) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में **कंडिका 142** में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे।

(2) हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी आवेदित संपरिवर्तन मंजूर कर सकेगा, यदि समाधान हो जाता है कि —

(क) भूमि का पट्टा वैध है;

(ख) पट्टों की शर्तों से संबंधित सभी शोध्यों के भुगतान कर दिये गये हैं;

(ग) पट्टे की शर्तों का उल्लंघन/अपालन नहीं हुआ है और यदि किन्हीं शर्तों का उल्लंघन/अपालन हुआ है तो ऐसे उल्लंघन/अपालन के लिये **कंडिका 82** के अनुसरण में शमन कर दिया गया है;

(घ) पट्टे की शर्तें संपरिवर्तन प्रतिषिद्ध नहीं करती हैं; और

(ङ) आवेदक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि किसी न्यायालय अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष ऐसी भूमि के संबंध में कोई मामला लंबित नहीं है।

(3) सक्षम प्राधिकारी उक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसरण में परीक्षण उपरांत **कंडिका 139** के अनुसार संगणित संपरिवर्तन प्रभार **परिशिष्ट 'क'** में उल्लेखित मद में जमा कराये जाने पर संपरिवर्तन की मंजूरी दे सकेगा।

**139. संपरिवर्तन प्रभार —** संपरिवर्तन प्रभार में सम्मिलित होगा,—

(क) संपरिवर्तन आदेश की दिनांक के आधार पर नियत दर पर पट्टे के नवीनीकरण की आगामी तिथि तक का वार्षिक भू-भाटक; और

(ख) पट्टाधीन भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत की राशि के बराबर संपरिवर्तन शुल्क।

**140. हस्तांतरण विलेख—** सक्षम प्राधिकारी के पट्टाधिकार से भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन मंजूर करने के लिये आदेश के पश्चात् तथा संपरिवर्तन प्रभार एवं अन्य



शोध्द्य, यदि कोई हो, के जमा कराये जाने पर प्ररूप सोलह में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (कमांक 16 सन् 1908) के अधीन रजिस्ट्रीकृत करायेगा तथा मुद्रांक शुल्क सम्मिलित करते हुए, ऐसे पंजीयन के खर्च पट्टेदार द्वारा वहन किये जाएंगे।

**141. भू-राजस्व-** भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तित भूमि पर वार्षिक भू-राजस्व मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारित एवं देय होगा।

## अध्याय – नौ प्रकीर्ण

**142. सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करने की रीति—** (1) इन निर्देशों के अंतर्गत नजूल भूमि के निर्वर्तन के मामलों में दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिये सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन आयुक्त, कलेक्टर, तहसील तथा स्थानीय निकाय के कार्यालयीन सूचना पटलों पर कराया जाएगा।

(2) उद्घोषणा की एक प्रति उद्घोषणा में संदर्भित भूमि पर या उसके समीप किसी लोक समागम के स्थान पर प्रकाशित की जाएगी।

(3) उद्घोषणा का प्रकाशन राजस्व विभाग तथा संबंधित जिले के कलेक्टर की अधिकृत वेबसाइटों पर भी किया जाएगा।

(4) जहां इन निर्देशों में विशिष्ट रूप से ऐसा विहित किया जाए उद्घोषणा का प्रकाशन समाचार पत्रों में ऐसे निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

**143. नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र—** (1) भूमिस्वामी हक में धारित अथवा सरकारी पट्टेदार के रूप में धारित भूखंडों पर निर्माण के पूर्व स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी से तत्समय प्रभावशील विधि के उपबंधों के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसी अनुमतियां जारी करने के पूर्व स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति के आधार पर किसी ऐसे भूखंड पर निर्माण न हो जाये जो वस्तुतः धारक द्वारा धारित न होकर राज्य शासन की दखलरहित या नजूल भूमि हो।

(2) नजूल अधिकारी के द्वारा समस्त नजूल भूमि के विवरण संबंधित स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे उपकंडिका (1) में उल्लेखित अनुमतियां जारी करने के पूर्व आवश्यक संतुष्टि कर लें। नजूल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे विवरणों में हुए परिवर्तनों को स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी के ध्यान में लाए तथा प्रतिवर्ष जनवरी माह में नजूल भूमि के अद्यतन विवरण उन्हें भिजवाए।

(3) उपरोक्त उपकंडिका (2) अनुसार अपेक्षित विवरण स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश को उपलब्ध कराये जाने के लिये अंतरिम व्यवस्था के रूप में उपकंडिका (4), (5) और (6) में विहित प्रक्रिया के अनुसार नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे, उसके उपरांत नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाएंगे।

(4) नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन **प्ररूप सत्रह** में नजूल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जो यथास्थिति नगर सर्वेक्षक या राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर इस आशय की संतुष्टि करेगा कि आवेदित भूखण्ड अभिलेख अनुसार रिक्त नजूल भूमि का अंश नहीं है और न ही आवेदित भूखण्ड का कोई भाग रिक्त नजूल भूमि पर अतिक्रमित है।

(5) नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन की आवेदक/संस्था को तत्काल पावती दी जाएगी जिस पर प्रस्तुति दिनांक अंकित होगी।

(6) नजूल अधिकारी आवेदन प्रस्तुति की दिनांक से तीस दिवस के भीतर **उपकंडिका (4)** के अनुसार परीक्षण उपरांत **प्ररूप अट्ठारह** में यथास्थिति नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र/आपत्ति पत्र जारी करेगा, जिसकी सूचना संबंधित स्थानीय निकाय/नगर तथा ग्राम निवेश को भी दी जाएगी। नियत अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र/आपत्ति पत्र जारी नहीं किये जाने की दशा में स्थानीय निकाय/नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नजूल की अनापत्ति समझी जाएगी।

**144. शासकीय निर्माण कार्य के लिये निजी भूमि का शासकीय भूमि से विनिमय** —(1) निजी भूमि का शासकीय भूमि से विनिमय केवल उन्ही मामलों में अनुमत होगा जहां किसी शासकीय निर्माण कार्य के लिए निजी भूमि का उपयोग अपरिहार्य हो। ऐसे मामले में केवल उतनी निजी भूमि का विनिमय किया जाएगा जो निर्माणकर्ता विभाग के मत में निर्माण के लिये आवश्यक है।

(2) विनिमय की स्वीकृति देने के लिए संभाग मुख्यालय में स्थित शासकीय भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी होगी।

(3) नगरेतर क्षेत्र की निजी भूमि का विनिमय नगरीय अथवा विकास योजना क्षेत्र की शासकीय भूमि से नहीं किया जाएगा।

(4) विनिमय के प्रत्येक प्रकरण में शासकीय भूमि एवं योजना में उपयोग में ली जा रही निजी भूमि के संगणित बाजार मूल्य के बराबर होना चाहिए। भूमि के कुल मूल्य के साथ साथ विनिमय की जाने वाली भूमियों की मूल्य दर भी यथासंभव समान हो। किसी भी स्थिति में निजी भूमि के मूल्य से अधिक मूल्य की शासकीय भूमि विनिमय में नहीं दी जाएगी।

(5) निर्माणकर्ता विभाग द्वारा भूमि विनिमय के लिए आवेदन पत्र कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा। इस हेतु कोई प्रक्रिया शुल्क देय नहीं होगा। विनिमय के प्रकरण पर विचार तभी किया जाएगा जब संबंधित विभाग द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि योजना/परियोजना हेतु भू-अर्जन किए जाने के लिए राशि का प्रावधान नहीं है तथा निजी भूमि के बिना योजना का क्रियान्वयन संभव नहीं है। आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर प्रकरण जांच हेतु नजूल अधिकारी को भेजेगा।

(6) यदि विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमि संहिता की धारा 237 की उपधारा (1) के अंतर्गत निस्तार अधिकार के लिए पृथक रखी गई भूमि है अथवा धारा 233-क के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई भूमि है तो कलेक्टर यथास्थिति सर्वप्रथम संहिता की धारा 237 की उपधारा (3) के अंतर्गत ऐसी शासकीय भूमि के व्यपवर्तन करने की या धारा 233-क के खण्ड (ग) के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करेगा।

(7) नजूल अधिकारी द्वारा 15 दिवस का समय देते हुए कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की जाएगी जिसमें सर्वसाधारण से, जिनके हितों पर विनिमय से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे।

(8) नजूल अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा एवं प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर अभिमत देते हुए एवं शासकीय एवं निजी भूमियों के मूल्य की गणना देते हुए प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा।

(9) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति विनिमय स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर आवेदक विभाग तथा निजी भूमिस्वामी को सूचित किया जाएगा। जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा।

(10) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति विनिमय स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक विभाग, निजी भूमिस्वामी तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा।

(11) सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने पर विनिमय पत्र का पंजीयन कराया जाएगा और तत्पश्चात् भू अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी।

**145. अभ्यावेदन—** (1) इन निर्देशों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इन निर्देशों के अधीन पारित किए गये किसी मूल आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकेगा—

- (क) कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कलेक्टर को;
- (ख) कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आयुक्त को;
- (ग) जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को; और
- (घ) संभाग नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध राज्य नजूल निर्वर्तन समिति को।

(2) ऐसा अभ्यावेदन आलोच्य आदेश की दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) मूल आदेश/निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पारित आदेश के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन ग्राह्य नहीं होगा।

**146. स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण—** (1) राज्य शासन किसी भी समय राज्य नजूल निर्वर्तन समिति, संभाग नजूल निर्वर्तन समिति, आयुक्त, जिला नजूल निर्वर्तन समिति,

कलेक्टर या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को अथवा उसके द्वारा पारित आदेश को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में ले सकेगा।

(2) आयुक्त किसी भी समय जिला नजूल निर्वर्तन समिति, कलेक्टर या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को अथवा उसके द्वारा पारित आदेश को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में ले सकेगा।

(3) कलेक्टर किसी भी समय उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को अथवा उसके द्वारा पारित आदेश को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में ले सकेगा।

(4) किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जायेगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

**147. नजूल भूमि के निर्वर्तन के मामलों में प्राप्त राशि शासकीय खजाने में जमा किया जाना—** नजूल भूमि के निर्वर्तन के मामलों में प्राप्त विक्रय धन, प्रब्याजि, भू-राजस्व, वार्षिक भू-भाटक, लाइसेंस फीस, प्रक्रिया शुल्क, स्थायी पट्टे का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन के लिये देय संपरिवर्तित शुल्क, अस्थायी पट्टे का स्थायी पट्टे में परिवर्तन के लिये देय परिवर्तन शुल्क तथा अभिहस्तांकन के मामले में अंतरण शुल्क, एवं उनके बकाया पर देय ब्याज की राशि यथासंभव ऑनलाइन पद्धति से शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा की जायेगी।

**148. निरसन तथा व्यावृत्ति—** (1) मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के प्रभावशील होने के दिनांक से—

(क) **विद्यमान राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक-5** — ऐसी भूमियों का जो राज्य की सम्पत्ति हो, हस्तांतरण या अदला-बदली;

(ख) **विद्यमान राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक-6** — व्यावसायिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिये शासकीय भूमि का हस्तांतरण अदला-बदली या पट्टे पर दिया जाना;

(ग) **विद्यमान राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक-7** — भारत शासन के विभागों, मंत्रालयों, इकाइयों या सार्वजनिक उपक्रमों की मध्यप्रदेश राज्य में विकास योजनाओं के लिए शासन की भूमि का हस्तांतरण;

(घ) विद्यमान राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 – नगर निगमों, नगरपालिकाओं, नगरों तथा अधिसूचित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर नजूल भूमियों की विधि तथा व्यवस्था;

<sup>1</sup>(ङ) राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-क्रमांक 3 एवं खण्ड चार-क्रमांक 3अ तथा उससे संबंधित समय-समय पर जारी निर्देश, हिदायतें, परिपत्र;

(च) गैर वनपड़त भूमि के विकास एवं उपयोग के संबंध में राज्य की नीति परिपत्र क्रमांक 1873-एफ-4-7/96/सात/2ए दिनांक 04.10.2006; और

(छ) उपरोक्त परिपत्रों के संदर्भ में समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश, हिदायतें या परिपत्र, चाहे वे उक्त परिपत्रों के विषय में उन्हें स्पष्ट करने के लिए जारी किए गए हों या उनमें संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिये जारी किए गए हों;

निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के फलस्वरूप निरसित किए गए परिपत्रों, निर्देशों या हिदायतों के अधीन पूर्व में निराकृत किए जा चुके मामले अप्रभावित रहेंगे।

(3) ऐसे मामले जो मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन, 2020 के प्रभावशील होने की तिथि को निरसित परिपत्रों, निर्देशों या हिदायतों के अंतर्गत लंबित हैं, उनमें जब तक कि इन निर्देशों में अन्यथा उपबन्धित न हो, इन्हीं निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी:

परन्तु राज्य शासन किसी लंबित मामले या लंबित मामलों के वर्ग के निराकरण के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसा कि वह उपयुक्त समझे।

1. म.प्र. राजपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 6-75/2019/सात-3 अनुसार संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित उक्त संशोधन दिनांक 24 सितम्बर, 2020 से प्रभावशील हुआ।

**परिशिष्ट 'क'****मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020****(देखें कंडिका 147)**

सरल क्रमांक	विवरण	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	स्कीम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<p>1. नजूल भूमि के वार्षिक भू-भाटक के बकाया पर ब्याज;</p> <p>2. नजूल भूमि का नगरीय निकाय या विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के मामले में देय भू-राजस्व के बकाया पर ब्याज</p> <p>3. नजूल भूमि के भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन किये जाने पर देय भू-राजस्व के बकाया पर ब्याज; तथा</p> <p>4. नजूल भूमि पर लाइसेंस फीस के बकाया पर ब्याज;</p> <p>जमा करने हेतु मद</p>	0029-Land Revenue	00-Land Revenue	101-Land Revenue/Tax	0011-Interest on Land Revenue from Nazul land
2	<p>1. नजूल भूमि का वार्षिक भू-भाटक;</p> <p>2. नजूल भूमि के भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन किये जाने पर देय भू राजस्व; तथा</p> <p>3. नजूल भूमि का नगरीय निकाय या विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के मामले में देय भू-राजस्व</p> <p>4. नजूल भूमि पर लाइसेंस फीस;</p> <p>जमा करने हेतु मद</p>	0029-Land Revenue	00-Land Revenue	101-Land Revenue/Tax	0016-Rent from Nazul lands
3	नजूल भूमि के शर्त उल्लंघन/ अपालन के मामले में शमन शुल्क जमा करने हेतु मद	0029-Land Revenue	00-Land Revenue	800-Other Receipts	0013-Penalty and for feitures
4	<p>1. नजूल भूमि के परिवर्तन से देय प्रब्याजि के बकाया पर ब्याज</p> <p>2. नजूल भूमि के नीलामी से निर्वर्तन में देय विक्रय धन के बकाया पर ब्याज</p> <p>3. नजूल भूमि का नगरीय निकाय या विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के मामले में देय प्रब्याजि के बकाया पर ब्याज</p>	0029-Land Revenue	00-Land Revenue	800-Other Receipts	0012-Interest on Nazul land premium



	<p>4. अभिहस्तांकन के मामले में अंतरण शुल्क के बकाया पर ब्याज</p> <p>5. स्थायी पट्टे का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन प्रभार के बकाया पर ब्याज;</p> <p>6. अस्थायी पट्टे का स्थायी पट्टे में परिवर्तन शुल्क के बकाया पर ब्याज; तथा</p> <p>7. वार्षिक भू भाटक या लाइसेंस फीस के बकाया पर ब्याज;</p> <p>जमा करने हेतु मद</p>				
5	<p>1. नजूल भूमि के निर्वर्तन से देय प्रब्याजि;</p> <p>2. नजूल भूमि के निर्वर्तन से देय विक्रय धन;</p> <p>3. नजूल भूमि का नगरीय निकाय या विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के मामले में देय प्रब्याजि</p> <p>4. अभिहस्तांकन के मामले में अंतरण शुल्क;</p> <p>5. स्थायी पट्टे का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन प्रभार; तथा</p> <p>6. अस्थायी पट्टे का स्थायी पट्टे में परिवर्तन शुल्क;</p> <p>जमा करने हेतु मद</p>	0029-Land Revenue	00-Land Revenue	800-Other Receipts	0015-Premium from Nazul lands
6	आवेदन के लिये प्रक्रिया शुल्क जमा करने हेतु मद	0029-Land Revenue	00-Land Revenue	800-Other Receipts	0019-Fee for Revenue Court case registration and processing

## प्ररूप एक

(देखें कंडिका 12, 21, 28, 29, 36, 37, 45, 93,100 और 106)

## नजूल भूमि के हस्तांतरण/आवंटन के लिए आवेदन का प्ररूप

यह प्ररूप निम्न श्रेणी के मामलों में प्रयुक्त किया जाएगा—

1. राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा नजूल भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन
2. स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि के आवंटन के लिए आवेदन
3. नगरीय निकाय द्वारा नजूल भूमि की भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिए आवेदन
4. ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए नजूल भूमि आवंटन के लिए आवेदन
5. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिए आवेदन

प्रति,

कलेक्टर,

जिला.....

विषय:— जिला..... तहसील/नगर.....के ग्राम/सेक्टर .  
 .....में..... (हेक्टेयर/वर्गमीटर) नजूल भूमि के  
 हस्तांतरण / स्थायी पट्टे पर आवंटन के लिए आवेदन पत्र

आवेदक की श्रेणी (सुसंगत बॉक्स को चिह्नित करें)

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> राज्य शासन का विभाग  | <input type="checkbox"/> केन्द्र शासन का विभाग         | <input type="checkbox"/> मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल   |
| <input type="checkbox"/> राज्य शासन के अधीनस्थ संगठन                                | <input type="checkbox"/> केन्द्र शासन के अधीनस्थ संगठन | <input type="checkbox"/> ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए |
| <input type="checkbox"/> नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | <input type="checkbox"/> निजी निवेशक                   | <input type="checkbox"/> युद्ध में मृत सैनिक का परिवार           |
| <input type="checkbox"/> पूर्ण संस्था   |  |  |
| <input type="checkbox"/> पंचायती राज संस्था   |  |  |
| <input type="checkbox"/> सहकारी संस्था  |  |  |

## भाग — एक

(सभी आवेदकों द्वारा भरा जाए)

1	<p>1.1 आवेदक का नाम (जिसके नाम से भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है)</p> <p>(संस्थागत आवेदन के मामले में)</p> <p>1.2 आवेदनकर्ता पदाधिकारी का पदनाम</p>	
---	---	--

	(व्यक्तिगत आवेदन के मामले में) 1.3. आवेदक के पिता/ माता/ पति का नाम  1.4 लिंग											
2	2.1 पत्राचार के लिए पता  2.2 दूरभाष क्रमांक  2.3 मोबाइल नम्बर  2.4 ई-मेल पता  2.5 संस्थागत आवेदन के मामले में, स्थानीय समन्वय हेतु अधिकृत कार्यालय का नाम, पता, कार्यालय के प्रमुख का नाम, पदनाम, दूरभाष क्रमांक, तथा ई-मेल पता दें											
3	प्रक्रिया शुल्क जमा करने के विवरण (जहां लागू हो)  3.1 जमा की गई राशि  3.2 चालान क्रमांक  3.3 जमा करने की दिनांक											
4	आवेदित भूमि के विवरण जिला ..... तहसील .....  <table border="1"> <tr> <td>नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त ..... पटवारी हल्का ..... ग्राम .....</td><td>नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर ..... सेक्टर .....</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>क्र.</th><th>खसरा क्रमांक/शीट क्रमांक/ब्लॉक क्रमांक/ भूखण्ड क्रमांक</th><th>कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)</th><th>आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)</th></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त ..... पटवारी हल्का ..... ग्राम .....	नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर ..... सेक्टर .....	क्र.	खसरा क्रमांक/शीट क्रमांक/ब्लॉक क्रमांक/ भूखण्ड क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	1				
नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त ..... पटवारी हल्का ..... ग्राम .....	नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर ..... सेक्टर .....											
क्र.	खसरा क्रमांक/शीट क्रमांक/ब्लॉक क्रमांक/ भूखण्ड क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)									
1												

	2			
	3			
	योग			
5	आवेदित भूमि की आवश्यकता किस लिए है?			
6	<p>(क) आवेदित क्षेत्रफल की आवश्यकता का औचित्य बताते हुए समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हों, संलग्न करें</p> <p>(ख) क्या आवेदित क्षेत्रफल की गणना अधिकतम अनुमत क्षेत्र तल अनुपात (F.A.R.) के आधार पर की गई है? यदि नहीं तो कारण दें</p> <p>(ग) आवेदित क्षेत्रफल का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना और उसके लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवरण दें तथा समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हों, तो संलग्न करें</p>			

**भाग – दो**  
(आवेदक की श्रेणी के अनुसार लागू खण्ड का प्रयोग करें)

**खण्ड क**

(यह खण्ड राज्य शासन या केन्द्र शासन का विभाग या उसके अधीनस्थ संगठन, नगरीय निकाय या पंचायती राज संस्था, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

7	<p>आवेदित भूमि पर क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित योजना/परियोजना/कार्य आदि के संबंध में विवरण दें</p> <p>7.1 नाम</p> <p>7.2 प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के विवरण (आदेश की प्रतिलिपी संलग्न करें)</p> <p>7.3 योजना/परियोजना/कार्य के घटक जिनमें आवेदित भूमि का उपयोग प्रस्तावित है</p> <p>7.4 योजना/परियोजना/कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का विवरण (समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हों, तो संलग्न करें)</p> <p>7.5 स्थानीय निकाय के मामले में भूमि आवंटन के लिए स्थानीय निकाय के संकल्प की प्रतिलिपी संलग्न करें</p> <p>7.6 विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 के अंतर्गत घोषित नगर विकास स्कीम में स्थित नजूल भूमि के मामले में (स्कीम की प्रतिलिपी संलग्न करें)</p> <p>7.7 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें</p>	
---	---	--

**खण्ड ख**

(यह खण्ड पूर्ण संस्था के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

7	<p>7.1 संस्था किस विधान/नियम के अंतर्गत पंजीकृत है?</p> <p>7.2 पंजीयन करने वाले अधिकारी का पदनाम</p> <p>7.3 पंजीयन क्रमांक और दिनांक</p> <p>7.4 पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें</p> <p>7.5 संस्था के उद्देश्य (संस्था के मेमोरेन्डम आफ एसोशिएशन तथा उपनियमों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करें)</p> <p>7.6 संस्था के पदाधिकारियों का विवरण</p>							
	क्रमांक	नाम	पदनाम	पता तथा दूरभाष	व्यवसाय	वैतनिक अथवा अवैतनिक  (वैतनिक हो तो वार्षिक वेतन दर्शाया जाय)	टिप्पणी	
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	7.7 संस्था के पास उपलब्ध अधोसंरचना के विवरण दें			वर्ष	कुल आय	कुल	संस्था के उद्देश्यों	संस्था के कार्पस

7.8 विगत तीन वर्षों में संस्था के कार्यकलापों, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण दें तथा प्रशासकीय प्रतिवेदनों को संलग्न करें			व्यय	पर किया गया व्यय	निधि में उपलब्ध राशि
7.9 संस्था में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके वेतन पर किए जा रहे वार्षिक व्यय के विगत तीन वर्षों के विवरण दें					
7.10 विगत तीन वर्षों की कुल आय कुल व्यय तथा संस्था के द्वारा अपने उद्देश्यों पर किए गए व्यय तथा कार्पस निधि (Corpus Fund) के विवरण दें					
(विगत तीन वर्षों की अंकेक्षित बैलेन्स शीट, आय-व्यय लेखा तथा प्राप्ति और अदायगी लेखों की प्रतियां संलग्न करें – Audited Balance Sheet, Income-Expenditure Account and Receipts and Payment Account)					
7.11 संस्था को आयकर विभाग से जारी स्थायी लेखा क्रमांक, यदि कोई हो					
(Permanent Account Number)					
7.12 संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में दाखिल की गई आयकर विवरणियों (Income Tax Returns) की प्रतियां संलग्न करें					
7.13 क्या संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हाँ तो पंजीयन क्रमांक, दिनांक तथा पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवरण दें तथा पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें					
7.14 क्या संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हां तो पंजीयन					
योग					

<p>कमांक, दिनांक तथा पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवरण दें तथा पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें</p> <p>7.15 संस्था को प्रदेश में यदि पूर्व में कोई शासकीय भूमियां आवंटित की गई हों तो उनके पूर्ण विवरण दें, वर्तमान में उन भूमियों के किये जा रहे उपयोग की जानकारी दें तथा अब की जा रही भूमि की मांग का औचित्य बताएं</p> <p>7.16 क्या संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म में आधार पर भेदभाव किया जाता है?</p> <p>7.17 क्या संस्था की आय तथा आस्तियां उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो कि उसके उद्देश्यों तथा उपविधियों में वर्णित हैं?</p> <p>7.18 क्या संस्था की आय का कोई अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके सदस्यों, संचालकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों को वितरित किया जाता है या किए जाने योग्य है?</p> <p>7.19 क्या संस्था की उपविधियों के अनुसार संस्था के परिसमापन पर उसकी निबल आस्तियां (Net assets) उसकी देनदारियों की पूर्ति के उपरांत उसके सदस्यों, संचालकों, संस्थापकों व दानदाताओं को वापस होती है?</p> <p>7.20 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें</p>	
<p>इस खण्ड में दी गई जानकारी का सत्यापन</p>	<p>मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि इस भाग में दी गई जानकारी सत्य है। मुझे ज्ञात है कि यदि यह जानकारी असत्य, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक पाई गई तो</p>
	<p>राज्य शासन मेरे तथा संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा और भूमि का आवंटन निरस्त कर सकेगा।</p> <p>आवेदक के हस्ताक्षर.....</p> <p>नाम.....</p> <p>पदनाम.....</p>



(यह खण्ड मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

7	<p>7.1 क्या आवेदक राजनैतिक दल प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित है?</p> <p>7.2 यदि हां, तो भारत निर्वाचन आयोग की नवीनतम अधिसूचना की प्रति संलग्न करें।</p> <p>7.3 दल के पदाधिकारियों का विवरण :</p>	हां / नहीं		
क्रमांक	नाम	पदनाम	पता तथा दूरभाष	व्यवसाय
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

क्रमांक	आवंटिती का नाम	ग्राम/नगर जिला	भूमि/भवन का विवरण (वर्गमीटर में)	आवंटित/आधिपत्य आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	वर्तमान उपयोग का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

7.5 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें					
इस खण्ड में दी गई जानकारी का सत्यापन			मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि इस भाग में दी गई जानकारी सत्य है। मुझे ज्ञात है कि यदि यह जानकारी असत्य, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक पाई गई तो राज्य शासन मेरे तथा संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा और भूमि का आवंटन निरस्त कर सकेगा। आवेदक के हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम.....		

**खण्ड घ**

(यह खण्ड युद्ध में मृत सैनिक का परिवार के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

7.	युद्ध में मृत हुए सैनिक के नाम तथा सक्षम प्राधिकार से जारी प्रमाणपत्र के विवरण दें तथा उसकी स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें	
----	---	--

**खण्ड ङ**

(यह खण्ड निजी पूंजी निवेशक के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

7.	7.1 विभाग का नाम जिसकी नीति के अंतर्गत भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया जाना है 7.2 विभागीय नीति का आदेश क्रमांक तथा दिनांक दे तथा आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें 7.3 परियोजना का विस्तृत विवरण (Detailed Project Report —डी.पी.आर)	
----	--	--

	<p>7.4 परियोजना का संक्षिप्त वर्णन करें तथा डी.पी.आर. की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें</p> <p>7.5 परियोजना द्वारा सृजित किया जाने वाला सीधा रोजगार</p> <p>7.6 परियोजना में किए जा रहे निवेश का आकार</p> <p>7.7 आवेदक द्वारा प्रदेश में पूर्व से स्थापित और गतिशील परियोजनाएं</p> <p>7.8 परियोजना की स्थापना से जिले को प्राप्त होने वाले अन्य लाभ</p>	
--	---	--

### खण्ड च

(यह खण्ड ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

7.	<p>7.1 प्रस्तावित कार्य का प्रकार (ध्वजदण्ड की स्थापना, व्यक्ति की प्रतिमा की स्थापना आदि)</p> <p>7.2 प्रस्तावित कार्य की पृष्ठभूमि तथा औचित्य</p> <p>7.3 प्रस्तावित कार्य का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा?</p> <p>7.4 प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत तथा उसके लिए वित्तीय व्यवस्था के विवरण</p> <p>7.5 प्रस्तावित कार्य सम्पन्न करने की समय-सीमा</p> <p>7.6 प्रस्तावित कार्य के संरक्षण तथा उसे गरिमामय एवं दर्शनीय स्थिति में रखने का दायित्व स्वीकार करने बाबत स्थानीय निकाय के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें</p> <p>7.7 प्रस्तावित स्थल पर भविष्य में</p>	
----	---	--

	<p>समय समय पर जयंती, पुण्यतिथि आदि अवसरों पर कार्यक्रम आयोजित होने पर क्या बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना है?</p> <p>(टीप- सड़क, चौराहा या तिराहा के बीच में ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी)</p>	
--	---	--

कार्यालय की मोहर

आवेदक के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

संलग्नक :

- (1) आवेदित भूमि के खसरा की प्रति
- (2) भूमि का नक्शा
- (3)
- (4)
- (5)

**प्ररूप दो**

(देखें कंडिका 13, 22, 29, 37, 48, 94, 101 और 107)

**नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जांच प्रतिवेदन का प्ररूप**

यह प्ररूप निम्न श्रेणी के मामलों में प्रयुक्त किया जाएगा –

1. राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा नजूल भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन
2. स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि के आवंटन के लिए आवेदन
3. नगरीय निकाय द्वारा नजूल भूमि की भूमिस्वामी हक में आवंटन के लिए आवेदन
4. ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए नजूल भूमि आवंटन के लिए आवेदन
5. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिए आवेदन

कार्यालय नजूल अधिकारी .....

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

प्रति,

कलेक्टर

जिला.....

जांच प्रतिवेदन  
(दिनांक .....)

आवेदक की श्रेणी (सुसंगत बॉक्स को चिह्नित करें)

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> राज्य शासन का विभाग  | <input type="checkbox"/> केन्द्र शासन का विभाग         | <input type="checkbox"/> मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल   |
| <input type="checkbox"/> राज्य शासन के अधीनस्थ संगठन                                | <input type="checkbox"/> केन्द्र शासन के अधीनस्थ संगठन | <input type="checkbox"/> ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए |
| <input type="checkbox"/> नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण | <input type="checkbox"/> निजी निवेशक                   | <input type="checkbox"/> युद्ध में मृत सैनिक का परिवार           |
| <input type="checkbox"/> पंचायती राज संस्था   | <input type="checkbox"/> पूर्त संस्था                  |  |
| <input type="checkbox"/> सहकारी संस्था  |  |  |

/

**भाग — एक**  
**सामान्य**  
**(सभी मामलों के लिए लागू)**

1	<p>1.2 आवेदक का नाम (जिसके नाम से भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है) (संस्थागत आवेदन के मामले में)</p> <p>1.2 आवेदनकर्ता पदाधिकारी का पदनाम  (व्यक्तिगत आवेदन के मामले में)</p> <p>1.3. आवेदक के पिता/ माता/ पति का नाम</p> <p>1.4 लिंग</p>	
2	<p>आवेदक के डाक पता, ईमेल पता तथा दूरभाष क्रमांक के विवरण</p> <p>मोबाइल नम्बर सहित</p>	
3	<p>आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों के विवरण</p>	
4	<p>प्रक्रिया शुल्क जमा करने के विवरण (जहां लागू हो)</p> <p>4.1 जमा की गई राशि</p> <p>4.2 चालान क्रमांक</p> <p>4.3 जमा करने की दिनांक</p>	
5.	<p>5.1 आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करने का दिनांक</p> <p>5.2 कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर की गई कार्यवाहियों के विवरण</p> <p>5.3 मामला जांच व प्रतिवेदन हेतु जांचकर्ता अधिकारी को प्राप्त होने का दिनांक</p>	

6.	आवेदित भूमि के विवरण			
जिला .....तहसील.....				
नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त ..... पटवारी हल्का ..... ग्राम .....		नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर ..... सेक्टर .....		
क्र.	खसरा कमांक/शीट कमांक/ब्लॉक कमांक/ भूखण्ड कमांक	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	
1				
2				
3				
योग				
7.	7.1 सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करने के विवरण 7.2 प्राप्त आपत्तियों, दावों और सुझावों के विवरण 7.3 प्राप्त आपत्तियों, दावों और सुझावों पर जांच अधिकारी द्वारा की गई विवेचना तथा निष्कर्ष			
8.	8.1 स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश तथा अन्य विभाग के अभिमत प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही के विवरण 8.2 प्राप्त अभिमतों के विवरण 8.3 प्राप्त अभिमतों पर जांच अधिकारी का निष्कर्ष			
9.	आवेदित भूमि के संबंध में कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित हो तो उसके विवरण दें तथा न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी किया गया हो तो उसके विवरण दें			

**भाग – दो**  
**आवेदक की श्रेणी के लिए सुसंगत बिन्दुओं पर जानकारी/प्रतिवेदन**  
**(आवेदक की श्रेणी के अनुसार लागू खण्ड का प्रयोग करें)**

**खण्ड क**

(यह खण्ड राज्य शासन या केन्द्र शासन का विभाग या उसके अधीनस्थ संगठन, नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या पंचायती राज संस्था के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

10.	<p>10.1 योजना/परियोजना/कार्य का नाम, प्रशासकीय स्वीकृति, भौतिक तथा वित्तीय घटक और आवेदित भूमि का प्रस्तावित उपयोग, तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.2 स्थानीय निकाय की ओर से आवेदन की दशा में भूमि आवंटन के लिए स्थानीय निकाय के संकल्प के विवरण</p> <p>10.3 विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 के अंतर्गत घोषित नगर विकास स्कीम में स्थित नजूल भूमि के मामले में (स्कीम के विवरण)</p>	
-----	--	--

**खण्ड ख**

(यह खण्ड पूर्त संस्था के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

10.	<p>10.1 आवेदक संस्था के पंजीयन, उद्देश्यों, पदाधिकारीगण पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.2 विगत तीन वर्षों में संस्था के कार्यकलापों, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण दें</p> <p>10.3 संस्था के पास उपलब्ध अधोसंरचना पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.4 संस्था में विगत तीन वर्षों में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके वेतन</p>	
-----	--	--



	<p>पर किए जा रहे वार्षिक व्यय पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.5 विगत तीन वर्षों की कुल आय कुल व्यय तथा संस्था के द्वारा अपने उद्देश्यों पर किए गए व्यय तथा कार्पस निधि (Corpus Fund) पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.6 संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में लेखों के अंकक्षण व आयकर विवरणी दाखिल करने की स्थिति पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.7 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के अंतर्गत संस्था के पंजीयन की स्थिति पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.8 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अंतर्गत संस्था के पंजीयन की स्थिति पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.9 संस्था को प्रदेश में यदि पूर्व में कोई शासकीय भूमियां आवंटित की गई हों तो उनके पूर्ण विवरण, वर्तमान में उन भूमियों के किये जा रहे उपयोग तथा अब की जा रही भूमि की मांग के औचित्य पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.10 क्या संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है?</p> <p>10.11 क्या संस्था की आय तथा आस्तियां उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो कि उसके उद्देश्यों तथा उपविधियों में वर्णित हैं?</p> <p>10.12 क्या संस्था की आय का कोई अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके सदस्यों, संचालकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों को वितरित किया जाता है</p>	
--	--	--

<p>या किए जाने योग्य है?</p> <p>10.13 क्या संस्था की उपविधियों के अनुसार संस्था के परिसमापन पर उसकी निबल आस्तियां (Net assets) उसकी देनदारियों की पूर्ति के उपरांत उसके सदस्यों, संचालकों, संस्थापकों व दानदाताओं को वापस होती है?</p> <p>10.14 अन्य कोई बिन्दु</p> <p>10.15 क्या संस्था मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 27 के अनुसार भूमि आवंटन के लिए अर्हता रखती है?</p> <p>10.16 आवेदित भूमि के लिए अन्य संस्थाओं के द्वारा मांग की जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के संबंध में कंडिका 1 से 11 तथा इस खण्ड की समस्त उपकंडिकाओं पर पृथक-पृथक विवरण/प्रतिवेदन दें</p> <p>10.17 आवेदित भूमि के लिए एक से अधिक अर्ह संस्थाओं के द्वारा मांग किए जाने की दशा में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 29 की उपकंडिका (8) में दिए गए मानदण्डों पर उनका तुलनात्मक परीक्षण कर भूमि आवंटन के लिए उनका वरीयता क्रम निर्धारित करें</p>	
---	--

**खण्ड ग**

(यह खण्ड मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

10.	<p>10.1 क्या आवेदक राजनैतिक दल प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित है?</p> <p>10.2 दल के पदाधिकारियों के विषय पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.3 दल को प्रदेश में पूर्व में आवंटित शासकीय भूमियों के पूर्ण विवरण, वर्तमान में उन भूमियों के किये जा रहे उपयोग तथा अब की जा रही भूमि की मांग के औचित्य पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.4 अन्य कोई बिन्दु</p> <p>10.5 क्या दल मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 35 के अनुसार भूमि आवंटन के लिए अर्हता रखता है?</p> <p>10.6 आवेदित भूमि के लिए अन्य राजनैतिक दलों के द्वारा मांग की जाने की दशा में प्रत्येक राजनैतिक दल के संबंध में कंडिका 1 से 11 तथा इस खण्ड की समस्त उपकंडिकाओं पर पृथक-पृथक विवरण/प्रतिवेदन दें</p> <p>10.7 आवेदित भूमि के लिए एक से अधिक अर्ह दल के द्वारा मांग किए जाने की दशा में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 37 की उपकंडिका (8) में दिए गए मानदण्डों पर उनका तुलनात्मक परीक्षण कर भूमि आवंटन के लिए उनका वरीयता कम निर्धारित करें</p>	
-----	---	--

**खण्ड घ**

(यह खण्ड युद्ध में मृत सैनिक का परिवार के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

10.	<p>10.1 युद्ध में मृत हुए सैनिक का नाम तथा सक्षम प्राधिकार से जारी प्रमाणपत्र पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.2 अन्य बिन्दु</p>	
-----	--	--

**खण्ड ङ**

(यह खण्ड निजी पूंजी निवेशक के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

10.	<p>10.1 राज्य शासन की नीति जिसके अंतर्गत भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया है से संबंधित विभाग का नाम, आदेश क्रमांक तथा दिनांक</p> <p>10.2 संबंधित विभाग के द्वारा परियोजना को भूमि आवंटन किए जाने की अनुशंसा पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.3 परियोजना का संक्षिप्त विवरण दें</p> <p>10.4 परियोजना में प्रस्तावित सीधे रोजगार पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.5 परियोजना में प्रस्तावित निवेश के आकार पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.6 आवेदक द्वारा प्रदेश में पूर्व से स्थापित और गतिशील परियोजनाओं पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.7 परियोजना की स्थापना से जिले को प्राप्त होने वाले अन्य लाभ पर प्रतिवेदन दें</p> <p>10.8 अन्य कोई बिन्दु</p> <p>10.9 आवेदित भूमि के लिए अन्य निवेशकों के द्वारा मांग की जाने की दशा में प्रत्येक निवेशक के संबंध में कड़िका 1 से 11 तथा इस खण्ड की</p>	
-----	---	--

<p>समस्त उपकंडिकाओं पर पृथक-पृथक विवरण/प्रतिवेदन दें</p> <p>10.10 आवेदित भूमि के लिए एक से अधिक अर्ह निवेशक के द्वारा मांग किए जाने की दशा में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 49 की उपकंडिका (4) में दिए गए मानदण्डों पर उनका तुलनात्मक परीक्षण कर भूमि आवंटन के लिए उनका वरीयता कम निर्धारित करें</p>	
--	--

### खण्ड च

(यह खण्ड ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

<p>10. 10.1 संस्था का नाम जिसके द्वारा ध्वजदंड अथवा अखिल भारतीय या राज्य स्तर के ख्याति प्राप्त व्यक्ति की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है</p> <p>10.2 यदि स्थानीय निकाय प्रस्तावित ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना के लिए सहमत है तो क्या उसके द्वारा यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति दी गई है कि ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना के उपरांत भविष्य में उसे संरक्षित, गरिमामय एवं दर्शनीय स्थिति में रखा जाएगा जिसका दायित्व स्थानीय निकाय का होगा?</p> <p>10.3 प्रस्तावित प्रयोजन के भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन</p> <p>10.4 ध्वजदंड या प्रतिमा की गरिमा एवं दर्शनीयता की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता</p> <p>10.5 सड़क-सुरक्षा तथा यातायात की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता</p> <p>10.6 प्रस्तावित स्थल पर भविष्य में समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होने (जैसे जयंती, पुण्यतिथि आदि अवसरों पर) अथवा</p>	
<p>बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना की दृष्टि से स्थल की उपयुक्तता</p> <p>(टीप- सड़क, चौराहा या तिराहा के बीच में ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह सड़क-सुरक्षा तथा यातायात की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। साथ ही भविष्य में सड़क, चौराहा आदि के विस्तार की स्थिति निर्मित होने पर प्रतिमा के अन्यत्र विस्थापन पर विवाद की संभावना रहेगी)</p>	

**भाग — तीन**  
**जांच अधिकारी की अनुशांसा**

(सभी मामलों के लिए लागू)

11.	<p>11.1 भूमि का प्रस्तावित उपयोग</p> <p>11.2 लैंड बैंक की प्रविष्टि के अनुसार क्या आवेदित भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु जिसके लिए आवंटन चाहा गया है, आवंटन योग्य है?</p> <p>11.3 क्या आवेदित भूमि विकास योजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में स्थित है? यदि हां, तो क्या भूमि का प्रस्तावित उपयोग विकास योजना में अनुमत है?</p> <p>11.4 क्या आवेदित भूमि पहाड़, चट्टान या पानी के नीचे मलों में दर्ज है? यदि हां, तो विवरण दें</p> <p>11.5 क्या आवेदित भूमि/संहिता की धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक् रखी गई है/थी? यदि हां, तो कलेक्टर द्वारा नोईयत परिवर्तन करने के आदेश के विवरण दें तथा आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें</p> <p>11.6 क्या आवेदित भूमि संहिता की धारा 233-क के अंतर्गत किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई है/थी? यदि हां, तो विवरण दें। क्या भूमि जिस प्रयोजन के लिए मांग की गई है वह ऐसे लोक प्रयोजन के अनुसार है? यदि कलेक्टर द्वारा भूमि लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखने की कार्यवाही खत्म की गई हो या लोक प्रयोजन में परिवर्तन किया गया हो तो उसके विवरण दें तथा आदेश की</p>
-----	---

	<p>प्रतिलिपि संलग्न करें</p> <p>11.7 क्या आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है? यदि नहीं तो उस पर कब्जे/ अतिक्रमण के विवरण दें</p> <p>11.8 राज्य/केन्द्र शासन के विभाग या उसके अधीनस्थ संगठन, नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्था या सहकारी संस्था के द्वारा भूमि की मांग के मामले में परीक्षण कर अभिमत दें कि क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?</p> <p>11.9 कंडिका 11.8 में उल्लेखित आवेदकों की श्रेणी से भिन्न आवेदक द्वारा भूमि की मांग के मामले में परीक्षण कर अभिमत दें कि क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?</p> <p>11.10 आवेदित भूमि की उपलब्धता तथा प्रस्तावित प्रयोजन के लिए उपयुक्तता पर जांचकर्ता अधिकारी का अभिमत</p>	
12	<p>12.1 भूमि आवंटन के लिए आवेदक की अर्हता तथा उपयुक्तता पर जांचकर्ता अधिकारी का अभिमत</p> <p>12.2 एक से अधिक आवेदक होने की दशा में भूमि का आवंटन किसे किया जाना उचित होगा इसके संबंध में जांचकर्ता अधिकारी की अनुशंसा</p>	
13	<p>13.1 भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर</p>	

	<p>भूमि की आवश्यकता का आकलन करें</p> <p>13.2 यदि कंडिका 13.1 में किए गए आकलन से अधिक क्षेत्रफल की मांग की गई है तो क्या उसे मान्य करने के लिए पर्याप्त औचित्य है?</p> <p>13.3 आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की आवेदक की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर परीक्षण करे तथा उस पर अभिमत दें</p> <p>13.4 आवेदक को भूमि का कितना क्षेत्रफल आवंटित किया जाना युक्तियुक्त होगा इस बारे में जांचकर्ता अधिकारी की अनुशंसा</p>	
14	यदि आवेदक को भूमि का अग्रिम आधिपत्य सौंपा गया हो तो उसके विवरण	
15	मध्यप्रदेश बाजार मूल्य (मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण) नियम, 2000 के अधीन वर्ष ..... के अनुसार बाजार मूल्य की गणना	
16	मामले में देय प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक	
17	अन्य कोई बिन्दु	
18	मामले में नजूल अधिकारी की स्पष्ट और सकारण अनुशंसा	

कार्यालय की सील

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....



**प्ररूप तीन**  
(देखें कंडिका 62)

**नजूल भूमि का स्थायी पट्टा**

पक्षकार	1. यह अनुबन्ध आज दिनांक.....मास.....सन्.....प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्ता कहा गया है) और द्वितीय पक्ष .....(नाम, पिता/माता/पति का नाम, पूर्ण पता ई-मेल एवं मोबाईल फोन नम्बर सहित, यथास्थिति संस्था/कंपनी/राजनैतिक दल आदि के मामले में पदाधिकारी का पदनाम तथा प्राधिकार पत्र के विवरण दें) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कहा गया है) के बीच किया जाता है।
प्रीमियम	<p>चूंकि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार को</p> <p>(क) पूर्ण प्रीमियम और वार्षिक भू-भाटक पर अथवा</p> <p>(ख) प्रीमियम और/या वार्षिक भू-भाटक में निम्नानुसार रियायत निम्न कारणों से देते हुए— प्रीमियम..... वार्षिक भू-भाटक ..... (रियायत के विवरण दें) रियायत के कारण .....</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(ग) अस्थायी पट्टे को स्थायी पट्टे में परिवर्तन की स्वीकृति के आधार पर देय परिवर्तन शुल्क..... (जो लागू न हो, काट दें)</p> <p>एतदपश्चात् वर्णित भूमि पट्टे पर देना मान्य किया है; और चूंकि पट्टेदार द्वारा प्रीमियम/परिवर्तन शुल्क के रूप में .....रुपये (शब्दों में रुपये.....) सरकारी खजाने में चालान कमांक..... .....दिनांक .....तथा पट्टावधि के प्रथम वर्ष के वार्षिक भू भाटक के रूप में .....रुपये (शब्दों में रुपये.....) सरकारी खजाने में चालान कमांक.....दिनांक .....द्वारा संदाय किए हैं, जिसकी कि प्राप्ति को पट्टाकर्ता एतद्वारा अभिस्वीकार करता है, अतएव यह अनुबंध इस बात का साक्षी है कि पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के, जो इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट है; <b>प्रतिफलस्वरूप—</b></p>
पट्टान्तरण	पट्टाकर्ता एतद्वारा, पट्टेदार को.....जिले की ..... तहसील के..... नगर/ग्राम ..... के भीतर स्थित वह संपूर्ण भूमि, जो माप में..... वर्गमीटर/हेक्टेयर या उसके लगभग है और जो इसके नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है, तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जिसकी

	सीमाएँ इससे उपाबद्ध रेखांक में चित्रित की गई हैं और उसमें.....रंग से बतलाई गई है,
<b>अवधि</b>	इस अनुबन्ध की दिनांक से प्रारम्भ होने वाली तथा 31 मार्च सन् .....को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उसे धारण करने के हेतु निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए पट्टान्तरित करता है,—
<b>सामान्य शर्तें</b>	<p>(1) प्रयोजन— पट्टेदार पट्टान्तरित की गई भूमि का उपयोग उस पर ..... का निर्माण करने तथा उसके अनुरक्षण करने के प्रयोजनों तथा उसके सहायक प्रयोजनों के लिए करेगा और वह उसको या उस पर निर्मित भवनों को या उनके किसी भी भाग को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए न तो उपयोग में लाएगा और न उपयोग में लाए जाने की अनुमति देगा।</p> <p>(2) भू-भाटक—</p> <p>(सामान्यतः देय भू-भाटक)</p> <p>वार्षिक भू-भाटक रुपये .....(केवल .....रुपये), जो कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार संगणित भू-राजस्व के दो गुनी राशि के बराबर होगी और जो पट्टावधि के दौरान उक्त नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगा, देय होगा जो पट्टेदार अप्रैल के प्रथम दिन से जून के अंतिम दिन के दौरान सरकारी खजाने में जमा करेगा।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(अग्रिम आधिपत्य में सौंपी गई भूमि के मामले में)</p> <p>चूँकि पट्टादाता द्वारा पट्टान्तरित भूमि का अग्रिम आधिपत्य दिनांक ..... को पट्टेदार को सौंपा जा चुका है, अतः अग्रिम आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से तत्समय प्रभावशील उपबंधानुसार वार्षिक भू भाटक.....रुपये.....(केवल.....रुपये) देय होगा जो पट्टावधि अवसान के पश्चात् नवीनीकरण किये जाने की दशा में आगामी वर्ष से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार संगणित भू-राजस्व के दो गुनी राशि के बराबर देय होगा जो पट्टेदार ऐसी नवीकृत अवधि के पश्चात् प्रारंभ होने वाली आगामी अवधि के प्रारंभ वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से जून के अंतिम दिन के दौरान वार्षिक भू-भाटक की राशि का संदाय सरकारी खजाने में जमा करेगा;</p> <p>नियत अवधि में भू-भाटक की राशि जमा नहीं किये जाने की दशा में पट्टेदार ऐसी बकाया राशि पर देयता की दिनांक से एक वर्ष तक बारह प्रतिशत और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक की शेष अवधि के लिये पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर साधारण ब्याज की राशि जमा करायेगा।</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p>

**(रियायती भू-भाटक पर दी गई भूमि के मामले में)**

वार्षिक भू-भाटक रुपये ..... (केवल.....रुपये) देय होगा जो पट्टेदार अप्रैल के प्रथम दिन से जून के अंतिम दिन के दौरान अथवा पूरी पट्टावधि के लिए एकमुश्त सरकारी खजाने में जमा करेगा।

**(जो लागू न हो, काट दें)**

(3) **कर, आदि**— पट्टेदार समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर, ऐसे समस्त कर, प्रभार तथा प्रत्येक प्रकार के निर्धारण का संदाय तथा उन्मोचन करेगा जो कि एतद्वारा पट्टान्तरित की गई उक्त भूमि पर या उस पर निर्मित किए जाने वाले भवनों पर या उसके/उनके सम्बन्ध में अभिधारी पर इस समय या एतदपश्चात् उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किए जाएँ।

(4) **निर्माण की कालावधि**— पट्टेदार इस पट्टे के प्रारंभ होने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर भवन निर्माण करना प्रारम्भ करेगा और ऐसी दिनांक से ..... वर्ष के भीतर निर्माण पूर्ण करेगा।

(5) **भवन का विनियमन**— उक्त भूमि पर किसी भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन के विषय में, पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के तथा उन नियमों, उपविधियों एवं आदेशों के, जो कि उसके (उक्त विधि के) अधीन बनाये गये हों, तथा दिए गये हों और जो कि तत्समय प्रवृत्त हों, अध्याधीन रहेगा।

(6) **समुचित अनुक्षण**— पट्टेदार, उक्त अवधि के दौरान, उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों को जिस प्रयोजन के लिए भूमि आबंटित है, के उपयोग के योग्य दशा में रखेगा।

(7) **व्यापार या कारबार**— पट्टेदार परिसर पर कोई भी ऐसा व्यापार, कारबार या क्रिया-कलाप, जिसके कि विनियमन के लिये स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विधि द्वारा या उसके अधीन तत्समय कोई उपबंध किए गए हों, ऐसे उपबंधों के अधीन ही करेगा या किये जाने की अनुज्ञा देगा।

(8) **समनुदेशन/अभिहस्तांकन/उप-पट्टा/अंतरण**—(क) पट्टेदार पट्टान्तरित भूमि या उसके किसी भी भाग को या इस अनुबंध के अधीन अर्जित किसी भी अधिकार को पट्टाकर्ता की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना न तो समनुदेशित या अभिहस्तांकित करेगा, न उप-पट्टे पर देगा, न ही अन्य प्रकार से अंतरित **(जो लागू न हो, काट दें)**

**(जो लागू न हो, काट दें)**

(3) **कर, आदि**— पट्टेदार समय-समय पर उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर, ऐसे समस्त कर, प्रभार तथा प्रत्येक प्रकार के निर्धारण का संदाय तथा उन्मोचन करेगा जो कि एतद्वारा पट्टान्तरित की गई उक्त भूमि पर या उस पर निर्मित किए जाने वाले भवनों पर या उसके/उनके सम्बन्ध में अभिधारी

	<p>पर इस समय या एतदपश्चात् उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय निर्धारित, प्रभारित या अधिरोपित किए जाएँ।</p> <p>(4) <b>निर्माण की कालावधि</b>— पट्टेदार इस पट्टे के प्रारंभ होने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर भवन निर्माण करना प्रारम्भ करेगा और ऐसी दिनांक से ..... वर्ष के भीतर निर्माण पूर्ण करेगा।</p> <p>(5) <b>भवन का विनियमन</b>— उक्त भूमि पर किसी भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन के विषय में, पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के तथा उन नियमों, उपविधियों एवं आदेशों के, जो कि उसके (उक्त विधि के) अधीन बनाये गये हों, तथा दिए गये हों और जो कि तत्समय प्रवृत्त हों, अध्यधीन रहेगा।</p> <p>(6) <b>समुचित अनुरक्षण</b>— पट्टेदार, उक्त अवधि के दौरान, उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों को जिस प्रयोजन के लिए भूमि आबंटित है, के उपयोग के योग्य दशा में रखेगा।</p> <p>(7) <b>व्यापार या कारबार</b>— पट्टेदार परिसर पर कोई भी ऐसा व्यापार, कारबार या क्रिया—कलाप, जिसके कि विनियमन के लिये स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विधि द्वारा या उसके अधीन तत्समय कोई उपबंध किए गए हों, ऐसे उपबंधों के अधीन ही करेगा या किये जाने की अनुज्ञा देगा।</p> <p>(8) <b>समनुदेशन/अभिहस्तांकन/उप-पट्टा/अंतरण</b>—(क) पट्टेदार पट्टान्तरित भूमि या उसके किसी भी भाग को या इस अनुबंध के अधीन अर्जित किसी भी अधिकार को पट्टाकर्ता की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना न तो समनुदेशित या अभिहस्तांकित करेगा, न उप-पट्टे पर देगा, न ही अन्य प्रकार से अंतरित करेगा।</p> <p>(ख) उक्त शर्त के अनुक्रम में पट्टेदार द्वारा किये गये प्रत्येक समानुदेशन/अभिहस्तांकन/उप-पट्टा/अंतरण के फलस्वरूप अंतरिती द्वारा अर्जित अधिकार की सूचना अंतरण की दिनांक से तीस दिवस के भीतर पट्टाकर्ता को देना अनिवार्य होगा।</p>
<p><b>विशिष्ट शर्तें</b></p> <p>(9) (क) या (9) (ख) या (9) (ग) में से जो लागू न हो, काट दें।</p>	<p>(9) (क) <b>पूर्ण संस्था के मामले में</b>—</p> <p>(एक) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा उसका विभाजन नहीं किया जाएगा;</p> <p>(दो) पट्टेदार संस्था द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो;</p> <p>(तीन) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत नजूल अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार या अन्य व्यक्ति को पट्टेदार संस्था के लेखा अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा;</p> <p>(चार) आवंटित भूमि पर संचालित पट्टेदार संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं</p>

	<p>किया जाएगा; और</p> <p>(पांच) आवंटित भूमि पर पट्टेदार संस्था द्वारा आवंटित भूमि में निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यावसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा।</p> <p>(ख) राजनैतिक दल के मामले में—</p> <p>(एक) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा विभाजन नहीं किया जाएगा;</p> <p>(दो) पट्टेदार राजनैतिक दल द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो;</p> <p>(तीन) यदि किसी कारणवश पट्टेदार राजनैतिक दल अस्तित्व में नहीं रहता है तो आवंटित भूखंड एवं उस पर निर्मित संरचना (भवन) राज्य शासन में वेष्टित हो जाएंगे तथा उसके द्वारा भूखंड के लिए राज्य शासन को प्रब्याजि अथवा भू-भाटक के मददे जमा की गई राशि वापिस नहीं लौटाई जाएगी और न ही भूखंड पर निर्मित संरचना के लिए कोई प्रतिफल देय होगा; और</p> <p>(चार) आवंटित भूमि पर पट्टेदार राजनैतिक दल के द्वारा आवंटित भूमि में से निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यावसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा।</p> <p>(ग) पूंजी निवेशकों के मामले में—</p> <p>विभागीय नीति के अनुक्रम में आवंटन मंजूरी आदेश में उल्लेखित शर्तें—</p> <p>(एक) .....</p> <p>(दो) .....</p> <p>(तीन) .....</p>
अतिरिक्त शर्तें	<p>(10) स्वीकृति आदेश में विहित की गई अतिरिक्त शर्तें (यदि कोई हों)</p> <p>(एक) .....</p> <p>(दो) .....</p> <p>(तीन) .....</p>
निर्बाध उपयोग	<p>(11) निर्बाध उपयोग— पट्टाकर्ता यह प्रसंगिदा करता है कि एतद्वारा नियमित रूप से भाटक का संदाय करने वाला और इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों का पालन तथा अनुपालन करने वाला पट्टेदार पट्टाकर्ता या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी विधिपूर्ण विघ्न या विक्षोभ पहुँचाये गये बिना, उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि को शान्तिपूर्वक धारण करेगा और उसका उपभोग करेगा।</p>
पुनःप्रवेश	<p>परन्तु यदि किसी भी समय, उक्त भाटक या उसका कोई भी भाग, चाहे उसकी विधिपूर्वक मांग की गई हो या नहीं, उस दिनांक के जिसको कि वह शोध्य हो गया हो ठीक पश्चात् एक कैलेण्डर मास तक बकाया या असंदत रहे, या यदि पट्टेदार उक्त शर्तों से किसी भी शर्त का भंग या अपालन करे, तो</p>

	<p>पट्टाकर्ता किसी भी पूर्व कारण का या पुनःप्रवेश के अधिकार का अधित्यजन कर देने पर भी, उक्त भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसे उसी प्रकार पुनः कब्जे में ले सकेगा मानो कि यह पट्टान्तरण किया ही नहीं गया हो, ऐसी दशा में पट्टेदार ऐसे पुनःप्रवेश की दिनांक से तीन कैलेण्डर मास के भीतर उन समस्त भवनों एवं स्थापकों को हटाने का हकदार होगा जो पट्टान्तरण के चालू रहने के दौरान किसी भी समय उसके द्वारा उक्त भूमि पर निर्मित किये गये हों या लगाये गये हों :</p> <p>परन्तु यह और भी कि जब पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई कारण या पुनः प्रवेश का अधिकार उत्पन्न हो जाये, तो पट्टाकर्ता के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुनः प्रवेश की शक्ति को प्रयोग में न लाने के फलस्वरूप इस संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों के अनुक्रम में शमन राशि जैसी कि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर नियत करे, पट्टेदार से प्राप्त करे और यदि पट्टेदार, कलेक्टर या प्राधिकृत अपर कलेक्टर के आदेश द्वारा नियत किये गये समय के भीतर ऐसी धनराशि का संदाय न करे, तो उसे भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूल करे या पूर्वगामी परन्तुक के अधीन पुनः प्रवेश के अधिकार को प्रयोग में लाये।</p>
नवीकरण	<p>(12) पट्टाकर्ता यह और प्रसंविदा करता है कि वह एतद्वारा मन्जूर की गई अवधि के अन्त में और उसी प्रकार उसके पश्चात् भी समय-समय पर, ऐसी प्रत्येक आनुक्रमिक उत्तरभावी अवधि के, जो कि पट्टेदार के निवेदन तथा खर्च पर मन्जूर की जायेगी, उक्त भूमि का नवीकृत पट्टा ..... वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित करेगा:</p> <p>परन्तु प्रत्येक नवीकृत पट्टे की मन्जूरी के लिये भू भाटक में तत्समय लागू विधि अनुसार वृद्धि की जा सकेगी और यह कि प्रत्येक नवीकृत पट्टे में, इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों में से ऐसी शर्तें जो कि लागू होने योग्य हों और ऐसी अन्य शर्तें जो कि भविष्य के लिये उचित समझी जाएँ, भी अन्तर्विष्ट की जा सकेंगी:</p> <p>परन्तु यह और भी कि प्रत्येक आनुक्रमिक नवीकरण पर अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के बारे में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम होगा।</p>
निर्वचन	<p>(13) इस बात पर सहमति है कि इसमें प्रयोग में लाई गई अभिव्यक्तियों "पट्टाकर्ता" तथा "पट्टेदार" के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से असंगत न हो, पूर्वकथित के मामले में उसके उत्तरवर्ती यथा समनुदेशिती और पश्चात् कथित के मामले में उसके वारिस, निष्पादक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती आएंगे।</p>

## अनुसूची पट्टान्तरित भूमि का वर्णन

आवेदित भूमि के विवरण जिला..... तहसील.....  
 नगर.....सेक्टर..... राजस्व निरीक्षक वृत्त.....पटवारी हल्का.....ग्राम.....  
 खसरा कमांक/शीट कमांक/ब्लॉक कमांक/ भूखण्ड कमांक.....  
 माप .....  
 नजरी नक्शा .....

चौहद्दी — पूर्व में .....  
 पश्चिम में .....  
 उत्तर में .....  
 दक्षिण में .....

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

### साक्षीगण—

1. ....
2. ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर  
से कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

.....  
 नाम.....  
 पदनाम.....  
 कार्यालय की मोहर.....  
 दिनांक.....

### साक्षीगण—

1. ....
2. ....

पट्टेदार के हस्ताक्षर

.....  
 नाम.....  
 पदनाम.....  
 कार्यालय की मोहर.....  
 दिनांक.....

**प्ररूप चार**  
**(देखिए कंडिका 90)**

**मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत**  
**अस्थायी पट्टाधिकार को स्थायी पट्टाधिकार में परिवर्तन हेतु आवेदन**

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी/कलेक्टर

जिला.....(मध्यप्रदेश)

मैं/हम, मेरे/हमारे अस्थायी पट्टाधिकार को स्थायी पट्टाधिकार में परिवर्तित कराना चाहते हैं, मेरे/हमारे विवरण निम्नानुसार हैं:-

आवेदक/आवेदको  
का स्वयं  
अनुप्रमाणित  
पासपोर्ट आकार का  
प्रयाचित्र

1. (क) \*आवेदक (पट्टाधारी) का नाम.....
- (ख) आधार नम्बर.....
- (ग) माता/पिता/पति का नाम.....
- (घ) स्थायी पता.....
- (ङ) वर्तमान डाक का पता.....
- (च) दूरभाष क्रमांक/मोबाईल नं०, (यदि कोई हो).....
- (छ) ई-मेल (यदि कोई हो).....

\*एक ही भूखण्ड के संयुक्त धारणाधिकार में एक से अधिक आवेदक (पट्टाधारी) होने की दशा में प्रत्येक पट्टाधारी के विवरण ऊपर बिन्दु क्रमांक 1 के खण्ड (क) से (छ) तक पृथक-पृथक दिये जाएं।

परिवर्तन के लिये एक भूखण्ड के एक से अधिक पट्टेदार होने पर आवेदन किसी एक के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकेगा किन्तु ऐसे आवेदक को अन्य सहपट्टेदारों की ओर से प्राधिकृत करने हेतु वैध खास मुख्तारनामा प्रस्तुत करना होगा।

2. अस्थायी पट्टादाता प्राधिकारी के विवरण : .....

3. अस्थायी पट्टे के विवरण

(एक) अस्थायी पट्टाधारी का नाम .....

(दो) भू-खण्ड क्रमांक .....

(तीन) ब्लॉक क्रमांक.....

(चार) ग्राम...../सेक्टर...../नगर.....

(पांच) भूमि (भू-खण्ड) का क्षेत्रफल.....वर्गमीटर

(छ) तहसील .....जिला.....

(सात) वर्तमान वार्षिक भू-भाटक : रुपये .....

(आठ) अस्थायी पट्टे का प्रयोजन जैसा कि पट्टा विलेख में दर्शाया गया है .....

(नौ) अस्थायी पट्टे की कालावधि.....से.....तक



(दस) क्या भुगतान, (यदि कोई शेष हो), के लिए ब्याज के साथ अद्यतन भू-भाटक  
संदत्त किया गया है? हाँ/ नहीं

4. क्या भूमि का स्थल पर उपयोग वही है जो पट्टानुसार अनुज्ञेय है? हाँ/ नहीं

5. क्या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई विवाद लंबित है? हाँ/ नहीं

6. संलग्नक :-

(क) अस्थायी पट्टा विलेख की प्रति

(ख) स्थल मानचित्र

अन्य अभिलेख :-

(1) अस्थायी पट्टाधारी का विशेष (खास) मुख्तारनामा (यदि कोई हो)

(2) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले का विवरण (यदि कोई हो)

(3) .....

दिनांक : .....

स्थान : .....

आवेदक के हस्ताक्षर

**प्ररूप पांच**

(देखें कंडिका 97, 102 तथा 109)

नगरीय निकाय / विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को नजूल भूमि का भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन आदेश का प्ररूप

कार्यालय कलेक्टर.....

राजस्व प्रकरण क्रमांक .....

क्रमांक .....

नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को नजूल भूमि का भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन आदेश  
(पारित दिनांक.....)

..... (नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम) के आवेदन पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... के संदर्भ में यथास्थिति जिला नजूल निर्वर्तन समिति/संभाग नजूल निर्वर्तन समिति/भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये गठित नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लेखित नजूल भूमि.....  
(नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम) के पक्ष में आवंटित किए जाने की स्वीकृति आयुक्त ...../इस कार्यालय (जो लागू न हों काट दें) के पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... से जारी हुई है।

2. इसके क्रम में ..... (नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम) द्वारा प्रब्याजि राशि रुपये.....(शब्दों में रुपये.....) चालान क्रमांक..... दिनांक ..... द्वारा सरकारी खजाने में जमा कर दिए गए हैं।

अथवा

2. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटन के इस आदेश की दिनांक ..... से तीन वर्ष के भीतर प्रब्याजि की राशि रुपये ..... (शब्दों में रुपये.....) शासकीय खजाने में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के परिशिष्ट 'क' उल्लेखित मद में जमा करेगा। आवंटन की दिनांक से दो वर्ष तक कोई ब्याज देय नहीं होगा किन्तु दो वर्ष की अवधि के अवसान उपरांत देय राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय होगा।

3. अतः ..... (नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम) को जिला.....की तहसील.....के ग्राम/सेक्टर /नगर.....की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि, जिसका क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर है और जिसके बारे में इसमें नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जिसकी सीमाएं इसमें आबद्ध रेखांक में चिह्नित की गई हैं और उसमें.....रंग से बतलाई गई हैं, भूमिस्वामी अधिकार में अंतरित किया जाता है।

4. .... (नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम)  
को उक्त भूमि पर निर्धारित किये गये भू-राजस्व का प्रतिवर्ष संदाय करना होगा। भू-राजस्व  
की अदायगी में चूक के मामले में बकाया पर प्रथम वर्ष के लिये 12 प्रतिशत और उसके  
पश्चात् अदायगी दिनांक तक की शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण  
ब्याज देय होगा।

### अनुसूची आवंटित भूमि का वर्णन

आवेदित भूमि के विवरण जिला..... तहसील.....  
नगर.....सेक्टर..... राजस्व निरीक्षक वृत्त.....पटवारी हल्का.....ग्राम.....  
खसरा कमांक/शीट कमांक/ब्लॉक कमांक/ भूखण्ड कमांक.....  
माप .....  
नजरी नक्शा .....

चौहद्दी — पूर्व में .....  
पश्चिम में .....  
उत्तर में .....  
दक्षिण में .....

कार्यालय की मोहर

कलेक्टर

पृष्ठांकन क्रमांक .....

जिला.....

प्रतिलिपि:-

दिनांक .....

1. .... (नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम)
2. आयुक्त, ..... संभाग
3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर.....
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग/पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल.....
5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास/आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास/संचालक पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल.....
6. तहसीलदार, तहसील..... आदेश के पालन में संबंधित नगरीय/स्थानीय निकाय को आवंटित भूखण्ड का आधिपत्य सौंपे तथा भू अभिलेख में समुचित प्रविष्टियां अंकित कराएं।
7. आदेश पत्रावली।

कलेक्टर

जिला.....

**प्ररूप छह****(देखिये कंडिका 97, 102 एवं 109)****मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत निष्पादित  
भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख**

यह भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष 20..... को मध्यप्रदेश में स्थित पट्टे की भूमियों के संबंध में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 97, 102 या 109 (जो लागू न हो, काट दें) के अनुसरण में कलेक्टर ..... मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जहां कि संदर्भ से वैसा अनुमत हो, उनके पदीय उत्तरवर्ती भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष तथा ..... (जिन्हें इसके पश्चात् भूमिस्वामी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत, जहां कि संदर्भ में वैसा अनुमत हो, उनके पदीय उत्तरवर्ती, अंतरिती भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच निष्पादित किया जाता है;

चूँकि, भूमि का समाविष्ट क्षेत्र का माप .....वर्गमीटर स्थित ग्राम/सेक्टर ..... तहसील .....जिला ..... मध्यप्रदेश, जो इससे संलग्न अनुसूची में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक ..... दिनांक.....माह.....वर्ष.....द्वारा..... प्रयोजन के लिये भूमिस्वामी अधिकार में देने का निर्णय लिया गया है;

**(नगरीय/स्थानीय निकाय के मामले में, यथास्थिति कंडिका 97 या 102)**

और चूँकि, भूमिस्वामी द्वारा चालान क्रमांक ..... दिनांक .....माह.....वर्ष.....द्वारा संपरिवर्तन प्रभार रुपये ..... (रुपये ..... केवल) का भुगतान शासकीय खजाने में कर दिया गया है;

**अथवा****(विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मामले में, कंडिका 109)**

और चूँकि, भूमिस्वामी इस विलेख के निष्पादन की दिनांक से दो वर्ष के भीतर उक्त भूमि के लिये प्रब्याजि के रूप में रुपये.....(शब्दों में रुपये.....केवल) का भुगतान शासकीय खजाने में जमा कर करेगा और यदि उक्त अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो आगामी एक वर्ष में अदायगी दिनांक तक के लिये देय राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज सहित प्रब्याजि की राशि जमा करेगा और जमा न करने की स्थिति में देय राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूलयोग्य होगी;

**(उक्त में से जो लागू न हो, काट दें)**

और, चूँकि, भूमिस्वामी सक्षम प्राधिकारी के आदेश क्रमांक .....दिनांक ..... माह.....वर्ष..... द्वारा नियत किए गये वार्षिक भू-राजस्व रुपये ..... (रुपये ..... केवल) का भुगतान करने हेतु जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अध्याधीन होगा, सहमत है।

**अनुसूची**

भूमि के विवरण जिला.....तहसील.....

नगर.....सेक्टर..... राजस्व निरीक्षक वृत्त.....पटवारी हल्का.....ग्राम.....

खसरा कमांक/शीट कमांक/ब्लॉक कमांक/भूखण्ड कमांक .....

नक्शा .....

चौहद्दी - पूर्व में.....

पश्चिम में.....

उत्तर में.....

दक्षिण में.....

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस पर अपने-अपने  
हस्ताक्षर कर दिये हैं।

स्थान.....

**साक्षीगण-**

1. ....

2. ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर  
से कलेक्टर के हस्ताक्षर

नाम.....

कार्यालय की मोहर.....

दिनांक .....

भूमिस्वामी के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

**साक्षीगण-**

1. ....

2. ....

**प्ररूप सात**  
(देखें कंडिका 112)

**नजूल अधिकारी द्वारा नीलामी के लिये भूमि के चयन हेतु  
प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन का प्ररूप**

कार्यालय नजूल अधिकारी .....

राजस्व प्रकरण क्रमांक

प्रति,

सदस्य सचिव,  
जिला नजूल निर्वर्तन समिति,  
जिला .....

प्रतिवेदन  
(दिनांक .....)

विषय:— मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अध्याय 5 के अंतर्गत नीलामी द्वारा भूमिस्वामी हक में निर्वर्तन के लिये भूमि के चयन का प्रस्ताव।

संदर्भ:— कलेक्टर का निर्देश पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... (यदि कोई है)

1.	नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिये प्रस्तावित नजूल भूमि का विवरण		
	जिला	तहसील	
	नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त ..... पटवारी हल्का ..... ग्राम .....		नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर ..... सेक्टर .....
	क्र.	खसरा क्रमांक/शीट क्रमांक/ब्लॉक क्रमांक/ भूखण्ड क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)
		नीलामी हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	
	1		
	2		
	3		

	योग			
2.	<p>प्रस्तावित भूमि की स्थिति</p> <p>2.1 क्या प्रस्तावित भूमि व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित है? यदि हाँ तो ऐसे क्षेत्र का सामान्य विवरण</p> <p>2.2 क्या प्रस्तावित भूमि निजी भूमियों से घिरी हुई है? यदि हाँ तो विवरण (नक्शा संलग्न करते हुए स्थिति स्पष्ट दर्शाये)</p> <p>2.3 क्या प्रस्तावित भूमि का निर्वर्तन व्यावसायिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कारण/आधार स्पष्ट करें</p>			
3.	<p>3.1 सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करने के विवरण</p> <p>3.2 प्राप्त आपत्तियों, दावों और सुझावों के विवरण</p> <p>3.3 प्राप्त आपत्तियों, दावों और सुझावों पर जांच अधिकारी द्वारा की गई विवेचना तथा निष्कर्ष</p>			
4.	<p>4.1 स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश तथा अन्य विभाग के अभिमत प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही के विवरण</p> <p>4.2 प्राप्त अभिमतों के विवरण</p> <p>4.3 प्राप्त अभिमतों पर जांच अधिकारी का निष्कर्ष</p>			
5.	<p>प्रस्तावित भूमि के संबंध में कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित हो तो उसके विवरण दें तथा न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी किया</p>			

	गया हो तो उसके विवरण दें	
6.	<p>6.1 भूमि का प्रस्तावित उपयोग</p> <p>6.2 लैण्ड बैंक की प्रविष्टि के अनुसार क्या प्रस्तावित भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु जिसके लिए नीलामी द्वारा निर्वर्तन प्रस्तावित है, आवंटन योग्य है ?</p> <p>6.3 क्या प्रस्तावित भूमि विकास योजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में स्थित है? यदि हां, तो क्या भूमि का प्रस्तावित उपयोग विकास योजना में अनुमत है?</p> <p>6.4 क्या प्रस्तावित भूमि पहाड़, चट्टान या पानी के नीचे मलों में दर्ज है? यदि हां, तो विवरण दें</p> <p>6.5 क्या प्रस्तावित भूमि/संहिता की धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक् रखी गई है/थी? यदि हां, तो कलेक्टर द्वारा नोईयत परिवर्तन करने के आदेश के विवरण दें तथा आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें</p> <p>6.6 क्या प्रस्तावित भूमि संहिता की धारा 233-क के अंतर्गत किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई है/थी? यदि हां, तो विवरण दें। क्या भूमि जिस प्रयोजन के लिए मांग की गई है वह ऐसे लोक प्रयोजन के अनुसार है? यदि कलेक्टर द्वारा भूमि लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखने की कार्यवाही खत्म की गई हो या लोक प्रयोजन में परिवर्तन किया गया हो तो उसके विवरण दें तथा आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें</p>	



	<p>6.7 क्या प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त है? यदि नहीं तो उस पर कब्जे/ अतिक्रमण के विवरण दें</p> <p>6.8 क्या प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता किसी लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?</p> <p>6.9 प्रस्तावित भूमि की उपलब्धता तथा प्रस्तावित प्रयोजन के लिए नीलामी द्वारा भूमिस्वामी हक में निर्वर्तन की उपयुक्तता पर जांचकर्ता अधिकारी का अभिमत</p>	
7.	भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ. ए.आर.) के विवरण	
8.	मध्यप्रदेश बाजार मूल्य (मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण) नियम, 2000 के अधीन वर्ष ..... के अनुसार बाजार मूल्य की गणना	
9.	भूमिस्वामी हक में दिये जाने पर प्रस्तावित प्रयोजन अनुसार प्रस्तावित निर्धारण	
10.	अन्य कोई बिन्दु	
11.	मामले में नजूल अधिकारी की स्पष्ट और सकारण अनुशंसा	

कार्यालय की सील

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पदनाम .....

**प्ररूप आठ**  
(देखें कंडिका 115)

नजूल भूमि के नीलामी द्वारा निर्वर्तन की सार्वजनिक उद्घोषणा का प्ररूप  
नजूल भूमि का नीलामी द्वारा निर्वर्तन  
सार्वजनिक उद्घोषणा

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी.....

राजस्व प्रकरण क्रमांक .....

शासकीय भूखण्ड की नीलामी का विज्ञापन

नीचे दर्शाये गए विवरण अनुसार शासकीय नजूल भूमि को प्रतिस्पर्धात्मक निविदा पद्धति से भूमिस्वामी हक में दिये जाने के लिये ई-ऑक्शन की प्रक्रिया अपनाते हुए ई-ऑक्शन पोर्टल ..... (पोर्टल का नाम दें) नीलाम किया जाएगा—

- (1) जिला.....(2) तहसील .....  
(3) नगर .....(4) सेक्टर.....(5) वार्ड क्रमांक .....(6)  
पटवारी हल्का नं. ....(7) ग्राम.....  
(8) भूमि, आधार मूल्य एवं प्रतिभूति राशि का विवरण—

सरल क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक	कुल क्षेत्रफल	विक्रय हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास योजना (यदि कोई है) में अनुमत भूमि उपयोग	* वार्षिक भू-राजस्व (रुपये में)	आधार मूल्य (Upset Price)	प्रतिभूति राशि (Earnest Money)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
योग							

\* ऊपर स्तम्भ 6 में दर्शाया गया वार्षिक भू-राजस्व मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अध्याधीन होगा।

- (9) नीलामी में भाग लेने के लिये अंतिम तिथि ..... समय..... बजे तक नियत है।  
(10) भूमि का नक्शा एवं अन्य अभिलेख उपरोक्त ई-ऑक्शन पोर्टल पर तथा सक्षम प्राधिकारी .....के कार्यालय में देखे जा सकते हैं।

- (11) उपरोक्त भूमि का निर्वर्तन भूमिस्वामी हक में किया जाएगा। ई-ऑक्शन की प्रक्रिया के विवरण उपरोक्त ई-ऑक्शन पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर पंजीयन कराया जा सकेगा, इसके पश्चात् प्रक्रिया अनुसार प्रथमतः निर्धारित प्रतिभूति राशि (Earnest Money) वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाईन जमा कर ई-ऑक्शन के लिये नियत समयावधि में विधिवत् लॉग-इन कर अपना ऑफर दर्ज कर भाग लिया जा सकेगा।
- (12) प्राप्त ऑफर्स खोलने की दिनांक .....समय.....बजे नियत है।
- (13) नीलामी के आधार पर प्राप्त ऑफर्स पर अंतिम निर्णय राज्य शासन अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी का होगा।

सील

हस्ताक्षर

दिनांक .....

सक्षम प्राधिकारी

**प्ररूप नौ**  
(देखें कंडिका 117)

**नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला नजूल भूमि की ई-नीलामी की  
कार्यवाही का प्रतिवेदन**

कार्यालय नजूल अधिकारी .....

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

प्रति,

सदस्य सचिव,  
जिला नजूल निर्वर्तन समिति,  
जिला .....

प्रतिवेदन  
(दिनांक .....) )

विषय:- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अध्याय 5 के अंतर्गत नगर.....  
.....सेक्टर.....वार्ड क्रमांक.....पटवारी हल्का.....ग्राम.....  
.....तहसील.....जिला.....में स्थित .....  
वर्गमीटर नजूल भूमि की ई-नीलामी दिनांक.....की कार्यवाही का प्रतिवेदन।

1.	नीलामी के लिये चयन की गई नजूल भूमि के विवरण <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>जिला.....</span> <span>तहसील.....</span> </div>		
नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त ..... पटवारी हल्का ..... ग्राम .....		नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर ..... सेक्टर .....	
क्र.	खसरा क्रमांक/शीट क्रमांक/ब्लॉक क्रमांक/ भूखण्ड क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	नीलामी हेतु चयनित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)
1			
2			

	3			
	योग			
2.	मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 110 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी के लिये भूमि चयन की स्वीकृति का विवरण दें तथा निर्णय की प्रति संलग्न करें			
3.	मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 142(3) के अंतर्गत नीलामी के लिये सार्वजनिक उद्घोषणा के प्रकाशन के विवरण दें तथा उद्घोषणा की प्रति संलग्न करें			
4.	भूमि का निर्धारित किया गया न्यूनतम आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) (एक से अधिक भूखण्ड के मामले में प्रत्येक भूखण्ड का अलग-अलग मूल्य दर्शाये)			
5.	निविदा ऑफर के लिये नियत की गई प्रतिभूति राशि (एक से अधिक भूखण्ड के मामले में प्रत्येक भूखण्ड का अलग-अलग मूल्य दर्शाये)			
6.	ई-नीलामी के लिये नियत समयावधि (अंतिम तिथि एवं समय अंकित करें)			
7.	नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची तथा उनके द्वारा अंकित अंतिम ऑफर के विवरण दिनांक, समय एवं राशि सहित दें			
8.	9.1 उच्चतम निविदा ऑफरकर्ता के पूर्ण विवरण (निविदाकर्ता का नाम एवं पता, ई-मेल में			

	तथा फोन/मोबाईल फोन नम्बर सहित) 9.2 निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी के विवरण (तिथि, राशि एवं जमा करने की रीति)	
9.	अन्य निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) संबंधितों के बैंक खाते में वापिस की गई, के विवरण	
10.	अन्य बिन्दु (यदि कोई हों)	
11.	उच्चतम निविदा ऑफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा टीप (एक से अधिक भूखण्डों के मामले में प्रत्येक भूखण्ड के लिये उच्चतम निविदा ऑफरकर्ता का नाम, ऑफर की गई राशि, ऑफर स्वीकृति की दशा में भूखण्ड पर देय वार्षिक भू-राजस्व की राशि भी दर्शाये)	

कार्यालय की सील

हस्ताक्षर नजूल अधिकारी .....  
नाम .....

**प्ररूप दस**  
**(देखें कंडिका 117)**

**भूमि प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला नजूल भूमि की ई-नीलामी के निर्णय की संसूचना**

कार्यालय भूमि प्रबंधन प्राधिकारी .....

प्रकरण क्रमांक.....

प्रति,

प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल

निर्णय की संसूचना  
(दिनांक .....)

**विषय:-** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अध्याय 5 के अंतर्गत नगर.....  
.....सेक्टर.....वार्ड क्रमांक.....पटवारी हल्का.....ग्राम.....  
.....तहसील.....जिला.....में स्थित .....  
वर्गमीटर नजूल भूमि की ई-नीलामी दिनांक.....के निर्णय की संसूचना।

1.	नीलामी के लिये चयन की गई नजूल भूमि के विवरण जिला.....तहसील.....			
	नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त ..... पटवारी हल्का ..... ग्राम .....		नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर ..... सेक्टर .....	
	क्र.	खसरा क्रमांक/शीट क्रमांक/ब्लॉक क्रमांक/ भूखण्ड क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	नीलामी हेतु चयनित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)
	1			
	2			

	3			
	योग			
2.	मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 110 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी के लिये भूमि चयन की स्वीकृति का विवरण दें तथा निर्णय की प्रति संलग्न करें			
3.	भूमि का निर्धारित किया गया न्यूनतम आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) (एक से अधिक भूखण्ड के मामले में प्रत्येक भूखण्ड का अलग-अलग मूल्य दर्शाये)			
4.	निविदा ऑफर के लिये नियत की गई प्रतिभूति राशि (एक से अधिक भूखण्ड के मामले में प्रत्येक भूखण्ड का अलग-अलग मूल्य दर्शाये)			
5.	6.1 सफल निविदाकर्ता के पूर्ण विवरण (निविदाकर्ता का नाम एवं पता, ई-मेल में तथा फोन/मोबाईल फोन नम्बर सहित) 6.2 निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी के विवरण (तिथि, राशि एवं जमा करने की रीति)			
6.	असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) संबंधितों के बैंक खाते में वापिस की गई, के विवरण			
7.	अन्य बिन्दु (यदि कोई हों)			



8.	सफल निविदाकर्ता के ऑफर को स्वीकृत किये जाने की निर्णय टीप (एक से अधिक भूखण्डों के मामले में प्रत्येक भूखण्ड के लिये सफल निविदाकर्ता का नाम, ऑफर की गई राशि, ऑफर स्वीकृति की दशा में भूखण्ड पर देय वार्षिक भू-राजस्व की राशि भी दर्शाये)	
----	--	--

कार्यालय की सील

भूमि प्रबंधन प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारी के  
हस्ताक्षर .....  
नाम .....

**प्ररूप ग्यारह**  
(देखें कंडिका 119)

नजूल भूमि का नीलामी द्वारा निर्वर्तन- विक्रय विलेख

कार्यालय कलेक्टर.....संभाग .....

राजस्व प्रकरण क्रमांक .....

**विक्रय विलेख**  
(दिनांक .....को जारी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....  
माता/पिता/पति.....निवासी (पूर्ण पता) .....  
दिनांक.....को आयोजित नीलामी द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का क्रेता घोषित किया गया है अतएव यह विक्रय विलेख आज दिनांक .....माह.....सन्.....प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से कलेक्टर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् विक्रयकर्ता कहा गया है) की ओर से द्वितीय पक्ष.....(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् क्रेता कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया जाता है।

2. यह विक्रय विलेख इस बात का साक्षी है कि द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा मूल्य के रूप में संदाय किये गये रुपये.....(शब्दों में रुपये ..... ) की प्राप्ति प्रथम पक्ष विक्रयकर्ता एतद्वारा अभिस्वीकार करता है और द्वितीय पक्षकार यह अभिस्वीकार करता है कि वह इसमें इसके पश्चात् निर्धारित किये गये भू-राजस्व का प्रतिवर्ष संदाय करेगा;

और यह भी कि इस विक्रय विलेख के निष्पादन के प्रभाव में प्रथम पक्ष विक्रयकर्ता एतद्वारा द्वितीय पक्ष क्रेता को जिला.....की तहसील.....के ग्राम/सेक्टर/नगर.....की सीमाओं के भीतर स्थित भूखंड, जिसका क्षेत्रफल ..... वर्गमीटर है और जिसके बारे में इसमें नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जिसकी सीमाएं इसमें आबद्ध रेखांक में चिन्हित की गई हैं और उसमें.....रंग से बतलाई गई हैं, भूमिस्वामी अधिकार में अंतरित करता है।

**अनुसूची-विक्रय की गई भूमि सम्पत्ति का वर्णन**

सरल क्रमांक	ग्राम/सेक्टर का नाम	सर्वेक्षण/ब्लॉक/भूखंड संख्यांक	कुल क्षेत्रफल	विक्रीत क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	भू-राजस्व (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
.....					

भूखंड की चतुर्सीमा

पूर्व में.....

पश्चिम में.....

उत्तर में.....

दक्षिण में.....

संलग्न रेखांक जो इस विलेख का भाग है।

3. उपर्युक्त के साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने, प्रत्येक मामले में लिखित दिनांक... माह.....वर्ष..... को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

**साक्षीगण—**

1.1 नाम.....

1.2 पता.....

कार्यालय की सील

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की  
ओर से कलेक्टर के हस्ताक्षर

2.1 नाम.....

2.2 पता.....

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक .....

**साक्षीगण—**

1.1 नाम.....

1.2 पता.....

2.1 नाम.....

2.2 पता.....

क्रेता के हस्ताक्षर

नाम ..... पता .....

दिनांक .....

**प्ररूप बारह**  
(देखें कंडिका 125)  
**नजूल भूमि पर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) हेतु आवेदन**

प्रति,

कलेक्टर  
जिला.....

विषय:- नजूल भूमि पर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) हेतु आवेदन।

1	<p>1.1 आवेदक का नाम (जिसके नाम से भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है) (संस्थागत आवेदन के मामले में)</p> <p>1.2 आवेदनकर्ता/ पदाधिकारी का पदनाम (व्यक्तिगत आवेदन के मामले में)</p> <p>1.3 आवेदक के पिता/ माता/ पति का नाम</p> <p>1.4 लिंग</p>			
2	<p>2.1 पत्राचार के लिए पता</p> <p>2.2 दूरभाष क्रमांक</p> <p>2.3 मोबाइल नम्बर</p> <p>2.4 ई-मेल पता</p>			
3	<p>प्रक्रिया शुल्क जमा करने के विवरण (जहां लागू हो)</p> <p>3.1 जमा की गई राशि</p> <p>3.2 चालान क्रमांक</p> <p>3.3 जमा करने की दिनांक</p>			
4	<p>आवेदित भूमि के विवरण</p> <p>जिला..... तहसील.....</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त .....</td><td style="width: 50%; padding: 5px;">नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर .....</td></tr> </table>		नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त .....	नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर .....
नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त .....	नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगर .....			

पटवारी हल्का .....		सेक्टर .....	
ग्राम .....			
क्र.	खसरा कमांक/शीट कमांक/ब्लॉक कमांक/ भूखण्ड कमांक	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)
1			
2			
3			
योग			
5	लाइसेंस का प्रयोजन	<input type="checkbox"/> तम्बू या शामियाना लगाने या निर्माण सामग्री इकट्ठी कर रखने के लिए <input type="checkbox"/> पुल/पुलिया के निर्माण या कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली के निर्माण के लिए <input type="checkbox"/> गौशाला के लिए <input type="checkbox"/> अन्य प्रयोजन के लिए (विवरण दें)	
6	अवधि जिसके लिए लाइसेंस चाहा जा रहा है	दिनांक..... से दिनांक ..... तक ..... दिन/माह/वर्ष के लिये	
7	अन्य जानकारी/दस्तावेज 7.1 पुल-पुलिया निर्माण या कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली के निर्माण के मामले में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें 7.2 गौशाला के मामले में निम्न जानकारी/दस्तावेज दें— 7.2.1 प्रस्तावित गौशाला के निर्माण तथा संचालन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट 7.2.2 गौशाला समिति के बैंक खाते के विवरण 7.2.3 गौशाला समिति के अंकेक्षित		

लेखाओं की प्रतिलिपी (पिछले तीन वर्षों की)	
7.2.4 गौशाला समिति के पदाधिकारियों के नाम, पदनाम, पता, ईमेल, दूरभाष के विवरण	
7.2.5 गौशाला की अधोसंरचना के निर्माण के लिए समिति के पास उपलब्ध पूंजी के विवरण	

दिनांक

हस्ताक्षर .....

नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय की मोहर.....

**संलग्नक—**

- (1) प्रक्रिया शुल्क पावती की छायाप्रति
- (2) आवेदित भूमि के खसरा की प्रति
- (3) भूमि का नक्शा
- (4) अन्य सुसंगत दस्तावेज.....
- (5) .....
- (6) .....

**प्ररूप तेरह**

(देखें कंडिका 127)

**नजूल भूमि पर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)**

यह अनुबन्ध आज दिनांक.....मास.....सन्.....प्रथम पक्ष प्राधिकृत अधिकारी/कलेक्टर ..... जिला ..... मध्यप्रदेश के माध्यम से मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अनुदाता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत, उनके पद के उत्तरवर्ती आएंगे) और द्वितीय पक्ष..... (नाम, पिता/माता/पति का नाम, पूर्ण पता ई-मेल एवं मोबाईल फोन नम्बर सहित, यथास्थिति समिति/संस्था/कंपनी आदि के मामले में पदाधिकारी का पदनाम तथा प्राधिकार पत्र के विवरण भरें) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत, जहां कि सन्दर्भ से वैसा अनुमत हो, उनके वारिस, निष्पादक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती आएंगे) के बीच किया जाता है।

चूंकि अनुदाता, अनुज्ञप्तिधारी के निवेदन पर, इस बात के लिए सहमत हो गया है कि वह उसे जिला..... तहसील..... नगर.....सेक्टर.....राजस्व निरीक्षक वृत्त..... पटवारी हल्का.....ग्राम..... (यथास्थिति विवरण भरें) में स्थित नजूल भू-खण्ड क्र. ....में से .....वर्गमीटर माप की भूमि, जो नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जो इससे उपाबद्ध रेखांक में चित्रित है और उसमें सुर्खी से बतलाया गया है (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट है), के ऊपर/पर तम्बू या शामियाना लगाने या निर्माण सामग्री इकट्ठी कर रखने के लिए/पुल-पुलिया के निर्माण या कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली के निर्माण के लिए या गौशाला के लिए/ ..... प्रयोजन के लिए (जो लागू न हो काट दें) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त निर्माण के नाम से निर्दिष्ट है) का निर्माण करने, स्थापन करने, अनुरक्षण करने तथा उपयोग करने के लिए;—

दिनांक..... से दिनांक.....तक इसके पश्चात् दिए गये निबन्धनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) मंजूर कर देगा;—

और चूंकि अनुज्ञप्तिधारी, उसे मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के प्रतिफलस्वरूप, अनुदाता को इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित किये गये अनुसार अनुज्ञप्ति फीस के मद्दे प्रतिमास/प्रतिवर्ष .... रुपये (शब्दों में.....) की राशि का संदाय करने के लिये सहमत हो गया है।

2. अतएव यह विलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और एतद्वारा करार किया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए उक्त भूमि के ऊपर/पर उक्त रचना का निर्माण, स्थापन, अनुरक्षण तथा उपयोग कर सकेगा, अर्थात् :—

### सामान्य शर्तें

- (1) (एक) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति चालू रहने के दौरान प्रतिमास/प्रतिवर्ष दिनांक ..... को या उसके पूर्व, मासिक/वार्षिक फीस के रूप में .....रुपये की राशि का अग्रिम में संदाय करेगा।
- (दो) (क) अनुज्ञप्ति चालू रहने के दौरान यदि अनुदाता को अपने स्वयं के या लोक प्रयोजन के लिए, जिसका कि एक-मात्र निर्णायक अनुदाता होगा, उक्त भूमि की आवश्यकता हो, तो अनुदाता, अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे उस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने की तीस दिन के भीतर उक्त निर्माण को हटा ले और तदुपरान्त अनुज्ञप्तिधारी उक्त निर्माण को हटा लेगा और यह अनुज्ञप्ति खत्म हो जायेगी। यदि सूचना द्वारा अनुज्ञात की गई कालावधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी उक्त निर्माण को हटाने में असफल रहे तो अनुदाता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के खर्च से हटवा दे।
- (ख) अनुज्ञप्तिधारी उपखण्ड (क) के अधीन उक्त निर्माण को हटा लेने के लिए अपेक्षित किए जाने या अनुज्ञप्ति खत्म किए जाने के लिए कोई प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और न ही वह जमा की गई अनुज्ञप्ति फीस या उसके किसी अंश की वापसी का हकदार होगा।
- (तीन) यदि उक्त निर्माण/संरचना, ढह जाये या ऐसी बेमरम्मत की दशा में हो जाए की उनका पुनर्निर्माण अपेक्षित हो जाए, तो अनुज्ञप्ति प्रतिसंहत हो जाएगी और उक्त जीर्ण-शीर्ण निर्माण को पूरी तरह हटा लिए जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी, कलेक्टर को सूचना देगा और तदुपरान्त अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्ति-फीस संदाय करने का दायित्व, कलेक्टर पर सूचना की तामील होने की दिनांक से समाप्त हो जायेगा।
- (2) इस विलेख के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शोध्य होने वाली कोई भी राशि, उससे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।
- (3) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी समय उक्त भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसका तथा उक्त निर्माण का निरीक्षण कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे निरीक्षण के लिये प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा और कलेक्टर या प्राधिकृत आफिसर द्वारा दिये गये किन्हीं भी अनुदेशों का अनुपालन करेगा।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग का या उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग के सम्बन्ध में इस अनुज्ञप्ति के अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं भी अधिकारों का कलेक्टर के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी रीति में अन्तरण नहीं करेगा।
- (5) अनुज्ञप्तिधारी उक्त भूमि का उपयोग.....प्रयोजन के लिए ही करेगा और कलेक्टर, .....की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना, उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए न तो करेगा, न करवायेगा और न करने की अनुज्ञा देगा या इसके नीचे लिखे हुये उन निर्माणों में, जिसके कि उक्त भूमि पर प्रतिधारित



किए रहने की अनुज्ञा दे दी गई हो, कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन न तो करेगा, न करवाएगा और न करने की अनुज्ञा देगा।

- (6) यदि किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी, इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग करे, तो अनुदाता अनुज्ञप्ति को तत्काल खत्म कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने के .....दिन के भीतर उक्त निर्माणों को हटा ले। यदि अनुज्ञप्तिधारी, सूचना में अनुज्ञात की गई कालावधि के भीतर उक्त निर्माणों को हटाने में असफल रहे, तो अनुदाता के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह उन्हें मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959), की धारा 248 के उपबन्धों में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के खर्च से हटवा दे :

परन्तु अनुदाता के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह अनुज्ञप्ति को खत्म न करने हेतु प्रतिफल के तौर पर अनुज्ञप्तिधारी से ऐसी बढ़ी हुई फीस प्राप्त करे जैसी कि अनुदाता अवधारित करे।

- (7) अनुज्ञप्तिधारी स्थानीय निकाय द्वारा नाली (ड्रेन) की सफाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा अथवा उसके संधारण में बाधा नहीं करेगा।

### विशिष्ट शर्तें

(पुल-पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली निर्माण की अनुज्ञप्तियों के लिए)

- (8) पुल-पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली की अनुमत ऊँचाई, तथा अन्य नाप (डाइमेंशन) निम्नानुसार होंगे— .....

- (9) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुल, पुलिया कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के निर्माण का संरचना रूपांकन (Structural Design) पंजीकृत संरचना यंत्री (Registered Structural Engineer) से तैयार कराकर, लोक निर्माण विभाग अथवा स्थानीय निकाय के कार्यपालन यंत्री से अनुमोदन कराया जाएगा।

- (10) पुल-पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली की संरचना के रखरखाव का दायित्व अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी पर होगा और अवधि के पश्चात् यदि नया लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो ऐसी संरचना अनुज्ञप्ति अवधि के पश्चात् तीन माह की अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हटाई जाएगी। यदि नियत अवधि में ऐसी संरचना नहीं हटाई जाती है तो अनुदाता अनुज्ञप्तिधारी के व्यय पर उससे हटवा सकेगा अथवा राजसात कर सकेगा।

**(जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा स्वीकृत गौशाला निर्माण की अनुज्ञप्तियों के लिए)**

- (11) (क) गौशाला में पंचायत क्षेत्र के ऐसे गौवंश (गाय, बछड़ा) रखे जाएंगे जिनका कोई स्वामी न हों, अशक्त, बीमार या वृद्ध हों; ऐसे कम से कम पचास गौवंशी पशु उपलब्ध हों;
- (ख) गौवंश के जीवित पशु व मृत पशु से होने वाली आय गौशाला के खातों में जमा होगी और उसका व्यय गौशाला के उन्नयन पर किया जाएगा।
- (ग) भूमि का उपयोग केवल गौशाला एवं तत्संबंधी गतिविधियों के लिए ही किया जा सकेगा;
- (घ) लाइसेंस प्राप्त भूमि को विक्रय, पट्टा, उप-पट्टा, बंधक, किराये द्वारा अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा;
- (ङ) भूमि के उपयोग का लाइसेंस अस्थायी तौर पर केवल गौशाला के उपयोग मात्र के लिए ही होगा; मूलतः यह भूमि शासकीय सम्पत्ति रहेगी तथा भू-अभिलेख इत्यादि में भूमिस्वामी के कॉलम में "मध्यप्रदेश शासन" लिखा रहेगा;
- (च) गौशाला की स्थापना के पश्चात् संचालक समिति को गौशाला का पंजीयन मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में कराना अनिवार्य होगा; और
- (छ) गौशाला के संचालन के लिये मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड तथा उसके द्वारा जारी नियमों के अनुसरण में समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना होगा।

**अतिरिक्त शर्तें**

(इस भाग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित अन्य शर्तें अंकित की जाएं)

- (12) .....
- (13) .....

**अनुसूची**

— लाइसेंस पर दी गई भूमि का वर्णन —

आवेदित भूमि के विवरण जिला..... तहसील.....  
 नगर.....सेक्टर..... राजस्व निरीक्षक वृत्त.....पटवारी हल्का.....ग्राम.....  
 खसरा कमांक/शीट कमांक/ब्लॉक कमांक/ भूखण्ड कमांक.....  
 माप .....

नजरी नक्शा .....

चौहद्दी — पूर्व में .....  
 पश्चिम में .....  
 उत्तर में .....  
 दक्षिण में .....

3. जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट की गई दिनांक तथा वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षीगण—

1. ....
2. ....

अनुदाता  
दिनांक .....

साक्षीगण—

1. ....
2. ....

अनुज्ञापिधारी  
दिनांक .....

**प्ररूप चौदह**  
(देखिये कंडिका 135)

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अध्याय सात 'भूमिस्वामी हक में कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन' के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार पत्र

न्यायालय तहसीलदार, तहसील.....जिला.....मध्यप्रदेश  
प्रकरण क्रमांक.....

**भूमिस्वामी अधिकार पत्र**

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अध्याय सात के उपबंधों के अधीन जिला नजूल निर्वर्तन समिति, जिला..... द्वारा लिये गये निर्णय क्रमांक .....दिनांक ..  
.....माह.....वर्ष..... के अनुसरण में कलेक्टर जिला.....द्वारा जारी निर्देश क्रमांक....  
.....दिनांक.....माह.....वर्ष..... के अनुपालन में ग्राम ..... पटवारी हल्का  
क्रमांक.....राजस्व निरीक्षक वृत्त.....तहसील.....जिला.....में  
स्थित भूमि, जिसके विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं, श्री.....  
माता/पिता/पति.....निवासी.....तहसील.....  
जिला.....मध्यप्रदेश को भूमिस्वामी अधिकार दिया जाता है।

2. अनुसूची में वर्णित भूमि उक्त भूमिस्वामी द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के उपबंधों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन धारण की जाएगी।

**अनुसूची**

ग्राम का नाम पटवारी हल्का क्रमांक, राजस्व निरीक्षक वृत्त एवं तहसील सहित	सर्वेक्षण क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	निर्धारण (भू-राजस्व) (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
योग			

नक्शा की प्रति संलग्न है। (यदि किसी सर्वेक्षण संख्यांक का अंश भाग भूमिस्वामी अधिकार में किया गया है तो नक्शे में ऐसे भाग को स्पष्टता: दर्शाया जाए।)

दिनांक .....  
स्थान.....

सील

तहसीलदार के हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
तहसील.....जिला.....

**प्ररूप पन्द्रह**  
**(देखिए कंडिका 137)**

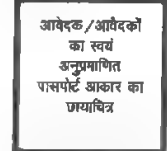
**मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत**  
**स्थायी पट्टाधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन हेतु आवेदन**

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी/कलेक्टर

जिला.....(मध्यप्रदेश)

मैं/हम, मेरे/हमारे स्थायी पट्टाधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तित कराना चाहते हैं, मेरे/हमारे विवरण निम्नानुसार हैं:-



1. (क) \*आवेदक (पट्टाधारी) का नाम.....
- (ख) आधार नम्बर.....
- (ग) माता/पिता/पति का नाम.....
- (घ) स्थायी पता.....
- (ङ) वर्तमान डाक का पता.....
- (च) दूरभाष क्रमांक/मोबाईल नं०, (यदि कोई हो).....
- (छ) ई-मेल (यदि कोई हो).....

\*एक ही भूखण्ड के संयुक्त धारणाधिकार में एक से अधिक आवेदक (पट्टाधारी) होने की दशा में प्रत्येक पट्टाधारी के विवरण ऊपर बिन्दु क्रमांक 1 के खण्ड (क) से (छ) तक पृथक-पृथक दिये जाएं।

संपरिवर्तन के लिये एक भूखण्ड के एक से अधिक पट्टेदार होने पर आवेदन किसी एक के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकेगा किन्तु ऐसे आवेदक को अन्य सहपट्टेदारों की ओर से प्राधिकृत करने हेतु वैध खास मुख्तारनामा प्रस्तुत करना होगा।

2. पट्टादाता प्राधिकारी के विवरण : .....

(यदि पट्टा राज्य सरकार या उसके द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सीधे नहीं दिया गया है)

3. पट्टे के विवरण

(एक) पट्टाधारी का नाम .....

(दो) भू-खण्ड क्रमांक .....

(तीन) ब्लॉक क्रमांक.....

(चार) ग्राम...../सेक्टर...../नगर.....

(पांच) भूमि (भू-खण्ड) का क्षेत्रफल.....वर्गमीटर/हेक्टेयर.....

(छ) तहसील ..... जिला.....

(सात) वर्तमान वार्षिक भू-भाटक : रुपये .....

(आठ) पट्टे का प्रयोजन जैसा कि पट्टा विलेख में दर्शाया गया है अथवा पट्टावधि के दौरान अनुमत परिवर्तन किया गया है.....

(नौ) पट्टा की कालावधि.....से.....तक

(दस) क्या भुगतान, (यदि कोई शेष हो), के लिए ब्याज के साथ अद्यतन भू-भाटक संदत्त किया गया है? हाँ / नहीं

4. क्या भूमि का स्थल पर उपयोग वही है जो पट्टानुसार अनुज्ञेय है? हाँ / नहीं

5. क्या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई विवाद लंबित है? हाँ / नहीं

6. संलग्नक :-

(क) पट्टा विलेख की प्रति

(ख) स्थल मानचित्र

(ग) अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि कंडिका 137 के अधीन अपेक्षित हो)

अन्य अभिलेख :-

(1) पट्टाधारी का विशेष (खास) मुख्तारनामा (यदि कोई हो)

(2) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले का विवरण (यदि कोई हो)

(3) .....

दिनांक : .....

स्थान : .....

आवेदक के हस्ताक्षर

**प्ररूप सोलह**  
**(देखिये कंडिका 140)**  
**मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत निष्पादित**  
**हस्तांतरण-विलेख**

यह हस्तांतरण विलेख आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष 20..... को मध्यप्रदेश में स्थित पट्टे की भूमियों के संबंध में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 137 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी, कलेक्टर ..... मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जहां कि संदर्भ से वैसा अनुमत हो, उनके पदीय उत्तरवर्ती भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष तथा ..... (जिन्हें इसके पश्चात् भूमिस्वामी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत, जहां कि संदर्भ में वैसा अनुमत हो, उनके पदीय उत्तरवर्ती, अंतरिती भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच निष्पादित किया जाता है;

चूँकि, भूमि का समाविष्ट क्षेत्र का माप .....वर्गमीटर स्थित ग्राम/सेक्टर ..... तहसील .....जिला ..... मध्यप्रदेश, जो इससे संलग्न अनुसूची में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित है, दिनांक.....माह.....वर्ष..... से प्रारंभ होने वाली दिनांक..... माह.....वर्ष.....को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए स्थायी पट्टे पर दी गयी थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक ..... दिनांक.....माह.....वर्ष.....द्वारा .....प्रयोजन के लिये भूमिस्वामी अधिकार में देने हेतु संपरिवर्तन मंजूर किया गया है;

और चूँकि, भूमिस्वामी द्वारा चालान क्रमांक ..... दिनांक .....माह.....वर्ष.....द्वारा संपरिवर्तन प्रभार रुपये ..... (शब्दों में रुपये ..... केवल) का भुगतान शासकीय खजाने में कर दिया गया है;

और, चूँकि, भूमिस्वामी सक्षम प्राधिकारी के आदेश क्रमांक .....दिनांक ..... माह.....वर्ष..... द्वारा नियत किए गये वार्षिक भू-राजस्व रुपये ..... (शब्दों में रुपये ..... केवल) का भुगतान करने हेतु जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अध्याधीन होगा, सहमत है;

अतएव, यह अभिलेख इस बात का साक्षी है कि उपरोक्त आदेश के अनुसरण में उक्त भूमि संबंधी पट्टा विलेख इस विलेख के निष्पादन के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगा।

### अनुसूची

भूमि के विवरण जिला.....तहसील.....  
 नगर.....सेक्टर..... राजस्व निरीक्षक वृत्त.....पटवारी हल्का.....ग्राम.....  
 खसरा क्रमांक/शीट क्रमांक/ब्लॉक क्रमांक/भूखण्ड क्रमांक .....  
 नक्शा .....  
 चौहद्दी – पूर्व में.....  
 पश्चिम में.....  
 उत्तर में.....  
 दक्षिण में.....

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

#### साक्षीगण—

1. ....
2. ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर  
 से कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
 नाम.....  
 पदनाम.....  
 कार्यालय की मोहर.....  
 दिनांक .....

#### साक्षीगण—

1. ....
2. ....

भूमिस्वामी के हस्ताक्षर  
 नाम.....  
 पदनाम.....  
 दिनांक.....



**प्ररूप सत्रह**  
**(देखिये कंडिका 143)**  
**नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र**

प्रति,

नजूल अधिकारी,

जिला— .....

विषय:— नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र देने विषयक।

महोदय,

निवेदन है, कि मुझे अपनी भूमि पर निर्माण करने के लिये मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम.....के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। मेरे तथा भूमि के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:—

1. आवेदक का नाम— .....
2. आवेदक के माता/पिता/पति का नाम— .....
3. पहचान पत्र का विवरण— .....  
 (पहचान पत्र— स्वप्रमाणित वोटर आई.डी./आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र की प्रति इत्यादि)
4. आवेदक का पता— .....  
 .....  
 .....
5. मोबाईल नं० .....
6. ई-मेल (यदि कोई हो) .....
7. भूमि का विवरण जिस के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा जा रहा है—

जिला .....तहसील .....

नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में	नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में
राजस्व निरीक्षक वृत्त .....	नगर .....
पटवारी हल्का .....	सेक्टर .....
ग्राम .....	

क्र.	ब्लॉक क्रमांक/भूखण्ड क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)
1			
2			
3			
योग			

8. भूमि पर धारणाधिकार का स्वरूप—  
(भूमिस्वामी हक या पट्टेदार)

9. प्रयोजन जिस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र  
चाहा जा रहा है—

10. संलग्न दस्तावेजों की सूची —

- (1) पहचान प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
- (2) भूखंड धारणाधिकार का प्रमाण
- (3) अनुमोदित ले-आउट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति (यदि कोई है)
- (4) नक्शा/नजरी नक्शा
- (5) .....

अनुरोध है कि मुझे उपरोक्त भूमि के संबंध में नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

**हस्ताक्षर**  
**आवेदक का नाम**

**:: सत्यापन ::**

मैं .....माता/पिता/पति .....निवासी .....  
.....सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी एवं वर्णित  
तथ्य पूर्ण एवं सत्य है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आवेदित भूखंड आवेदक के  
भूमिस्वामित्व हक/पट्टेदारी हक के धारणाधिकार का है और रिक्त नजूल भूमि/सरकारी भूमि  
का अंश नहीं है और न ही रिक्त नजूल भूमि पर अतिक्रमण है।

स्थान—  
दिनांक—

**हस्ताक्षर**  
**आवेदक का नाम**

**प्ररूप अद्वारह  
(देखिये कंडिका 143)**

**कार्यालय नजूल अधिकारी.....**  
**जिला .....**

राजस्व प्रकरण क्रमांक .....

**नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र**  
**(दिनांक..... / ..... / 20....)**

प्रति,

श्री/सुश्री.....

.....

.....

**विषय:- आपका आवेदन पत्र क्रमांक..... दिनांक.....**

आवेदक श्री/सुश्री .....माता/पिता/पति का नाम.....निवासी  
.....के द्वारा जिला.....तहसील.....पटवारी हल्का  
क्रमांक.....ग्राम.....नगर.....सेक्टर.....  
.....वार्ड.....में स्थित भूमि खसरा क्रमांक.....ब्लॉक नं. ....शीट नं. ....  
.....भूखंड क्रमांक .....रकबा .....वर्गमीटर में से .....वर्गमीटर के  
संबंध में नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के आवेदन पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि  
उक्त भूमि शासकीय नजूल भूमि नहीं है और न ही आवेदित भूखंड का कोई अंश शासकीय नजूल  
भूमि पर अतिक्रमण है।

यह प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन होगा :-

1. भवन निर्माण के पूर्व नगर एवं ग्राम निवेश तथा स्थानीय निकाय से वांछित अनुमति लेना होगी।
2. यह प्रमाण पत्र किसी को हक संबंधी कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है और न ही किसी स्वत्व संबंधी प्रकरण में इसका उपयोग अनुमत होगा।
3. उक्त भूमि के संबंध में विवाद निर्मित होने पर यह अनापत्ति किसी विधिक अथवा तथ्य संबंधी बिन्दु के निर्धारण में उपयोग नहीं की जा सकेगी।

**कार्यालय की सील**

**नजूल अधिकारी.....**  
**जिला .....**

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

क्रमांक-यूडीएच-3/0096/2023/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-1065/टी सी/93/खण्डवा/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल दिनांक 01/03/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित खण्डवा विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

## अनुसूची

ग्राम/ तहसील एवं जिला	नजूल शीट क्रमांक	प्लॉट क्रं.	क्षेत्रफल		विकास योजना में निर्दिष्ट उपयोग	उपांतरण पश्चात प्रस्तावित भू उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
ग्राम कस्बा खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा	86	01	3.202 हेक्टेयर (344563 वर्ग फीट)	3.202 हेक्टेयर (344563 वर्ग फीट)	वाणिज्यिक (विशेषीकृत)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग
		02	7.434 हेक्टेयर (799914 वर्ग फीट)	7.434 हेक्टेयर (799914 वर्ग फीट)	वाणिज्यिक (विशेषीकृत)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग
	84	14	1.880 हेक्टेयर (202326 वर्ग फीट)	1.880 हेक्टेयर (202326 वर्ग फीट)	वाणिज्यिक (विशेषीकृत)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग
	83	05	3.083 हेक्टेयर (331787 वर्ग फीट)	3.083 हेक्टेयर (331787 वर्ग फीट)	वाणिज्यिक (विशेषीकृत)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग
कुल रकबा			15.600 हेक्टेयर (1678590 वर्गफीट)			

शर्तें:-

1. खण्डवा हरसूद मार्ग से प्रश्नाधीन भूमि तक पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर रखी जाना अनिवार्य होगा ।
2. प्रश्नाधीन भूमि की उत्तर दिशा में सिंचाई विभाग एवं केन्द्रीय विद्यालय परिसर से लगकर प्रश्नाधीन भूमि की सीमा में समानान्तर 18.00 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा ।
- 4 उपरोक्त उपांतरण खण्डवा विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा।

क्रमांक-यूडीएच-3/0097/2023/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-435/टी सी/132/कटनी/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल दिनांक 24/01/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित कटनी विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक 118/1	क्षेत्रफल यर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम चाका तहसील कटनी नगर जिला कटनी	118 (118/1)	0.5020 हेक्टेयर में से 0.190 हेक्टर	कृषि एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
		योग :-	कुल रकबा 0.5020 हेक्टेयर में से 0.190 हेक्टर		

**नोट:-**

- 1 प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख कटनी बायपास मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30) की चौड़ाई 60.00 मीटर प्रस्तावित है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा।

**शर्तें:-**

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी।
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 एवं कटनी विकास योजना, 2021 के प्रावधानानुसार लागू होंगे।
- 4 उपरोक्त उपांतरण कटनी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

भोपाल, दिनांक 18 मई 2023

क्रमांक-यूडीएच-3/0106/2023/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-49/टी सी/146/इंदौर/ उपां/नग्रानि/2022 भोपाल दिनांक 03/01/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

### अनुसूची

क्र.	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल		विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग	उपांतरण पश्चात प्रस्तावित भू उपयोग
			कार्यालय जिला कलेक्टर इंदौर के द्वारा प्रतिवेदित रकबा (वर्गमीटर में)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)		
1	गाडराखेडी तहसील	215/1	3066.78	0.3066	आवासीय एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
2	मल्हारगंज जिला इंदौर (वार्ड क्र. 09)	216/1	1033.32	0.1030	आवासीय एवं मार्ग	
3		217/1/2	2027.60	0.2070	आवासीय	
4		218/2	1454.29	0.1450	आवासीय	
5		219/2	605.01	0.060	आवासीय एवं मार्ग	
	कुल रकबा		8187.00 वर्गमीटर	0.8216 हेक्टेयर		

नोट :-1. इंदौर विकास योजना, 2021 में प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख स्थित किला मैदान मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

शर्त :-1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियां मान्य होंगी।

2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं इंदौर विकास योजना 2021 के प्रावधानानुसार लागू होंगे।

3. स्थल के पास अवस्थित नाला के किनारे से वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट सीमा तक प्रभावित भूमि को वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

5. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

## वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

क्रमांक-एफ-FOR/9/0003/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 18, सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°34' से 22°43' उत्तर अक्षांश तथा 76°13' से 76°35' पूर्व देशांश के बीच स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागली जिला देवास (म0प्र0) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

## अनुसूची

जिला - देवास

तहसील - बागली

वनमंडल - देवास

वन परिक्षेत्र - बागली

क्र	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
1.	बागली	मध्यभारत शासन गजट भाग-1 (फारेस्ट एण्ड ड्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्वालियर) 1101/दस एफ/203 (54) ग्वालियर दिनांक 01.03.1955	बागली	*पुराना ब्लॉक नोटिफिकेशन	-	-	1101/दस एफ/203 (54) दिनांक 01.03.1955	01 मार्च 1955	उत्तर- तहसील बागली के राजस्व क्षेत्र के ग्राम करोदिया, बोरानिया, करमखंडा, चारिया, नयापुरा, छोटपुरा, बागली, जटाशकर, नयाखुर्द, कोटडा, सलखितिया, बरझाई, बीरगाँव, नयागाँव, कूपगाँव, सेवनाखुर्द, बारपुरा, अम्बापानी, मालीपुरा, रामपुरा, चारबर्जी, गुवाडी,





भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

एफ-For-9-0003-2022-दस-3 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-For-9-003-2022-दस-3, दिनांक 15 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव।

Bhopal the, 15th May 2023

NO.-FOR/9/0003/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927(No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

(A) declares that is has been decided to constitute the waste land and Forest land schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22°34' to 22°38" North Latitude and 76°13'76°35" East Longitude specified in the.

(B) appoints Suh Divisional Magistrate (Revenue) Bagli Dist. Dewas (M.P.) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

### SCHEDULE

District - Dewas  
Tehsil- Bagli

Forest Division - Dewas  
Forest Range- Bagli

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notificatio n Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				*Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bagli	Madhy Bharat Shasan Gazette Part- 1(Forest &Tribal Welfare Department Gwalior) 1101/XF/203	Bagli	Blanket Notific ation		10168.626	-	1101/XF/ 203(54) Date 01.03.19 55	1 <sup>st</sup> March 1955	North- Revenue villages karondiya, Bauraniya,Kramk hera,Chaiya, Nayapura, Chhotapura, Bagli, Jatashankar, Nayakhurt, Kotra, Salkhetiya,

Therefore the above land is being declared as Reserved forest under section 4 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
**ASHOK KUMAR, Addl. Secy.,**

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

क्रमांक-एफ-FOR/9/0003/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22<sup>0</sup>42' से 22<sup>0</sup>43' उत्तर अक्षांश तथा 76<sup>0</sup>26' से 76<sup>0</sup>28' पूर्व देशांश के बीच स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागली जिला देवास (म0प्र0) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

### अनुसूची

जिला - देवास  
तहसील - बागली

वनखंडल - देवास  
वन परिक्षेत्र - बागली

क्र	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका भव	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिपूचना क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				*पुराना	नया					
1.	सायन	मध्यभारत शासन गजट भाग-1 (फारेस्ट एण्ड ट्रायबल रेलफेयर डिपार्टमेंट ग्वालियर)	सायन	ब्लैकट नोटिफिकेशन	-	31.079	-	1101/दस एफ/203 (54) दिनांक 01.03.1955	01 मार्च 1955	उत्तर- इन्दौर - हरदा रोड। पूर्व- राजस्व ग्राम चंद्रकेश एंव खेड़ाखाली/ दक्षिण- राजस्व ग्राम करौदिया। पश्चिम-राजस्व ग्राम अगुली।

1101/दस एफ/203 (54) ग्वालियर दिनांक 01.03.1955										
योग (वनखण्ड का क्षेत्रफल)										
						31.079	हेक्टेयर			

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत आरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

एफ-FOR-9-0003-2022-दस-3 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-FOR-9-0003-2022-दस-3 दिनांक 15 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal the 15th May 2023

NO.-FOR/9/0003/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927(No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

(A) declares that is has been decided to constitute the waste land and Forest land schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22°35' to 22°43' North Latitude and 76°26' 76°28' East Longitude specified in the.

(B) appoints Sub Divisional Magistrate (Revenue) Bagli Dist. Dewas (M.P.) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

#### SCHEDULE

District - Dewas  
Tehsil- Bagli

Forest Division - Dewas  
Forest Range- Bagli

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publica tion of Gazette	Description of Boundaries
				*Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sayan	Madhy Bharat Shasan Gazette Part-1(Forest & Tribal Welfare Department Gwalior) 1101/XF/203(5 4)Gwalior Date	Sayan	Blanket Notification		31.079	-	1101/XF/2 03(54) Date 01.03.1955	1st March 1955	North- Indore-Harda Road East- R.V. Chandrakeshar and kherakhal South- R.V. Karondiya West- R.V. Agurli,

01.03.55										
Total (Block Area)						31.079				

Therefore the above land is being declared as Reserved forest under section 4 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

क्रमांक-एफ-FOR/9/0003/2022/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि :-

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वनभूमि जो वनखण्ड 22°37' से 22°38' उत्तर अक्षांश तथा 76°18' से 76°20' पूर्व देशांश के बीच स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागली जिला देवास (मोप्र0) को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

### अनुसूची

जिला - देवास  
तहसील - बागली

वनमंडल - देवास  
वन परिक्षेत्र - बागली

क्र	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना क्रमांक और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				*पुराना	नया					
1.	मालीपुरा	मध्यभारत शासन गजट भाग-1 (फारेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रवालियर) 1101/दस एफ/203 (54)	मालीपुरा	ब्लैकट नोटिफिकेशन	-	111.369	-	1101/दस एफ/203 (54) दिनांक 01.03.1955	01 मार्च 1955	उत्तर- राजस्व ग्राम बेहरी एवं अडालिया। पूर्व- राजस्व ग्राम नयागाव। दक्षिण- राजस्व ग्राम सेवन्धाखुर्द। पश्चिम-राजस्व ग्राम अडालिया, मालीपुरा।
	रवालियर दिनांक 01.03.1955									
	योग (वनखण्ड का क्षेत्रफल)					111.369 हेक्टेयर				

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत आरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

एफ-FOR-9-0003-2022-दस-3 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-FOR-9-0003-2022-दस-3 दिनांक 15 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव।

Bhopal the 15th May 2023

NO.-FOR/9/0003/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927(No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

(A) declares that is has been decided to constitute the waste land and Forest land schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between 22°37' to 22°38' North Latitude and 76°18' 76°20' East Longitude specified in the.

(B) appoints Sub Divisional Magistrate (Revenue) Bagli Dist. Dewas (M.P.) to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

#### SCHEDULE

District - Dewas  
Tehsil- Bagli

Forest Division - Dewas  
Forest Range- Bagli

No.	Proposed RF Forest Block	Parwari Helka No.	Village/P F Block	Khasra		Area (Hectares)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
1	2	3	4	*Old	New					
1	Malipura	Madhy Bharat Shasan Gazette Part-I(Forest & Tribal Welfare Department Gwalior) 1101/XF/203(54)	Malipura	Blanket Notification		111.369		1101/XF/203(54) Date 01.03.55	1 <sup>st</sup> March 1955	North- R. V. Behri, Adalya East- R. V. Nayagaon South- R. V. Sewanyakhurd West- R. V. Adalya, Malipura
Total (Block Area)						111.369				
		Gwalior Date 01.03.1955								

Therefore the above land is being declared as Reserved forest under section 4 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

क्रमांक-एफ-25-47/2018/10-3 :: चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1) दिनांक 12.01.2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7205-3177-06-दस-3 दिनांक 29.12.2006 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था;

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जा चुकी हैं।

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है। यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी। यह वनखण्ड से 22° 02' 1.924" से 22° 02' 27.304" उत्तर अक्षांश तथा 75° 26' 51.569" से 75° 26' 29.346" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

### अनुसूची

जिला :- खरगोन  
तहसील:- कसरावद

वनमण्डल:-खरगोन  
वनपरिक्षेत्र :- कसरावद

क्र	आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्रमांक / वन परिसर	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्र./ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसका अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	सीमाएं
-----	----------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--	------------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जहांगीरपुरा	34/ बालसमु द	जहांगीर पुरा/ जहांगीर पुरा	159/1 212/1 P-1176	ना- काबिल चरनोई	डी-886-4148-दस- 3-2003 दिनांक 24. 12.03 प्रकाशन दिनांक 16.01.04	11.00 19.00	उत्तर :- मुनारा क्र. 1 से 2 तक खसरा क. 213 की दक्षिणी सीमा। पूर्व :- मुनारा क्र. 2 से 26 तक खसरा क. 214, 210, 208, 207, 204 एवं ख. क्र. 200 की सीमा। दक्षिण:- मुनारा क्र. 26 से 30 तक खसरा क्र. 212/2 159/2 एवं 161 की सीमा पश्चिम :- मुनारा क्र. 30 से 35 एवं 1 तक खसरा क्र. 158 एवं ग्राम नायदड़ की सीमा।
		योग :-					30.00	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

एफ 25-47-2018-दस-3 : भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-9-47-2018-10-3 दिनांक 15 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार, अपर सचिव.



Bhopal, the 15th May 2023

No.F-25-47/2018/10-3 :: Where as, by this department Notification No. 7205--3177-06-X-3 dated 29.12.2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 12.01.2007 the State Government, under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest;

And whereas, all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between  $22^{\circ} 02' 1-924^{**}$  to  $22^{\circ} 02' 27-304^{**}$  North Latitude and  $75^{\circ} 26' 51-569^{**}$  to  $75^{\circ} 26' 29-346^{**}$  East Longitude.

### SCHEDULE

District- Khargone  
Tahsil- Kasrawad

Forest Division- Khargone (T)  
Forest Rang- Kasrawad

S. No.	RF Block	Patwari Halka No./Forest Beat	Village/ PF Block	Khasra No./PF Comparison	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date	Area (hectare)	Limits
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Jahangir pura	34/ Balsamud	Jahangir pura/ Jahangir pura	159/1 212/1 P-1176	Nakabil Charnoi	D-886-4148- X-3-2003- Date 24.12.03 Published Date 16.01.04	11.00 19.00	<p><b>North:-</b> Pillar no. 1 to 2 southern Boundary of Khasra no. 213.</p> <p><b>West :-</b> Pillar No. 2 to 26, boundaries of Khasra no. 214, 210, 208, 207, 204, and 200.</p> <p><b>South :-</b> Pillar No. 26 to 30, Boundary of Khasra no. 212/2, 159/2 and 161.</p> <p><b>West :-</b> Pillar No. 30 to 35 and 1, boundaries of khasra no. 158 and village Naided.</p>
<b>Total (Block Area)</b>							<b>30.00</b>	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

## कार्यालय, कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

क्र. 282-सहा. आयु.-वन अधि. -2023

डिण्डौरी, दिनांक 24 अप्रैल 2023

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल के जप क्रमांक एफ 23-2/2021/25-3/384 भोपाल दिनांक 22.04.2022 एवं जपान क्र. एफ 23-2/2021/25-3/484 भोपाल दिनांक 26.05.2022 द्वारा जारी निर्देश के तारतम्य में मंत्री परिषद आदेश आईएम क्रमांक 15 दिनांक 04 मई 2022 द्वारा किये गये अनु समर्थन के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (ज) के प्रावधान अंतर्गत प्रदेश के 827 वनग्रामों (वर्तमान में वन विभाग के प्रबंधन एवं नियंत्रणाधीन) को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें से 86 वनग्राम डिण्डौरी जिले के सम्मिलित हैं।

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला डिण्डौरी के पत्र क्रमांक 3478/सहा.आयु./वन अधि./2022 डिण्डौरी दिनांक 18.11.2022 के द्वारा 82 वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने की अधिसूचना जारी की गई है। शेष 04 वनग्राम- पौड़ी विकासखण्ड समानापुर, खम्हेरा, शीतलपानी एवं खपरीपानी विकासखण्ड बजाग में से निम्नांकित वनग्रामों को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा के परीक्षण उपरान्त जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा डिण्डौरी जिले के निम्नांकित वनग्रामों को राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

## विकासखण्ड-समानापुर

क्र.	तहसील का नाम	वनमण्डल का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वनकक्षा / कक्षों का क्रमांक जिसमें वन ग्राम स्थित है	वन ग्राम का नाम	वनग्राम का भौगोलिक रकबा	वनग्राम का क्षेत्र (हे.से.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की चयुक्त सीमाएँ				ग्राम की कुल जनसंख्या	वन अधिकार पट्टेदारों की संख्या
											उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	डिण्डौरी	डिण्डौरी	बजाग	पौड़ी	D-12 ढावा	491, 493B, 494B, 500B	पौड़ी	236.070	226.410	वनग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तन करने हेतु	आर.एफ. 493, 495	आर.एफ. 500	आर.एफ. 496	राजस्व सीमा	602	81

डि. प्र. 282-सहा. आयु.-वन अधि. -2023

विकासखण्ड-बजाग																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	बजाग	डिडीरी	बजाग	खम्हरा	K-2 बिजौरी	527B, 529B, 530B, 531B, 532B, 533B, 537C, 496B, 497B, 498B, 506B, 507B	खम्हरा	850.770	850.770	—	आर.एफ. 537	आर. एफ. 507, 506	आर.एफ. 527, 529, 531	आर. एफ. 598, 596	1115	129
3	बजाग	डिडीरी	बजाग	शीतलपान	K-2 बिजौरी	518B, 521B, 522B, 524B, 525B, 528B, 529C	शीतलपानी	410.200	368.610	—	आर.एफ. 525, 526	आर. एफ. 522, 524	आर.एफ. 528, 529	आर. एफ. 523 एवं राजस्व क्षेत्र	686	121

उपरोक्त संपरिवर्तन राजस्व ग्रामों में भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना, संधारण एवं प्रबंधन तथा अद्वितीयकरण किये जाने तथा राजस्व विवादों के निपटारे हेतु व्यवस्था बनाये जाने का भी निर्णय लिया गया है। उक्त के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

1/ वनग्राम से संपरिवर्तन राजस्व ग्राम में भू-अभिलेखों का तैयार किया जाना- (1) सर्वप्रथम ऐसे राजस्व ग्राम को, जिस तहसील में वे स्थित हैं, के निकटतम पटवारी हल्के के साथ संबद्ध किया जाए, इस प्रकार उनके भू-अभिलेख तैयार करने हेतु भू-सर्वेक्षण का कार्य ऐसे पटवारी हल्के का अंशभाग मानते हुए प्रारंभ किया जा सकेगा। वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम को निकटतम पटवारी हल्के में समाभिलेखित कर ऐसे पटवारी हल्के की पुनर्विचयना का प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख की ओर भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 104 के उपबंधों के अधीन ऐसे पटवारी हल्के की पुनर्विचयना का आदेश जारी करेंगे।

(2) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम की बाह्य सीमाओं को चिह्नित करते हुए ऐसे राजस्व ग्राम का कुल भू-भाग, तथा वन विभाग के पास उपलब्ध सभी भू-अभिलेख, भू-सर्वेक्षण कर राजस्व भू-अभिलेख तैयार करने तथा राजस्व भू-अभिलेख संधारित करने हेतु, जिला सर्वेक्षण अधिकारी (कलेक्टर) को सौंपे जाएंगे, जिन्हें भू-सर्वेक्षण के कार्य के लिए प्राथमिक अभिलेख के रूप में उपयोग किया जाएगा। वन विभाग द्वारा चिह्नित बाह्य सीमाओं के विषय में सीमा चिन्हों तथा निर्देशांकों (रिफरेंस पॉइंट) का रजिस्टर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख) नियम, 2020 (जिन्हें आगे सर्वेक्षण नियम कहा गया है) के नियम 210 में विहित प्रारूप-दस्ता में रखा जायेगा।

- (3) आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा भू-सर्वेक्षण प्रारंभ करने के लिए सर्वेक्षण नियम के नियम 10 के अधीन प्रारूप-बारह में अधिसूचना जारी की जाएगी और उक्त अधिसूचना की दिनांक से ऐसे राजस्व ग्राम के क्षेत्र को भू-सर्वेक्षण के अधीन धारित समझा जाएगा। राजस्व ग्राम में भू-सर्वेक्षण का कार्य संपन्न हो चुकने के पश्चात आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा भू-सर्वेक्षण को बंद करने की घोषणा सर्वेक्षण नियम के नियम 10 के अधीन विहित प्रारूप-तेरह में जारी की जाएगी।
- (4) सर्वेक्षण सक्रियार्ण संपन्न करने के दौरान और बाद में भू-अभिलेख संधारण के प्रत्येक प्रक्रम पर यथास्थिति नगरेत्तर क्षेत्रों की भूमि (आबादी को छोड़कर) के सर्वे हेतु मार्गदर्शिका जो आयुक्त भू-अभिलेख के पत्र क्रमांक 158/2021 दिनांक 16/02/2021 द्वारा जारी की गई है, के प्रोवधान भी यथोचित परिवर्तन सहित अनुसरित किए जाएंगे।
- (5) जिला सर्वेक्षण अधिकारी (जिला कलेक्टर) ऐसे राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण संचालन के प्रारंभ होने की अधिसूचना सर्वेक्षण नियम के नियम 14 के अधीन विहित प्रारूप-चौदह में जारी करेंगे। इस प्रकार सर्वेक्षण सक्रिया प्रारंभ कर सर्वप्रथम ड्रोन पदति का उपयोग करते हुए नक्शा तैयार कराया जाएगा, जिसमें स्थल पर भूमि उपयोग के आधार पर कृषि उपयोग में लिए जा रहे भू-खण्ड को सर्वेक्षण संख्यांक तथा कृषि भिन्न प्रयोजन में उपयोग में लिए जा रहे भू-भाग को ब्लॉक संख्यांक दिए जाएंगे और ब्लॉक संख्यांक के भीतर अलग-अलग प्रयोजन के अनुसार उपयोग में लिये जा रहे भू-खण्ड संख्यांक की सीमाएं संरक्षित करते हुए नक्शा तैयार किया जाएगा और प्रत्येक संख्यांक को यथास्थिति पृथक-पृथक क्रमांक दिये जाएंगे। इस कार्य हेतु जिला सर्वेक्षण अधिकारी अपने जिले में पदस्थ अन्य राजस्व कमियों को जिन्हें यह उचित समझे नियोजित कर सकेंगे।
- (6) इस प्रकार तैयार नक्शों में सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक तथा भू-खण्ड संख्यांक का आकार प्रदर्शित करते हुए उनके विषय में प्रारंभिक माप की गणना हेतु माप पुस्तिका तैयार की जाएगी और पैमाइश के अनुसार अद्यतन किये गए विद्यमान भू-अभिलेखों (वन विभाग से प्राप्त) का उपयोग करते हुए प्रारूप अभिलेख तैयार किया जायेगा। परन्तु यदि कोई भू-अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो भू-सर्वेक्षण के दौरान लिये गये माप तथा किये गये अवलोकन के आधार पर प्रारूप अभिलेख तैयार किया जायेगा।
- (7) इस प्रकार तैयार किये गये प्रारूप अभिलेख के विद्यमान अभिलेख अनुसार वनाधिकार की सूची तैयार की जाएगी, जिसमें सामुदायिक उपयोग में मान्य भू-भाग के ब्यारे भी वर्णित होंगे। जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी (जो उपखंड अधिकारी होगा) प्रारूप भू-अभिलेख के संबंध में दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु उद्घोषणा सर्वेक्षण नियम के नियम 17 के अधीन विहित प्रारूप-पंद्रह में जारी करेंगे, जिसमें दावे-आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु कम से कम 15 दिवस की अवधि दी जायेगी।
- (8) जिला सर्वेक्षण अधिकारी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे वनाधिकार प्राप्त हैं और जिसका नाम प्रारूप अभिलेख में है, सर्वेक्षण नियम 17 के अधीन विहित प्रारूप-सोलह में अपने दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु सूचना जारी करेंगे और सूचनाओं की तामिली की अभिसूचीकृति का रजिस्टर सर्वेक्षण नियम के नियम 17 के अधीन विहित प्रारूप-सत्रह में रखा जायेगा।
- (9) इस प्रकार दावे और आपत्तियों के लिये नियत अंतिम तिथि के पश्चात उनका जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी (जो उपखंड अधिकारी होगा) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और सर्वेक्षण नियम के नियम 17 एवं 18 के अनुसार कार्यवाही करते हुए प्रस्तुत दावे/आपत्तियों का विनिश्चय किया जाएगा। अंतिम भू-अभिलेखों के प्रकाशन की सूचना सर्वेक्षण नियम के नियम 20 के अधीन विहित प्रारूप उन्नीस में जारी की जायेगी।
- (10) उल्लेखनीय है कि ऊपर दिये गये उल्लेखानुसार प्रारूप अभिलेख के आधार पर तैयार किये गये अंतिम अभिलेख के रूप में ग्राम का खसरा सर्वेक्षण नियम के नियम 6प के अधीन विहित प्रारूप-एक में तैयार किया जायेगा, जिसमें कॉलम (7) में वनाधिकार धारक का नाम अंकित किया जायेगा। ऐसे व्यक्ति को वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधान अंतर्गत उद्भूत अधिकार प्राप्त रहेंगे, न कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन भूमिस्वामी के अधिकार। वनाधिकार धारक संहिता की धारा 181 के उपबंधों का सरकारी पैट्रदार नहीं है अतएव कॉलम (7) में उसके नाम व अन्य विवरण के साथ "वनाधिकार धारक" अवश्य लिखा जाएगा, साथ ही "अहस्तांतरणीय" भी लिखा जाएगा। ऐसे मामलों में खसरा के कॉलम (4), (5), (6) एवं (8) अनुपयोगी हैं, अतएव इन कॉलमों में "वनाधिकार धारक होने से लागू नहीं" अंकित किया जाएगा। तैयार किये गये अंतिम भू-अभिलेख के खसरा के आधार पर ग्रामवार खतौनी सर्वेक्षण नियम के नियम 8 के अधीन विहित प्रारूप-आठ में तैयार की जायेगी।
- (11) संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के ऐसे भू-भाग को, जिसमें वनवासी निवास करते हैं अर्थात् बसाहट-आबादी है, उसे स्थल की स्थिति के अनुसार एक या अधिक ब्लॉक संख्यांक दिए जाएंगे। जिसमें वनवासी द्वारा निवास या आनुवंशिक में उपयोगित भू-भाग को भू-खण्ड संख्यांक के रूप में दर्शाया जाएगा।

- (12) बसाहट-आबादी के भू-भाग की सर्वेक्षण सक्रियता संपन्न करने के दौरान और बाद में उनके भू-अभिलेख संधारण के प्रत्येक प्रक्रम पर यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के सर्वेक्षण का सर्वे कर अधिकार अभिलेख के निर्माण के लिए जारी दिशा निर्देश क्रमांक 3-4/2020/सात/शा.6 दिनांक 07.07.2020 के प्रावधान भी यथावश्यक परिवर्तन सहित अनुसरित किए जाएंगे।
- (13) खसरा में सामुदायिक उपयोग के भू-खंडों को सामुदायिक उपयोग-प्रयोजन अंकित किया जायेगा, यथा श्मशान/कब्रिस्तान, चारागाह, हाट-बाजार, स्कूल, आंगनवाड़ी, खेल का मैदान, स्वास्थ्य केन्द्र, खाल निकालने का स्थान, खाद के गड्डे, सड़क/गली आदि। इस प्रकार प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये सामुदायिक उपयोग के भू-खंडों हेतु एक पृथक सामुदायिक उपयोग-निस्तर पत्रक संधारित किया जायेगा।
- (14) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम में बसाहट-आबादी के भू-अभिलेख एवं निस्तर भूमि के भू-अभिलेख तैयार करने एवं संधारण के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा बाजिल-उल-अर्ज) नियम, 2020 (जिसे आगे दखलरहित भूमि नियम कहा गया है) यथावश्यक परिवर्तन सहित अनुसरित किए जाएंगे।
- (15) इस प्रकार तैयार किये गये खसरा के साथ-साथ एक पुनर्क्रमांकन रजिस्टर सर्वेक्षण नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्रारूप-छ: में रखा जायेगा जिसमें सर्वेक्षण के पूर्व के अभिलेखों के संख्यांक तथा सर्वेक्षण उपरांत दिये गये संख्यांक अंकित होंगे।
- (16) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के अंतिम भू-अभिलेख के तौर पर उपरोक्तानुसार तैयार किया गया नक्शा, खसरा तथा पुनर्क्रमांकन रजिस्टर भू-सर्वेक्षण की संक्रिया से निर्मित अंतिम अभिलेख के रूप में संधारित किये जायेंगे और खसरा के आधार पर तैयार की गयी ग्रामवार खतौनी ऐसे ग्राम का उपसंगी अभिलेख होगा।
- (17) भू-सर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान विभिन्न प्रक्रम पर तैयार किए जाने वाले अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करते हुए उनकी सॉफ्टवेयर की सुरक्षित रखी जाएगी और भविष्य में वैध आदेश के अनुसरण में किए जाने वाले परिवर्तनों का ऐसे आदेश के संदर्भ उल्लेख के साथ कंप्यूटरीकृत अभिलेख में प्रविष्टि अंकित की जाएगी।
- (18) यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि वनाधिकार धारक के भूमि में के हित वंशागत न्यायगमित हो सकते हैं, संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं हो सकते। अतः भू-अभिलेखों में और उनकी प्रतिलिपि प्रदान के समय प्रतिलिपियों में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि वनाधिकार धारक के भूमि के हित अहस्तरणीय हैं। वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के वनाधिकार धारकों को उनकी भूमि के विषय में कोई भू-अधिकार पुरस्तिता या ऐसा अन्य कोई अभिलेख या उसकी प्रति जारी नहीं की जाएगी जिससे उसके भूमिस्वामी होने का भ्रम होने की संभावना हो। ऐसी सतर्कता से भविष्य के विवादों से बचा जा सकेगा।
- 2/ नामांतरण:- (1) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के अनुसार वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना प्रावधानित है। धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसार ऐसे प्रदत्त कोई अधिकार वंशागत होंगे किन्तु, संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं होंगे।
- (2) वनाधिकार धारक भूमि में के अपने वनाधिकार या कोई हित विक्रय, दान या अन्यथा अंतरित नहीं कर सकता, तथापि ऐसे वनाधिकार धारक की मृत्यु के कारण उसके अधिकार वंशागत होंगे। अर्थात् धारक की मृत्यु के उपरांत उसकी स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अनुसार न्यायमित होंगे। स्पष्ट है कि धारक की मृत्यु होने पर भू-अभिलेखों में उसके वैध वारिसों के नाम से नामांतरण कर अभिलेखों को अद्यतन किया जाएगा।
- (3) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के भू-अभिलेखों को अद्यतन रखने के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 (जिन्हें आगे नामांतरण नियम कहा गया है) यथावश्यक परिवर्तन सहित संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के मामलों में अनुसरित किए जाएंगे।
- (4) भू-अभिलेखों को अद्यतन एवं शुद्ध रखने का दायित्व पटवारी का होगा और मृत वनाधिकार धारक के वैध वारिस धारक की मृत्यु की दिनांक से छह माह के भीतर भू-अभिलेखों में नामांतरण के लिए अपने अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट, पटवारी के माध्यम से या सीधे तहसीलदार को नामांतरण नियमों में विहित यथास्थिति प्रारूप का उपयोग ~~उत्कृष्ट~~ हुए, कर सकते हैं।

(5) तहसीलदार मृत वनाधिकार धारक के वारिसों की ओर से प्राप्त रिपोर्ट या पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन को संज्ञान में लेते हुए नामांतरण नियमों के उपबंधों का अनुसरण करते हुए सभी हितबद्धपक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे, संबंधित पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे, संबंधित पटवारी से आपत्ति/दावा हेतु सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे और इस प्रकार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट/नामांतरण हेतु आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिवस के भीतर परीक्षण कर भू-अभिलेखों में नामांतरण हेतु विधि अनुसार आदेश पारित कर भू-अभिलेख अद्यतन किए जाएंगे। इस प्रकार नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण होने पर नामांतरण आदेश की प्राप्ति और अद्यतन भू-अभिलेख की प्रति (खसरा एवं खतौनी की प्रति) समस्त हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की जाएगी।

3/ ~~सीमांकन~~ **सीमांकन:** (1) वनग्राम से संपरिवर्तन राजस्व ग्राम में वनाधिकार धारक की कृषि भूमि के विषय में यदि कोई सीमा विवाद है अथवा वह अपनी जानकारी/संतुष्टि के लिए सीमांकन कराना चाहता है तो वह तहसीलदार को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम में कृषिभूमि के सीमांकन के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन वने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 (जिन्हें आगे सीमांकन नियम कहा गया है) यथावश्यक परिवर्तन सहित संपरिवर्तित राजस्व ग्राम के मामलों में अनुसरित किए जाएंगे।

(3) सीमांकन के लिए उक्त सीमांकन नियमों में विहित प्रारूप में उक्त नियमों में विहित फीस के भुगतान के साथ आवेदन करना होगा। इस प्रकार आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को आवेदित सर्वेक्षित संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक पड़ोस के धारकों सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात आवेदित संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन करेगा और सीमांकन नियमों में विहित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट आवश्यक संलग्नकों सहित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा जिसका समुचित परीक्षण कर तहसीलदार अभिप्रमाणन करेगा।

(4) यदि कोई पक्षकार उक्तानुसार सीमांकन से प्रतिवेदित है तो यह उपखण्ड अधिकारी को अभ्यावेदन कर सकेगा और ऐसे मामले में उपखण्ड अधिकारी पुनः सीमांकन हेतु एक दल का गठन करेगा जिसमें अधीक्षक भू-अभिलेख या सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख या राजस्व निरीक्षक दल नायक होगा और एक अन्य राजस्व निरीक्षक सदस्य होगा, जो पुनः सीमांकन कर अपनी रिपोर्ट नियमों में विहित प्रारूप में आवश्यक संलग्नकों सहित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिस पर उपखण्ड अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

4/- **वन विभाग द्वारा जारी किए गए पंद्रह वर्षीय पट्टे-** (1) आरक्षित वन एवं संरक्षित वन के भीतर स्थित कतिपय भू-भाग पर राज्य शासन के वन विभाग द्वारा ऐसे क्षेत्र जो वनाच्छादित नहीं हैं, पर कतिपय कृषकों को पंद्रह वर्षीय कृषि पट्टे दिये हैं, जिनका अवधि अवसान के दौरान नवीकरण भी नहीं किया गया है, किन्तु वन विभाग द्वारा उन्हें अभी तक ऐसी पट्टाधीन भूमि पर से बेटखल नहीं किया गया है, और वे अभी भी अपने पूर्व पट्टे के आधार पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। ऐसे कृषि पट्टाधारियों के विवरण, उन्हें दिए गये मूल पट्टा या नवीकृत पट्टा तथा नक्सा के साथ, जिला सर्वेक्षण अधिकारी (कलेक्टर) को सौंपे जाएंगे।

(2) उपरोक्त उप कंडिका (1) के विवरण अनुसार ऐसे पंद्रह वर्षीय पट्टों को नवीकृत मानते हुए उनके विषय में भी भू-अभिलेख तैयार किए जाएंगे तथा उनके नामांतरण एवं सीमांकन के मामलों का इस परिपत्र के अनुसरण में, ऐसी प्रक्रिया जैसी कि वनाधिकार धारक के लिए प्रावधानित की गई है लागू करते हुए, निराकरण भी किया जाएगा।

परन्तु ऐसे मामलों में खसरा में वनाधिकार धारक नहीं लिखा जाएगा, बल्कि खसरा के कॉलम (7) में "पंद्रह वर्षीय कृषि पट्टा धारक" तथा "अहस्तानांतरणीय" लिखा जाएगा।

(3) यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पंद्रह वर्षीय पट्टा धारक की पट्टा अवधि भू-सर्वेक्षण के कृषि वर्ष से आगामी पंद्रह वर्ष पश्चात, जब तक वह नवीकृत नहीं कर दिया जाना, स्वतः सन्तप्त समझा जाएगा और तत्पश्चात ऐसा पट्टा धारक ऐसी भूमि पर अतिक्रमक माना जाएगा।

(4) चूंकि उक्तानुसार पंद्रह वर्षीय पट्टाधीन भूमि आरक्षित या संरक्षित के भीतर स्थित है, इस कारण ऐसे पट्टों का नवीकरण वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके अपने विभागीय दिशा निर्देश के अनुक्रम में किया जा सकेगा। यदि नवीकरण किया जाना है तो वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पट्टा नवीकरण की सूचना, एक प्रति के साथ तहसीलदार को संसूचित की जाएगी, जिसके अनुक्रम में भू-अभिलेख में प्रविष्टि अंकित की जाएगी।

तहसीलदार को संसूचित की जाएगी, जिसके अनुक्रम में भू-अभिलेख में प्रविष्टि अंकित की जाएगी।

- 5/- भू-अभिलेखों/राजस्व अभिलेखों का संधारण तथा प्रतिलिपि प्रदाय- (1) वनग्राम से संपरिवर्तित राजस्व ग्राम में इन दिशा निर्देशों की कंडिका 3 की प्रावधानित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जिला सर्वेक्षण अधिकारी (जिला कलेक्टर) अथवा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भू-सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप भू-सर्वेक्षण की कार्य संपन्न होने के पश्चात् बंद किए जाने की अधिसूचना के दिनांक की स्थिति में जो अंतिम अभिलेख तैयार किए गए हैं, यथा नक्शा खसरा पुनर्क्रमांक रजिस्टर एवं वनाधिकार धारकों के खातों के संधारण के लिए तैयार अंतिम अभिलेख यथास्थिति सॉफ्टवेयर एवं हार्डकोपी में तीन प्रति में तैयार किए जाएंगे जिनमें से एक प्रति आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश, एक प्रति जिला कलेक्टर के कार्यालय तथा एक प्रति तहसील कार्यालय के अभिलेखागार में संरक्षित रखी जाएगी। तहसील कार्यालय के अभिलेखागार में संरक्षित भू-अभिलेख में भू-सर्वेक्षण की संक्रियाएं बंद किए जाने की अधिसूचना के पश्चात् पारित किए गए विधिसंगत आदेशों के प्रभाव में ऐसे आदेशों के संदर्भ उल्लेख के साथ समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। इस प्रकार प्रथम बार तैयार भू-अभिलेख की एक-एक प्रति आयुक्त, भू-अभिलेख कार्यालय एवं जिला कार्यालय में सुरक्षित संधारित रहेगी और तहसील कार्यालय की प्रति विधिसंगत आदेशों के प्रभाव में आगामी प्रविष्टियां दर्ज की जाएगी।
- (2) उपरोक्तानुसार संधारित भू-अभिलेख एवं पश्चातवर्ती मामलों के राजस्व अभिलेख यथास्थिति तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय एवं आयुक्त भू-अभिलेख के कार्यालय के अभिलेखागार में सुरक्षित संधारित किए जाएंगे और इन्हें कार्यालयों की अभिलेखागार-सह-प्रतिलिपि शाखा में कोई भी व्यक्ति भू-अभिलेखों/राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा।
- (3) भू-अभिलेखों/राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन बने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के अध्याय-छः के प्रावधान अनुसरित किए जाएंगे अर्थात् इन प्रावधानों का अनुसरण करते हुए आवेदक खसरा, खतौनी या अन्य भू-अभिलेख अथवा राजस्व मामलों में पारित आदेशों का नियत शुल्क का भुगतान कर निरीक्षण कर सकेगा अथवा उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा।

विकास मिश्रा, कलेक्टर.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र. 5324 भू-अ.-2023

राजगढ़, दिनांक 18 मई 2023

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम रोजडखुर्द एवं किशनपुरिया के लिए डूब में प्रभावित शेष भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## -: अनुसूची :-

## गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम -रोजडखुर्द

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
1	प्यारा पिता देवीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	19/1/2	0.884	0.150
	योग	1	0.884	0.150
2	बीरम पिता बिहारीलाल पांचूबाई बेवा बिहारीलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	19/2/2	1.445	0.200
	योग	1	1.445	0.200
3	दुलैसिंह पिता बालूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	13/2/2	5.360	0.300
	योग	1	5.360	0.300
4	जगदीश पिता प्यारा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	17/5	1.836	1.077
	योग	1	1.836	1.077
5	जशवंतसिंह पिता जयनारायण जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	21/15/1	0.333	0.333
	योग	1	0.333	0.333
6	नारायण पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	21/15/2	0.667	0.667
	योग	1	0.667	0.667
7	घीसालाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी	15/2	2.496	1.450
	योग	1	2.496	1.450
8	शिवनारायण पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	13/3/2	0.843	0.250

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टे.)	शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
1	2	3	4	5
	योग	1	0.843	0.250
9	बीरम पिता हीरालाल, धापूबाई बेवा हीरालाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	13/4	3.794	0.360
	योग	1	3.794	0.360
10	रामप्रसाद, रमेश पिता नानूराम जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	33/7/2	1.455	0.100
	योग	1	1.455	0.100
	कुल योग	10	19.113	4.887
गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम – किशनपुरिया				
1	नारायण सिंह पिता शिवसिंह सौधिया नि. करेडी	197/9	0.759	0.150
	योग	1	0.759	0.150
	महायोग :-	11	19.872	5.037

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल एवं समुचित सरकार  
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. 02-अ-82-2022-23

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1, कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2022-23 चूँ कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में राजगंज मण्डी से भोपाल स्टेशन तक बड़ी रेल लाईन में तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम झिरनिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

**अनुसूची-1**

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	झिरनिया	0.5641	उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III, पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल	रामगंज मण्डी नई बड़ी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी लाईन।

**अनुसूची-2**

( प्रभावित धारको की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4	5.
1.	श्रीमती मनी बोरा पत्नी महेन्द्र बोरा, महेन्द्र बोरा आ० चंपालाल, नि नि०-भोपाल	632/2	0.650	0.045
2.	शायरा बानो पत्नी अय्यूब 128 नीलकंठ कॉलोनी, भोपाल	636 641/2 642/2	0.400 0.429 0.266	0.001 0.027 0.042
3.	अशोक कुमार आ० रामलाल यादव, मुंगालियाहाट	646/2	0.126	0.016
4	कामता प्रसाद आ० रामलाल यादव, मुंगालियाहाट	648/2	0.650	0.005

5.	रमेश, घनश्याम, प्रेमनारायण पुत्र रामप्रसाद, सुमित्राबाई बेवा फूलसिंह, शुभम दिनेश पिता फूलसिंह, झिरनिया	655	0.500	0.052
6.	कालूराम आ० धनलाल	656 / 1 / 2	0.173	0.103
7.	महेश आ० धनलाल	656 / 2	0.400	0.0006
8.	रामरतन आ० उमराव, मुंगालियाहाट	658 / 1 / 1 / 2	0.246	0.1580
9.	श्रीमती रिकी पाटीदार आ० हरिओम पाटीदार	658 / 1 / 2	0.182	0.0360
10.	श्रीमती मधु पाटीदार पत्नी हरगोविंद पाटीदार	658 / 1 / 3	0.182	0.0005
11.	रामरतन आ० उमराव, मुंगालियाहाट	659 / 1 / 2	0.137	0.078
	<b>कुल योग</b>		<b>4.341</b>	<b>0.5641</b>

चूँकि रामगंज मण्डी नई बड़ी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 03-अ-82-2022-23

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1, कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2022-23 चूँ कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में राजगंज मण्डी से भोपाल स्टेशन तक बड़ी रेल लाईन में तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम दौलतपुर ठिकरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	दौलतपुर ठिकरिया	0.208	उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III, पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल	रामगंज मण्डी नई बड़ी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी लाईन।

## अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	रामनारायण मांगीलाल नवलसिंह राजाराम ओमप्रकाश आ० रामफूल पार्वतीबाई पुत्री रामफूल भागवती बाई वि रामफूल कमलसिंह शिवनारायण आत्माराम आ० जगन्नाथ चतरीबाई वि० जगन्नाथ	110/2	0.241	0.014
2.	नन्हीबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण, विंध्याबाई पत्नी परमानन्द	158/2 159	0.428 0.440	0.030 0.015

3.	लक्ष्मीनारायण एवं परमानन्द आ० सालिगराम	164 / 2 165 / 2 166 / 2	1.101 0.318 0.729	0.031 0.039 0.009
4.	ओमप्रकाश आ० हरीदास मेघानी	168 / 2	0.3050	0.008
5.	शिव वाधवा आ० गालाराम	100 / 2 / 1 / 2	1.131	0.010
6.	रामनारायण आ० मांगीलाल वगैरह	100 / 2 / 2	0.350	0.006
7.	रामनारायण मांगीलाल नवलसिंह राजाराम वगैरह	111 / 1 / 2 / 2	0.388	0.006
8.	राधेश्याम लखनलाल तुलसीराम, लालजीराम आ० रामकिशन	88 / 2 / 1 / 2	0.560	0.014
9.	रामकिशन आ० दौलतराम	88 / 2 / 2 / 2 / 2	0.430	0.026
10.	शशिकला राजपूत पत्नि कमलसिंह राजपूत	111 / 1 / 1 / 2 / 1	—	पौधे का मुआवजा
11.	कमलसिंह राजपूत आ० जी०आर० राजपूत	108 / 1 / 2	—	पौधे का मुआवजा
	कुल योग	किता 14	6.421	0.208

चूँकि रामगंज मण्डी नई बड़ी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 04-अ-82-2022-23

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1, कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2022-23 चूँ कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में राजगंज मण्डी से भोपाल स्टेशन तक बड़ी रेल लाईन में तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम मुंगालिया हाट के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

## अनुसूची-1

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	मुंगालिया हाट	1.816	उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III, पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल	रामगंज मण्डी नई बड़ी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी लाईन।

## अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	वर्तमान भूमि खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	टेकचंद पिता शीतलदास, गांधीनगर	653/1/2/1	0.140	0.011
2.	टेकचंद पिता शीतलदास गांधीनगर	653/1/1/2	0.585	0.411
3.	घुडीलाल पिता शालिकराम गुजराती	660/2	0.827	0.121
4.	रघुवीर सिंह, बद्रीप्रसाद, गोविंदप्रसाद पुत्रगण बाबूलाल, रामकुंवर बाई पत्नी बाबूलाल गाडरी निवासी- ग्राम	672/2	0.079	0.036
5.	घिसीबाई बेवा उमराव सिंह जाति नाथ	663/6/2	0.158	0.085
6.	परमानंद पिता शालगराम नि ग्राम	670/2	0.608	0.046
7.	लक्ष्मीनारायण पिता शालगराम नि ग्राम	727/2	0.346	0.141

8.	राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती	726 / 2	0.117	0.081
9.	राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती	722 / 2	0.080	0.068
10.	हरिओम पिता परमानंद गुजराती	707 / 2	0.052	0.034
11.	लक्ष्मीनारायण आ० सालकराम गुजराती	718 / 2	0.666	0.100
12.	हरगोविंद पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार	703 / 2	0.518	0.113
13.	प्रभुलाल आ० देवीलाल साहू	702 / 2	0.404	0.061
14.	हरीनारायण पिता देवीलाल राठौर	700 / 2	0.940	0.070
15.	रामबाबू पुत्र झुन्नूलाल	695 / 1 / 2	0.490	0.154
16.	यादवेन्द्र पाटीदार पिता राधाकिशन पाटीदार	765 / 2	0.830	0.077
17.	विकास कुमार अग्रवाल पिता रमेशचन्द्र	766 / 2	0.715	0.001
18.	विमलाबाई पुत्री उमराव सिंह	663 / 5	0.170	0.005
19.	परमानंद पिता शालगराम	728 / 2	0.484	0.014
20.	राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती	731	0.260	0.057
21.	हरिओम पिता परमानंद गुजराती	708	0.400	0.045
22.	लक्ष्मीनारायण पिता शालगराम	721	0.200	0.009
23.	घुडीलाल पिता सालिगराम	653 / 2 / 1 / 1	0.4720	0.076
	कुल योग	22 किता	9.253	1.816

चूँकि रामगंज मण्डी नई बड़ी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
क्र. 440-भू-अर्जन-2023 सतना, दिनांक 4 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - गोबराव खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 5.5204 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	162	0.0300
2	163	0.0670
3	164	0.1450
4	165	0.0210
5	175	0.0520
6	176/1	0.0150
7	176/2	0.0110
8	177/2	0.0840
9	181	0.0450
10	182	0.0450
11	183	0.0420
12	184/1	0.0050
13	184/2	0.0110
14	186/1	0.0050
15	206	0.0100
16	207	0.0350
17	211	0.0380
18	212	0.0156
19	215	0.0050
20	217	0.0570
21	218/1	0.0150
22	218/2	0.0840
23	219/1	0.0450
24	219/2	0.0730
25	222	0.0030
26	223	0.0100

27	224/1	0.0450
28	225/1	0.0170
29	226	0.0080
30	227	0.2910
31	231/1/2	0.0260
32	232/1/2	0.0280
33	233/1	0.0450
34	234/2	0.0210
35	235	0.2680
36	236	0.0450
37	354	0.0750
38	362	0.0210
39	363	0.2550
40	364	0.1610
41	368	0.0210
42	369	0.2910
43	375/1	0.0682
44	375/2	0.1082
45	375/3	0.0402
46	377/1	0.0720
47	377/2	0.0840
48	377/3	0.0630
49	377/4	0.0720
50	381	0.2910
51	384/1	0.0312
52	385/1/2/2	0.0280
53	390/2	0.0130
54	391/1	0.0310
55	391/2	0.0310
56	391/3	0.0670
57	392	0.2600
58	393	0.0750
59	394	0.0840
60	395/1/1	0.0420
61	395/1/2	0.1100
62	395/1/3	0.0600
63	395/2	0.1050
64	578/1	0.0050
65	579	0.1650
66	580/1	0.0030

67	580/2	0.0420
68	581/2	0.0780
69	583	0.0310
70	608/2	0.0360
71	608/3	0.0550
72	609/1	0.0050
73	609/2	0.0170
74	609/3	0.0110
75	637	0.0630
76	638	0.0760
77	639	0.0520
78	640	0.0920
79	641	0.0210
80	642	0.0940
81	643	0.3040
82	646	0.0120
83	730/2	0.0360
निजी खाता भूमि योग रकबा - 5.5204 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 455-भू-अर्जन-2023

सतना, दिनांक 9 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - सेमरी दुबे

(घ) क्षेत्रफल- 1.9762 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	198/1	0.0800
2	198/2	0.0396
3	199/1/2	0.0856
4	199/2	0.0857
5	205/1	0.1508
6	212/3	0.0104
7	213/1	0.1280
8	213/2	0.1372
9	218	0.0644
10	219/1	0.0638
11	219/3	0.0090
12	220	0.0728
13	225	0.0728
14	231	0.1456
15	240/1	0.0560
16	240/2	0.0372
17	256	0.0405
18	257	0.0494
19	260	0.0552
20	261	0.0032
21	263	0.0140

22	264	0.1144
23	274	0.0336
24	275	0.0506
25	276	0.0280
26	279/1	0.0702
27	279/2	0.0702
28	280	0.0728
29	285	0.0364
30	286	0.0468
31	287	0.0520
निजी खाता भूमि योग रकवा - 1.9762 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 456-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - तुरकहा

(घ) क्षेत्रफल- 2.917 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	336/2	0.0690
2	313	0.0150
3	321	0.0440
4	333	0.0020
5	330	0.0150
6	331	0.1260
7	328	0.0480
8	324	0.0630
9	323	0.0310
10	322	0.0120
11	304	0.1850
12	222/2	0.0100
13	222/1	0.1550
14	201/2	0.1470
15	201/1	0.0100
16	197/1/1	0.0180
17	196/2	0.0760
18	196/1/2	0.0850
19	196/1/1	0.0850
20	193	0.0340
21	192	0.0320
22	185/1	0.0560
23	183	0.0480
24	182	0.0600
25	174/1/1	0.0200
26	174/1/2	0.0050
27	173	0.0940
28	168	0.1600
29	164/1	0.0060
30	163/2	0.0180
31	163/1	0.0210
32	162/2	0.0190
33	162/1	
34	162/3	
35	162/4/2	

36	162/4/1	
37	157/2	0.0650
38	157/1	0.0650
39	156/1	0.0050
40	155/1	0.1400
41	155/2	0.0200
42	154	0.0050
43	161/1	0.0050
44	161/2	
45	161/3	
46	161/4	
47	179/1/1	0.0840
48	185/2	0.0240
49	181	0.0150
50	223	0.0330
51	325	0.0290
52	327	0.0150
53	364/2/3	0.0210
54	364/2/2	0.0210
55	364/2/1	0.0200
56	363	0.0520
57	362	0.0210
58	361	0.0100
59	360/1	0.0180
60	360/2	0.0180
61	359/2	0.0370
62	359/1	0.0370
63	358/2	0.0250
64	358/1	0.0270
65	355	0.0140
66	354/3/1	0.1000
67	354/3/2	0.1020
68	364/4	0.0400
69	357/2	0.0480
70	351/1	0.0320
निजी खाता भूमि योग रकवा - 2.917 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 457-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - लगरगवां

(घ) क्षेत्रफल- 5.3698 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	39	0.4620
2	40	0.4250
3	41	0.0312
4	42	0.0104
5	137/1	0.0720
6	137/2	0.0730
7	138/1	0.2110
8	138/2	0.1410
9	139/2	0.0080
10	140/2	0.1040
11	141/1	0.0150
12	142/1/2	0.1250
13	143/1	0.0160
14	143/2/2	0.0100
15	144/1/1	0.1600
16	144/1/2	
17	144/1/3	
18	144/2/1	0.1250
19	144/3/2	0.1100
20	144/5/1	0.0160
21	144/5/2	0.1730
22	144/5/3	0.0840
23	164/2	0.0060
24	165/1	0.0130
25	165/2	0.0120
26	166/1	0.0090
27	166/2	0.0140
28	251/1	0.0032
29	252	0.0460
30	271	0.0920
31	272	0.1050
32	273	0.0104
33	275/2	0.0050
34	276/1	0.1300



35	276/2	0.1560
36	277	0.0380
37	278	0.0252
38	279	0.0020
39	280	0.0350
40	281	0.0310
41	282	0.0160
42	385/2	0.5410
43	411	0.0048
44	413	0.0154
45	415/1	0.0210
46	415/2	0.0940
47	416	0.0050
48	435	0.0350
49	436/1/1	0.5520
50	440	0.1510
51	443	0.0360
52	444	0.0504
53	445	0.0680
54	447	0.0312
55	448	0.0840
56	477	0.0196
57	478	0.0420
58	480	0.1360
59	481	0.0180
60	482	0.0570
61	483	0.0020
62	484/1	0.0550
63	484/2	0.0210
64	485	0.0260
65	488/1	0.0100
66	488/2	0.0940
67	488/3	0.0720
68	488/4	0.0080

निजी खाता भूमि योग रकवा - 5.3698 हे.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 458-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - गोबराव कला

(घ) क्षेत्रफल- 14.3391 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	26/20/1	0.1680
2	26/21	0.0840
3	26/22	0.0840
4	28/1	0.0050
5	28/2	0.0050
6	28/3	0.0050
7	28/4	0.0050
8	28/5	0.0050
9	53/1	0.1052
10	54	0.1738
11	56/1	0.0620
12	56/2	0.0610
13	56/3	0.0610
14	57/1/1	0.0560
15	57/1/2	0.0560
16	57/1/3	0.0560
17	58/1	0.1008
18	64	0.0100
19	65/2	0.0376
20	67/2	0.2280
21	83/1/1/1	0.2260
22	83/1/1/2/2	0.1640

23	83/1/1/5	0.2000
24	83/2	0.0200
25	84/1/1	0.0150
26	84/1/2	0.0490
27	114/2/2	0.0108
28	115/1	0.2800
29	115/2/2	0.2992
30	116	0.0228
31	117/1	0.0914
32	117/2	0.0150
33	239/1	0.1456
34	240	0.0288
35	241	0.2368
36	243	0.2208
37	244/1/1	0.0760
38	244/1/2	0.0776
39	266/1/2/2/2	0.0630
40	266/1/2/2	0.1713
41	266/1/1/1/2	0.1713
42	267/1	0.1924
43	268/1	0.3432
44	272/3	0.3484
45	275/1/1	0.0840
46	275/1/2	0.0830
47	327/1	0.1106
48	327/2	0.1240
49	327/3	0.1240
50	327/4	0.1250
51	328	0.0104
52	329	0.0208
53	334/3/3	0.1412
54	335/1	0.1398
55	335/2	0.2000

56	336	0.1352
57	342/1	0.2600
58	342/2	0.2600
59	393	0.1800
60	408	0.1040
61	409/1	0.0325
62	409/2	0.0325
63	409/3	0.0325
64	409/4	0.0325
65	410/1	0.1378
66	476	0.0120
67	477	0.0528
68	478	0.6240
69	479	0.0380
70	480	0.0780
71	523	0.0060
72	525	0.0520
73	526	0.0030
74	527	0.0730
75	529	0.0532
76	531	0.0728
77	532	0.0064
78	533	0.0720
79	534	0.0096
80	539/1/2	0.0080
81	540	0.1012
82	541	0.0030
83	543/1	0.0460
84	543/2	0.0476
85	585	0.0420
86	586	0.0070
87	596	0.0084
88	597	0.0210

89	598		0.0310
90	599/1		0.0020
91	1056		0.0520
92	1058/1		0.0031
93	1058/2		0.0031
94	1058/3		0.0082
95	1059		0.0100
96	1060		0.0100
97	1061		0.0520
98	1062		0.0520
99	1063/2		0.1208
100	1063/3		0.1288
101	1064		0.2210
102	1068/1		0.0090
103	1068/2		0.0090
104	1090		0.2080
105	1091		0.2184
106	1092		0.0320
107	1093		0.2340
108	1095/1		0.0210
109	1095/2		0.0570
110	1164/1		0.0312
111	1278		0.0670
112	1279		0.0200
113	1280		0.0048
114	1281		0.1560
115	1282		0.0562
116	1283		0.0020
117	1288		0.0020
118	1298/1	0.0780	
119	1298/2		
120	1298/3		
121	1298/4		

122	1299/1		
123	1299/2		
124	1299/3		0.0104
125	1299/4		
126	1299/5		
127	1300/1		
128	1300/2		0.0468
129	1300/3		
130	1303		0.0194
131	1304		0.0520
132	1305		0.1300
133	1306		0.0380
134	1309		0.0050
135	1310		0.0200
136	1312		0.0900
137	1343		0.0040
138	1350		0.0094
139	1351		0.0420
140	1352		0.0180
141	1353		0.0830
142	1354		0.0020
143	1369		0.0360
144	1370/2		0.0900
145	1371/2		0.0963
146	1372/1		0.0780
147	1372/2		0.0780
148	1373		0.0100
149	1381/1		0.1228
150	1381/2/1		0.0100
151	1381/2/2		0.2000
152	1382/1		0.1040
153	1382/2		
154	1401/2		0.1200

155	1545	0.0286
156	1546	0.0040
157	1561	0.1070
158	1562	0.0070
159	1563	0.0470
160	1564	0.0060
161	1567/1	0.1165
162	1567/2	
163	1568	0.1092
164	1570	0.0052
165	1571	0.1640
166	1572	0.0300
167	1573	0.0290
168	1585/1/2	0.0180
169	1598/1/2	0.0010
170	1599	0.1872
171	1600/1	0.0480
172	1600/2	
173	1602	0.0120
174	1603	0.0960
175	1606/1	0.0030
176	1607	0.0370
177	1608/1	0.0676
178	1608/2	
179	1616	0.0040
180	1617	0.2773
181	1618	0.0520
182	1619/1/1	0.2080
183	1619/1/2	
184	1619/1/3	
185	1619/1/4	
186	1619/2/2	
187	1631/2	0.1560

188	1632		0.0020
189	1633/1		0.0080
190	1634/4/2		0.2090
191	1636		0.0520
192	1637		0.0832
193	1638		0.0480
निजी खाता भूमि योग रकवा - 14.3391 हे.			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।



क्र. 459-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - श्यामनगर

(घ) क्षेत्रफल- 10.0999 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	135/1	0.0210
2	136/1	0.1920
3	137/1	0.1030
4	138	0.0600
5	141	0.0110
6	160/2	0.1920
7	161/2	0.0100
8	165/2	0.0100
9	166	0.0105
10	168	0.0840
11	171	0.1200
12	172	0.0160
13	175	0.0040
14	176	0.0020
15	178	0.1320
16	179	0.1200
17	180/2	0.0160
18	181/1	0.2080
19	268/2/1/1	0.0200
20	269/1/1	0.0840
21	269/1/2	0.0840
22	269/3	0.1040
23	269/5/2	0.0340
24	269/8/1	0.0240
25	275	0.0400
26	276	0.0160
27	278	0.1620
28	279	0.1620
29	705	0.0400
30	706	0.0250
31	709/2	0.0200
32	711	0.0080

33	712/1	0.0120
34	713	0.0600
35	717/2	0.0120
36	718/1	0.1580
37	718/2	0.1740
38	719/2	0.0020
39	724	0.0520
40	729	0.0200
41	730	0.0310
42	753/2	0.0400
43	754/1	0.1220
44	754/2	0.1220
45	755/1	0.0040
46	836	0.0060
47	837	0.0050
48	838	0.6020
49	839	0.0130
50	840	0.0080
51	841	0.0080
52	1301/2	0.1040
53	1303/2	0.1870
54	1303/3	0.0400
55	1303/4/1/2	0.0250
56	1303/5/1	0.0700
57	1303/5/2	0.0500
58	1303/6	0.0100
59	1303/7	0.0940
60	1353	0.0840
61	1355/1	0.0580
62	1355/2/1	0.0400
63	1355/2/2	0.0140
64	1356	0.0020
65	1360	0.0600
66	1361	0.0800
67	1697/1	0.0740
68	1697/2/4	0.1020
69	1698/1	0.0100
70	1698/3/2	0.3180
71	1699/1	0.0030
72	1699/2	0.0030
73	1735	0.0220
74	1737	0.0420
75	1740	0.0410
76	1741	0.0120
77	1742	0.0420
78	1743	0.0300
79	1744	0.0020
80	1745	0.0680
81	1746	0.0360

82	1751	0.0140
83	1753	0.0160
84	1754	0.0330
85	1755	0.0160
86	1756	0.0480
87	1757	0.0700
88	1758	0.0020
89	1768	0.0360
90	1769	0.0250
91	1770	0.0390
92	1772	0.0780
93	1773	0.0210
94	1924	0.0050
95	1934/1	0.0600
96	1934/2	0.0200
97	1935/1	0.0010
98	1935/2	0.0010
99	1936/1/1	0.0440
100	1936/1/2/1	0.0280
101	1936/1/2/2	0.0280
102	1936/2/1	0.0500
103	1936/2/2	0.0500
104	1937	0.0800
105	1946	0.0010
106	2095/1/1/1/1	0.0050
107	2095/1/1/1/2	0.0050
108	2095/1/1/1/3	0.0050
109	2095/1/2	0.0150
110	2095/2/1	0.0200
111	2095/2/2	0.0100
112	2095/2/3	0.0100
113	2097/1/2/1	0.3580
114	2172	0.0021
115	2173	0.0320
116	2185	0.0500
117	2186	0.0010
118	2187	0.0360
119	2188	0.0800
120	2189	0.0360
121	2190/2	0.0200
122	2190/3	0.0520
123	2191	0.0160
124	2192	0.0040
125	2213	0.0560
126	2214	0.0180
127	2215	0.0600
128	2220	0.0020
129	2221	0.0240
130	2222	0.0300

131	2223	0.0320
132	2225	0.0083
133	2226	0.0400
134	2227	0.0560
135	2229	0.0010
136	2230	0.0020
137	2234	0.0160
138	2246	0.0080
139	2247	0.0100
140	2250	0.0160
141	2252	0.0470
142	2257	0.0640
143	2259	0.0590
144	2260	0.0870
145	2261	0.1100
146	2283	0.0210
147	2286	0.0310
148	2287	0.0050
149	2285	0.0640
150	2325/1/1/1	0.0280
151	2325/1/1/2	0.0280
152	2325/1/1/3	0.0280
153	2325/1/2	0.0940
154	2325/2/1	0.0420
155	2325/2/2	0.0100
156	2326/2/2	0.0140
157	2326/5/1/1	0.1120
158	2326/5/2/1	0.1540
159	2326/5/3/1	0.1800
160	268/2/1/1	0.0220
161	269/5/2	0.0180
162	389/1/1	0.0050
163	389/1/2	0.0050
164	389/2/1	0.0210
165	389/3/2	0.0110
166	392/1/2/2/1	0.0410
167	392/1/2/2/2	0.0410
168	392/1/2/3/1	0.0360
169	392/1/2/3/2	0.0360
170	392/1/2/4/2	0.0790
171	392/2/2	0.0300
172	392/2/4	0.0550
173	394/1/1	0.0020
174	394/1/2	0.0020
175	394/2/1	0.0020
176	394/2/2	0.0020
177	394/3/2	0.0020
178	394/4	0.0020
179	395/1/1	0.0180

180	395/1/2	0.0180
181	395/2/1	0.0180
182	395/2/2	0.0170
183	395/3/1	0.0230
184	395/3/2	0.0170
185	395/4	0.0370
186	398	0.0100
187	399	0.1300
188	400	0.0160
189	423	0.4050
190	426	0.0400
191	430	0.0400
192	431	0.0240
193	432/1/1/1	0.0800
194	432/1/4	0.3560
195	432/2/3	0.0500
निजी खाता भूमि योग रकवा - 10.0999 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 462-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - मैसासुर

(घ) क्षेत्रफल- 3.5241 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	264	0.0145
2	263	0.1052
3	266/1	0.0390
4	206	0.2104
5	210	0.0221
6	211	0.0319
7	205/1	0.0258
8	205/2	
9	212	0.0420
10	884	0.1013
11	886/1	0.4951
12	886/2	
13	886/3	
14	888/2/3	0.1395
15	888/2/4	
16	890	0.0240
17	891	0.0940

18	892	0.0840	
19	882	0.1670	
20	885/1	0.3959	
21	885/2		
22	887/2	0.0020	
23	878/2/1/1	0.0020	
24	880	1.0000	
25	845	0.0630	
26	844/11	0.2202	
27	879	0.0146	
28	846/1	0.0020	
29	883	0.0100	
30	881	0.0310	
31	213/2/1/1/1	0.0926	
32	213/2/1/1/2		
33	213/2/1/2		
34	213/2/2		
35	209	0.0950	
निजी खाता भूमि योग रकवा - 3.5241 हे.			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 555-भू-अर्जन-2023

सतना, दिनांक 15 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - अंतरवेद

(घ) क्षेत्रफल- 5.5300 हे०

स.क्र.	आराजी क्र.	अर्जित रकबा
1	39/2	0.0310
2	39/4	0.1460
3	39/5	0.1460
4	41/2	0.0130
5	41/94/1	0.0050
6	42	0.6130
7	42/97	0.0420
8	43/1	1.7040
9	43/2	
10	43/3	
11	43/4	
12	44/1	0.0080
13	45/1	0.0020
14	47/98	0.0430
15	47	0.0120
16	49/1	0.0360



17	49/3	0.0050
18	49/4	0.0160
19	49/5	0.9160
20	50/1	0.2300
21	50/2	0.2930
22	50/3	0.1360
23	51/1	0.0210
24	51/2	0.0420
25	53/1	0.0940
26	53/2	0.0840
27	53/3	0.0630
28	55	0.0630
29	57/2	0.4280
30	57/3	0.0650
31	60	0.1260
32	61	0.1470
निजी खाता भूमि योग रकवा – 5.5300 हे.		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है— बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
प्र. क्र. 010-अ-82-2022-2023 सीहोर, दिनांक 23 मई 2023

### प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क' 30 सन् 2013).)  
प्रकरण क्रमांक 010/अ-82/2022-2023, चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें सलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

### -अनुसूची - भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल एकड़/हेक्टर	धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सीहोर	जावर	गुराडिया बर्मा	137.721 हेक्टर	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग सीहोर	गुराडियाबर्मा जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन

स.क्र.	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्ट.)	अर्जित रकबा (हेक्ट.)
1	2	3	4
<b>इस प्रभावित भूमि</b>			
1	479/1	0.551	0.135
2	480	0.955	0.081
3	487/2/1	1.457	0.490
4	514/1	0.514	0.305
5	514/2	0.514	0.315
6	514/3	0.514	0.185
7	515/1, 516	1.039	0.405
8	515/2, 516/2	1.043	0.245
9	517/1, 518, 551	0.498	0.325
10	517/2	0.494	0.025
11	519/2	0.757	0.250
12	520/1	0.526	0.526
13	520/2	0.526	0.425
14	520/3	0.526	0.285
15	521/1/1/1	0.174	0.174
16	521/1/1/2	0.178	0.178
17	521/1/1/3	0.356	0.325
18	521/1/1/4	0.356	0.300
19	521/1/2	1.060	1.060
20	521/2	0.146	0.146
21	530/1	0.880	0.225
22	530/2	0.775	0.375
23	533/1/1	1.619	0.290
24	533/1/2	0.676	0.200

25	533/2	0.105	0.105
26	534/1/1	0.117	0.117
27	534/1/2	0.809	0.100
28	534/6	1.396	0.070
29	535	3.906	0.525
30	536/1, 536/2, 537	2.736	0.125
31	538/1/1, 539/1/1	0.874	0.600
32	538/1/2, 539/1/2	0.874	0.290
33	538/1/3, 539/1/3	0.882	0.275
34	540/1	0.902	0.902
35	540/2	0.202	0.202
36	542/1	0.032	0.032
37	542/2/1	0.109	0.109
38	542/2/2	0.255	0.255
39	542/2/3	0.255	0.255
40	542/3	0.065	0.065
41	543/1/1	0.243	0.243
42	543/1/2/1	0.437	0.437
43	543/1/2/2	0.433	0.433
44	543/2/1	0.202	0.202
45	543/2/2/1	0.736	0.736
46	543/2/2/2	0.454	0.454
47	543/3/1/1 (s) 543/3/1/1 क	0.332	0.332
48	543/3/1/2	0.522	0.522
49	543/3/1/1/2	0.129	0.129
50	543/3/1/3	0.647	0.647
51	543/3/2	0.129	0.129
52	544/1	0.563	0.563
53	544/2/1	0.567	0.567
54	544/2/2	0.040	0.040
55	545, 546	2.514	2.514
56	547/1, 548/1	0.551	0.551
57	547/2, 548/2	0.498	0.498
58	549, 550	1.477	1.250
59	552, 553, 554	1.097	1.097
60	555/1	0.053	0.053
61	555/2	0.324	0.324
62	555/3	0.053	0.053
63	557/1, 558/1	0.162	0.162
64	557/2/1	0.146	0.146
65	557/2/2, 558/2 ख	0.413	0.413
66	557/2/3, 558/2 ग	0.137	0.137
67	557/2/4	0.267	0.267
68	557/5, 558/5	0.162	0.162
69	559/1	0.890	0.890
70	559/2	0.890	0.890
71	559/3	0.890	0.890
72	560/1	0.316	0.316
73	560/2	0.320	0.320
74	561/1	0.374	0.374

75	561/2	0.375	0.375
76	563/1, 564, 565/1	0.320	0.320
77	563/2, 564, 565/2	0.320	0.320
78	566/1, 569/1	1.044	1.044
79	566/2, 569/2	1.271	1.271
80	567/1/1	0.227	0.227
81	567/1/2	0.227	0.227
82	567/2/1	0.227	0.227
83	567/2/2	0.227	0.227
84	567/3	0.453	0.453
85	568/1, 601/1	0.575	0.575
86	568/2, 601/2	0.575	0.575
87	568/3/1, सा. 601	0.206	0.206
88	568/3/2, सा. 601	0.162	0.162
89	568/3/3, 601/3	0.206	0.206
90	568/4, 601/4	0.579	0.579
91	570/1	1.505	1.505
92	570/2	1.773	1.773
93	571/1, 558	1.271	0.305
94	571/2	0.227	0.110
95	582/2, 827, 582	0.680	0.060
96	582/3, 827, 582	0.267	0.040
97	600/2	0.539	0.539
98	600/3	0.543	0.543
99	861/601	0.486	0.468
100	602	0.190	0.150
101	604	0.879	0.600
102	605/1	0.405	0.405
103	605/2	0.397	0.397
104	611/1	0.538	0.538
105	611/2	0.538	0.538
106	686/3/2, 687, 819/3 ख	0.461	0.050
107	688/4/1, 689, 819/4/1	1.878	1.420
108	688/4/2, 689, 819/4/2	0.934	0.720
109	688/4/3, 689, 819/4/3	0.938	0.770
110	690/5/1, 691, 819/5/1	3.080	3.080
111	690/5/2, 691, 819/5/2	1.477	1.477
112	690/5/2/2, 691, 819	1.477	1.477
113	690/5/3, 691, 819	0.970	0.970
114	690/5/4, 691, 819/5/4	0.931	0.931
115	690/5/5, 691, 919	0.409	0.409
116	690/5/6, सा. 691, 919	0.365	0.365
117	690/5/9, 691, 919/5 ख	0.405	0.405
118	692/1, 693	0.765	0.225
119	694, 695, 696, 697	3.298	0.675
120	699/1/1	0.959	0.959
121	699/1/2	0.959	0.959
122	699/2, 700, 701/2	0.774	0.525
123	699/3, 700, 701/3	0.774	0.265
124	699/4, 700, 701/4	0.369	0.160

125	702/1/1, 703/1 क	0.800	0.690
126	702/1/2, 703/1 ख	0.996	0.385
127	702/2/1, 703/2/1	1.267	0.100
128	705/1 अ	0.295	0.295
129	705/1/23	0.291	0.291
130	705/1/32	0.587	0.587
131	705/2/1	0.024	0.024
132	705/2/2	0.024	0.024
133	705/2/3	0.024	0.024
134	706/1	0.203	0.203
135	706/2	0.080	0.080
136	707	0.405	0.405
137	708/1, 709/1	1.096	1.096
138	708/2, 709/2	1.096	1.096
139	708/3, 709/3	1.096	1.096
140	710/1, 711	0.486	0.486
141	710/2/1, 711/2	0.137	0.137
142	710/2/2, 711/2	0.349	0.349
143	712/1, 713, 714/1	1.230	1.230
144	712/2, 713, 714/2	0.202	0.202
145	718/1, 719/1	1.056	1.056
146	718/2/1	0.405	0.405
147	718/2/2	0.647	0.647
148	718/3, 719/3	0.405	0.405
149	720/1/1	0.933	0.933
150	720/1/2	0.933	0.933
151	720/2, 721/2	1.866	1.866
152	722	1.193	1.193
153	723	0.327	0.327
154	725/1	0.624	0.624
155	725/2	0.093	0.093
156	726/1/1/1	0.158	0.158
157	726/1/1/2	0.153	0.153
158	726/1/2	0.404	0.404
159	726/2, 727/2	0.377	0.377
160	729/1	1.028	1.028
161	729/2/1	1.024	0.945
162	729/2/23	1.024	1.024
163	729/3	0.247	0.247
164	730/1	0.834	0.834
165	730/2	0.146	0.146
166	731	0.316	0.316
167	733/1, 734, 735/1	1.134	1.134
168	733/2, 734, 735/2	1.136	1.136
169	736/1, 737, 739/1	0.558	0.558
170	736/2, 737, 739/2	0.567	0.567
171	736/3, 737, 739/3	0.567	0.567
172	736/4, 737, 739/4	0.562	0.562
173	738/1	0.190	0.190
174	738/2	0.190	0.190

175	738/3	0.190	0.190
176	738/4	0.190	0.190
177	740/1	0.239	0.239
178	740/2	0.243	0.243
179	741, 742, 743	1.623	1.623
180	745/46	1.085	1.085
181	747, 748	2.007	2.007
182	749	1.092	1.092
183	750	2.027	2.027
184	751/52	1.383	1.383
185	753	0.543	0.543
186	754/1, 755	0.218	0.218
187	754/2, 755/2	0.470	0.470
188	754/3, 755/3	0.458	0.458
189	757, 758, 759	4.754	4.754
190	760/1, 761, 762, 763, 764/1	1.598	1.598
191	760/2, 761, 762, 763, 764/2	2.140	1.695
192	760/3/1	0.467	0.467
193	760/3/2	0.467	0.467
194	760/4, 761, 762, 763, 764/4	1.214	1.214
195	765/4	0.405	0.085
196	769/1	0.595	0.285
197	769/3	1.191	0.065
198	781/1	0.881	0.110
199	781/2/1	0.186	0.060
200	781/2/2	0.190	0.061
201	784/2	0.763	0.260
202	796/2	0.340	0.240
203	797/1/1, 798/1/1	0.433	0.433
204	797/1/2, 798/1/2	0.433	0.433
205	797/2/1	1.015	0.600
206	797/2/2	1.016	0.600
207	800/1, 801, 802/1	2.655	2.335
208	803/1/1/1, 804, 805/1/1	0.397	0.344
209	803/1/1/2, 804, 805/1/1/ख	0.781	0.202
210	803/1/2, 804, 805/1/2	0.514	0.514
211	803/1/3, 804, 805	0.388	0.388
212	806, 807/1	1.438	1.055
213	813/1	1.539	0.510
214	814/1	2.602	1.450
215	814/2	3.253	2.000
216	814/3	0.388	0.050
217	815/2	0.202	0.105
218	816/1/1, 817, 818/2 ख	0.587	0.587
219	816/1/2, 817, 818/1 ख	1.420	1.420
220	816/1/3, 817, 818/1 ग	0.547	0.547
221	816/2	2.428	2.428
222	819/1/5	0.656	0.050
223	819/1/13	3.157	1.214
224	819/1/15	0.587	0.245

225	891/611	1.072	0.810
	योग	169.337	128.112
स्मिल चनेल हेतु भूमि			
1	469/1/1/1, 494/1, 495/2/1/क/1	1.263	0.420
2	469/1/1/2, 495/2/1/क/2	1.197	0.680
3	469/2/1/1	0.615	0.030
4	469/2/1/2, 494/1, 495/2/1/ख	0.615	0.100
5	469/2/1/7, 494/1, 495/2/छ	1.230	0.325
6	470/2	0.765	0.070
7	485/1	0.291	0.195
8	485/2	0.295	0.030
9	486	0.583	0.380
10	487/1/2/1, 487/2/1क	0.761	0.600
11	487/1/2/2, 487/2/2ख	0.700	0.190
12	487/1/3/2, 487/2/3ख	0.732	0.732
13	487/2/1, 487/2/1	1.457	1.165
14	487/2/3/1, 487/2/3/क	0.728	0.728
15	488/1	0.504	0.250
16	488/2	0.504	0.504
17	488/3	0.505	0.505
18	489/1	0.360	0.098
19	489/2	0.267	0.080
20	489/3	0.360	0.180
21	489/4	0.361	0.255
22	490	0.656	0.600
23	491/1	0.065	0.039
24	491/2	0.065	0.065
25	491/3	0.065	0.065
26	492/1	0.494	0.275
27	492/2	0.494	0.185
28	492/3	0.494	0.125
29	492/4	0.494	0.070
30	513	0.830	0.260
31	514/1	0.514	0.209
32	514/2	0.514	0.199
	योग	18.778	9.609

2. भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील आष्टा में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।
4. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कोई भी व्यक्ति अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलिंगम सृजित नहीं करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश  
क्र.-री-1-2023-1251

उज्जैन, दिनांक 26 मई 2023

**प्रारूप 'घ'**

(नियम-6 के अंतर्गत)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमि पाईप लाईन केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा (3) उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी के अधिसूचना पत्र क्रमांक 680 रिडर 1/2023 उज्जैन दिनांक 16.03.2023 राज्य सरकार ने नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना उज्जैन नगर जिला उज्जैन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाए। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केवल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवेक प्रतीत होता है संलग्न अधिसूचना बिना विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन इस आशय की घोषणा की है और अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम अधिकारी तहसील कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत व संबंधित ग्राम के लोग समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी/अधिभोगी को दे दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (1) पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि का उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

**/अनुसूची/**

क्र.	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	आर.ओ.यू. (फसल)	प्रभावित क्षेत्र पाईप	सिंचित/असिंचित
01	सूर्याशइफाकान प्रायवेट लिमिटेड, उज्जैन द्वारा डायरेक्टर नीरज जैन पिता नरेन्द्र कुमार जैन	3296/1(s)	0.5330	0.2280	0.255	सिंचित
02	अंशुल कुमार पिता सुशील जैन	3297/1(s)	0.8780	0.2860	0.032	सिंचित
03	विनायक बिल्डर्स द्वारा भागीदार मुकेश पिता मनोहरलाल, सत्यनारायण माली पिता यालमुकुंद माली	3293/1/3(s)	1.0250	0.1480	0.0166	सिंचित
04	विष्णुलाल, नागूलाल, शिवनारायण गोवर्धन, मोतीलाल, परमानंद, चंदरबाई पिता मूलचंद	3306/1(s)	7.0380	0.3540	0.0396	सिंचित
05	भरत पिता करमशी भाई, प्रमोदा बेन पति भरत कुमार, नीरा शाह पिता आशीष शाह	3307/2/1(s)	0.1060	0.0570	0.0064	सिंचित
06	गोविन्द पिता पन्नालाल हिस्सा 1/8, संजय पिता चण्णालाल, इंदरबाई, चंदाबाई, पार्वतीबाई, मंजुबाई, कोमल पुत्रियां चण्णालाल, भगवन्ताबाई बेवा चण्णालाल हिस्सा 1/8, हुकुमचंद पिता पन्नालाल हिस्सा 1/8, रमेश पिता पन्नालाल 1/8, बसन्तीबाई बेवा पन्नालाल	3308/2(s)	1.2540	0.4570	0.0512	सिंचित



07.	मेहनलाल पिता रामरतन	3324/1(s)	1.6200	0.1260	0.041	सिंचित
08.	मेसर्स गौतम इन्फ्रा सुशील जैन पिता वसंतीलाल, मुकेश राका पिता हीरालाल जी	3324/2(s)	3.1360	0.4340	0.486	सिंचित
09.	कैलाश नारायण, कौशल, किशोर पिता हीरालाल	3326/1/4(s)	0.0390	0.0370	0.0041	सिंचित
10.	जवाहरलाल, गोविन्द जी पिता बेनीराम अहीर	3334/1(s)	1.1080	0.1490	0.0167	सिंचित
11.	जवाहरलाल, गोविन्द जी पिता बेनीराम अहीर	3335 (s)	0.5230	0.2510	0.0281	सिंचित
12.	शासकीय	3337(s)	0.2300	0.0680	0.0076	सिंचित
13.	रमेशचन्द्र पिता वेणीराम	3338(s)	1.0140	0.2290	0.0226	सिंचित
14.	रमेशचन्द्र पिता वेणीराम	3228(s)	0.1880	0.1030	0.0115	सिंचित
15.	रमेशचन्द्र पिता वेणीराम	3226(s)	0.9930	0.1710	0.0192	सिंचित
16.	शासकीय	3328, 3329, 3330	8.0270	0.4220	0.0473	सिंचित
	कुल		28.712	3.520	0.3911	सिंचित

कल्याणी पाण्डे, सक्षम प्राधिकारी एवं भू अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी.

## नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

## सूचना

क्र. यूडीएच-03-0043-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश
- (2) कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
- (3) आयुक्त, नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
- (4) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

क्र. यूडीएच-03-0043-2023-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-यूडीएच-03-0043-2023-अठारह-5, दिनांक 26 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 26<sup>th</sup> May 2023

## NOTICE

No. UDH-3-0043-2023-XVIII-5.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Chhindwara (Planning Area) 2035 under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Commissioner, Jabalpur division, Jabalpur, Madhya Pradesh.
- (2) Collector, District Chhindwara, Madhya Pradesh
- (3) Commissioner, Nagar Palik Nigam, Chhindwara, Madhya Pradesh
- (4) Deputy Director, Town & Country Planning, District Office Chhindwara, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

## सूचना

क्र. यूडीएच-3-0087-2023-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा अशोकनगर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (1) आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- (2) कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश
- (3) मुख्य नगर पालिक अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अशोकनगर, मध्यप्रदेश
- (4) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, गुना, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

क्र. यूडीएच-3-0087-2023-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-क्र. यूडीएच-3-0087-2023-अठारह-5, दिनांक 26 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 26<sup>th</sup> May 2023

## NOTICE

No. UDH-3-0087-2023-XVIII-5.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Ashok Nagar (Planning Area) 2035 under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Commissioner, Gwalior division, Gwalior, Madhya Pradesh.
- (2) Collector, District Ashok Nagar, Madhya Pradesh
- (3) Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Ashok Nagar, Madhya Pradesh
- (4) Deputy Director, Town & Country Planning, District Office Guna, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

सूचना

क्रमांक एफ-3-86/2021/18-5 :- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि, राज्य सरकार द्वारा उज्जैन निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन, म0प्र0।
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन, म0प्र0।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, उज्जैन, म0प्र0।
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन, म0प्र0।

2/ उज्जैन विकास योजना (प्रारूप) 2035 में उपांतरण संबंधी मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (2) में जारी सूचना दिनांक 01/04/2022 (म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 08.04.2022 को प्रकाशित) पर निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सुनवाई उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है कि, निम्न दो उपांतरण विलोपित करते हुये उज्जैन विकास योजना (प्रारूप) 2035 को अंतिम किया जायें :-

1/ अनुसूची की कंडिका क्रमांक-2 सरल क्रमांक-15 (4) अध्याय-6 विकास नियमन की कंडिका-6.27 के बिन्दु क्रमांक-1 को प्रतिस्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव।

2/ अनुसूची की कंडिका क्रमांक-2 सरल क्रमांक-17(1) में क्रमांक-7 पर गऊघाट से सावराखेड़ी को जोड़ने हेतु नदी पर ब्रिज।

टीप :- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-23-क(1)(ख) के तहत जिस भूमि पर उपयोग उपांतरण संबंधी प्रकरण अंतिम अधिसूचना जारी किये जाने हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम-15 उपनियम-(15) के प्रभावशील होने की दिनांक 29.08.2022 के पूर्व विभाग को प्राप्त हो गये थे एवं अंतिम अधिसूचना जारी करने के पूर्व उज्जैन विकास योजना-2035 में उनका समाधान हो जाता हो, उन पर उज्जैन विकास योजना 2035 के भूमि उपयोग प्रस्ताव तभी प्रभावशील होंगे जब उस पर भू-उपयोग उपांतरण संबंधी लेव्ही विभाग में जमा करा दी गई हो।

3/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-19 की उपधारा-(5) के प्रावधान अनुसार इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

क्र. एफ-03-86-2021-अटारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक- एफ-03-86-2021-अटारह-5, दिनांक 26 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 26<sup>th</sup> May 2023

#### NOTICE

**No. F-3-86/2021/18-5 :** Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Ujjain (Planning Area) 2035 under sub-section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

- 1- Commissioner, Ujjain division Ujjain, M.P.,
- 2- Collector, District Ujjain, M.P.,
- 3- Commissioner, Municipal Corporation, Ujjain, M.P.,
- 4- Joint Director, Town & Country Planning, District Office Ujjain, M.P.,

2/ Objection/suggestion received within the stipulated time period on the notification dated 01-04-2022 (Published in State Gazette on 08-04-2022) regarding modification in Ujjain Development Plan, 2035 were heard and it has been decided that :-

The following two proposed modifications be deleted and Ujjain Development Plan be finalized: -

- 1- Proposal regarding substitution of clause 6.27 of chapter 6 Development regulations, mentioned in point no 2 serial no. 15 (4) of the schedule.
- 2- Bridge joining Gaughat to Sawarakhedi on river mentioned is serial no. 7 of point no 17 (1) of the schedule.

**Note-** The cases regarding modification in development Plan under section 23-a(1)b, which have been received in the department before coming into effect of sub rule 15 of rule 15 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012 get resolved in Ujjain Development Plan, 2035 shall only be effective, when the levy regarding change of land use is deposited with the department.

**3/** The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazette under section 19 (5) of M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

---